राष्ट्रीय संस्करण

विजडन की टी-20 टीम में कोहली और बुमराह
>> 14

वर्ष 3 अंक 203

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 31 दिसंबर 2019

www.jagran.com
पृष्ठ 16

सरोकार

लोहे से लड़ रणजीत ने बदल दी दो पीढ़ियों की तकदीर

गुरदासपुर : जज्बे और हिम्मत की मिसाल हैं पंजाब के गुरदासपुर जिले के छोटे से कस्बे कलानौर की 60 वर्षीय रणजीत कौर। उन्होंने 24 साल पहले पति की मौत के बाद परिवार के सामने खड़ी मुसीबतों को अपने हौसले से बौना साबित कर दिखाया। (पेज-11)

जागरण विशेष

अनसुलझी पहेली! शीला की जुबानी पूरी कहानी...

नई दिल्ली : ओशो का इतिहास पहेली है। मानो रहस्य-रोमांच से भरी कोई अधूरी कहानी। ओशो यानी रजनीश की सबसे करीबी व सबसे विद्रोही शिष्या रहीं मां आनंद शीला की जुबानी वह पूरी कहानी। शीला का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

सतत विकास में केरल अव्वल और बिहार फिसड्डी

नई दिल्ली : नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सूचकांक-2019 में केरल ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है जबकि बिहार प्रदर्शन के मामले में फिसड्डी रहा है। इस सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 7

मप्र के हनी ट्रैप मामले में मंत्रियों के ओएसडी भी शामिल

भोपाल : मध्य प्रदेश के हनी ट्रैप मामले में दो मंत्रियों के ओएसडी के नाम भी सामने आए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। मानव तस्करी से जुड़े मामले में विशेष जांच दल (एसआइटी) द्वारा पेश चालान में ओएसडी हरीश खरे और अरुण निगम के नाम शामिल हैं।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 12

एसबीआइ ने लोन ग्राहकों को दिया नए साल का तोहफा

मुंबई : भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने खुदरा लोन समेत एमएसएमई सेक्टर के ग्राहकों को नए साल का तोहफा दिया है। एसबीआइ ने एक्सटर्नल बेंचमार्क-बेस्ड रेट को 8.05 से घटाकर 7.80 परसेंट प्रतिवर्ष कर दिया है। नई ब्याज दरें बुधवार से प्रभावी होंगी।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

हिजबुल्ला के ठिकानों पर अमेरिकी हमला, 25 की मौत

बगदाद : इराक व सीरिया में कातिब हिजबुल्ला और हिजबुल्ला ब्रिगेड के पांच ठिकानों पर अमेरिकी सेना के हमले में 25 लोग मारे गए और 51 घायल हो गए। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने कहा, हमले यह संदेश देने के लिए किए गए हैं कि अमेरिकियों के जीवन को खतरे में डालने वाली ईरान की किसी कार्रवाई को अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा।

ठंड के साथ कोहरे की मार, दिल्ली में टूटा 119 साल का रिकॉर्ड

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

दिल्ली में शायद ही कोई होगा, जिसने सोमवार जैसी ठिठुरन अपने जीवन में देखी हो। पखवाड़े भर से कंपकंपा देने वाली ठंड ने 119 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिन ही नहीं, बल्कि पूरा दिसंबर माह सन् 1901 के बाद सबसे ठंडा रहा है। अधिकतम तापमान सामान्य से 11 डिग्री नीचे गिरकर 9.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। 1997 में दिसंबर माह में अधिकतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस गया था।

रविवार रात से ही राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे की मोटी परत दिखने लगी थी। सोमवार सुबह दृश्यता शून्य हो गई। दिन में भी कोहरे एवं प्रदूषण के मिश्रण से घना स्मॉग छाया रहा। इससे पूरे दिन जबरदस्त ठंड रही। गर्म कपड़े पहनने के बावजूद लोग कांपते रहे। न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री कम 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 97 से 100 फीसद रहा।

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पारा जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मप्र में ग्वालियर व दतिया का न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस था। जयपुर में 55 साल बाद एक डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उत्तराखंड में सुबह-शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों समेत कई झीलें जम गई हैं।

आज भी परेशान करेगी सर्दी : प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि मंगलवार को भी सर्दी का प्रकोप ऐसे ही बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुधवार और गुरुवार को बारिश के कारण रात का तापमान बढ़कर 7 से 8 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिन का तापमान 15 से 16 डिग्री के आसपास जा सकता है।

ठंड से उप्र में 62 मरे पेज>>6

- पूरे उत्तर भारत में जनजीवन प्रभावित, रेल और हवाई यातायात बाधित
- 1901 के बाद दिल्ली में रही सबसे लंबी शीतलहर
- जयपुर में 55 साल बाद 1 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान

दिल्ली में सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे घने कोहरे से दृश्यता बेहद कम रही। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर गुजरना पड़ा। ध्रुव कुमार

लगातार शीतलहर के हुए 18 दिन

दिल्ली में 18 दिनों से शीतलहर चल रही है, जबकि दिसंबर 1997 में 17 दिन बर्फीली हवाएं चली थी। इस दृष्टि से शीतलहर का भी ऑल टाइम रिकॉर्ड बन गया है। मौसम विभाग के अनुसार 1919, 1929, 1961 और 1997 में दिसंबर माह का औसत अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहा है। इस वर्ष अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री पहुंच गया है, जो शुक्रवार तक और नीचे जाएगा ।

डायवर्ट करनी पड़ीं 500 उड़ानें

कोहरे के चलते दृश्यता बहुत कम होने से रेल और सड़क यातायात प्रभावित हैं। राजधानी व शताब्दी जैसी ट्रेनें भी घंटों विलंब से चल रही हैं। दिल्ली, लखनऊ और चंडीगढ़ हवाई अड्डों पर विमान सेवाएं प्रभावित हुईं। दिल्ली में लगभग 500 उड़ानें डायवर्ट करनी पड़ीं।

शहर	न्यूनतम तापमान
श्रीनगर	-6.6
मथुरा	.5
मनाली	-2.8
शिमला	3.6
पिथौरागढ़	1.4
फरीदकोट	0.7
सीकर	0.5
ग्वालियर	2.0
दिल्ली	2.6

(डिग्री सेल्सियस में)

हथियारों के फर्जी लाइसेंस केस में सीबीआइ की बड़ी कार्रवाई

भ्रष्टाचार पर वार ▸ जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद राज्य में केंद्रीय एजेंसी ने पहली बार की छापेमारी

दो वरिष्ठ आइएएस अफसरों समेत कई राज्यों में 17 ठिकानों की ली तलाशी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन और उसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने वहां के प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआइ ने गैरकानूनी तरीके से दूसरे राज्यों के लोगों को हथियारों के लाइसेंस देने के मामले में जम्मू-कश्मीर के आठ जिलों के उपायुक्त या जिलाधिकारियों के ठिकानों समेत कुल 17 स्थानों पर छापा मारा, जिनमें दो आइएएस अधिकारी यशा मुद्गल और कुमार राजीव रंजन शामिल हैं। 2007 बैच की आइएएस अधिकारी मुद्गल फिलहाल जम्मू पॉवर डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन की सीएमडी और 2010 बैच के आइएएस अधिकारी राजीव रंजन जम्मू-श्रीनगर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सीईओ हैं।

सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, राज्य प्रशासन की सिफारिश पर पिछले साल अगस्त में इस मामल में दो केस दर्ज किए गए थे और जुलाई महीनेमें मुख्य तौर हथियार बेचने वाले लाइसेंसी दुकानदारों के यहां छापा मारा गया था, जिसमें बड़ी मात्रा में दस्तावेज बरामद हुए थे। उनकी पड़ताल व जांच के बाद सोमवार को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुला, उधमपुर, किश्तवार, सोपियां,राजौरी, डोडा, पुलवामा के तत्कालीन उपायुक्तों या जिलाधिकारियों के ठिकानों की तलाशी ली गई। इनमें कश्मीर में तीन, जम्मू में 11 और मोहाली (पंजाब), गुरुग्राम (हरियाणा), और नोएडा (उत्तर प्रदेश) में एक-एक स्थान शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर से 2012 से 2017 के बीच जारी सभी लाइसेंस की जांच की जा रही है।

दरअसल जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर गैरकानूनी तरीके से हथियार का लाइसेंस दूसरे राज्यों के लोगों को देने के रैकेट को राजस्थान के आतंकरोधी दस्ते (एटीएस) ने उजागर करते हुए नवंबर 2017 में 52 लोगों को गिरफ्तार किया था। एटीएस के अनुसार जम्मू क्षेत्र के डोडा, रामबन और उधमपुर जिले में कुल एक लाख 43 हजार 13 हथियारों के लाइसेंस में से एक लाख 32 हजार 321 लाइसेंस दूसरे राज्यों के लोगों को जारी किए गए थे। पूरे जम्मू-कश्मीर में पिछले एक दशक में जारी चार लाख 29 हजार 301 लाइसेंस में से केवल 10 फीसदी ही राज्य के लोगों को दिए गए थे।

जाहिर है आतंकवाद से ग्रस्त राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से हथियारों के लाइसेंस जारी किए जा रहे थे। इसके बाद राजस्थान के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक ओपी गलहोत्रा ने पूरे मामले की जांच सीबीआइ से कराने का अनुरोध किया था। बाद में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल एसपी मलिक ने इसकी जांच सीबीआइ से कराने की सिफारिश की थी। यही नहीं उन्होंने जुलाई 2018 में जनवरी 2017 से लेकर फरवरी 2018 के बीच राज्य से जारी किए गए हथियारों के सभी लाइसेंस को रद कर दिया था। (पेज-सात भी देखें)

फर्जी गन लाइसेंस मामले की जांच कर रही सीबीआइ की टीम सोमवार को जम्मू में सतवारी के अशोक नगर स्थित जम्मू-कश्मीर पॉवर डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन (जेकेपीडीसी) कार्यालय में आइएएस अधिकारी यशा मुदगल से पूछताछ करने पहुंची। जागरण

बेटे आदित्य को उद्धव ने बनाया कैबिनेट मंत्री

राज्य ब्यूरो, मुंबई

▸ महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार, अजीत पवार फिर बने उप मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र में करीब एक माह पुरानी उद्धव ठाकरे सरकार का सोमवार को पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने पुत्र आदित्य ठाकरे को कैबिनेट मंत्री बनाया है। महाराष्ट्र में पिता के मुख्यमंत्री रहते पुत्र के मंत्री बनने का यह संभवतः पहला मामला है। राकांपा नेता अजीत पवार ने एक बार फिर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वह रिकॉर्ड चौथी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है।

महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में 26 कैबिनेट एवं 10 राज्य मंत्रियों को राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अजीत पवार ने दो माह के भीतर दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 23 नवंबर को उन्होंने भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस के साथ इस पद की शपथ ली थी। मंत्रिमंडल में आदित्य के अलावा कुछ और युवा चेहरों को शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल में तीन महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इनमें से दो को कैबिनेट एवं एक को राज्यमंत्री बनाया गया है। दोपहर एक बजे शुरू हुए शपथ ग्रहण समारोह में राकांपा के 10 कैबिनेट,चार राज्यमंत्री, कांग्रेस के आठ कैबिनेट, दो राज्यमंत्री तथा शिवसेना कोटे से आठ कैबिनेट एवं चार राज्यमंत्रियों ने शपथ ली। शिवसेना ने अपने कोटे में निर्दलीय विधायक शंकरराव गडाख को तथा राज्यमंत्री कोटे में दो निर्दलीय विधायकों बच्चू कडू एवं राजेंद्र यड्रावकर को स्थान दिया है। इस प्रकार ठाकरे मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 43 हो गई है। इनमें 16 राकांपा के, 15 शिवसेना के एवं 12 कांग्रेस के हैं। उद्धव के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय शिवसेना, कांग्रेस एवं राकांपा के दो-दो कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी।

मुंबई में सोमवार को विधान भवन में आयोजित समारोह में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पिता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का अभिवादन करते आदित्य ठाकरे। प्रेट्र

भाजपा ने किया बहिष्कार पेज>>4

फेसबुक ने कश्मीर पर पाकिस्तान के फर्जी प्रचार पर लगाई रोक

- सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अब नहीं हो सकेगा पीबीसी की खबरों का सीधा प्रसारण
- प्रसारण मानकों के उल्लंघन को लेकर पीबीसी को पहले भी दी थी चेतावनी

इस्लामाबाद, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर में तेजी से सामान्य होते हालात को देखकर पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार के लिए वो हर हथकंडा अपना रहा है। सोमवार को उसने फेसबुक के जरिए दुष्प्रचार करना चाहा, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। फेसबुक ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (पीबीसी) की ओर से कश्मीर को लेकर किए जा रहे फर्जी प्रचार के उसके सीधे प्रसारण पर रोक लगा दी। पीबीसी अब इसका रोना रो रहा है।

पीबीसी ने सोमवार को कहा कि कश्मीर में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन, कर्फ्यू और पाबंदी को लेकर रेडियो पाकिस्तान के बुलेटिन के सीधे प्रसारण को फेसबुक प्रशासन ने रोक दिया। पीबीसी ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें फेसबुक की तरफ से मई में उसे चेतावनी दी गई है। फेसबुक ने तब पीबीसी पर प्रसारण मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। पाकिस्तान सरकार की मुख्य प्रवक्ता फिरदौस आशिक अवान ने फेसबुक की तरफ से लगाई गई रोक को मूल मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार फेसबुक पर रेडियो पाकिस्तान की खबरों का दोबारा सीधा प्रसारण शुरू कराने की कोशिश करेगी।

नौसेना में फेसबुक पर पाबंदी पेज>>3

जनरल बिपिन रावत बने देश के पहले सीडीएस

- सरकार ने लगाई मुहर, तीनों सेनाओं के समन्वयक के रूप में निभाएंगे भूमिका
- कारगिल युद्ध के समय से ही उठ रही थी इस पद के सृजन को लेकर मांग

नई दिल्ली, आइएएनएस : देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के तौर पर जनरल बिपिन रावत के नाम पर मुहर लग गई है। सोमवार को सरकार ने इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को यह पद सृजित करने का एलान किया था और 24 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सीडीएस की भूमिका तीनों सेनाओं और सरकार के बीच समन्वयक की रहेगी। कारगिल युद्ध के बाद से ही इस तरह के पद की मांग उठ रही थी। उस समय रिपोर्टों में यह सामने आया था कि सेनाओं के बीच समन्वय की कमी के कारण युद्ध में ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था।

पद सृजित किए जाने के बाद से ही जनरल बिपिन रावत को पहला सीडीएस बनाए जाने की चर्चा थी। रविवार को सरकार ने सीडीएस के लिए अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाकर 62 से 65 साल कर दिया था। इसे भी इस पद पर रावत की नियुक्ति से जोड़कर देखा जा रहा था। जनरल रावत सेना प्रमुख के पद से मंगलवार को रिटायर होने जा रहे हैं। 16 मार्च, 1958 को जन्मे बिपिन रावत मार्च, 2020 में 62 साल के हो जाएंगे। सीडीएस पद पर रावत की नियुक्ति की खबर आते ही ट्विटर पर शुभकामनाओं की बाढ़ आ गई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, 'जनरल रावत को पहला सीडीएस बनने पर बधाई। सशस्त्र बलों से संबंधित सभी मसलों के प्रधान सैन्य सलाहकार के नए मिशन के लिए मेरी शुभकामनाएं।' भाजपा नेता बैजयंत जय पांडा और कई ट्विटर यूजर्स ने भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं।

इसलिए पड़ी जरूरत : युद्ध की स्थिति में तीनों सेनाओं के बीच समन्वय सबसे बड़ी चुनौती रहती है। युद्ध के बदलते हालात में देश की सुरक्षा को देखते हुए इस समन्वय की जरूरत और भी बढ़ गई है। सीडीएस की नियुक्ति से इसमें मदद मिलेगी। तीनों सेनाओं को समान गति से बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

यह है प्रस्ताव : सीडीएस की भूमिका रक्षा व इससे जुड़े मामलों में प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री के एकीकृत सलाहकार की होगी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय में 'डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स' के नाम से नया विभाग गठित होगा और सीडीएस इसके सचिव होंगे। यह विभाग केवल सैन्य क्षेत्र से जुड़े मामले देखेगा। सीडीएस का उद्देश्य सेनाओं को ट्रेनिंग, स्टाफ व अन्य अभियानों के लिए एकीकृत करना होगा। सरकार को बेहतर सैन्य सुझाव भी मिल सकेंगे।

भूमिका और जिम्मेदारी : सीडीएस की नियुक्ति के बाद भी तीनों सेना प्रमुख विशेष मामलों को लेकर रक्षा मंत्री को सलाह देते रहेंगे। सीडीएस को किसी कमांड के लिए कोई भूमिका नहीं निभानी होगी। सीडीएस रक्षा संपदा परिषद, रक्षा प्लानिंग कमेटी के सदस्य होंगे। वह ऑपरेशन, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, मेंटिनेंस जैसी बातों के लिए तीनों सेनाओं के एकीकरण पर काम करेंगे।

नई दिल्ली में सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करते थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत। एएनआइ

दूर होगा भ्रम

प्रधानमंत्री मोदी ने आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव का वीडियो किया ट्वीट, सद्गुरु ने साझा किया पाक में अल्पसंख्यकों के साथ प्रताड़ना का अनुभव

सीएए संग भारत, पीएम की अगुआई में भाजपा ने शुरू किया अभियान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर समर्थन जुटाने के लिए भाजपा नेताओं ने सोमवार को सोशल मीडिया पर 'इंडिया सपोर्ट्स सीएए' हैशटैग से अभियान शुरू किया। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव का वीडियो ट्वीट कर सच्चाई सामने रखी। प्रधानमंत्री ने सद्गुरु के वीडियो से नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से सुनने और सच्चाई जानने की अपील की।

प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा कि सद्गुरु ने ऐतिहासिक संदर्भों के साथ भाईचारे की हमारी संस्कृति पर शानदार ढंग से प्रकाश डाला है। यही नहीं सद्गुरु ने वीडियो में बताया है कि किस तरह निहित स्वार्थी समूहों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के बारे में गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। दरअसल, सद्गुरु से लखनऊ की एक लड़की ने नागरिकता संशोधन कानून से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने की गुजारिश की थी। इस दौरान सद्गुरु ने बताया कि भारत में हमेशा से सभी धर्मों के लिए समान आदर की परंपरा रही है और किसी के साथ धर्म के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया गया। यही नहीं, आजादी के समय धर्म के आधार पर देश का बंटवारा जरूर हो गया, लेकिन भारत ने पंथनिरपेक्षता को स्वीकार किया। जबकि पड़ोसी देश ने इस्लामिक गणतंत्र को स्वीकार किया।

नरेंद्र मोदी फाइल फोटो

वीडियो में सद्गुरु ने अजरबैजान के बाकू मंदिर में पाकिस्तान से आए हिंदुओं के साथ अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि किस तरह वहां कानून के तहत धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उनके अनुसार पाकिस्तान से आए एक हिंदू ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा था कि शादी के ढाई साल बाद उसकी पत्नी को जबरन उठाकर ले जाया गया और उसी दिन शाम को धर्म परिवर्तन कर उसका निकाह किसी अन्य मुस्लिम के साथ कर दिया गया। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह व्यक्ति पुलिस या अदालत में कोई शिकायत दर्ज नहीं करा पाया क्योंकि पाकिस्तान में कानूनन सिर्फ इस्लाम के तहत हुए निकाह को मान्यता है, किसी अन्य धर्म के अनुरूप हुई शादी की कानूनी मान्यता ही नहीं है। सद्गुरु ने पड़ोसी देशों में हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध जैसे अल्पसंख्यकों के अलावा अन्य समुदाय के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के आधार पर सीएए में उन्हें भी शामिल करने के तर्क को भी खारिज कर दिया। उनका कहना था कि दुनिया के सभी देशों में कोई न कोई समुदाय इस तरह के आरोप लगाता रहता है, लेकिन हम सभी के लिए नागरिकता के दरवाजे नहीं खोल सकते। यह केवल 2014 तक आने अल्पसंख्यकों तक सीमित है।

सीएए के खिलाफ हो रहे विरोध पर दुख जताते हुए जग्गी वासुदेव ने कहा कि सरकार को भी इतने बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बताया कि किस तरह आम भारतीय मुसलमानों को नागरिकता खत्म हो जाने का भय दिखाया गया जो पूरी तरह से गलत है। साथ ही जग्गी वासुदेव ने बताया कि पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में एनआरसी है। देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें रहने वाले सभी नागरिकों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जग्गी वासुदेव के अनुसार सरकार इस मामले में जनता को पूरी जानकारी देने में असफल रही। यह जानकारी दी जानी चाहिए।

कानून पर सियासत (विशेष) पेज>>5

रेलवे भी उपद्रवियों से नुकसान की वसूली की तैयारी में

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सीएए विरोध के नाम पर उपद्रवियों ने पहुंचाया 80 करोड़ का नुकसान
- तोड़फोड़ करने वालों पर रेलवे एक्ट की धारा 151 के तहत दर्ज होंगे मुकदमे

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर रेलवे भी सीएए विरोध के नाम पर परिसंपत्तियों का नुकसान करने वाले उपद्रवियों से वसूली करेगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद यादव ने इसका एलान किया। उन्होंने कहा कि सीएए का विरोध करने के नाम पर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और आगजनी के जरिये विभिन्न जोनों में 80 करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। अब उन्हीं लोगों से वसूली कर नुकसान की भरपाई की जाएगी। रेलवे अफसरों के अनुसार, इसके लिए उपद्रवियों के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 151 के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। रेलवे एक्ट में रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को सात साल तक की कैद का प्रावधान है। चूंकि कानून-व्यवस्था राज्यों का विषय है, इसलिए उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए रेलवे को राज्यों की सहमति लेनी होगी। असम में भाजपा सरकार होने के कारण यह आसान होगा, जबकि बंगाल में तृणमूल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख को देखते हुए ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। हालांकि, रेल मंत्री पीयूष गोयल ममता बनर्जी से उपद्रवियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर चुके हैं।

सबसे ज्यादा 70 करोड़ की परिसंपत्तियों का नुकसान पूर्व रेलवे में हुआ है। 10 करोड़ का नुकसान पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में हुआ है। दक्षिण-मध्य रेलवे को हुई क्षति का आकलन किया जा रहा है।

4 जनवरी को राजधानी के सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होगी। सुबह की पाली के स्कूलों में सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक और शाम की पाली के स्कूलों में दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक पीटीएम होगी।

घोषणा ▸ एनडीएमसी और कैंट के सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिया तोहफा

बोर्ड परीक्षा की फीस भरेगी दिल्ली सरकार

कैंट क्षेत्र में भी 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू, फौजियों को होगा लाभ

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने सोमवार को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और कैंट एरिया के सरकारी स्कूलों के छात्रों की बोर्ड परीक्षा फीस भरने के फैसले को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यह योजना पिछले कुछ माह से लागू है, मगर इसमें एनडीएमसी और कैंट एरिया के स्कूल शामिल नहीं थे। अब एनडीएमसी और दिल्ली कैंट एरिया के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की बोर्ड परीक्षा फीस दिल्ली सरकार देगी।

केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के नतीजों का निरीक्षण किया तो पाया कि गणित व विज्ञान के अलावा सभी विषयों में परिणाम 95 फीसद से अधिक रहा है। सरकारी स्कूलों का गणित का परिणाम 76 फीसद से कम रहा, इसलिए सरकार ने तय किया है कि जहां-जहां जरूरत होगी, वहां पर गणित की अतिरिक्त कोचिंग दी जाएगी। इसके अलावा जो परीक्षा में फेल हो जाएंगे या जिन्हें पूरक परीक्षा देनी होगी, उनको भी अतिरिक्त कक्षाएं दिलाकर उन्हें पास कराने की कोशिश की जाएगी।

एंटरप्रन्योरशिप कार्यक्रम के तहत प्रति छात्र हजार रुपये की मंजूरी : दिल्ली सरकार के स्कूलों में चलाए जा रहे एंटरप्रन्योरशिप कार्यक्रम के तहत 11वीं और 12वीं के हर बच्चे को एक-एक हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए छात्रों को अपना एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। यह पैसा उस प्रोजक्ट को तैयार करने के लिए दिया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों में व्यावसायिक सोच पैदा करना है। पांच-छह बच्चे एक साथ मिल कर पार्टनरशिप में कोई प्रोजेक्ट भी तैयार कर सकते हैं। अपने शिक्षक से बात कर सकते हैं।

कैंट एरिया में भी बिजली मुफ्त : दिल्ली कैबिनेट ने कैंट एरिया में रहने वालों के लिए भी बिजली पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इस फैसले से दिल्ली कैंट में रह रहे भारतीय सैनिकों को इसका लाभ मिल सकेगा। इस बारे में केजरीवाल ने कहा कि कुछ माह पहले हम लोगों ने दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री और 400 यूनिट तक बिजली के दाम आधे करने के लिए योजना शुरू की थी। मगर इसका लाभ कैंट एरिया को नहीं मिल रहा था। उस योजना में कैंट एरिया रह गया था। कैंट एरिया में रह रहे फौजियों को इसका फायदा नहीं मिल रहा था। अब उन्हें भी बिजली सब्सिडी का फायदा मिलेगा।

अतिआत्मविश्वास नहीं होना चाहिए : प्रशांत किशोर को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव में कभी भी किसी चीज को लेकर अतिआत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। चुनाव ऐसी चीज है कि 24 घंटे के अंतर स्थितियां पलट जाती हैं, कुछ भी घटनाएं घट सकती हैं। प्रशांत किशोर ने टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में दिल्ली की राजनीति को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि अतिआत्मविश्वास में कभी भी नहीं रहना चाहिए।

दिल्ली सचिवालय में सोमवार को पत्रकारों से बात करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। साथ में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। जागरण

राजधानी में लगने लगीं 2.10 लाख स्ट्रीट लाइटें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीसीटीवी की तर्ज पर मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सोमवार से स्ट्रीट लाइटें लगाने के काम का शुभारंभ कर दिया। इस योजना के तहत दिल्ली में 2.10 लाख स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। इन्हें लगाने की जिम्मेदारी तीनों डिस्कॉम (बिजली कंपनी) की होगी। इसमें 40 वाट की एलईडी लाइटें लगेंगी। तीन से पांच साल तक ये स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता कंपनी की होगी। इस योजना पर सौ करोड़ का खर्च आएगा। दस करोड़ रुपये प्रति वर्ष रखरखाव पर खर्च होंगे। दिल्ली के डार्क स्पॉट को अगले चार माह में खत्म करने का लक्ष्य है। जनवरी में 50-60 हजार स्ट्रीट लाइटें लग जाएंगी। अगले चार माह में 2.10 लाख स्ट्रीट लाइटों को लगा दिया जाएगा। लोधी रोड और गोल मार्केट में इस कार्य का केजरीवाल ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए जितनी स्ट्रीट लाइटें लगाने की जरूरत होगी, लगाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए हमें जितने भी पैसे और काम करने पड़ेंगे, वह सब हम करने के लिए तैयार हैं।

कांग्रेस खालेगी भाजपा व आप की पोल : कीर्ति

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते प्रचार समिति के अध्यक्ष कीर्ति आजाद। साथ में संयोजक चतर सिंह (दाएं) और प्रवक्ता मुकेश शर्मा (बाएं)। सौजन्य : कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली कांग्रेस की प्रचार समिति के अध्यक्ष कीर्ति आजाद और संयोजक चतर सिंह ने सोमवार को विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पार्टी ने दिल्ली में चुनाव अभियान को प्रभावी रूप से चलाने के लिए सभी मोर्चों पर रणनीति तैयार कर ली है। पहले चरण में 2 से 6 जनवरी तक कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर जाकर भाजपा और आप की जन विरोधी नीतियों को लोगों तक पहुंचाएंगे।

कांग्रेस के 15 साल के शासन काल में हुई उपलब्धियों को भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जिला व ब्लॉक स्तर पर चुनाव अभियान समितियों का गठन किया जा रहा है। पार्टी स्थानीय प्रचार माध्यमों व सोशल मीडिया पर भी विशेष ध्यान देगी।

प्रदेश पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आजाद ने बताया कि मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी बड़े पैमाने पर दिल्ली में रोड शो व रैलियों का आयोजन भी करेगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा भी दिल्ली के चुनाव प्रचार में हिस्सेदारी करेंगे। इसके लिए बाकायदा समय निर्धारित किया जा रहा है। मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने कहा कि पार्टी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करने का काम शुरू हो गया है, जहां से पार्टी भाजपा व आप के खिलाफ आक्रामक प्रचार शुरू करेगी। घोषणा पत्र में शीला दीक्षित पेंशन योजना के नाम से एक विस्तारित योजना समाहित होगी। सभी मदों में पेंशन राशि को दुगना करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि 69 वर्ष से वृद्ध लोगों को 5000 रुपये महीना पेंशन राशि देने का प्रावधान भी इस योजना में किया जाएगा।

नववर्ष की पूर्वसंध्या पर सामूहिक अवकाश : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के नेतृत्व में नववर्ष की पूर्व संध्या पर मंगलवार शाम से बुधवार सुबह तक पार्टी कार्यकर्ता उपवास करेंगे और नव वर्ष के किसी भी जश्न में शामिल नही होंगे। यह घोषणा सोमवार को मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते दिल्ली की बदहाली, जानलेवा प्रदूषण, आर्थिक मंदी, बढ़ती बेरोजगारी, अनाधिकृत कालोनियों व झुग्गीवालों के साथ हो रही धोखाधड़ी के प्रति प्रतीकात्मक विरोध जताने के लिए पार्टी ने यह निर्णय लिया है।

अनधिकृत कॉलोनी के मामले गुमराह कर रही भाजपा : चोपड़ा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दक्षिणी दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी पर कांग्रेस की हल्ला बोल रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को मालिकाना हक देने व नियमन संबंधी अधिसूचना दिल्ली के 40 लाख लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। उन्होंने एलान किया कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार आने पर सभी अनधिकृत कालोनियों को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की नीति पर नियमित किया जाएगा। चोपड़ा ने कहा कि मोदी सरकार ने अनधिकृत कालोनियों के मामले में संसद को गुमराह किया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इन 40 लाख लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के संदर्भ में संसद में बिल लाने की कोई आवश्यकता ही नही थी, लेकिन जान बूझकर भाजपा व केजरीवाल सरकार ने एक सुनियोजित साजिश के तहत इस मामले को संसद में भेजा ताकि इन कालोनियों के नियमन को हमेशा के लिए उलझा दिया जाए।

न्यूज गैलरी

बोर्ड के छात्रों का परीक्षा परिणाम सुधारेगी सीएयू

नई दिल्ली : बोर्ड कक्षाओं के नतीजों को सुधारने के लिए शिक्षा निदेशालय के परीक्षा सेल की कोर अकादमिक इकाई (सीएयू) ने 42 स्कूलों को गोद लिया है। इसके लिए पहले स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं की मध्यावधि परीक्षा परिणाम का विश्लेषण किया गया था। इसके बाद यह कदम उठाया गया है। इन 42 स्कूलों का मध्यावधि परीक्षा परिणाम बेहतर नहीं रहा। लिहाजा इन स्कूलों के नतीजों में सुधार करने के लिए सीएयू ने इन्हें गोद लिया है। निदेशालय की तरफ से सीएयू की टीम को 31 दिसंबर तक इन स्कूलों का दौरा करने के लिए भी कहा गया है। इसके लिए अब चयनित स्कूलों के प्रमुखों (एचओएस) को मध्यावधि परीक्षा के विश्लेषण एक्सल शीट का प्रिंट आउट और ऑटो जेनरेटेड विश्लेषणों को तैयार रखने के लिए निर्देश दिया गया है। सीएयू की टीमें इन विश्लेषणों को एकत्रित कर इनका सत्यापन करेंगी और विश्लेषणों के प्रभावी उपयोग के लिए शिक्षकों और छात्रों का मार्गदर्शन करेंगी। स्कूल में दौरा करने के दौरान सीएयू टीम की ओर से छात्रों के संदेह को दूर करने और प्रश्नपत्रों के नवीनतम पैटर्न से परिचित करने और उनके लिए परीक्षा उन्मुख कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। (जासं)

इंडिया गेट के कई रास्तों पर प्रतिबंधित हो जाएंगे वाहन

जासं, नई दिल्ली : नए साल पर इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के मद्देनजर यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। इस दौरान पैदल लोगों की भीड़ बढ़ने पर इंडिया गेट के कई रास्ते पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा। वाहनों को सी-हेक्सागोन, इंडिया गेट क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन स्थानों पर यातायात परिवर्तित रहेगा उनमें क्यू प्वाइंट, एमएलएनपी गोलचक्कर, सुनहरी मस्जिद गोलचक्कर, जनपथ गोलचक्कर, राजपथ रफी मार्ग, विंडसर प्लेस गोलचक्कर, राजेंद्र प्रसाद रोड-जनपथ, केजी मार्ग- फिरोजशाह रोड, मंडी हाउस, मथुरा रोड-पुराना किला रोड, मथुरा रोड-शेरशाह रोड, एसबीएम-जाकिर हुसैन मार्ग इत्यादि शामिल हैं। वहीं चिड़ियाघर में जाने वालों से मथुरा रोड पर भीड़ जमा होने की उम्मीद है। इस कारण यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को हजरत निजामुद्दीन और प्रगति मैदान के बीच भैरों रोड-मथुरा रोड पर जाने से बचने की सलाह दी है। दूसरी ओर नए साल के जश्न के दौरान राजीव चौक के आसपास होने वाली भीड़ को कम करने के लिए मंगलवार की रात नौ बजे से मेट्रो स्टेशन के निकास द्वार बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि प्रवेश द्वार आखिरी ट्रेन आने तक खुले रहेंगे। (जासं)

‘वेबसाइट पर पंजीकरण जनता के साथ धोखा’

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को फिर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा ट्वीट कर 35,000 लोगों के लिए किए गए पंजीकरण के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब मैंने रविवार को भाजपा के झूठ को उजागर किया तो उनके नेताओं के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि 24 घंटे बाद एक और झूठ के साथ हरदीप पुरी जनता को गुमराह करने आए। उन्होंने वेबसाइट पर 35,000 पंजीकरण होने का दावा किया है।

प्रेसवार्ता के दौरान सिसोदिया ने कहा कि मैं जनता को बताना चाहता हूं कि वेबसाइट पर कोई कहीं का भी पंजीकरण कर सकता है। मैंने इंडिया गेट स्थित अपने सरकारी मकान को भी अनधिकृत कॉलोनी के तौर पर पंजीकरण करा दिया है। इससे साबित होता है कि वेबसाइट पर पंजीकरण सिर्फ जनता को धोखा देने के लिए किया जा रहा है। पुरी इस प्रकार का झूठ फैलाना बंद करें। जनता को वेबसाइट का पंजीकरण नहीं, अपने मकान की पक्की रजिस्ट्री चाहिए।

पुरी ने ट्वीट कर यह भी दावा किया है कि 8 से 10 दिन में रजिस्ट्री देंगे। इस पर सिसोदिया ने कहा कि पहले तय कर लीजिए कि कॉलोनियों को नियमित कर रहे हैं या नहीं। यह संभव नहीं है कि कॉलोनी की जमीन किसी और के नाम पर हो और घर का मालिकाना हक, मकानों की पक्की रजिस्ट्री किसी और के नाम पर कर दें। डीडीए की वेबसाइट पर साफ तौर से लिखा है कि कॉलोनियों का नियमितीकरण नहीं होगा। भाजपा वहां से इस लाइन को हटाकर लिख दे कि सभी कॉलोनियों का नियमितीकरण किया जाएगा। सभी को मकानों की पक्की रजिस्ट्री व उनका मालिकाना हक दिया जाएगा। भाजपा अनधिकृत कॉलोनियां नियमित करने वाली नहीं है। पहले भाजपा होर्डिंग-बैनर लगाकर अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का दावा कर रही थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले वह अपने वादे से मुकर गई है।

दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। जागरण

सिसोदिया ने कहा कि रविवार को जब मैंने भाजपा के झूठ को बेनकाब किया तो उनके किसी भी नेता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उलटे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी ने फिर जनता से झूठ बोला कि हम जनता को मालिकाना हक देंगे। इस पर प्रश्न पूछते हुए सिसोदिया ने कहा कि जब कॉलोनियों का नियमितीकरण ही नहीं कर रहे हो तो मालिकाना हक किस प्रकार से देंगे? केवल मीडिया में बाइट देने से जनता को मालिकाना हक नहीं मिलेगा।

झूठ बोल रही भाजपा : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने के भाजपा के दावे को झूठा करार दिया। दिल्ली सचिवालय में प्रेसवार्ता के दौरान पूछे जाने पर कहा कि भाजपा दिल्ली के लोगों से झूठ बोल रही है। सभी पार्टियां राजनीति करती हैं, लेकिन कोई इस तरह से गलत जानकारी देता है तो दुख की बात है। अगर डीडीए की वेबसाइट पर जाकर देखें तो दूसरा सवाल वेबसाइट पर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि न तो कॉलोनी का नियमितीकरण है और न घर का है। भाजपा वालों ने पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगाए हैं, जिनमें पीएम की फोटो लगी है। यह वोट लेने के लिए झूठ बोला जा रहा है।

व्यापारियों से किए वादे भी पूरे नहीं कर पाए केजरीवाल : पीयूष गोयल

जासं, नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री व्यापारियों से किए वादे भी पूरे नहीं कर सके हैं। गोयल सोमवार को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित व्यापारियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में गोयल व अन्य भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों के हित में किए गए कार्यों की जानकारी दी। इसमें लघु घरेलू उद्योग में बिजली के मीटर की क्षमता 11 किलोवॉट करने और मजदूरों की संख्या पांच से नौ करने की जानकारी दी गई। इसके साथ ही भाजपा ने व्यापारियों की मांग पर मास्टर प्लान 2021 में हुए संशोधन की जानकारी दी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने व्यापारियों की समस्या को समझकर उसका समाधान किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने व्यापारियों से किए वादे पूरे नहीं किए। व्यापारियों को केवल छलने का कार्य किया है। गोयल ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने 57 माह कुछ काम नहीं किया, लेकिन आखिरी के तीन माह में जनता को भ्रमित करने की कोशिश की है। केजरीवाल की पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि उन्हें कांग्रेस के साथ रहना है या नहीं।

बच्चे के अपहरण जैसे मामले में रद न हो एफआइआर : हाई कोर्ट

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बच्चे के अपहरण जैसे गंभीर मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद एफआइआर रद करने की आरोपित विष्णु कुमार यादव की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट न अहम टिप्पणी की है। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुरेश कैट की पीठ ने कहा कि याचिका में बच्चे का अपहरण करने जैसा गंभीर आरोप है और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अदालत आरोपित को कोई राहत देने के पक्ष में नहीं है। पीठ ने कहा कि इस तरह के मामले की एफआइआर को रद नहीं किया जाना चाहिए और आरोपित पर मुकदमा चलना चाहिए। पीठ ने उक्त टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता विष्णु कुमार यादव की याचिका को खारिज कर दिया।

याचिका के अनुसार 2009 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में 15 जुलाई 2019 को अंबाला जीआरपी के सब इंस्पेक्टर सतबीर सिंह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने बताया कि शिकायकर्ता नीरज लांबा की शिकायत पर अंबाला जीआरपीएफ में इससे जुड़ी जीरो एफआइआर दर्ज की गई थी। अंबाला जीआरपी ने इस दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (एनडीआरएस) एसएचओ के समक्ष उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निवासी आरोपित विष्णु कुमार यादव को पेश किया। एनडीआरएस के एसएचओ ने जीरो एफआइआर को नियमित एफआइआर में तब्दील कर मामले की जांच शुरू करने का आदेश दिया था।

जीरो एफआइआर में नीरज ने शिकायत की थी कि 2009 में परिवार के साथ नई दिल्ली से अमृतसर के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यात्रा कर रहे थे। ट्रेन प्लेटफार्म से चलने लगी तभी एक व्यक्ति उनकी गोद में बैठे ढाई साल के अजय को लेकर भागा। प्लेटफार्म पर ही उसे दबोच लिया गया था और ट्रेन में मौजूद आरपीएफ के जवान को सौंप दिया था। आरोपित के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। लेकिन 25 सितंबर 2019 को शिकायकर्ता व आरोपित के बीच समझौता हो गया और याचिकाकर्ता ने एफआइआर रद करने की हाई कोर्ट से मांग की थी। याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपित द्वारा बच्चे का अपहरण करने जैसा गंभीर अपराध किया गया है और उसे मुकदमे का सामना करना चाहिए।

आप को छोड़ कर भाजपा में लौटे गुगन सिंह

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) को झटका लगा है। पार्टी के टिकट पर उत्तर-पश्चिमी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले गुगन सिंह भाजपा में वापस आ गए हैं। वह वर्ष 2017 में बवाना सीट पर हुए उपचुनाव में टिकट न मिलने की वजह से आप में चले गए थे। सोमवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ली।

गुगन सिंह ने कहा कि उनका आप में दम घुट रहा था, क्योंकि वहां विधायकों तक का सम्मान नहीं होता। लोकसभा चुनाव के दौरान एक बैठक में लोगों ने अपने विधायकों की शिकायत की उनका विधायक उनकी बात नहीं सुनता तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विधायकों के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि वह किसी कारणवश भटक गए थे उनका परिवार तो भाजपा ही है। उन्होंने अपील की जो गलती उन्होंने की कोई और न करें। केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ वह मोदी ने करके दिखाया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि गुगन सिंह का भाजपा के परिवार में फिर से स्वागत है।

सेमेस्टर परीक्षा नहीं देने वाले छात्रों को पंजीकरण का मौका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुलपति प्रो. एम जगदीश कुमार ने दिसंबर में सेमेस्टर परीक्षा नहीं देने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने सोमवार को छात्रों के नाम पत्र लिखते हुए संस्थान की उपलब्धियों को बताया। साथ ही कहा कि सोमवार को सभी रेक्टर, केंद्रों के डीन, अध्यक्षों के साथ हुई बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि जिन भी छात्रों ने दिसंबर में परीक्षा नहीं दी है, उन सभी को मौका देते हुए 1 से 5 जनवरी के बीच अस्थायी पंजीकरण कराने के लिए कहा है। जिन छात्रों ने मानसून सेमेस्टर 2019 (जुलाई से दिसंबर) में अपनी अकादमिक गतिविधियों को पूरा नहीं किया है, उन्हें 20 जनवरी तक मॉनसून सेमेस्टर की सभी अकादमिक गतिविधियों को पूरा करने का मौका दिया है। साथ ही सभी शिक्षकों, केंद्रों के डीन व अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि इन सभी छात्रों के परीक्षा मूल्यांकन का काम भी पूरा किया जाए।

इन छात्रों के अस्थायी पंजीकरण की वैधता 20 जनवरी तक रहेगी। इससे पहले इन्हें मानसून सेमेस्टर की अकादमिक गतिविधियों को पूरा करना होगा। कुलपति ने छात्रावास की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों से विरोध खत्म करने का भी निवेदन किया है। इसके अलावा जिन छात्रों ने दिसंबर में सेमेस्टर परीक्षा दी है, उनका 1 से 5 जनवरी के बीच स्थायी पंजीकरण होगा। 20 जनवरी से विंटर सेमेस्टर शुरू हो जाएगा।

कुलपति प्रो. एम जगदीश कुमार ने कहा कि इस वर्ष जनवरी से दिसंबर के दौरान शिक्षकों को उनके शोध के प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न एजेंसियों से 190 करोड़ रुपये की निधि मिली है। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआइआरएफ) 2019 में जेएनयू को देशभर के विश्वविद्यालयों की सूची में दूसरी रैंक मिली है।

जेएनयू प्रशासन ने सोमवार को छात्रावास की फीस से जुड़ा परिपत्र जारी किया है। इसमें एक कमरे का किराया 3600 रुपये प्रति सेमेस्टर यानी 600 रुपये प्रति महीना देने के लिए कहा गया है। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के छात्रों को इसके लिए 1800 रुपये प्रति सेमेस्टर यानी 300 रुपये महीना देने के लिए कहा है।

मेट्रो के चौथे चरण का काम हुआ शुरू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली वालों को मेट्रो की तरफ से एक और सौगात मिलने वाली है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) की तरफ से सोमवार से मेट्रो फेज-4 के लिए औपचारिक रूप से हैदरपुर बादली मोड़ में शुरुआत हुई है।

फेज 4 के तहत मेट्रो के तीन कॉरिडोर का निर्माण होगा। जिसमें कुल 61.67 किलोमीटर के कॉरिडोर तैयार होंगे। इसमें एरोसिटी से तुगलकाबाद के बीच 20.20 किलोमीटर कॉरिडोर, आरके आश्रम मार्ग से जनकपुरी वेस्ट के बीच 28.92 किलोमीटर और मौजूपुर से मजलिस पार्क के बीच 12.55 किलोमीटर का कॉरिडोर तैयार होगा। इसमें आरके आश्रम मार्ग से जनकपुर वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर मेजेंटा लाइन का विस्तार है, जो अभी जनकपुरी वेस्ट से बॉटेनिकल गार्डन के बीच संचालित हो रहा है। इसमें दस मेट्रो स्टेशन का निर्माण होगा, जिसे 30 महीने में पूरा किए जाने की योजना है। आरके आश्रम मार्ग से जनकपुरी वेस्ट मेजेंटा लाइन के लिए केशोपुर, पश्चिम विहार, पीढ़ागढ़ी, मंगोलपुरी, पश्चिम एन्कलेव, पुष्पांजलि, दीपाली चौक, मधुबन चौक, प्रशांत विहार और पीतमपुरा उत्तर मेट्रो स्टेशन तैयार होंगे। यह एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। मेट्रो फेज 4 के निर्माण के पूरे होने पर छह और इंटरचेंज स्टेशन तैयार हो जाएंगे।

दावा

दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा, हेल्प डेस्क की जा रही दोगुनी, हो जाएंगी 25 से 50

जल्द 25 लोगों को मिल जाएगा मालिकाना हक

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

सियासी सरगर्मियों और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दावा किया है कि अधिकतम एक सप्ताह के भीतर अनधिकृत कॉलोनियों के 25 निवासियों को उनके घर का मालिकाना हक मिल जाएगा। इनकी पक्की रजिस्ट्री भी हो जाएगी। इसके बाद यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा।

जानकारी के मुताबिक 1731 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए डीडीए के पोर्टल पर 16 दिसंबर से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सोमवार, 30 दिसंबर तक इस पर लगभग 45 हजार लोगों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। डीडीए की ओर से तैनात विभिन्न चार निजी फर्मों ने इनमें से 25 संपत्तियों का जियो कॉर्डीनेट एवं की- प्लान तैयार कर लिया है। इनके कागजों का सत्यापन भी हो गया है। अब इन्हें इनकी संपत्ति का शुल्क बताया जाना है। शुल्क जमा कराने के बाद डीडीए इन्हें कन्वेंस डीड जारी करेगा, जिसके आधार पर यह लोग अपनी पक्की रजिस्ट्री करवा सकेंगे।

डीडीए अधिकारियों के मुताबिक अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए पूरी प्रक्रिया बनी हुई है। इसी के अनुरूप सारा कामकाज किया जा रहा है। आठ लाख संपत्तियों का जियो कॉर्डीनेट और की प्लान हाथोंहाथ तैयार नहीं किया जा सकता। इनके दस्तावेजों का सत्यापन भी इतनी जल्दी नहीं हो सकता। इसके अलावा इन संपत्तियों के मालिकाना हक को लेकर अगर कहीं से किसी की कोई आपत्ति आती है तो उसका निपटारा भी अनिवार्य है। इसीलिए इसमें समय लगना स्वाभाविक है। एक रजिस्ट्री कराने में भी कम से कम आधे से एक घंटा लग जाता है। ऐसे में लाखों रजिस्ट्रियां होने में समय लगना तय है।

दूसरी तरफ डीडीए ने इन कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए हेल्पडेस्क दोगुना करने का निर्णय लिया है। इनकी संख्या 25 से बढ़ाकर 29 की जा चुकी हैं। जल्द ही यह 50 कर दी जाएंगी। इस दिशा में स्टाफ भी नियुक्त कर लिया गया है और कंप्यूटर वगैरह भी मंगवा लिए गए हैं। हेल्प डेस्कों के लिए बहुत सी जगह नगर निगम से भी जगह किराए पर ले ली गई है। अब नए हेल्प डेस्क इन कॉलोनियों में ही खोले जाएंगे।

अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया चल रही है। जल्दबाजी इसलिए नहीं की जा रही जिससे बाद में कहीं कोई कानूनी अड़चन न आ जाए। अलबत्ता, रजिस्ट्री मिलने की शुरुआत बहुत जल्द हो जाएगी और इसके बाद लगातार जारी रहेगी।

-तरुण कपूर, उपाध्यक्ष, डीडीए

रेलवे स्टेशनों पर भी सुनाई देगा ‘बनवा लीजिए वोटर आइडी कार्ड’

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव में सभी योग्य मतदाताओं को जोड़ने के लिए दिल्ली चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही जागरूकता अभियान भी तेज कर दिया है। इन्हीं कोशिशों के तहत दिल्ली के सात रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

चुनाव आयोग द्वारा जारी घोषणा में कहा जा रहा है कि ‘यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप दिल्ली के निवासी हैं और 01-01-2020 या उससे पहले 18 साल के हो रहें हैं तो आप अपना नाम मतदाता सूची मे पंजीकृत करा सकते हैं। आप डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एनवीएसपी डॉट इन या वोटर हेल्प मोबाइल एप पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं या मतदाता पंजीकरण केंद्र मे जाकर फॉर्म 6 भर सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए आप सीईओ, दिल्ली की वेबसाइट पर या 1950 पर कॉल कर सकते है।’

पीएम की रैली में एएफआरएस के प्रयोग पर उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में दिल्ली पुलिस की ओर से प्रयोग की गई ऑटोमेटेड फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (एएफआरएस) का इस्तेमाल किए जाने पर एक संस्था ने सवाल उठाए हैं। रैली में आई भीड़ को पहचानने के लिए दिल्ली पुलिस ने पहली बार किसी राजनीतिक रैली में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था।

डिजिटल एडवोकेसी ग्रुप इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक अपार गुप्ता ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर प्रोफाइलिंग और निगरानी के लिए एएफआरएस तकनीक का उपयोग अवैध और असंवैधानिक है। यह आम भारतीयों के अधिकारों को प्रभावित करता है। इससे लोगों की निजता का उल्लंघन होता है। सार्वजनिक स्थानों पर गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए इस तकनीक को लाया गया है, लेकिन अब यह उद्देश्य से भटक गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में आधार कार्ड पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि व्यक्तिगत निजता एक मौलिक अधिकार है। हालांकि, फैसले में एएफआरएस का उल्लेख नहीं किया गया था।

अब कई देशों की सुरक्षा एजेंसियां अपराधियों तथा आतंकियों को पकड़ने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करने लगी हैं। भारत में इस वर्ष कई एयरपोर्ट पर एएफआरएस को लगाया गया है। अपराधियों और लापता बच्चों को खोजने के उद्देश्य से सरकार की देशभर में इस तकनीक को स्थापित करने की योजना है। दिल्ली पुलिस ने गत दिनों हुई पीएम की दिल्ली रैली में इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। पुलिस को रैली में खुफिया सूचनाओं से आतंकी हमले का इनपुट मिला था।

2018 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स को भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शुरू किया था। इस साल राज्यों का मूल्यांकन संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुझाए गए 306 में से 54 लक्ष्यों के 100 सूचकांकों के आधार पर किया गया है।

रैंकिंग ▸ नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने जारी किया 'एसडीजी इंडिया इंडेक्स-2019'

सतत विकास में केरल अव्वल, बिहार फिसड्डी

उत्तर प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम सर्वाधिक सुधार करने वाले राज्यों में

नई दिल्ली, प्रेट्र : नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सूचकांक-2019 में केरल ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है जबकि बिहार प्रदर्शन के मामले में फिसड्डी रहा है। इस सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

सोमवार को जारी 'एसडीजी इंडिया इंडेक्स-2019' के मुताबिक उत्तर प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम ने सर्वाधिक सुधार प्रदर्शित किया है जबकि गुजरात जैसे राज्यों ने 2018 की रैंकिंग के मुकाबले कोई प्रगति नहीं दिखाई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, '70 अंकों के साथ केरल ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में 70 अंकों के साथ चंडीगढ़ भी शीर्ष स्थान पर बरकरार है। हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं।

इस साल की सूची में बिहार, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शुमार हैं।' नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, 'संयुक्त राष्ट्र के 2030 के एसडीजी लक्ष्य को भारत के बिना कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता। हम संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी लक्ष्य को हासिल करने लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।'

इस मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर दक्षिणी राज्यों ने अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा, 'पश्चिम बंगाल (14वें स्थान पर) ने भी नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक-2019 में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन शिक्षा के स्तर (राज्य में) के मद्देनजर पश्चिम बंगाल को शीर्ष तीन राज्यों में होना चाहिए।' नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि भारत द्वारा एसडीजी 2030 के एजेंडे को हासिल करने के लिए मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

रिपोर्ट के मुताबिक जल, स्वच्छता, उद्योग और नवाचार में बड़ी सफलता के कारण 2018 के मुकाबले 2019 में भारत के समग्र अंक 57 से बढ़कर 60 हो गए हैं। हालांकि कुपोषण और लैंगिक असमानता अभी भी भारत के लिए समस्या बने हुए हैं और सरकार को इस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।

रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष पांच राज्यों में से तीन ने 12 लक्ष्यों पर देश के औसत के बराबर या उससे बेहतर प्रदर्शन किया है। जबकि दो अन्य राज्यों ने 11 लक्ष्यों पर इस स्तर का प्रदर्शन किया है। 2018 में सिर्फ तीन राज्यों हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु को अव्वल (65 से 99 अंक) की श्रेणी में रखा गया था। जबकि 2019 में पांच और राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, सिक्किम व गोवा इस श्रेणी में शामिल हो गए हैं।

गरीबी मिटाने के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में तमिलनाडु, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम शामिल हैं। शून्य भुखमरी के मानक पर गोवा, मिजोरम, केरल, नगालैंड और मणिपुर शीर्ष राज्य रहे।

मालूम हो कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स को पिछले साल नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शुरू किया था और सुझाए गए 17 में से 16 लक्ष्यों को मानक बनाया था। इस साल राज्यों का मूल्यांकन संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुझाए गए 306 में से 54 लक्ष्यों के 100 सूचकांकों के आधार पर किया गया।

नई दिल्ली में सोमवार को सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सूचकांक जारी करते, दाएं से, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और संयुक्त राष्ट्र की स्थानीय समन्वयक रेनाटा डेजलिन। एएनआइ

प्रधानमंत्री आवास के एसपीजी रिसेप्शन में आग से हड़कंप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ दमकल पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया, घटना के समय प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बारे में जानकारी नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित आवास में सोमवार शाम आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की नौ गाड़ियां तत्काल मौके पर भेजी गईं, लेकिन तब तक वहां तैनात कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। यह पता नहीं चल सका है कि घटना के वक्त प्रधानमंत्री परिसर में थे या नहीं।

प्रधानमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बताया गया कि आग पीएम के आवास या कार्यालय क्षेत्र में नहीं लगी थी बल्कि परिसर में स्थित स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) सुरक्षा कार्यालय के रिसेप्शन में स्थित यूपीएस में लगी थी। दमकल अधिकारियों के मुताबिक शाम करीब साढ़े सात बजे विभाग को आग लगने की सूचना मिली थी। तुरंत नौ गाड़ियां भेजी गईं। स्थानीय प्रशासन भी घटनास्थल पर पहुंच चुका था। पता चला कि आग पीएम के आवास परिसर स्थित एसपीजी सुरक्षा कार्यालय के रिसेप्शन में लगी थी, जिसे वहां मौजूद अग्निशामक उपकरणों की मदद से बुझा लिया गया और दमकलों को गेट से ही वापस भेज दिया गया। इसमें किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। उधर, सोमवार दोपहर बाद जनपथ स्थित खुर्शीद लाल भवन की लिफ्ट में भी आग लग गई। दमकल की दो गाड़ियों को भेजा गया था, लेकिन तब तक उस पर काबू पा लिया गया। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि खुर्शीद लाल भवन की लिफ्ट में आग लगने की सूचना करीब पांच बजे मिली थी। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

नई दिल्ली में सोमवार को प्रधानमंत्री आवास पर लगी आग बुझाने पहुंचे अग्निशमन वाहन। प्रेट्र

न्यूज गैलरी

आज सेना प्रमुख का पद संभालेंगे मुकुंद नरवाने

ले. जनरल मुकुंद नरवाने। फाइल फोटो

नई दिल्ली : लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने देश के नए सेना प्रमुख होंगे। वे मंगलवार को सेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे। वे जनरल बिपिन रावत का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने फिलहाल सेना उप प्रमुख हैं। वे सितंबर में सेना उप प्रमुख बनने से पहले सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख थे, जो चीन के साथ लगती करीब 4,000 किमी लंबी सीमा की देखभाल करती है। 37 वर्षों के सेवा काल में लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने जम्मू-कश्मीर व पूर्वोत्तर में कई अहम पदों पर रहे। वे श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षक बल का हिस्सा थे व तीन वर्षों तक म्यांमार स्थित भारतीय दूतावास में रक्षा अताशे रहे। लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के छात्र रहे हैं। वे जून 1980 में सिख लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट के सातवें बटालियन में कमीशन हुए थे। उन्हें सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जा चुका है। (प्रेट्र)

एसपीजी प्रमुख अरुण कुमार सिन्हा को सेवा विस्तार

नई दिल्ली : वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) के निदेशक के रूप में एक साल का विस्तार दिया गया है। एसपीजी पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सिन्हा की प्रतिनियुक्ति को 19 मार्च 2020 से 30 जुलाई 2021 तक का विस्तार देने की मंजूरी दी। 1987 बैच के आइपीएस अधिकारी सिन्हा मार्च 2016 से एसपीजी प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। (प्रेट्र)

सेवानिवृत्ति के बाद फिर चुनाव आयुक्त बने उमेश सिन्हा

नई दिल्ली : वरिष्ठ आइएएस अधिकारी उमेश सिन्हा को चुनाव आयोग में फिर से उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, मंगलवार को सेवानिवृत्त हो जाने के बाद उनकी यह नियुक्ति की गई है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ठेका आधार पर उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आइएएस अधिकारी की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दी। उन्हें एक जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। (प्रेट्र)

पांच साल में दिल्ली से कोलकाता व मुंबई रूट पर प्रतीक्षा सूची होगी खत्म

▸ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, तीन डीएफसी के चालू होने पर हमेशा मिलेगी कंफर्म टिकट

▸ चार साल में दोनों रूट पर 160 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें

2.6 लाख करोड़ रुपये की लागत वाले कॉरिडोर के 10 साल में बनने की उम्मीद

नई दिल्ली, प्रेट्र : अगर आप दिल्ली से कोलकाता और दिल्ली से मुंबई के बीच ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। पांच साल के भीतर-भीतर आपको इन दोनों ही रूट पर जब चाहें तब यानी हर वक्त कंफर्म टिकट मिलेगी। इस दौरान इन दोनों रूट को प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने सोमवार को यह बात कही।

संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि माल गाड़ियों के लिए तीन अलग कॉरिडोर (डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर-डीएफसी) पर काम चल रहा है। 2.6 लाख करोड़ रुपये की लागत वाले इन कॉरिडोर के 10 साल में बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर तो डीएफसी का काम 2021 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। डीएफसी के पूरा होने के बाद इन दोनों ही रूट पर मालगाड़ियों का परिचालन बंद हो जाएगा और यात्रियों की संख्या के आधार पर मांग के मुताबिक यात्री ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। इस तरह पांच साल के भीतर इन दोनों रेल मार्ग को प्रतीक्षा सूची के टिकटों से मुक्ति मिल जाएगी।

यादव ने कहा कि अगले चार साल में इन दोनों ही रूट पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे करने की दिशा में भी काम चल रहा है। यात्री ट्रेनों की औसत गति को 60 फीसद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। इससे राजधानी ट्रेनें रात-रात में ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगी।

विनोद कुमार यादव। फाइल फोटो

उन्होंने यह भी बताया कि 2019-20 में 194 ट्रेनों को अपग्रेड कर उन्हें उत्कृष्ट स्तर का बनाया गया और अप्रैल-अक्टूबर, 2019 के बीच 78 नई ट्रेनें शुरू की गईं।

इस साल की उपलब्धियां : इससे पहले 2019 की उपलब्धियों पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि अप्रैल-नवंबर के दौरान हमने 1.60 लाख करोड़ रुपये के वार्षिक पूंजीगत परिव्यय में से 1.02 लाख करोड़ खर्च किए हैं। इस दौरान नई लाइन, दोहरीकरण व आमान परिवर्तन समेत कुल 1,165 किलोमीटर के कार्य हुए, जो पिछले वर्ष इसी अवधि से 15 फीसद अधिक हैं। विद्युतीकरण का कार्य 42 फीसद बढ़कर 2,041 किलोमीटर हो गया। इसके अलावा 3,560 किमी ट्रैक का नवीकरण (27 फीसद अधिक) कर 118 के मुकाबले 170 फुट ओवरब्रिज बनाए गए।

फ्रेट कॉरिडोर : अप्रैल-नवंबर के दौरान भादन-खुर्जा के बीच पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर के 194 किमी लंबे सेक्शन के अलावा पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर के 305 किमी लंबे रेवाड़ी-मदार खंड को चालू किया गया।

रोलिंग स्टॉक : आठ माह में 60 फीसद ज्यादा अर्थात 495 इलेक्ट्रिक इंजनों तथा 40 फीसद ज्यादा अर्थात 3,837 एलएचबी डिब्बों का उत्पादन हुआ।

नई ट्रेनें : दो सेमी-हाईस्पीड वंदे भारत ट्रेनों के अलावा पहली प्राइवेट तेजस एक्सप्रेस का संचालन प्रारंभ हुआ। इसके अलावा 194 ट्रेनों को उत्कृष्ट रेक में तब्दील कर 78 नई ट्रेन सेवाएं प्रारंभ की गईं। यही नहीं, 120 जोड़ी ट्रेनों में पुराने आइसीएफ कोच की जगह सुरक्षित एलएचबी कोच लगाए गए। 104 ट्रेनों को तीव्रगामी मेमू ट्रेनों में बदला गया।

बिबेक देबराय समिति ने दिया था रेलवे में दो सेवाओं का सुझाव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेलवे अधिकारियों के एक बड़े तबके ने बिबेक देबराय समिति का हवाला देकर रेलवे की आठ सेवाओं के एकीकरण का विरोध किया है। उनका कहना है कि देबराय का रेल सेवाओं को एक के बजाय दो सेवाओं, तकनीकी और गैर-तकनीकी में समेटने का सुझाव तर्कसंगत था। उसमें इंजीनियरिंग और सिविल सेवा परीक्षा से आने वाले अधिकारियों के बीच वरिष्ठता की समस्या को ध्यान में रखा गया था। एकीकरण में इसकी उपेक्षा की गई है जिससे आने वाले समय में नई परेशानी खड़ी होगी।

स्वयं देबराय ने भी एक साक्षात्कार में इन रेलवे अफसरों की चिंता को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि दो सेवाओं का सुझाव उन्होंने रेलवे अफसरों की यूनियन से बातचीत के आधार पर ही दिया था। ज्यादातर अधिकारियों का मत था कि विभागों के बीच खींचतान पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे की आठ सेवाओं को दो सेवाओं-तकनीकी और गैर-तकनीकी में विलीन किए जाने की जरूरत है।

अभी तक रेलवे में अफसरों की भर्ती सिविल सेवा परीक्षा और रेलवे इंजीनियरिंग सेवा के माध्यम से होती रही है। सिविल सेवा से आने वालों में गैर इंजीनियर और इंजीनियर दोनों होते हैं। जबकि इंजीनियरिंग सेवा से आने वाले सारे इंजीनियर होते हैं। यही वजह है कि रेलवे में इंजीनियरों की संख्या गैर-इंजीनियरों के मुकाबले ज्यादा है। ऐसा शायद यह मानकर किया गया था कि रेलवे का मुख्य कार्य ट्रेन चलाना है। लेकिन इंजीनियरिंग विशेषज्ञता की जरूरत प्रायः डायरेक्टर स्तर तक होती है। उसके उपरांत मुख्यतः प्रबंधकीय कौशल की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमने दो सेवाओं की सिफारिश की थी। एकीकरण से अलग-अलग काडर वाले 8000 अधिकारियों की वरिष्ठता प्रभावित होने की समस्या से जूझना पड़ेगा। अधिकारी भले इस बात को खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यह उनकी मुख्य चिंता का विषय है। हालांकि रेलवे बोर्ड चेयरमैन विनोद यादव बार-बार भरोसा दे रहे हैं कि किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

दिव्यांगों के लिए अनुकूल बसें अगले साल मार्च से

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिव्यांग यात्रियों या कम चलने-फिरने वाले लोगों के लिए अनुकूल बसें अगले साल मार्च से चलने लगेंगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में सोमवार को यह जानकारी दी गई। इससे उन्हें यात्रा करने में कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। यह संशोधन एक मार्च, 2020 से लागू हो जाएगा। इसमें प्रस्ताव किया गया है कि बसों में प्राथमिकता वाली सीटों, निशान, बैसाखी/केन/वॉकर, हैंड रेल आदि की सुविधा होगी। बसों के फिटनेस निरीक्षण के समय इन सुविधाओं की जांच की जाएगी।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के मसौदे को प्रकाशित किया गया। इससे प्रभावित होने वाले सभी पक्षों से इस पर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए। आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद अधिसूचना जारी की गई।

अब फेसबुक नहीं चला सकेंगे भारतीय नौसैनिक, लगी रोक

▸ बेस, डॉकयार्ड और ऑन-बोर्ड युद्धपोत पर स्मार्टफोन ले जाने पर भी पाबंदी

▸ सात नौसैनिकों के सूचना लीक करते पकड़े जाने के बाद नौसेना ने की सख्ती

नई दिल्ली, एजेंसियां : भारतीय नौसेना ने अपने अफसरों और सैनिकों के फेसबुक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। नौसेना के अड्डे (बेस), डॉकयार्ड और ऑन-बोर्ड युद्धपोत पर स्मार्टफोन ले जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हाल ही में सात नौसैनिकों के हनी-ट्रैप में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आइएसआइ) को संवेदनशील सूचनाएं लीक करते हुए पकड़े जाने के बाद नौसेना ने यह कदम उठाया है। इस मामले की जांच अब आंध्र प्रदेश पुलिस से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को सौंप दी गई है।

नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है। हालांकि, नौसेना ने यह भी माना है इन पाबंदियों से नौसैनिकों को कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन व्यापक राष्ट्रीय हित को देखते हुए यह फैसला करना पड़ा है। नौसेना द्वारा जारी आंतरिक आदेश में कहा गया है कि मैसेजिंग एप, नेटवर्किंग एवं ब्लॉगिंग, सामग्री साझा करने, होस्टिंग, ई-कॉमर्स साइटों का इस्तेमाल पाबंदी के दायरे में है। बता दें कि 20 दिसंबर को आंध्र प्रदेश पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने जासूसी रैकेट को उजागर किया था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों द्वारा सोशल मीडिया पर यह रैकेट चलाया जा रहा था, इसमें संवेदनशील सूचनाएं दुश्मन देश को लीक करने के आरोप में सात नौसैनिकों और एक हवाला कारोबारी को विशाखापत्तनम, करवार और मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। ये नौसैनिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों के बारे में दुश्मनों को जानकारी दे रहे थे। इस मामले की अभी जांच चल रही है और कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि नौसैनिकों के सोशल मीडिया और अन्य नेटवर्किंग साइटों के इस्तेमाल पर पहले भी पाबंदी लगाई गई थी।

भारतीय नौसेना का लोगो। फाइल फोटो

निजी डॉक्टर भी अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ा सकेंगे

▸ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इस संबंध में अधिसूचना जारी कर चुका है

▸ चुनिंदा संस्थानों में लागू नहीं होगा यह नया नियम

नई दिल्ली, एएनआइ : मेडिकल कॉलेजों में अध्यापकों की कमी दूर करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब निजी और विदेशी डॉक्टरों को नियुक्त करने की योजना बनाई है। हालांकि यह नया नियम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों, चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और पुडुचेरी स्थित जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पर लागू नहीं होगा।

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) इस संबंध में अधिसूचना जारी कर चुका है। इसके मुताबिक, अध्यापकों की नियुक्ति अल्पकालिक आधार पर की जाएगी जिन्हें 'विजिटिंग फैकल्टी' कहा जाएगा। इस नियुक्ति के लिए निजी डॉक्टर के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने के बाद विशेषज्ञता वाले विभाग में आठ साल का अनुभव अनिवार्य होगा। इसके अलावा 70 साल से अधिक उम्र के डॉक्टरों को 'विजिटिंग फैकल्टी' नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'विजिटिंग फैकल्टी की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जाएगी। इस समिति में निदेशक, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज के डीन, संबंधित विभाग का प्रमुख, किसी अन्य विभाग का प्रमुख और संबंधित विषय का किसी अन्य शहर के मेडिकल कॉलेज का विशेषज्ञ शामिल होगा। वह राष्ट्रीय महत्व के किसी संस्थान से हो सकता है।' उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती नियमों में निजी डॉक्टरों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने की अनुमति नहीं थी।

प्रतीकात्मक फोटो

130 करोड़ हिंदू टिप्पणी को लेकर संघ प्रमुख के खिलाफ शिकायत

▸ हैदराबाद की पुलिस ने अभी तक दर्ज नहीं किया है मामला

▸ कांग्रेस नेता ने टिप्पणी के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने की मांग की है

हैदराबाद, एएनआइ : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में 130 करोड़ लोग धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता से परे हिंदू समुदाय के हैं।

सोमवार को पुलिस ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि एलबी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस नेता ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने की मांग की है। एलबी नगर थाने ने कहा है कि शिकायत के आधार पर उन्होंने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है। आगे की किसी कार्रवाई से पहले वे कानूनी राय ले रहे हैं।

क्या कहा था भागवत ने : आरएसएस-तेलंगाना के विजय संकल्प शिविर के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा था कि भारत पारंपरिक रूप से हिंदुत्ववादी रहा है और संघ का मानना है कि देश की 130 करोड़ आबादी धार्मिक एवं सांस्कृति विविधता से इतर हिंदू समुदाय की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, 'जब आरएसएस किसी को हिंदू कहता है उसका मतलब होता है कि जो लोग भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं और इससे प्रेम करते हैं। भारत माता का बेटा भले ही वह किसी भी भाषा में संवाद करता हो, वह जिस किसी भी धर्म को मानता हो, वह पूजा-प्रार्थना के किसी तरीके का पालन करता हो या नहीं, वह एक हिंदू है, इसलिए संघ के लिए भारत के सभी 130 करोड़ लोग हिंदू समुदाय के हैं। आरएसएस हर किसी को अपना मानता है और हर किसी का विकास चाहता है।'

मोहन भागवत। फाइल फोटो

क्राइम कंट्रोल

पोर्टल की मदद से आइएमईआइ को ब्लॉक और अनब्लॉक करना होगा संभव, अभी दिल्ली-एनसीआर में मिलेगा लाभ, धीरे-धीरे पूरे देश में विस्तार की तैयारी

खोये या चोरी हुए मोबाइल का पता लगाने वाला पोर्टल लांच

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को एक ऐसा पोर्टल लांच किया जिसके जरिये खोये या चोरी हुए मोबाइल फोन का पता लगाया जा सकेगा। फिलहाल इसका लाभ दिल्ली-एनसीआर के लोगों को मिलेगा। धीरे-धीरे पूरे देश में इसका प्रसार करने की तैयारी है। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सितंबर में मुंबई से की गई थी।

पोर्टल 'सीईआइआर डॉट जीओवी डॉट इन' का लाभ लेने के लिए सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखाकर खोये या चोरी हुए नंबर को ब्लॉक कराना होगा। तत्पश्चात एफआइआर की कॉपी और आइडी प्रूफ के साथ अपने मोबाइल ऑपरेटर को नया सिम कार्ड देने के लिए आवेदन करना होगा।

इसके बाद आइएमईआइ ब्लॉक कराने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। इस पर आपको एक रिक्वेस्ट आइडी मिलेगी। इसके जरिये आप पोर्टल पर अपने मोबाइल की स्थिति पर नजर रख सकते हैं। मोबाइल मिल जाने की स्थिति में भविष्य में आप आइएमईआइ को अनब्लॉक भी कर सकते हैं। इस पोर्टल के लांच होने से मोबाइल चोरी संबंधी अपराधों में कमी आ सकती है। हालांकि, फिलहाल इस सुविधा का लाभ दिल्ली-एनसीआर के लोगों को ही मिलेगा।

इस सुविधा के लिए दूरसंचार विभाग ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री (सीईआइआर) नाम से एक प्रणाली विकसित की है और उसे सभी मोबाइल ऑपरेटरों के आइएमईआइ डाटाबेस से कनेक्ट किया है।

सीईआइआर में सभी मोबाइल ऑपरेटर अपने नेटवर्क पर ब्लैकलिस्ट अथवा ब्लॉक किए गए मोबाइल सेट्स का डाटा शेयर करते हैं, ताकि एक नेटवर्क पर ब्लैकलिस्ट या ब्लॉक किया गया मोबाइल फोन दूसरे नेटवर्क पर भी काम नहीं कर सके। ऐसा होने से मोबाइल फोन पाने या चोरी करने वाला व्यक्ति सिम कार्ड बदलने के बाद भी उसका उपयोग नहीं कर पाता है। इससे मोबाइल फोन लौटाए जाने या चोर के पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाती है।

नई दिल्ली में सोमवार को खोये या चोरी हुए मोबाइल फोन का पता लगाने के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर सिस्टम (सीईआइआर) लांच करते केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद (मध्य में)। साथ में संचार सचिव अंशु प्रकाश (बाएं) और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल। प्रेट्र

क्लोन आइएमईआइ पर भी कारगर

आमतौर पर हर मोबाइल फोन के डिवाइस का आइएमईआइ नंबर अलग होता है। लेकिन हाल में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जहां एक ही आइएमईआइ नंबर पर एक से ज्यादा हैंडसेट मिले। ऐसी स्थिति में आइएमईआइ नंबर ब्लॉक करने पर उसी आइएमईआइ वाला दूसरा फोन भी ब्लॉक होने का खतरा रहता है। ऐसे में इस नई व्यवस्था की मदद से एक जैसे आइएमईआइ नंबर होने पर भी केवल उसी फोन को ब्लॉक करना संभव होगा, जो चोरी हुआ है या खोया है। सरकार का यह कदम मोबाइल फोन की चोरियां कम करने में कारगर साबित होगा।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

28 नवंबर को महाराष्ट्र में उद्धव समेत शिवसेना के 3 और राकांपा-कांग्रेस के 2-2 मंत्रियों ने शपथ ली थी। वर्तमान में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब 43 मंत्री हैं। राकांपा के 16 और कांग्रेस-शिवसेना के 12-12 मंत्री हैं। गठबंधन में राकांपा के 54, शिवसेना के 56 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 31 दिसंबर 2019

‘केस वापसी के लिए कोर्ट की सहमति जरूरी’

जानकारों की राय ▸ झारखंड सरकार ने की है पत्थलगड़ी से जुड़े मुकदमे वापस लेने की घोषणा

सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ हुए आंदोलन के केस होने हैं वापस

राज्य ब्यूरो, रांची

मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन ने अपनी पहली कैबिनेट में पत्थलगड़ी के दौरान दर्ज किए गए देशद्रोह सहित अन्य मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। कानून के जानकारों की मानें तो सरकार को इस तरह के मामलों को वापस लेने का अधिकार है लेकिन इसके लिए अदालत की सहमति लेनी होगी। सीआरपीसी की धारा 321 के तहत मुकदमों को वापस लेने के लिए सरकारी वकील के जरिये निचली अदालत में आवेदन देना होगा। कोर्ट की सहमति के बाद ही मुकदमा वापस किया जा सकता है। यह प्रक्रिया अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने से पहले करनी होती है। कानूनी जानकारों का यह भी कहना था कि सरकार सिर्फ देशद्रोह या फिर पूरे मामलों को भी वापस ले सकती है। इसके लिए भी उन्हें अदालती प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

पत्थलगड़ी से संबंधित मुकदमे खूंटी व सरायकेला जिले में हैं। इसमें दर्जनभर से ज्यादा लोग जेल में बंद हैं। इनपर पूर्व में ही देशद्रोह का मुकदमा चलाने की स्वीकृति मिल चुकी है। खूंटी व सरायकेला के कुछ गांवों में ताबड़तोड़ पत्थलगड़ी हुई थी। तत्कालीन रघुवर सरकार ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। मुकदमे सरकार, सरकारी अधिकारी के कानूनी आदेश व निर्देश को नहीं मानने, विधि-व्यवस्था को अपने हाथों में लेने, अपना बैंक खोलने की कोशिश करने व अपना सिक्का चलाने की भी पत्थलगड़ी समर्थकों ने कोशिश की थी। इसी मामले में पुलिस-प्रशासन ने सख्ती बरती थी और देशद्रोह सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। पत्थलगड़ी समर्थकों पर समानांतर सरकार चलाने, ग्राम सभा की गलत व्याख्या करने, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। इसके अलावा यह भी आरोप है कि संविधान की पांचवीं अनुसूची की गलत व्याख्या कर ग्राम सभा को सरकार के विरुद्ध भड़काया जा रहा है। गांवों में पत्थलगड़ी कर उक्त क्षेत्रों में पुलिस-प्रशासन को जाने से रोका जा रहा है।

अराजक तत्व हो गए थे सक्रिय

पत्थलगड़ी वाले इलाकों में पुलिस और प्रशासन के प्रवेश पर पाबंदी का लाभ अराजक तत्वों ने उठाया था। जब ये आंदोलन चरम पर था तो खूंटी, सरायकेला के कई गांवों में उग्रवादियों और अराजक तत्वों की शह पर अफीम की फसल लगाई जाने लगी थी। यहां अपराध के मामले में भी बढ़ गए थे। यहां पुलिसकर्मियों को भी बंधक बनाया गया था।

घोषणापत्र का हिस्सा था पत्थलगड़ी के मुकदमों की वापसी : कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, रांची

कांग्रेस कोटे से झारखंड सरकार में मंत्री बने रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम ने कहा है कि आदिवासी किसी से भी अधिक देशभक्त होते हैं, लेकिन इनके खिलाफ गलत धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गया। पत्थलगड़ी करने पर इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा किया गया, जबकि पत्थलगड़ी हमारी परंपरा का हिस्सा है। दोनों ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस कर दावा किया कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुए मुकदमों की वापसी की बात गठबंधन के सभी दलों ने की थी और जो भी वादे किए गए थे उसे पूरा करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोनों नेताओं ने कहा कि जनता से हमारा वादा लगभग एक जैसा है और शीघ्र ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (साझा न्यूनतम कार्यक्रम) के तहत आगे की रणनीति तय की जाएगी।

रामेश्वर उरांव ने कहा कि 1857 से पहले आदिवासियों ने ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया था। आदिवासी कभी देशद्रोही हो ही नहीं सकते। दैनिक जागरण के सवाल - डीसी और एसपी को बंधक बनानेवालों के साथ आप कैसे खड़े हो सकते हैं, पर नेताओं ने कहा कि परिस्थितियां ऐसी बन गई थीं लेकिन इससे सही ढंग से निपटा नहीं गया। आइपीएस अधिकारी रह चुके रामेश्वर उरांव ने कहा कि खूंटी, चाईबासा और संताल परगना के आदिवासी हमेशा से राष्ट्रभक्त रहे हैं। मुकदमा वापसी के सवाल पर नेताओं ने कहा कि प्रक्रिया के तहत सभी फैसलों पर अनुकरण होगा। जिन मामलों में चार्जशीट भी हुई होगी उनपर भी सरकार फैसले लेगी।

आलमगीर आलम ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून लोगों पर थोपा जा रहा था और जनता का फैसला यही बता रहा है कि यह कानून मंजूर नहीं है। जनता ने डर का वातावरण बनाने के खिलाफ अपना वोट दिया है। एक अन्य सवाल के जवाब ने दोनों ने कहा कि अब विकास योजनाओं के लिए पेड़ कटेंगे तो उससे कहीं ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। सरकार यह सुनिश्चित करेगी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर व अन्य मौजूद थे।

पीसीएस परीक्षा देने के घटेंगे मौके

अजय जायसवाल, लखनऊ

▸ संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर उप्र लोक सेवा आयोग में लागू होगी व्यवस्था

▸ अधिकतम आयु की घटेगी सीमा, नहीं दे सकेंगे 20-25 बार परीक्षा

आधी-अधूरी तैयारी के साथ ही वर्षों किस्मत आजमाते रहने की फितरत वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) परीक्षा के दरवाजे बंद होने जा रहे हैं। योग्य अभ्यर्थियों की व्यवस्थित परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) अधिकतम आयु सीमा को घटाकर पीसीएस परीक्षा देने के अवसरों को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तर्ज पर सीमित करने जा रहा है।

वर्तमान व्यवस्था में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रांतीय सिविल सेवा के पदों के लिए कराई जाने वाली सबसे अहम परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा जहां 21 वर्ष है। वहीं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 व ओबीसी सहित अन्य आरक्षित वर्ग, भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 वर्ष है। सरकारी सेवा में नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट है, जिससे वे भी 45 वर्ष तक परीक्षा दे सकते हैं। दिव्यांगों के लिए 55 वर्ष की आयु सीमा है।

उम्मीद में देते रहते हैं परीक्षा : इस तरह सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पीसीएस की परीक्षा में भाग लेने के 20 अवसर तक मिल सकते हैं, आरक्षित वर्ग को 25 और दिव्यांग को 40। इतने अधिक अवसर मिलने के कारण कई बार बिना पूरी तैयारी के भी अभ्यर्थी, सफलता की उम्मीद में परीक्षा में भाग लेते रहते हैं। पीसीएस परीक्षा में अभ्यर्थियों की बढ़ती संख्या का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 2016 में जहां तकरीबन 4.36 लाख आवेदन किए गए, वहीं 2017 में 4.55 लाख और 2018 में 6.36 लाख।

इंतजाम और नतीजों की चुनौती : परीक्षार्थियों की बढ़ती संख्या से आयोग के सामने जहां बड़े पैमाने पर इंतजाम करने की चुनौती रहती है, वहीं नतीजे घोषित करने में समय लगता है। राज्य सरकार को अपेक्षाकृत युवा अफसर मिलने की संभावना भी कम रहती है। सूत्रों को मुताबिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। आयोग जल्द ही इस संबंध में फैसला कर सकता है। जरुरत पड़ने पर आयोग, संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भी भेजेगा।

यूपीएससी की व्यवस्था ही उचित

आयोग का मानना है कि यूपीएससी द्वारा अखिल भारतीय स्तर की सिविल सेवा परीक्षा के लिए लागू व्यवस्था ही उचित है। आइएएस परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु तो 21 वर्ष ही है, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु की सीमा 32 वर्ष होने के साथ ही अवसरों की संख्या छह ही है। यानी आइएएस बनने के लिए 11 साल में छह बार ही परीक्षा दे सकते हैं। ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए 35 वर्ष व नौ अवसर यानी 14 साल में नौ अवसर तय हैं। एससी व एसटी के लिए जहां आयु की कोई बाध्यता नहीं है। वहीं, जम्मू कश्मीर के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच साल की, जबकि दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट है।

मिल सकेंगे युवा अधिकारी

प्रस्तावित नई व्यवस्था से राज्य सरकार को ज्यादातर 32 वर्ष तक के युवा पीसीएस अफसर मिल सकेंगे। वहीं, यूपीएससी जैसी परीक्षा में सफलता न मिलने पर 32 वर्ष के युवाओं के सामने दूसरे क्षेत्र में भविष्य बनाने के बहुत से मौके भी रहेंगे।

अखिल भारतीय स्तर के पदों पर भर्तियों के लिए संघ लोकसेवा आयोग द्वारा अपनाई जा रही बेहतर व्यवस्था को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी लागू कर रहा है। अब काफी हद तक यूपीएससी जैसा ही यूपीपीएससी का परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम है। अभ्यर्थियों के हित में और भी जो कुछ करना जरूरी होगा, उसे भी जल्द किया जाएगा।
- डॉ. प्रभात कुमार, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

न्यूज गैलरी

आज शपथ लेंगे प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी

रांची : झारखंड के प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी मंगलवार को शपथ लेंगे। राजभवन में शाम पौने पांच बजे उन्हें राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत मंत्रिपरिषद के सदस्य भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। ज्ञात हो कि झारखंड की नई विधानसभा का विशेष सत्र छह जनवरी से शुरू हो रहा है। (राब्यू)

नगालैंड में छह माह के लिए और बढ़ाया गया अफस्पा

नई दिल्ली : पूरे नगालैंड को अगले छह माह के लिए गड़बड़ी वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। जून के आखिर तक राज्य में अफस्पा बढ़ा दिया गया है। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और बिना पूर्व सूचना के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार हासिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। (प्रेट्र)

गुजरात के मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश

अहमदाबाद : मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने गुजरात के गृह मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। 2007 के विधानसभा चुनाव में गृह मंत्री असारवा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी थे। उस समय नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शाह ने जडेजा के खिलाफ 22 अक्टूबर 2007 को चुनाव आयोग को शिकायत सौंपी थी। (प्रेट्र)

नारायणसामी की सिंगापुर यात्रा की सीबीआइ जांच की मांग

पुडुचेरी : पुडुचेरी में विपक्षी अन्नाद्रमुक ने उपराज्यपाल किरन बेदी से मुलाकात कर मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी की सिंगापुर यात्रा की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की। केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में अन्नाद्रमुक के सचेतक वाय्यापुरी मणिकांदम ने बेदी से उनके कार्यालय में मुलाकात की और इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। (प्रेट्र)

सिर्फ नीतीश की बातों की ही अहमियत : गिरिराज

पटना : केंद्रीय मंत्री और बिहार भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि जदयू में नीतीश कुमार क्या कहते हैं सिर्फ उसी बात की अहमियत है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जैसे भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बिहार में सुशील मोदी की बातों की अहमियत है वैसे ही नीतीश के बयान का महत्व है। (जासं)

सबको साथ लेकर करेंगे विकास : हेमंत

राज्य ब्यूरो, रांची

सुबह से ही लंबी कतार, कोई दुमका से आया है तो कोई चाईबासा से। उन लोगों का बड़ा जमावड़ा कांके रोड स्थित नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास है जो रविवार को शपथ ग्रहण समारोह देखने आए थे। आवास में लोगों को संभालने में सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद हैं। एक बैरिकेडिंग सुरक्षा के मद्देनजर बनाई गई है जो मुख्य भवन से सटी है।

विनोद किस्कू नए मुख्यमंत्री को एक बार मिलकर शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं जमशेदपुर से। कहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनसे मिलकर। किसी को नौकरी की आस है तो कई बस चेहरा दिखाने के लिए जुटे हैं दरवाजे पर। झामुमो कार्यकर्ताओं का एक जत्था भी डटा है जो रह-रहकर नारे लगाता है पूरे उत्साह से। कई लोग सुबह ही चले आए थे। इंतजार है दीदार का। दोपहर में जानकारी मिलती है कि लोगों से मिलेंगे। सुरक्षाकर्मी मुस्तैद। हेमंत सोरेन बाहर आते हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। मौजूद बच्चों को दुलारते हैं। कुछ लोगों की इच्छा साथ में तस्वीर लेने की है। उनको भी निराश नहीं करते। सेल्फी के लिए पोज देते हैं। गुलदस्ते का ढेर लगा है। किताबें लेकर आने वालों की तादात ज्यादा है। इस बारे में हेमंत सोरेन की अपील का असर पड़ा है।

रांची स्थित सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देते राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश (बाएं)। जागरण

राज्यसभा के उप सभापति से मुलाकात

राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। वे रविवार को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे। उन्होंने लाल गुलाब का गुलदस्ता मुख्यमंत्री को सौंपा और बधाई दी। मुख्यमंत्री को किताब भी सौंपी। दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई।

उनके आवास पर तैनात एक कर्मी बताता है कि कमरा भर गया है किताबों से। सबको सहेजकर रखने के लिए कहा गया है।

कुछ लोग बरामदे तक आकर मिलते हैं। युवा कार्यकर्ता पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। हेमंत सोरेन सबसे गर्मजोशी से मिलते हैं। मीडिया के लोगों से भी बातचीत का दौर चलता है। कहते हैं-सबको लेकर साथ बढ़ना है। झारखंड का नए सिरे निर्माण करना है। सपने के अनुरूप बनाना है राज्य को। बहुत काम है करने के लिए। सबके मदद की जरूरत होगी। उनकी सरकार झारखंड के सर्वांगीण विकास और कल्याण के प्रति निरंतर कटिबद्ध रहेगी। झारखंड की समस्त जनमानस की अपेक्षा के अनुरूप राज्य प्रगति के नए मापदंड स्थापित करेगी।

रात में मिलने पहुंचे प्रदीप यादव : झारखंड विकास मोर्चा के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव सोमवार को मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। झारखंड विकास मोर्चा ने हेमंत सरकार को बिना शर्त समर्थन की घोषणा की है। प्रदीप यादव ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट करार दिया। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान जन सरोकार के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं-सहायिकाओं की ही तरह लंबित वृद्धा पेंशन भुगतान की ओर भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। साथ ही राशन कार्ड से वंचित राज्य की बड़ी आबादी पर भी गौर फरमाने का अनुरोध किया। बकौल प्रदीप, सीएम ने इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही।

जब मुख्यमंत्री पिता ने संतान को बनाया मंत्री

महाराष्ट्र की सियासत में भाजपा से अलग होकर सरकार बनाने वाले उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने बेटे आदित्य ठाकरे को मंत्री बना दिया है। संभवत: यह महाराष्ट्र का पहला मामला है, लेकिन देश में ऐसे और भी कई उद्धरण मौजूद हैं जब मुख्यमंत्री पिता ने अपनी संतान को कैबिनेट में शामिल किया है। वैसे तो सियासत में परिवारवाद का मामला अब नया रहीं रहा। आइए, राजनीति के इस रंग को देखने के लिए उन मामलों पर डालते हैं एक नजर :

करूणानिधि-स्टालिन

तमिलनाडु की सियासत में वंशवाद का बोलबाला रहा है। 2006 में करुणानिधि के नेतृत्व में डीएमके की सरकार बनी तो उन्होंने अपने छोटे बेटे एमके स्टालिन को कैबिनेट मंत्री बनाया। 2006 से 2009 तक स्टालिन मंत्री पद पर बने रहे। 2009- 2011 तक वे उप मुख्यमंत्री रहे।

केसीआर-केटीआर

तेलंगाना के अलग राज्य बनने के बाद पहले ही चुनाव में टीआरएस की सरकार बनी। मुख्यमंत्री के बाद के .चंद्रशेखर राव ने अपने बेटे केटी रामा राव को मंत्री बनाया। 2018 में टीआरएस फिर सत्ता में लौटी और केसीआर ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। उन्होंने एक बार फिर अपने बेटे को मंत्री बनाया।

चौधरी देवीलाल और रणजीत चौटाला

हरियाणा के दिग्गज नेता चौधरी देवीलाल 17 जुलाई 1987 को मुख्यमंत्री बने तो बेटे रणजीत चौटाला को मंत्रिमंडल में शामिल किया। रणजीत चौटाला कृषि मंत्री बनाए गए थे। देवीलाल का यह कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 तक रहा। रणजीत उस समय सिरसा के रोड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे। वर्तमान में हरियाणा के बिजली मंत्री हैं और सिरसा के रानिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय जीते हैं।

प्रकाश सिंह बादल-सुखबीर सिंह

2007 में पंजाब की अकाली सरकार की कमान प्रकाश सिंह बादल ने संभाली। प्रकाश सिंह बादल को अपनी राजनीतिक विरासत सुखबीर को सौंपनी थी। इसलिए पहले उन्हें 2008 में अकाली दल की कमान सौंपी और फिर 2009 में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 2012 में भी यही कहानी दोहराई गई। जब प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री और सुखबीर सिंह बादल मंत्री बने थे।

भाजपा ने किया बहिष्कार

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के मंत्रिमंडल विस्तार का विरोधी दल भाजपा ने बहिष्कार किया। समारोह में राकांपा अध्यक्ष शरद पवार, कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे और उद्धव ठाकरे के परिवार सहित शिवसेना, कांग्रेस, राकांपा के सभी विधायक उपस्थित थे।

संजय राउत रहे गैरहाजिर : शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत समारोह में नजर नहीं आए। बताया जाता है कि वे अपने भाई सुनील राउत को मंत्री बनाए जाने की अपेक्षा रख रहे थे, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिलने से संजय नाराज हो गए हैं।

जेपी की तरह एलपी आंदोलन चलाने की तैयारी में तेजप्रताप

राज्य ब्यूरो, पटना

▸ प्रदेश छात्र राजद कमेटी को किया भंग जनवरी में बनेगी नई कमेटी

विधानसभा चुनाव के पहले तेज प्रताप यादव सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने छात्र राजद की कमेटी को भंग कर दिया है और जनवरी में नई कमेटी के विस्तार की बात की है। साथ ही जेपी (जयप्रकाश नारायण) आंदोलन की तर्ज पर एलपी (लालू प्रसाद) आंदोलन चलाने का एलान किया है। तेज प्रताप ने सारी जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। लालू प्रसाद ने उन्हें छात्र राजद की कमान सौंप रखी है।

सृजन स्वराज वाली छात्र राजद की वर्तमान कमेटी को भंग करने की घोषणा के साथ तेज प्रताप ने कहा है कि नए वर्ष में नई कमेटी का विस्तार किया जाएगा, जिसमें कर्मठ लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी कमेटी के नेतृत्व में छात्र, बेरोजगार एवं किसानों के हक की रक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी एलपी आंदोलन चलाया जाएगा। चारा घोटाले में रांची जेल अस्पताल में बंद लालू प्रसाद को छुड़ाने के लिए तेज प्रताप इसके पहले भी एलपी आंदोलन चलाने की बात कह चुके हैं। हालांकि उनका आंदोलन अभी तक शुरू नहीं हो सका है।

तेज प्रताप ने अपने ट्वीट में लालू प्रसाद के साथ अपनी एक तस्वीर भी डाली है। तस्वीर में एक नारा लिखा है- जब-जब छात्र बोला है। राज सिंहासन डोला है।' तेज प्रताप के अचानक इस कदम से सवाल उठ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि अभी हाल में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में राजद का अच्छा प्रदर्शन रहा है। परिणाम को लेकर वह उत्साह का प्रदर्शन भी कर चुके हैं। उनके करीबी नेताओं का दावा है कि अब वह फिर से आकाश यादव के हाथ में कमान सौंपने की तैयारी में हैं। आकाश पूर्व में छात्र राजद के अध्यक्ष रह चुके हैं। किंतु किसी कारणवश उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कहा जा रहा है कि आकाश दोबारा राजद में लौट आए हैं।

झारखंड में भाजपा को नेता विधायक दल और प्रदेश अध्यक्ष की तलाश

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड में सत्ता हाथ से फिसलने के बाद भाजपा सदमे में हैं। भाजपा विधायक दल के नेता रघुवर दास और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा चुनाव हार चुके हैं। बदले राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सबकी नजर भाजपा विधायक दल के अगले नेता पर है। इस रेस में रांची के विधायक सीपी सिंह और खूंटी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा आगे बताए जाते हैं। सीपी सिंह का राजनीतिक अनुभव नीलकंठ सिंह मुंडा से ज्यादा है। वह छठी बार लगातार जीत हासिल करने में सफल रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष समेत विभिन्न अहम विभागों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर रही है। उधर नीलकंठ सिंह मुंडा पांचवी बार विधायक चुने गए हैं। फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए इस नतीजे पर पहुंचना कठिन है कि रघुवर दास के स्थान पर किसी गैर आदिवासी को ही विधायक दल के नेता पद की कमान दी जाए या नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुकाबले के लिए आदिवासी नेता पर दांव लगाया जाए। भाजपा के एक वरीय नेता के मुताबिक विधायक दल के नेता पद पर चयन का निर्णय आलाकमान को लेना है। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व द्वारा पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। विधायकों से मंतव्य लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

रघुवर दास। फाइल

कद्दावर नेता की तलाश : प्रदेश भाजपा को एक नए अध्यक्ष की भी तलाश है। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने इस्तीफा दे दिया है। गिलुवा पहले लोकसभा का चुनाव सिंहभूम संसदीय सीट से हारे। इसके बाद उन्हें चक्रधरपुर विधानसभा सीट से भी पराजय का सामना करना पड़ा। बदली परिस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए किसी कद्दावर नेता की तलाश है। बताया जाता है कि विधायक दल के नेता पद पर चयन के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद पर अंतिम निर्णय होगा। अगर विधायक दल के नेता पद की जिम्मेदारी जनजातीय समुदाय के विधायक को मिली तो प्रदेश अध्यक्ष गैर आदिवासी होगा।

अर्जुन मुंडा की सक्रियता के मायने : जनजातीय मामलों के केंद्रीयमंत्री अर्जुन मुंडा की सक्रियता बढ़ गई है। चर्चा है कि उन्हें प्रदेश में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इस पर फैसला जल्द नहीं होगा। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार अभियान के क्रम में भी अर्जुन मुंडा को अहमियत मिली थी।

छग में पंचायत चुनाव का नामांकन शुरू, छह तक जमा होंगे पर्चे

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के लिए नामांकन सोमवार से शुरू हो गया। नामांकन के पहले दिन उम्मीदवारों ने प्रदेशभर में नामांकन पत्रों की खरीदा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुरराम सिंह ने बताया कि जिलों में निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ आरक्षण का भी प्रकाशन किया गया। साथ ही मतदाता सूची का भी प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव में एक लाख 60 हजार 725 वार्ड पंच, 11 हजार 664 सरपंच, दो हजार 979 जनपद पंचायत सदस्य और 400 जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। इसके लिए प्रदेश भर में 29 हजार 525 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पंचायत चुनाव में एक करोड़ 44 लाख 68 हजार 763 ग्रामीण मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नामांकन फार्म छह जनवरी तक मिलेगा। नौ जनवरी तक नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों की घोषणा होगी। तीन चरणों में होने वाले मतदान के दौरान पहले चरण में 28 जनवरी को वोटिंग होगी।

बनाया दबाव

कई सिख संगठनों ने श्री अकाल तख्त साहिब को सौंपा ज्ञापन, गुरदासपुर में पुलिस को दी शिकायत, गिरफ्तार करने की मांग

पंजाब में मंत्री रंधावा के खिलाफ सिख संगठनों ने खोला मोर्चा

जेएनएन, जालंधर

श्री गुरु नानक देव जी की फोटो पर आपत्तिजनक शब्दावली का इस्तेमाल करने की वीडियो वायरल होने के बाद कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। सोमवार को रंधावा के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक सिख संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। गुरदासपुर में भी सिख संगठनों ने पुलिस को शिकायत दे गिरफ्तारी की मांग की। एसजीपीसी, डीएसजीपीसी और शिरोमणि अकाली दल ने भी रंधावा के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

अमृतसर में सोमवार को करीब आधी दर्जन से अधिक संगठनों ने श्री अकाल तख्त साहिब में अधिकारियों को रंधावा के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि उन्हें श्री अकाल तख्त साहिब पर तलब कर उन पर कार्रवाई करवाई जाए।

गुरदासपुर में कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की गिरफ्तार की मांग को लेकर डीएसपी राजेश कक्कड़ (बाएं) को मांग पत्र सौंपते हुए जत्थेदार। जागरण

जत्था सिर लत्थ खालसा, अकाल खालसा दल, बाबा बुड्ढा जी सभा, गुरमत ग्रंथी सभा, बाबा दीप सिंह शिरोमणि गतका अखाड़ा, दशमेश तरना दल, जत्था 6 जून, बाबा बाज सिंह मिसल के पदाधिकारी बाबा नरायण सिंह, सुरिंदर पाल सिंह, सर्बजीत सिंह हरपाल सिंह, सरदूल सिंह, भूपिंदर सिंह, सुखवंत सिंह हरकीर्तर सिंह, सतनाम सिह अकाली, अमरजीत सिंह, परमजीत सिह अकाली और दिलबाग सिहं ने श्री अकाल तख्त साहिब पर ज्ञापन सौंपने के बाद कहा कि रंधावा ने गुरु नानक देव जी से सीएम की तुलना करके सिख कौम को गहरी ठेस पहुंचाई है।

गुरदासपुर में सिख संगठनों ने डीएसपी हेडक्वार्टर राजेश कक्कड़ को शिकायत दे धारा 295ए के तहत मामला दर्ज कर रंधावा को गिरफ्तार करने की मांग की। जत्थेदार सतनाम सिंह सूच ने कहा कि अगर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तो राज्य स्तरीय संघर्ष शुरू किया जाएगा। उधर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने रविवार को ही रंधावा के खिलाफ श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह से सख्त कार्रवाई की मांग की थी। एसजीपीसी के वरिष्ठ उपप्रधान भाई रजिंदर सिंह मेहता ने कहा था कि रंधावा ने गुरु नानक देव जी का अपमान करके छोटी मानसिकता का प्रमाण दिया है।

व्यावसायिक शिक्षा को लेकर बिहार में बन रही नई नीति

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार में कौशल विकास कार्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा को गति देने के मकसद से सरकार नई नीति तैयार कर रही है। यदि इस पर अमल हुआ तो व्यावसायिक शिक्षा से 2024 तक हरेक विद्यार्थी को जोड़ने का लक्ष्य पूरा होगा और स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों से निकलने वाले छात्र डिग्री और डिप्लोमा के साथ हुनरमंद बनकर भी निकलेंगे।

जानकारी के मुताबिक व्यावसायिक शिक्षा को लेकर तैयार होने वाली नीति का मसौदा तैयार करने में शिक्षा,श्रम संसाधन, कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, योजना एवं विकास व वित्त विभाग समेत अन्य कई विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि नई नीति के साथ व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की यह पहल उस समय की गई है, जब स्कूल-कॉलेजों से निकलने के बाद विद्यार्थियों को अभी नौकरी की तलाश में भटकना पड़ता है। इसकी वजह इनके पास कोई व्यावसायिक हुनर का न होना है। यही वजह है कि शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य रुप से जोड़ने की पहल तेज की गई है।

प्रस्तावित नीति के मसौदे में व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न विभागों से उच्चस्तर पर सलाहकार पर्षद के गठन का प्रस्ताव भी शामिल किया जाएगा। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के मसौदे में भी व्यावसायिक शिक्षा को स्कूलों में छठीं से पढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा ही प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बीच व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने का भी सुझाव दिया गया है। मसौदे में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित पारंपरिक हुनर को भी व्यावसायिक शिक्षा में शामिल करने की सिफारिश की गई है।

8 राज्य की सरकारें नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का कड़ा विरोध कर रही हैं। इनमें बंगाल, राजस्थान, केरल, पुडुचेरी, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हैं। यहां देश की 35 प्रतिशत आबादी रहती है। वहीं, झारखंड, तेलंगाना और दिल्ली भी इस कानून के विरोध में हैं।

प्रियंका ने कहा ▸ योगी के बदला लेने वाले बयान पर काम कर रहा है उत्तर प्रदेश का पुलिस-प्रशासन

'भगवा पहना है तो उस धर्म को भी धारण करें योगी'

कांग्रेस महासचिव ने उप्र के मुख्यमंत्री पर साधा निशाना

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ कांग्रेस का हमला लगातार जारी है। कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई को पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने बदला लेने का जो बयान दिया था, पुलिस-प्रशासन उसी पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहा कि यह भगवा आपका नहीं है। हिंदू धर्म का प्रतीक है। इसे पहना है तो उस धर्म को भी धारण करें। इसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।

सीएए पर प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्रियों ने कह दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून उनके राज्यों में लागू नहीं होगी। तमाम दूसरी पार्टियों ने भी एलान किया है। जनता ही इसे लागू नहीं होने देगी। कहा, सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) पर भाजपा का जागरूकता अभियान झूठों का अभियान है। सच्चाई सब जानते हैं, इसीलिए पढ़े-लिखे छात्र भी सड़कों पर हैं। वहीं एक प्रश्न के जवाब में कहा, मेरी सुरक्षा का विषय बहुत छोटा है। हम तो जनता की सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं।

▸ **बोलीं, जनता लागू नहीं होने देगी एनआरसी, कई सीएम कर चुके इन्कार**

लखनऊ में सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बात करतीं पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। जागरण

गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को कानूनी मदद देगी कांग्रेस

लखनऊ आईं प्रियंका ने दिल्ली रवानगी से पहले सोमवार को अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार आरोपितों के मामलों पर विधिक नजरिये से विचार-विमर्श किया गया। प्रदेश भर के ऐसे प्रकरणों की रिपोर्ट को साझा किया गया। तय किया कि कांग्रेस ऐसे आरोपितों को मुफ्त कानूनी मदद मुहैया कराएगी। बैठक में हुई चर्चा की जानकारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्रकारों से बातचीत में भी दी। कहा कि जिन निर्दोषों को सरकार ने फंसाया है, कांग्रेस उनके साथ है।

किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है पुलिस : लखनऊ में प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में प्रियंका ने कहा कि प्रदेश सरकार, प्रशासन और पुलिस द्वारा कई जगह अराजकता की गई है। उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं, जिनका कोई न्यायिक आधार नहीं है। प्रियंका ने बिजनौर में हिंसा के दौरान मारे गए अनस, सुलेमान, लखनऊ में गिरफ्तार किए गए सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी, पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सदफ जाफर, दीपक कबीर के साथ ही बनारस हिंदू विवि के गिरफ्तार छात्रों का उदाहरण दिया। कहा कि यह तो वह केस हैं, जिनका रिकॉर्ड है। कई मुकदमों में अज्ञात लिखा है। उसकी आड़ में पुलिस किसी को भी जेल भेज सकती है। राज्यपाल को पत्र के जरिये पूरा दस्तावेज भेजा है। उसमें तमाम मिसाल हैं, जहां पुलिस और प्रशासन गलत काम कर रहे हैं। पुलिस ने तोड़फोड़ की, उसका वीडियो है। देश के इतिहास में पहली एक मुख्यमंत्री ने जनता से बदला लेने का बयान दिया है। यह भगवान कृष्ण और राम का देश है। वह करुणा के प्रतीक हैं। इस देश की आत्मा में हिंसा, बदला, रंज के लिए जगह नहीं है।

स्कूटर पर बैठ प्रियंका ने किया सुरक्षा मानकों का उल्लंघन

नई दिल्ली, एजेंसियां : सीआरपीएफ ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के लखनऊ के हालिया दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं हुई। बल ने प्रियंका पर स्कूटर पर पीछे बैठकर यात्रा कर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

प्रियंका को मिली 'जेड प्लस' सुरक्षा घेरे के तहत उन्हें सशस्त्र कमांडो मुहैया कराने वाले बल ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस नेता ने बिना पूर्व सूचना दिए यात्रा की। 28 दिसंबर को प्रियंका के कार्यालय ने सीआरपीएफ के महानिरीक्षक (खुफिया और वीआइपी सुरक्षा) पीके सिंह को पत्र लिखकर सुरक्षा में चूक की शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि लखनऊ में पुलिस के सीओ ने कांग्रेस नेता की सुरक्षा को खतरा हो गया था। सीओ ने कांग्रेस नेताओं की गतिविधियों को सीमित करने की चेतावनी दी थी।

इसके जवाब में सिंह ने कहा कि हजरतगंज के सीओ अभय मिश्रा से कोई सुरक्षा भंग नहीं हुई है। प्रियंका ने सीआरपीएफ की टीम को उस दिन अपने सिर्फ एक कार्यक्रम की जानकारी दी थी। उन्होंने स्थानीय प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बारे में बताया था। इसके लिए सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए गए।

▸ **सीआरपीएफ ने कहा, सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं हुई**
▸ **सुरक्षा बल को कांग्रेस नेता का सिर्फ एक कार्यक्रम पता था**

सिंह ने कहा कि पुलिस के सीओ जब प्रियंका के दौरे का विस्तृत कार्यक्रम जानने गए, तो उनके निजी स्टाफ ने कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व आइपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी के घर जाने के क्रम में कांग्रेस नेता ने कम-से-कम तीन बार सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया। उन्होंने ऐसे वाहन का इस्तेमाल किया, जो बुलेट प्रूफ नहीं था। उनके साथ कोई सुरक्षा अधिकारी नहीं था। उनकी इस यात्रा के बारे में सीआरपीएफ टीम को कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि, इसके बावजूद सीआरपीएफ ने उनको उचित सुरक्षा मुहैया कराई।

उपद्रवियों पर कार्रवाई रुकवाने के लिए राज्यपाल से मिले कांग्रेसी

लखनऊ में सोमवार को राजभवन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ ज्ञापन सौंपते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा। सौजन्य से - कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने आईं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने चार दिन के प्रवास में सिर्फ नागरिकता संशोधन कानून के विरोध और प्रदर्शनकारियों को ही एजेंडे में रखा। बैठकों के बाद उन्होंने खुद 16 पेज का ज्ञापन तैयार कराया।

उनकी ओर से लिखा गया पत्र लेकर कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिला और मामले की न्यायिक जांच कराते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई रुकवाने की मांग की। प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में प्रियंका ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल को पत्र नहीं, पूरा दस्तावेज भिजवाया है। उसमें उल्लेख है कि पुलिस-प्रशासन ने किस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ गलत कार्रवाई की है। प्रियंका ने दावा किया कि जितने तथ्य कांग्रेस ने जुटाए हैं, उतने किसी राजनीतिक दल या संस्था के पास नहीं हैं। राज्यपाल से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव पीएल पुनिया, पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आचार्य प्रमोद कृष्णम और शहर अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान शामिल थे।

न्यूज गैलरी

भाजपा के खिलाफ एकजुट हो विपक्ष : ममता बनर्जी

कोलकाता : सीएए और एनआरसी को भाजपा के खिलाफ हथियार बना बंगाल की मुख्यमंत्री सोमवार को पहली बार कोलकाता से बाहर पुरुलिया जिले में सड़क पर उतरीं। इस दौरान उन्होंने तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। पुरुलिया में पैदल मार्च शुरू करने से पहले यहां आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नए कानून को लेकर अल्पसंख्यक में भय है। एनआरसी के बहाने उन्हें देश की नागरिकता से बेदखल करने की साजिश चल रही है। सभी राजनीतिक दलों, नागरिकों से जुड़े संगठनों से कहूंगी कि एकजुट हों। यह जनता का आंदोलन है। यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। (जासं)

भाजपा ने पूर्वोत्तर, बंगाल के लिए नियुक्ति की

नई दिल्ली : सीएए पर मचे विवाद के बीच भाजपा ने पूर्वोत्तर में कुछ सांगठनिक बदलाव किए हैं। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। फणिंद्रनाथ शर्मा को भाजपा का प्रदेश सचिव (संगठन) नियुक्त किया है। वह भाजपा शासित असम और त्रिपुरा के लिए जवाबदेह होंगे। अमिताभ चक्रवर्ती को बंगाल का संयुक्त महासचिव (संगठन) नियुक्त किया गया है। इस राज्य में भाजपा 2021 का विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। अनंत नारायण मिश्रा को अरुणाचल प्रदेश का प्रदेश सचिव (संगठन) नियुक्त किया गया है। (आइएएनएस)

सीएए के समर्थन में चलाया हैशटैग इंडिया सपोर्ट कैंपेन

रायपुर : भाजपा ने सीएए को लेकर पूरे देश में हैशटैग इंडिया सपोर्ट सीएए कैंपेन चलाया। राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुए कैंपेन के समर्थन में छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों ने मेगा ट्वीटथॉन में हिस्सा लिया। इसे छत्तीसगढ़ में भी व्यापक जनसमर्थन मिला। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ सिंह ने लिखा- सीएबी 2019 देश की सुरक्षा को बल प्रदान करने के साथ ही अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों को उनके अधिकार भी प्रदान करेगा। (नई दुनिया)

एनआरसी पर सोनिया की चुप्पी पर प्रशांत किशोर ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, एएनआइ : राजनीतिक रणनीतिकार और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं।

एक साक्षात्कार में प्रशांत किशोर ने कहा, 'अगर कांग्रेस अध्यक्ष एक बयान (एनआरसी मसले पर) दे दें तो इससे स्पष्टता आएगी। धरनों और विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेना कानूनसम्मत और वैध हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से इस पर एक भी आधिकारिक बयान का नहीं आना मेरी समझ से परे है।' प्रशांत किशोर मानते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष या कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्लूसी) सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस बात की घोषणा करने के लिए कहें कि वे अपने राज्यों में एनआरसी की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस समेत 10 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि वे अपने राज्यों में एनआरसी की अनुमति नहीं देंगे। क्षेत्रीय पार्टियों में नीतीश कुमार, नवीन बाबू, ममता दीदी या जगन मोहन रेड्डी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपनी पार्टियों के प्रमुख भी हैं। कांग्रेस के मामले में मुख्यमंत्री अंतिम फैसला लेने वाले नहीं हैं, बल्कि सीडब्लूसी फैसला लेने वाली उच्चतम संस्था है। मेरा सवाल और चिंता यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष आधिकारिक रूप से यह क्यों नहीं कह रहीं कि कांग्रेस शासित राज्यों में एनआरसी की अनुमति नहीं दी जाएगी।'

▸ **जदयू उपाध्यक्ष बोले, कांग्रेस अध्यक्ष का एक भी बयान नहीं आना समझ से परे**

प्रशांत किशोर। फाइल

सिर्फ नीतीश बता सकते हैं संसद में सीएए का समर्थन क्यों किया

प्रशांत किशोर ने कहा कि सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बता सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में जदयू ने किन परिस्थितियों में नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन किया। इस मुद्दे पर उन्होंने सोशल मीडिया पर नाखुशी जाहिर की थी और नीतीश से मुलाकात भी की थी।

प्रशांत किशोर ने सवाल किया, 'नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) 2003 में बनाया गया था। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। अगर यह कानून इतना ही असंवैधानिक था, जो कि सही है, कांग्रेस के पास इसमें संशोधन करने का मौका था।' वह गृह मंत्री अमित शाह के उस स्पष्टीकरण से भी असहमत हैं कि एनपीआर और एनआरसी का कोई संबंध नहीं है।

'राज्यों को सीएए को लागू करना ही होगा'

नई दिल्ली, एजेंसियां : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ गैर-भाजपा शासित राज्यों में बढ़ते विरोध के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को साफ किया कि सभी राज्यों को यह कानून लागू करना ही होगा, क्योंकि संसद ने इसे पारित किया है।

सीएए पर केंद्र के साथ ही साथ भाजपा के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए केरल के कोच्चि में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, 'संविधान के तहत उन्हें (राज्यों) इसे (सीएए) लागू करना ही होगा।' एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या मध्य प्रदेश की सरकारें कह रही हैं कि वो अपने यहां सीएए नहीं लागू करेंगी तो यह संविधान के खिलाफ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) भी लागू करना होगा, जो जनगणना का हिस्सा है।

वहीं, हैदराबाद में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि एनपीआर लगभग वैसा होगा जैसा 2010 में था, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए कुछ अतिरिक्त जानकारियां मांगी जाएंगी। उन्होंने कहा कि एनपीआर और जनगणना लगभग समान हैं। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर सीएए पर राजनीति करने का आरोप लगाया।

▸ **संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, एनपीआर को भी राज्यों को लागू करना होगा**

अर्जुन राम मेघवाल। फाइल

सीएए से मुस्लिम प्रभावित नहीं : सावंत

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य के मुस्लिम समुदाय से सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं करने का अनुरोध किया है। मुस्लिम समुदाय के नेताओं के साथ मुलाकात में सावंत ने कहा कि सीएए का मुस्लिम समुदाय पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

'सीएए-एनआरसी पर झूठ बोल रही है कांग्रेस' : तेलंगाना के करीमनगर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मुस्लिमों के मन में डर पैदा करने के लिए सीएए और एनआरसी को लेकर झूठ बोल रहे हैं। इस कानून के लागू होने से कोई मुस्लिम देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा। कांग्रेस और सहयोगी दल मुस्लिम वोट बैंक के लिए सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं।

असम में विरोधियों की जुबां पर हजारिका के गीत

असम में सीएए का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की जुबां पर भूपेन हजारिका और जूबीन गर्ग के गीत हैं। प्रदर्शनकारी हजारिका के प्रसिद्ध गीत 'विस्व विजयी नौजवान' की जुगलबंदी के साथ विरोध को धार दे रहे हैं।

आइएनपीटी की धमकी

त्रिपुरा को सीएए के दायरे से बाहर नहीं रखने पर इंडिजेनस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्रिपुरा (आइएनपीटी) ने दोबारा आंदोलन छेड़ने की धमकी दी है। संगठन के महासचिव जगदीश देबबर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य को सीएए के दायरे से बाहर रखने की मांग पर विचार करने का भरोसा दिलाया था।

संभल में बवाल से हुए नुकसान की भरपाई करेंगे 59 उपद्रवी

जासं, सम्भल

सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित भीड़ की ओर से की गई तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में उप्र प्रशासन ने संभल में 59 बवालियों को नोटिस जारी किया है। करीब 15 लाख रुपये की निजी और सार्वजनिक संपत्ति की क्षति का आकलन किया गया है। फोटो व वीडियो के आधार पर शिनाख्त करते हुए प्रशासन ने बवालियों को चिह्नित किया है। इनको नोटिस दिया गया है। ये अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रख सकेंगे। बीते 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में संभल शहर में प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने चौधरी सराय में पुलिस पर पथराव किया था और रोडवेज बस में आग लगा दी थी। कई वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया था। अगले ही दिन जुमा की नमाज के बाद भी संभल के अलावा चंदौसी में प्रदर्शनकारियों के बीच से कुछ बवालियों ने तोड़फोड़ की थी। इसके बाद निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले बवालियों को चिह्नित करने का काम शुरू हुआ। पहली बार अपर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 26 लोगों को नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस जारी किए गए। इसके बाद 31 लोगों को नोटिस जारी किए गए। सोमवार को 59 और लोगों को नोटिस दिया गया है।

'मेरे दरवाजे पर राजनीति न करें नेता'

जागरण संवाददाता, लखनऊ : लखनऊ में 19 दिसंबर को हुई हिंसा में मारे गए मोहम्मद वकील के पिता सर्फुद्दीन ने कहा कि मेरे दरवाजे पर नेता लोग राजनीति न करें। मुझे शासन और प्रशासन पूरा भरोसा है, पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रशासन मेरे साथ खड़ा है। राजनीति के चक्कर में मैं बेटे को खो चुका हूं। गौरतलब है कि रविवार को कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधि मंडल मोहम्मद वकील के घर पहुंचा था। मीडिया को दिए बयान में सर्फुद्दीन ने कहा कि नेता लोग मेरे दरवाजे पर किसी भी प्रकार की राजनीति न करें।

पंजाब में सीएए विरोध में कांग्रेस का पैदल मार्च

जासं, लुधियाना

लोकसभा में बिल पास होने के बाद भी पंजाब में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में सोमवार को कांग्रेस ने 'संविधान बचाओ, देश बचाओ' पैदल मार्च निकाला। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में निकले पैदल मार्च में प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, आशा कुमारी, मनप्रीत बादल समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए लेकिन पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू नदारद रहे।

लुधियाना के दरेसी मैदान से माता रानी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक निकाले गए पैदल मार्च के दौरान कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री कैप्टन ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को पंजाब में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश को बांटने में जुटी हुई है, लेकिन पंजाब के लोग एकजुट हैं। वे इस नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण पूरे देश में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ रहा है। 16 राज्य नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं, इसमें पंजाब भी शामिल रहेगा।

लुधियाना में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सोमवार को कांग्रेस ने 'संविधान बचाओ, देश बचाओ' पैदल मार्च निकाला। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (ग्रीन पगड़ी व ब्लैक कोट में) कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मार्च का नेतृत्व करते हुए। फोटो : जागरण

लोगों को संबोधित करते हुए कैप्टन ने संविधान की कापी भी पढ़ी और कहा कि केंद्र सरकार संविधान की बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ कर रही है। इसे वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैप्टन ने कहा कि देश भर में सीएए के विरोध की आवाज अब पूरे विश्व में गूंज रही है, लेकिन दिल्ली बैठे भाजपा के नेताओं को इस विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मार्च को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

'मेरठ एसपी ने वही किया जो देशभक्त को करना चाहिए'

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध कर रहे कुछ प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान जाने की सलाह देने वाले मेरठ के पुलिस अधीक्षक अखिलेश नारायण सिंह का बचाव किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एसपी ने वही किया जो एक पुलिस अधिकारी और एक देशभक्त को करना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा, 'एसपी ने वही किया जो पुलिस को करना चाहिए, जो देशभक्त को करना चाहिए... जो लोग भारत में रहते हैं लेकिन इसे अपशब्द कहते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, उन्हें यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है।' उन्होंने कहा, 'जो लोग पुलिस अधीक्षक के खिलाफ बोल रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि पूरी घटना देखें, अन्यथा देश के लोग उनसे सवाल करेंगे।' गिरिराज सिंह की यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राथमिकता शांति स्थापना की होनी चाहिए, न कि भड़काने की और अगर अधिकारी का वीडियो सही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

अपील

आइआइटी कानपुर के पूर्व छात्र सम्मेलन में पहुंचे देश-विदेश से 90 पूर्व छात्र, संस्थान को 1.7 करोड़ रुपये की गुरुदक्षिणा भी दी

'सुरक्षित भविष्य की ओर कदम है सीएए'

जागरण संवाददाता, कानपुर

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर हो रही चर्चा से हर व्यक्ति जुड़ गया है। कोई इसे अपने भविष्य से जोड़कर देख रहा है तो कोई राष्ट्र हित से। इस चर्चा में शिक्षाविद्, प्रोफेसर व पेशेवर के बाद आइआइटी कानपुर के पूर्व छात्रों ने खुलकर अपनी बात रखी।

सोमवार को पूर्व छात्र सम्मेलन में देश-विदेश से 90 पूर्व छात्र पहुंचे थे। किसी ने इसे सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ता कदम बताया तो किसी की नजर में ठीक नहीं रहा। 2013 में केमिकल इंजीनियरिंग (नैनो टेक्नोलाजी) से पीएचडी करने वाले डॉ. संदीप पाटिल का कहना है कि सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ाया गया यह कदम आम से लेकर खास व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। एक राष्ट्र के लिए यह जरूरी है कि हर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चत हो। इससे गलत व सही का पता आसानी से लगाया जा सकेगा जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है।

कोई खामी नहीं : आइआइटी से बैचलर इन साइंस व मास्टर इन साइंस की दोहरी डिग्री प्राप्त करने वाले आयुष पाठक की नजर में सीएए में कोई खामी नहीं है। बोले, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की जो बात की जा रही है, उसके परिणाम क्या होंगे, अभी यह कह पाना मुश्किल है। हां, किसी का इससे नुकसान न हो, यह जरूरी है।

एक वर्ग को बाहर रखने की बात उचित नहीं: मैटीरियल इंजीनियरिंग साइंस के पूर्व छात्र रहे शुभम गुप्ता कहते हैं, किसी भी कानून में एक वर्ग को बाहर रखना उचित नहीं। जो खबरें आ रही हैं, उससे लग रहा है कि इससे एक वर्ग को शायद पूरा लाभ नहीं मिले। इसे लागू करने के बाद ही तस्वीर स्पष्ट होगी। हालांकि समय की नजाकत कहती है, अर्थव्यवस्था व रोजगार जैसे मुद्दों पर विचार अधिक हो।

मेडिकल डिवाइस व दवाइयों पर रिसर्च होगी

आइआइटी कानपुर में मेडिकल डिवाइस व दवाइयों पर रिसर्च होगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग ने यहां रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाने की इच्छा जताई है। विभाग के संयुक्त सचिव नवदीप रिनवा ने सोमवार रात पूर्व छात्र सम्मेलन के इसका प्रजेंटेशन दिया और आइआइटी प्रशासन ने प्रस्ताव तैयार करने को कहा। पूर्व छात्र सम्मेलन में शिरकत करने आए आइएएस (1999 बैच) नवदीप रिनवा ने बताया कि इस सेंटर में प्रोफेसर व छात्रों के अलावा कंपनी विशेषज्ञ भी मेडिकल डिवाइस व दवाइयां बनाने का फार्मूला तैयार कर सकेंगे। बोले कि विभिन्न राज्यों में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाने की भी योजना है। इसके लिए तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से प्रस्ताव आ चुके हैं। वहीं 1995 बैच के छात्रों ने संस्थान को 1 करोड़ 70 लाख रुपये की गुरुदक्षिणा दी है।

सीएए विरोधी प्रदर्शनों के कारण प्रभावित परिवारों से मिले नेता : राहुल

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं से ऐसे परिवारों से मुलाकात करने की अपील की है जिनके सदस्य सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान मारे गए हैं या घायल हुए हैं। असम में शनिवार को कांग्रेस नेता ने दो पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। सोमवार को उन्होंने कहा कि सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान कई लोग घायल हुए और मारे गए।

उन्होंने ट्वीट किया, 'पूरे भारत में कई नौजवान पुरुष एवं महिलाएं सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए घायल हुईं और यहां तक कि कुछ की तो मौत भी हो गई। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे पीड़ितों के परिवारों से मिलें और हरसंभव सहायता प्रदान करें। शनिवार को मैंने असम में मारे गए दो युवकों के परिवारों से मुलाकात की।' गौरतलब है कि कांग्रेस सीएए को 'असंवैधानिक' करार देते हुए इसका खुलकर विरोध कर रही है।

असम में अवैध प्रवासियों का पता लगाएंगे ई-फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स

गुवाहाटी, आइएएनएस : केंद्र सरकार द्वारा 99 करोड़ रुपये से प्रायोजित स्मार्ट डिजिटल पद्धति ई-फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स (ई-एफटी) से असम में उन अवैध प्रवासियों का पता (ट्रैक) लगाया जाएगा जिनकी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के जरिये पहचान हो चुकी है।

असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह एवं राजनीतिक) कुमार संजय कृष्ण ने बताया कि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने 99 करोड़ रुपये की ई-एफटी योजना को स्वीकृति दी है जिसके तहत एनआरसी के जरिये पहचाने गए संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए बायोमैट्रिक आधारित रीयल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया, 'राज्यभर में ई-एफटी पर काम शुरू हो गया है। गृह विभाग जिलाधिकारियों, जिला पुलिस प्रमुखों, सभी फॉरेनर्स टिब्यूनलों और सीमा शाखा विभाग के समन्वय से इस काम को संयुक्त रूप से पूरा करेगा।' बता दें कि संजय कृष्ण को पिछले हफ्ते राज्य का अगला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वह मंगलवार को सेवानिवृत्त हो रहे वर्तमान मुख्य सचिव आलोक कुमार का स्थान लेंगे। संजय कृष्ण ने बताया कि असम में फिलहाल 100 फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (एफटी) काम कर रहे हैं, 200 और एफटी के गठन की प्रक्रिया जारी है।

▸ **केंद्र सरकार ने दी इस योजना को मंजूरी**

असम गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, ई-एफटी सिंगल विंडो सिस्टम है जिससे घोषित विदेशियों का रीयल टाइम आधार पर पता लगाने, उन पर मुकदमा चलाने, हिरासत में लेने और उन्हें निर्वासित करने में मदद मिलेगी। असम सरकार इसे केंद्र सरकार के साथ संयुक्त रूप से कार्यान्वित कर रही है।

90 दिन से अधिक समय तक कश्मीर में इंटरनेट बंद होने से सभी निष्क्रिय वाट्सएप अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। द कश्मीर चेंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है कि पांच अगस्त से इंटरनेट बंद होने से कश्मीर में 18,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

जंगलों से आई खुशखबरी, देश में बढ़ रहा वन क्षेत्र

जंगलों से खुशखबरी आई है। देश में वन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। दो साल में पांच हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र फैल गया है। इसमें वन क्षेत्र और वन से इतर पेड़ों को भी हरित क्षेत्र में शुमार किया गया है। केंद्रीय जलवायु, वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सोमवार को देश में वन क्षेत्र की स्टेटस रिपोर्ट 2019 जारी की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सभी श्रेणियों में देश का वन क्षेत्र बढ़ा है।

बढ़ रहा है वनों दायरा

जावडेकर ने कहा कि देश के कुल वन क्षेत्र का दायरा 21.67 फीसद हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से 2019 की पांच साल की अवधि में देश के वन क्षेत्र में 13 हजार वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। इस दौरान सघन वन क्षेत्र और विरल वन क्षेत्र समेत सामान्य वन क्षेत्र की श्रेणियों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है जो अकेले भारत में संभव हो सका है।

पेरिस समझौते के लक्ष्यों की ओर

जलवायु, वन एवं पर्यावरण मंत्री जावडेकर ने कहा कि देश के उत्सर्जित कार्बन में 2017 के पिछले आकलन के मुकाबले 4.26 करोड़ टन की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि भारत पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

कर्नाटक, आंध्र में बढ़े वन

देश में कुल वन व पेड़ आच्छादित क्षेत्र 8.07 करोड़ हेक्टेयर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56 फीसद है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल क्रमशः सबसे अधिक तेजी से बढ़ रहे वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। जबकि मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े वन क्षेत्र वाले राज्य हैं।

पूर्वोत्तर में घटे वन

देश के अमूमन सभी राज्यों में वन क्षेत्र बढ़ रहा है, लेकिन इसके विपरीत पूर्वोत्तर राज्यों में वन आच्छादित क्षेत्र में कमी आई है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा, मौजूदा आकलन दिखाता है कि पूर्वोत्तर भारत में वन आच्छादित क्षेत्र में 765 वर्ग किलोमीटर (0.45 प्रतिशत) तक की कमी आई। असम और त्रिपुरा के अलावा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में वन आच्छादित क्षेत्र में कमी देखी गई।

आग लगने की घटनाओं में कमी

मालूम हो कि आइएसएफआर रिपोर्ट हर दो साल में एक बार जारी की जाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के जंगलों में आग लगने की वारदातों में 20 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है।

5,000 वर्ग किमी — दो साल में इतना अधिक बढ़ा वन क्षेत्र

21.67% — देश के कुल वन क्षेत्र का दायरा

13,000 वर्ग किमी — पांच साल में देश के वन क्षेत्र में हुआ इजाफा

4.26 करोड़ टन — उत्सर्जित कार्बन में 2017 के मुकाबले वृद्धि

8.07 करोड़ हेक्टेयर — देश में कुल वन एवं पेड़ आच्छादित क्षेत्र

765 वर्ग किमी — पूर्वोत्तर में वन आच्छादित क्षेत्र में कमी आई

20% — जंगलों में आग लगने की वारदातों में कमी

कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल में सबसे तेजी से बढ़ रहे वन क्षेत्र

असम-त्रिपुरा के अलावा सभी पूर्वोत्तर राज्यों में वन क्षेत्र कम हुआ

अरुणाचल, छत्तीसगढ़ मप्र और महाराष्ट्र बड़े वन क्षेत्र वाले राज्य

न्यूज गैलरी

नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी के पांच नेता किए गए रिहा

जम्मू : जम्मू कश्मीर में सुधर रहे हालात को देखते हुए सरकार ने सोमवार को पांच और नेताओं को रिहा कर दिया। इनमें दो नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) और तीन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेता शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद इन नेताओं को एहतियातन हिरासत में लिया गया था। रिहा किए गए नेताओं में इशफाक जब्बर व गुलाम नबी भट नेकां और बशीर मीर, जहूर मीर व यासिर रेशी पीडीपी के हैं। रेशी को पीडीपी के बागी नेता के रूप में जाना जाता है। अब तक सात नेता रिहा हो चुके हैं। (राब्यू)

हीरानगर में रात से सुबह तक होती रही गोलाबारी

हीरानगर : नियंत्रण रेखा पर सोमवार को शांति रही, लेकिन जम्मू के कठुआ जिले में हीरानगर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाक रेंजर्स ने रविवार रात रात साढ़े दस बजे से सोमवार तड़के तक भारी गोलाबारी की। चक चंगा, छन्नटांडा, करोल और माथरियां आदि गांवों को निशाना बनाया। रेंजरों ने मशीनगनों से गोलीबारी की और मोर्टार के गोले भी दागे। गोलाबारी से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। जिला उपायुक्त ओम प्रकाश ने लोक निर्माण विभाग को प्रभावित गांवों में बंकर निर्माण कार्य तेज कर देने का निर्देश दिया है। (संवाद सहयोगी)

नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाला एएसआइ बर्खास्त

चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस ने शनिवार को बटाला के महावीर नगर में 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले एएसआइ सुरिंदर कुमार को बर्खास्त कर दिया है। रविवार को पीड़ित लड़की की दादी ने बटाला में एफआइआर दर्ज करवाई थी। इसे बाद सुरिंदर कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने उसकी बर्खास्तगी के आदेश जारी किए। डीजीपी ने सुरिंदर कुमार के खिलाफ जल्द चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस को जांच में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। (राब्यू)

पहाड़ से भी ज्यादा ठंडा हो गया मैदान

मौसम की मार ▸ शिमला और मनाली से भी कहीं ज्यादा ठंडे रहे उत्तर प्रदेश के कई जिले

बादल और प्रदूषण से धरती पर नहीं पहुंच पा रही सूर्य की किरण

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

लगभग एक पखवाड़े से पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है। हालत यह है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई जिलों में न्यूनतम तापमान पहाड़ों पर स्थित शिमला, मसूरी और मनाली से भी कम रहे हैं। दिल्ली में दिसंबर माह में सबसे कम औसतन अधिकतम तापमान का 119 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। रविवार को राजस्थान के पांच शहरों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे रहा, जबकि हरियाणा के हिसार में कई दिनों से न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान भी 2.4 डिग्री सेल्सियस तक आ पहुंचा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों का न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ठंड की वजह से अपने घरों से भी निकलने से कतरा रहे हैं।

राजस्थान में माइनस तीन, झारखंड और मध्यप्रदेश में 1 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार दिन में गुनगुनी धूप निकल रही है। यह अलग बात है कि शाम को अचानक तापमान गिरने से ठंड तेजी से बढ़ जाती है।

प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र, दिल्ली के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव कहते हैं कि इसमें शक नहीं कि जलवायु परिवर्तन से मौसमी गतिविधियां अब चरम पर पहुंचने लगी हैं। गर्मी में तापमान बहुत अधिक चला जाता है तो मानसून में बारिश का रिकॉर्ड टूटने लगा है और सर्दियों में शीतलहर भी ज्यादा ही लंबी चल गई है।

मौसम विज्ञानी के अनुसार, पिछले लगभग एक पखवाड़े से बादल महज 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पर ही सिमटे हुए हैं। धूल और प्रदूषण ने बादलों की परत को और मोटा कर दिया है। नतीजतन सूरज की गर्म किरणें इन बादलों को भेदकर धरती तक नहीं पहुंच पा रही हैं। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही हवा में नमी बहुत है। ऐसे में यह बादलों को न तो उड़ा पा रही है और न ही उन्हें ऊपर ले जा पा रही है।

ठंड से बचाना है : उत्तर और पूर्वी भारत इन दिनों भीषण ठंड से ठिठुर रहा है। इंसानों के साथ-साथ पशु-पक्षी भी सर्दी से बेचैन व परेशान हैं। गुवाहाटी स्थित असम स्टेट जू में मादा व्हाइट टाइगर खुशी को सर्दी के प्रकोप से बचाने के लिए इनदिनों हीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। एएफपी

ठंड से उत्तर प्रदेश में 62 मरे

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

ठंड के कारण लोगों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। सोमवार को उप्र में 63 और पंजाब में तीन लोगों की मौत हो गई। कोहरे कारण हुए हादसों में उप्र में सात और पंजाब में दो लोगों की मौत हो गई।

अस्पतालों में ओपीडी बढ़ी

लगातार बढ़ रही इस ठंड के कारण अस्पतालों में बीमार लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड बढ़ने से लोगों को ज्यादातर सांस से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मामल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ओपीडी में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इनमें ज्यादातर लोग सांस रोगों से पीड़ित हैं। उन्हें यह समस्या बढ़ती ठंड की वजह से हो रही है।

शहर और न्यूनतम तापमान (दिसंबर)

शहर	30	29	28	27
दिल्ली	2.6	3.4	2.4	4.2
बठिंडा	3.8	2.4	3.0	2.8
पचमढ़ी	3.8	1.2	1	3.8
हिसार	3.8	.02	-1	.3
शिमला	3.6	4.0	4.0	3.8
मसूरी	4.1	3.5	3.9	1.5
मनाली	-2.8	-2.6	-2.6	-1
नैनीताल	3.5	4.0	4.0	3.0

(डिग्री सेल्सियस में)

17वें दिन सुरक्षित निकाले गए आइटीबीपी के आठ जवान

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़

भारत-चीन सीमा पर उच्च हिमालय क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण आइटीबीपी (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) की अग्रिम चौकी रिलकोट में फंसे आठ जवानों को आखिरकार 17वें दिन सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं, दो जवानों को मुनस्यारी और छह अन्य को हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ पहुंचाया गया।

आइटीबीपी की मिलम चौकी से दूसरी जगह जाने के दौरान 12 और 13 दिसंबर को भारी बर्फबारी होने के चलते आठ जवान और सात पोर्टर रिलकोट चौकी में फंस गए थे। छह से सात फीट बर्फ जमने तथा अन्य संसाधन न होने के कारण इनका पैदल आगे बढ़ पाना संभव नहीं हो पा रहा था। तीन दिन पूर्व सात पोर्टर जोखिम उठाकर बर्फ के बीच पैदल चलकर मुनस्यारी पहुंच गए थे, जबकि चौकी में तैनात आठ जवान हथियार व अन्य जरूरी वस्तुएं होने के कारण नहीं निकल पा रहे थे। जिला प्रशासन ने जवानों को हेली रेस्क्यू करने का फैसला किया, लेकिन उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौसम की खराबी बाधा बनी हुई थी। विगत तीन दिनों के अंतराल में वायु सेना की टीम ने कई मर्तबा रेस्क्यू के लिए उड़ान भरने की कोशिश की, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। सोमवार सुबह अनुकूल मौसम होने पर वायु सेना का हेलीकॉप्टर जवानों को लेने के लिए रिलकोट पहुंचा।

बुगडियार चौकी में भी फंसे थे 19 जवान

12 दिसंबर को ही रिलकोट के साथ ही अग्रिम चौकियों से लौट रहे 19 जवान और चार पोर्टर बुगडियार चौकी में भी फंस गए थे। इन्होंने खुद ही बर्फ हटाकर रास्ता बनाया और चार दिन बाद मुनस्यारी पहुंच गए थे।

'जवान सकुशल हैं। सभी अपनी चौकी में थे, वहां उनके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं। इस दौरान जवानों को कोई परेशानी नहीं हुई। अब सभी जवान वाहिनी मुख्यालय पहुंच चुके हैं।'
-अशोक कुमार, सेनानी, 14वीं वाहिनी आइटीबीपी

डेढ़ घंटे चला रेस्क्यू : वायुसेना की टीम ने तीन चरणों में रेस्क्यू पूरा किया। पूर्वाह्न 11 बजे रेस्क्यू शुरू किया। सभी आठ जवानों को डेढ़ घंटे के अंतराल में रेस्क्यू कर लिया गया। इनमें छह जवानों को 14वीं वाहिनी के जाजरदेवल पिथौरागढ़ स्थित मुख्यालय और दो अन्य को मुनस्यारी पहुंचाया गया।

पिथौरागढ़ में सोमवार को आइटीबीपी की रिलकोट चौकी में फंसे जवानों को हेलीकाप्टर से निकालकर मुनस्यारी लाया गया। जागरण

साइबर अपराधी ने बैंक खाते से रुपये उड़ा सीएम राहत कोष में भेजे

जागरण संवाददाता, हाजीपुर : बिहार के वैशाली जिले में बदमाशों ने बैंक खाते से रुपये उड़ाकर तीन राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा स्थानांतरित कर पुलिस को अचरज में डाल दिया है।

जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के त्रिमूर्ति चौक के सुबोध कुमार सिंह की पुत्री आकृति राज का जौहरी बाजार स्थित सेंट्रल बैंक की शाखा में बचत खाता है। खाते में 1 लाख 70 हजार रुपये जमा थे। इसमें से साइबर अपराधियों ने धोखाधड़ी कर तीन दिन में छह किस्त में 70 हजार रुपये उड़ा लिए। उड़ाई गई राशि में 20 हजार रुपये किसी साहिल खान नामक व्यक्ति के खाते में स्थानांतरित कर दिए गए। उसके बाद दूसरी निकासी 10 हजार रुपये की हुई और उसे किसी राज सिंह के खाते में डाल दिए। इसके बाद 10-10 हजार रुपये असम और केरल के सीएम के रिलीफ फंड में स्थानांतरित कर दिए। इतना ही नहीं 10-10 हजार रुपये दो किस्तों में मेघालय के सीएम रिलीफ फंड में भी स्थानांतरित किए गए। जानकारी मिलने पर आकृति राज ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

संभल में रिटायरमेंट से एक दिन पहले एसडीएम बर्खास्त

जागरण संवाददाता, संभल

▸ राज्यपाल के आदेश पर शासन की ओर से की गई कार्रवाई

▸ अलीगढ़ में वर्ष 2014-15 में तहसीलदार रहते शासकीय क्षति पहुंचाने का आरोप

जिला मुख्यालय बहजोई में तैनात एसडीएम ओमवीर सिंह को शासन ने रिटायरमेंट से एक दिन पहले बर्खास्त कर दिया है। 31 दिसंबर, 2019 को उनका रिटायरमेंट है। उन पर वर्ष 2014-15 के दौरान अलीगढ़ में तहसीलदार रहते हुए शासकीय जमीन का निजी नाम पर दाखिल-खारिज करने और एक वाद नियम विरुद्ध निस्तारित करने का आरोप है। शासन से आदेश आने के बाद जिलाधिकारी ने एसडीएम के आवास पर इसे चस्पा करा दिया है।

वर्ष 2014-15 में अलीगढ़ जिले की कोल तहसील में तहसीलदार रहते हुए ओमवीर सिंह ने दो अलग-अलग मामलों का आदेश करते हुए नियमों का उल्लंघन किया था। इसमें शासकीय जमीन को निजी नाम पर दाखिल-खारिज करते हुए पांच करोड़ सात लाख 20 हजार रुपये की शासकीय क्षति पहुंचाई। साथ ही समझौते के चलते निस्तारित हुए एक मामले में 13 साल बाद बिना सुनवाई किए एकपक्षीय आदेश कर दिया। इन मामलों की शिकायत जब शासन में की गई तो अलीगढ़ के तत्कालीन मंडलायुक्त को जांच सौंपी गई, जिसमें पद का दुरुपयोग पाया गया। उन्होंने जांच रिपोर्ट 11 जनवरी, 2019 को शासन को प्रेषित की। जांच रिपोर्ट के आधार पर इसकी शिकायत राज्यपाल से की गई। राज्यपाल के आदेश पर उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव ने एसडीएम को बर्खास्त कर दिया है। चंदौसी व गुन्नौर तहसीलों में एसडीएम के पद पर रह चुके ओमवीर सिंह वर्तमान में जिला मुख्यालय पर तैनात हैं।

सम्भल के जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि जिले में तैनात एसडीएम ओमवीर सिंह को उत्तर प्रदेश शासन की ओर से बर्खास्त किया गया है। शासन की ओर से इसका आदेश हमें प्राप्त हुआ है, जिसे तामील भी करा दिया गया है।

मप्र में दो ट्रकों में टक्कर के बाद लगी आग, तीन की मौत

नईदुनिया, रतलाम : मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में नयागांव-लेबड़ फोरलेन स्थित घटला ब्रिज के निकट रविवार रात करीब डेढ़ बजे ट्रक और मिनी ट्रक में टक्कर हो गई। इसके बाद मिनी ट्रक में लगी आग से ड्राइवर, सहायक ड्राइवर सहित एक व्यापारी की जिंदा जलने से मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, हादसे में मिनी ट्रक में सवार व्यापारी असलम पुत्र मकबूल शेख (24), ड्राइवर विष्णु पुत्र मथुरालाल भास्कर (35) और सहायक ड्राइवर रमेश पुत्र पातलिया (26) की मौत हो गई। मिनी ट्रक सवार अन्य व्यापारी मुर्तुजा पुत्र गुलाम मुस्तफा खान (43) केबिन का कांच टूटने पर समय रहते बाहर निकल आए। मुर्तुजा ने बताया कि वे खरगोन से मिनी ट्रक (एमपी 10-एच 0727) में सोमवार रात करीब नौ बजे मिर्च भरकर अजमेर के लिए रवाना हुए थे। वहां पहुंचते ही मिनी ट्रक डिवाइडर से टकरा गया। इसके बाद मिनी ट्रक दूसरे लेन पर पहुंचा और सामने मार्बल से भरे ट्रक (आरजे 09-जीडी 5871) से टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। इस आग में तीन लोग जल गए।

उपराष्ट्रपति ने की भारत में जाति व्यवस्था खत्म करने की अपील

वरकला (केरल), प्रेट्र : उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने सोमवार को कहा कि आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर देश ने महत्वपूर्ण कामयाबी अर्जित की है, लेकिन जाति, समुदाय और लिंग के आधार पर भेदभाव के बढ़ते मामले बड़ी चिंता का कारण हैं। उन्होंने कहा कि जातिगत भेदभाव खत्म किया जाना समय की जरूरत है।

राज्य की राजधानी से 45 किलोमीटर दूर शिवगिरि मठ में 87वें शिवगिरि श्रद्धालु सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश से जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए और भविष्य का भारत जातिविहीन और वर्गविहीन होना चाहिए। उन्होंने गिरजाघरों, मस्जिदों और मंदिरों के प्रमुखों से जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए काम करने को कहा। नायडू ने कहा कि मठ के संस्थापक श्री नारायण गुरु महान संत और क्रांतिकारी मानवतावादी थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था और अन्य विभाजनकारी प्रवृत्ति को खारिज किया। उन्होंने कहा कि भारत को आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है, लेकिन देश में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां सामाजिक बुराइयां विद्यमान हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा, 'हम अशांति के समय में रह रहे हैं। जाति, समुदाय और लिंग के आधार पर भेदभाव बढ़ना बड़ी चिंता का कारण है। हम सबको आत्मविश्लेषण करना होगा और व्यावहारिक कदम उठाना होगा।' इस मौके पर केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान, केंद्रीय मंत्री वी. मुरलीधरन, पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी और राज्य के मंत्री के. सुरेंद्रन मौजूद थे।

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू। फाइल

शुरुआत से ही बच्चों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति पैदा करनी चाहिए

तिरुवनंतपुरम, प्रेट्र : उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने सोमवार को कहा कि शुरुआत से ही बच्चों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति और जिज्ञासा पैदा की जानी चाहिए क्योंकि विज्ञान के पास हमारी हर समस्या का समाधान है और राष्ट्र के प्रौद्योगिकीय विकास में उसका बहुत योगदान है। यहां 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सोच में जिज्ञासा, तार्किकता और खुली विचारशीलता समाहित होती है। नायडू ने जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें न सिर्फ इसका समाधान खोजना है बल्कि हमें प्रकृति को भी सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा, 'विज्ञान की शिक्षा बच्चों को बिना किसी पूर्वाग्रह के सत्य को खोजने की प्रेरणा देती है। इसके जरिये किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले बच्चे विश्लेषण, सवाल-जवाब और तार्किकता से काम ले सकते हैं।'

अभियान

आतंकरोधी अभियानों के साथ ऑपरेशन सद्भावना भी चला रही सेना, दूरदराज के इलाकों में भी लोगों को राहत देने की मुहित तेज की

नए मिशन पर सेना : अवाम की दोस्त, तो दुश्मन के लिए होगी काल

राज्य ब्यूरो, जम्मू

नये जम्मू कश्मीर में सेना नये मिशन पर है। आवाम की दोस्त, पर दुश्मन के लिए काल। पाकिस्तान की साजिशों का करार जवाब देने के साथ ही सेना लोगों के मनोभाव बदलने की कोशिश में भी लगी हुई है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत शिक्षा, खेल और चिकित्सा से आवाम को अपने साथ जोड़ रही है। बर्फबारी वाले इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालकर सेना लोगों का विश्वास और दिल जीतने में भी कामयाब रही है।

आतंकवाद पर लगाए लगाम : जम्मू कश्मीर में वर्ष 2019 में सुरक्षाबलों ने विभिन्न अभियानों में 163 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान 78 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए। आतंकी संगठन लश्कर और जैश की तो सेना ने कमर ही तोड़ दी। इस साल कई प्रमुख कमांडर मारे गए। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद आतंकवाद में खासी कमी आई। जम्मू कश्मीर में एक जनवरी से लेकर पांच अगस्त तक 136 आतंकी मारे गए थे। पांच महीनों में 27 आतंकी मारे गए। गत वर्ष जम्मू कश्मीर में 86 नागरिक मारे गए थे, जबकि इस वर्ष सिर्फ 42 नागरिक मारे गए।

लोगों का बढ़ाया जा रहा हौसला : लेफ्टिनेंट कर्नल : जम्मू के पीआरओ डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा कि सेना ने दूरदराज इलाकों में लोगों को राहत देने की मुहित तेज कर दी है। लोगों का हौसला बढ़ाकर सुनिश्चित किया जा रहा है कि दुश्मन उन्हें गुमराह न कर पाए। लोगों की सुध लेने के लिए सेना का ऑपरेशन सद्भावना कई दशकों से जारी है। लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा कि सेना शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र की मुश्किलों को प्राथमिकता पर दूर कर रही है।

कारगर साबित हो रहा ऑपरेशन 'रीच आउट' : सेना ने लोगों का दिल जीतने के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत मिशन 'रीच आउट' अभियान भी छेड़ रखा है। लोगों तक पहुंच बनाने के इस अभियान में सेना के जवान व अधिकारी खुद लोगों के पास जाकर उनके दुख दर्द के बारे में जानकारी हासिल कर उनकी सहायता कर रहे हैं। इसमें लोगों के लिए चिकित्सा शिविर लगाने से लेकर अन्य सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाती हैं।

इसी वर्ष पुलवामा हमले के बाद 26 फरवरी को वायुसेना की ओर से पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविरों पर हमले से खिसियाए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में 3200 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। मिशन रीच आउट के तहत थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, सेना की उत्तरी कमान के शीर्ष कमांडरों ने नियंत्रण रेखा के निरंतर दौरे कर लोगों की मुश्किलों को दूर करने की सेना की मुहिम को बल दिया।

ऑपरेशन मां ने मुख्याधारा में लाए भटके हुए 50 युवा : सेना ने ऑपरेशन 'मां' चलाकर पाकिस्तान के दुष्प्रचार से प्रभावित होकर बंदूक थामने वाले 50 युवाओं की वापसी की राह सुनिश्चित की। इसके तहत सेना ने आतंकी बने बच्चों की मां से अपील करवाई कि वे लौट आएं। सेना की तरफ से इस पहल का असर भी दिखा।

साल	मामले	नागरिक	सुरक्षाकर्मी	आतंकी	कुल मौतें
2019	135	42	78	163	283
2018	203	86	95	267	448
2017	164	53	83	218	354
2016	112	14	88	115	267
2015	88	19	43	116	178
2014	90	28	46	114	188

शिक्षा, खेल, चिकित्सा हर तरफ मदद

लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि सेना के 43 गुडविल स्कूल में पंद्रह हजार बच्चे अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। इसके साथ सेना तीन ट्रेनिंग-कोचिंग सेंटर भी चला रही है। युवाओं के लिए जारी वर्ष में 120 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दूरदराज के लोगों के लिए वर्ष में 200 मेडिकल कैंप व मवेशियों के इलाज के लिए 90 वैटेनरी कैंप लगाए गए। पूर्व सैनिकों के मसलों को दूर करने के लिए भी 35 रैलियों का आयोजन किया गया।

फेसबुक पर लाइक कर कमाई का झांसा देने वाला हुआ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आगरा : निवेशकों को फेसबुक पर लाइक करने का लालच देकर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाली गाजियाबाद की पेवे आइटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक अमन शर्मा को आगरा पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। वह दो साल से फरार था। 2016 में पंजीकृत इस कंपनी का कार्यालय गाजियाबाद के पैसेफिक बिजनेस पार्क में था। इसके निदेशक अमन शर्मा और वरुण कुमार गुप्ता थे। कंपनी का एक अन्य अधिकारी अमित सक्सेना निवासी सेक्टर 93बी नोएडा निदेशकों का मुख्य सहयोगी था। वरुण गुप्ता व अधिकारी अमित सक्सेना को साइबर सेल ने अक्टूबर में गिरफ्तार किया था। निदेशक अमन शर्मा फरार चल रहा था। साइबर सेल ने उसे भी नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। मामले में पांच पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

45 लाख पूर्व सैनिकों का निजी डाटा नहीं लौटाने पर रक्षा मंत्रालय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एक निजी कंपनी स्कोर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एसआइटीएल) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। यह डाटा ईसीएचएस (एक्स सर्विसमैन कांट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम) स्मार्ट कार्ड के लिए उपलब्ध कराया गया था।

हनी ट्रैप मामले में खाद्य व खनिज मंत्री के ओएसडी भी शामिल

खुल रहीं परतें ▶ मध्य प्रदेश के दोनों आरोपितों पर कार्रवाई होना तय

दोनों भाजपा सरकार में भी रह चुके हैं ओएसडी

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में दो मंत्रियों के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) के नाम भी सामने आए हैं। मानव तस्करी से जुड़े मामले में विशेष जांच दल (एसआइटी) द्वारा पेश चालान में हरीश खरे और अरुण निगम के नाम शामिल हैं। खरे खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और निगम खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल के यहां पदस्थ हैं।

सूत्रों का कहना है कि चालान में नाम आने के बाद अब इन्हें मंत्री के ओएसडी जैसे महत्वपूर्ण पद पर नहीं रखा जा सकता है। मंत्री तोमर ने खरे की सेवाएं लौटाने को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से बात भी की है। अधिकारियों ने उन्हें सलाह दी है कि वे नोटशीट लिखकर भेज दें तो सेवाएं वापस लेने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

निगम भाजपा सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रहीं रंजना बघेल के स्टाफ में पदस्थ रह चुके हैं। वहीं, खरे भी पूर्व में मंत्री नरोत्तम मिश्रा के स्टाफ में रह चुके हैं। यह बात भी उठती रही है कि अधिकांश मंत्रियों के यहां स्टाफ वही है, जो भाजपा सरकार के वक्त मंत्रियों के यहां हुआ करता था। इस संबंध में चर्चा के लिए मंत्री तोमर और जायसवाल से संपर्क करने का प्रयास किया गया पर उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

उधर, मामले के आरोपितों की जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इंदौर जिला कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने आरोपितों को 13 जनवरी तक जेल में भेज दिया।

आयकर विभाग भी सक्रिय

मामले में दलाल-बिचौलिए, आरोपित महिलाओं और अधिकारियों के बीच हुए लाखों-करोड़ों रुपयों के लेनदेन संबंधी जानकारी सामने आते ही आयकर की इन्वेस्टिगेशन विंग के साथ इंटेलीजेंस एवं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग भी सक्रिय हो गई है। मामले के प्रमुख किरदार श्वेता-विजय जैन, श्वेता-स्वप्निल जैन के एनजीओ का लेखा-जोखा और आरती दयाल के घर से मिले करोड़ों रुपये के चेक व महंगी प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के दस्तावेज भी जांच के दायरे में हैं।

थाना प्रभारी का नाम अधिकारियों को नहीं पता: हनी ट्रैप मामले की जांच के स्तर का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि छतरपुर के उस थाना प्रभारी के नाम की जानकारी पुलिस के आलाधिकारियों को भी नहीं है, जिसका जिक्र आरोपित मोनिका यादव ने बयान में किया था। उसने यह भी बताया था कि थाना प्रभारी का नाम आरती दयाल के मोबाइल में दर्ज है। भोपाल की अदालत में मोनिका यादव ने छतरपुर में एक फार्म हाउस पर तीन लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनवाकर वीडियो तैयार करने का बयान दिया है। यह फार्म हाउस छतरपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी का बताया गया है। मोनिका ने त्रिवेदी के अलावा उनके दो अन्य साथियों टिल्लू चौबे व चुलबुल पांडे का नाम भी बताया है। हालांकि, इन दोनों के असल नाम कुछ और हैं जो चालान में नहीं आ सके हैं। मामले में छतरपुर कांग्रेस अध्यक्ष का नाम आने पर प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी उपाध्यक्ष चंद्रप्रभाष शेखर ने कहा कि उनकी जानकारी में यह नहीं है। वहीं, सागर के आइजी सतीश सक्सेना ने कहा कि किसी थाना प्रभारी के बारे में मोनिका यादव कह रही है, नाम सामने आए तो कुछ कह सकते हैं।

कैदी की मौत पर पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : फिरोजपुर जेल में लगभग दस साल पहले हुई कैदी की मौत के लिए जेल विभाग को लापरवाह ठहराते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मृतक के परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। कैदियों को संविधान के तहत जीवन का अधिकार प्राप्त होने पर सख्त टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि जेल अधिकारी मृतक अमरजीत सिंह को दो दिन तक जेल में उपलब्ध करवाए गए उपचार का रिकार्ड तक पेश नहीं कर पाए। अमरजीत सिंह के खिलाफ मक्खू पुलिस थाने में 25 नवंबर, 2005 को एफआइआर दर्ज की गई थी, जिसमें उसने अपने पुत्र समेत फरवरी, 2010 को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सरेंडर कर दिया था। जेल में 5 फरवरी को अमरजीत की तबीयत खराब हो गई, लेकिन उसे 7 फरवरी को अस्पताल ले जाया गया, उसकी मौत हो गई।

अमरजीत की मौत के लिए जेल अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कैदी की पत्नी ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की थी। उसने अपने 48 वर्षीय पति की असमय मौत के लिए दस लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि मृतक को जेल में उपलब्ध करवाए गए उपचार के विषय में बरती गई चुप्पी इस मामले में आधिकारिक लापरवाही को उजागर करते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

जम्मू-कश्मीर में बाहर के लोगों के लिए भी खुलीं नौकरियां

- जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में 33 पदों के लिए आवेदन मांगे गए

जागरण न्यूज नेटवर्क, जम्मू

अनुच्छेद 370 और 35ए के खात्मे के साथ जम्मू-कश्मीर की नौकरियों में पहली बार राज्य से बाहर के लोगों के लिए आवेदन की छूट दी गई है। जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में 33 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें सामान्य श्रेणी के सभी पदों के लिए राज्य के स्थायी निवासी की कोई शर्त नहीं रखी गई है। अभी तक राज्य के स्थायी निवासी (स्टेट सब्जेक्ट) की शर्त अवश्य रहती थी। अर्थात आवेदनकर्ता जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का स्थायी निवासी हो।

राज्य के पुनर्गठन के बाद से नौकरियों को लेकर अभी तक नियम स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। भाजपा और कई अन्य संगठन नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की वकालत करते रहे हैं। वहीं कुछ लोग 15 साल से अधिक समय से राज्य में रह रहे लोगों को ही नौकरी और जमीन खरीदने का अधिकार देने की बात कर रहे हैं।

अब हाई कोर्ट ने 33 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें सीनियर स्केल और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के अलावा, टाइपिस्ट और अन्य पदों पर भर्ती की जानी है। 33 में से 17 पद ओपन मेरिट के लिए रखे गए हैं। अर्थात स्टेट सब्जेक्ट की शर्त का इसमें कोई जिक्र नहीं है।

यू कर सकेंगे आवेदन : जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्थायी निवासियों को इन पदों के लिए आवेदन अपने क्षेत्र के प्रिंसिपल जिला जज के कार्यालय में जमा करने होंगे। वहीं राज्य से बाहर के निवासियों को यह आवेदन हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास भिजवाने होंगे। संबंधित न्यायिक अधिकारियों को छुट्टियों में भी आवेदन स्वीकार करने की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं।

सियासत तेज, कांग्रेस, नेकां, पैंथर्स ने धोखा करार दिया

इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियों कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस, पैंथर्स ने इसे राज्य के नौजवानों से धोखा करार दिया है। इसके साथ ही इस मुद्दे को तूल देने की तैयारियों में जुट गई हैं। अनुच्छेद 370 हटने से पहले राज्य में नौकरियों के लिए स्टेट सब्जेक्ट मांगा जाता था। विज्ञापन में साफ तौर पर लिखा होता था कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी ही नौकरियों के लिए आवेदन करें। इसके साथ ही स्टेट सब्जेक्ट को लगाना अनिवार्य होता था। अब हाईकोर्ट में 33 पदों के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं, उनके लिए बाहरी राज्यों के उम्मीदवार भी फार्म भर सकते हैं।

आइआइटी मद्रास की छात्रा की मौत मामले की जांच करेगी सीबीआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र: सीबीआइ ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मद्रास की छात्रा फातिमा लतीफ की मौत मामले की जांच अपने हाथों में ले ली है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। जांच एजेंसी की विशेष अपराध शाखा ने 27 दिसंबर को स्थानीय पुलिस की एफआइआर फिर दर्ज की और मामले की जांच अपने हाथों में ले ली।

केरल के कोल्लम की रहने वाली छात्रा लतीफ आइआइटी मद्रास में मानविकी संकाय (पांच वर्षीय एमए प्रोग्राम) की प्रथम वर्ष की छात्रा थी। नौ नवंबर को छात्रावास के कमरे में एक पंखे से उसका शव लटकता मिला था। शुरू में इस मामले की जांच चेन्नई की कोट्टुपुरम पुलिस कर रही थी। बाद में उसे सीसीबी को हस्तांतरित किया गया था। छात्रा के पिता अब्दुल लतीफ और उसकी मां साजिता ने केरल के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पांच दिसंबर को मुलाकात की थी और अपनी बेटी के लिए न्याय मांगा था। इसके बाद यह मामला सीबीआइ को सौंप दिया गया। छात्रा के परिवार को उसके मोबाइल फोन पर सुसाइड नोट मिला था। बेटी की मौत के तुरंत बाद अब्दुल लतीफ ने चेन्नई में आरोप लगाया था कि उनके पास इस बात के सुबूत हैं कि उनकी बेटी को मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग के कुछ प्रोफेसर प्रताड़ित कर रहे थे।

न्यूज गैलरी

बीएसएफ जवानों की फायरिंग के बाद पाकिस्तानी तस्कर भागे

फिरोजपुर: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के फिरोजपुर सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पांच किलो 190 ग्राम हेरोइन बरामद की है। बीएसएफ जवानों ने रविवार रात कंटीली तार के नजदीक हलचल होती देखी। जब आवाज लगाई तो सामने से कोई जवाब नहीं आया। इस पर जवानों ने फायरिंग की। बीएसएफ जवानों ने आगे जाकर देखा तो वहां दस पैकेट हेरोइन के फेंके गए थे और फायरिंग के बाद पाक तस्कर वापस भाग गए। बीएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से फिरोजपुर सेक्टर से हेरोइन की तस्करी की गई है। उन्होंने कहा कि अब तक बीएसएफ पाकिस्तान की ओर से आई 227.77 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि तस्कर धुंध का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। (जासं)

कांडला पोर्ट पर आइएमसी टैंक में विस्फोट

अहमदाबाद : गुजरात के कांडला पोर्ट पर आइएमसी टैंक में अचानक विस्फोट होने से चार कर्मचारियों की मौत हो गई। सोमवार दोपहर करीब दो बजे मेथेनॉल टैंक के पास पांच कर्मचारी काम कर रहे थे तभी धमाका हुआ। सभी पांचों कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए। सूचना पाते ही दीनदयाल पोर्ट की फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं। धुएं के गुबार व भीषण आग के चलते अफरातफरी मच गई। काफी देर तक फायर ब्रिगेड कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे रहे। पुलिस के मुताबिक, आइएमसी टैंक नंबर 303 में 2000 मीट्रिक टन मेथेनॉल भरा हुआ। टैंक में जोरदार धमाके के साथ भीषण आग लग गई। चार कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। एक कर्मचारी को 108 एंबुलेंस की टीम द्वारा अस्पताल ले जाया गया। घटना में घायल हो गए कर्मचारी की हालत नाजुक बनी हुई है। खबर लिखे जाने तक फायर ब्रिगेड कर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे थे। (राब्यू)

भूल-सुधार: 28 दिसंबर, 2019 (शनिवार) के अंक में 'कैंसर के इलाज में भारतीय वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता' शीर्षक से प्रकाशित समाचार में एक स्थान पर आइआइटी बेंगलुरु का उल्लेख हो गया है, जिसकी जगह आइआइटी हैदराबाद होना चाहिए था। इस त्रुटि के लिए खेद है।

आग से दम घुटने से महिला व पांच बच्चों की मौत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की उत्तरांचल विहार सोसायटी में रविवार रात मोमबत्ती से कूलर और एलसीडी में आग लगने के बाद दम घुटने से एक महिला समेत पांच बच्चों की मौत हो गई। बिल जमा न होने पर बिजली कनेक्शन कटने के चलते महिला ने मोमबत्ती जलाकर कूलर के ऊपर रख दिया था, इसके बाद सभी सो गए थे। मोमबत्ती से कूलर व एलसीडी टीवी में आग लग गई थी।

मूलरूप से मेरठ निवासी यूसुफ चार भाइयों आसिफ, राशिद, मुन्ना, आरिफ व परिवार के साथ लोनी की उत्तरांचल विहार सोसायटी में रहते हैं। कॉलोनी में उनके तीन मकान हैं और पांचों भाई मोबाइल चार्जर के इलेक्ट्रॉनिक प्लेट बनाने और तार के स्क्रैप का काम करते हैं।

मेरठ निवासी रिश्तेदारों के घर शादी होने के चलते पांचों भाई पत्नियों के साथ शुक्रवार शाम वहां गए थे। बच्चे घर पर थे तो उनकी देखरेख के लिए शादी समारोह सम्पन्न होने पर रविवार रात यूसुफ और उनकी पत्नी परवीन लोनी आ गए। रविवार रात 40 वर्षीय परवीन, आसिफ की 12 वर्षीय बेटी फातिमा, 10 वर्षीय साहिमा और

लोनी स्थित उत्तरांचल विहार सोसायटी में लगी आग के बाद जला सामान। जागरण

आठ वर्षीय रुकईया और राशिद के आठ वर्षीय पुत्र अब्दुल अजीज व पांच वर्षीय अब्दुल अहद आसिफ के मकान के भूतल पर बने कमरे में सोए हुए थे, जबकि युसुफ अपने मकान में सोने चले गए थे।

घर से नहीं निकले तो लोगों को हुआ शक : फातिमा, साहिमा कक्षा तीन की छात्रा थी। रुकईया और अब्दुल अजीज यूकेजी में पढ़ाई कर रहे थे, जबकि अहद नर्सरी का छात्र था। सभी बच्चों का सोमवार को पेपर था, जिसकी वजह से वह रिश्तेदारी में हुई शादी में शामिल नहीं होने गए थे। सोमवार सुबह आठ बजे तक बच्चे स्कूल जाने के लिए बाहर नहीं निकले तो पड़ोस में रहने वाले बच्चों ने दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर आसपास के लोग एकत्र हो गए। इसके बाद लोगों ने यूसुफ के साथ मकान का दरवाजा तोड़ा तो कमरे में सो रहे सभी मृत अवस्था में पड़े थे।

फराह खान, रवीना टंडन ने कार्डिनल से माफी मांगी

मुंबई, प्रेट्र : फिल्म निर्माता फराह खान और अभिनेत्री रवीना टंडन ने रोमन कैथोलिक चर्च के भारतीय कार्डिनल, कार्डिनल ओस्वाल्ड ग्रैसिआस से मुलाकात की और उनसे माफी मांगी। एक टीवी शो में समुदाय की भावना आहत करने के आरोप में अपने खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद दोनों माफी मांगने पहुंची थीं।

इससे पहले फराह ने पूरी फ्लिपकार्ट वीडियो ओरिजनल क्विज शो 'बैकबेंचर्स' की पूरी टीम की ओर से ट्विटर पर माफी मांगी थी। इस शो में वह होस्ट थीं। उन्होंने कहा कि इस एपिसोड को फ्लिपकार्ट वीडियो ने हटा लिया है। एक बयान में शो की होस्ट डाइरेक्टर ने कहा है कि वह और रवीना बिना शर्त माफी मांगने के लिए ग्रैसिआस के पास गई थीं। फराह ने कहा है, 'कार्डिनल ओस्वाल्ड ग्रैसिआस ने हमसे मुलाकात की। हमने खेद जताया और उनसे हमारी गलतियों के लिए क्षमा करने को कहा। उन्होंने उदारता पूर्वक हमारी माफी स्वीकार कर ली। उन्होंने इस मुद्दे को समाप्त करने का बयान भी जारी कर दिया।' इंडियन क्रिश्चियन वायस के अध्यक्ष डॉ. अब्राहम मथाई ने कहा कि ईसाई समुदाय ने फराह, रवीना और भारती सिंह की माफी स्वीकार कर ली है।

एक दिन पहले ही जम्मू पहुंच गई थी सीबीआइ टीम

जेएनएन, जम्मू

सीबीआइ की 27 सदस्यीय टीम एक दिन पहले रविवार को ही जम्मू और श्रीनगर पहुंच गई थी। सोमवार को उसने कार्रवाई शुरू कर दी, जो घंटों चली।

कुमार राजीव रंजन : सीबीआइ ने 2010 बैच के आइएएस कुमार राजीव रंजन के जम्मू में कार्यालय में जांच की। राजीव अभी जम्मू विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन और जम्मू-श्रीनगर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सीईओ भी हैं। राजीव दोपहर 2:15 बजे बाहू प्लाजा स्थित अपने जेडीए कार्यालय में पहुंचे। इसके ठीक पांच मिनट बाद सीबीआइ टीम उनके कार्यालय में पहुंची और देर शाम तक वहां मौजूद रही। सूत्रों के अनुसार, टीम ने राजीव रंजन से कुपवाड़ा के जिला आयुक्त रहते हुए बनाए गए गन लाइसेंस के बारे में पूछताछ की।

यशा मुद्गल : इसके बाद सीबीआइ अधिकारी वर्ष 2007 बैच की आइएएस यशा मुद्गल से पूछताछ करने उनके सरकारी आवास जम्मू के सतवारी के अशोक नगर में गए। यशा इस समय पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कॉरपोरेशन की सीईओ और प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात हैं।

जावेद अहमद खान : इसी दौरान सीबीआइ की टीम जम्मू में पूर्व आइएएस अधिकारी जावेद अहमद खान के आवास पर गई। जावेद से कश्मीर में जिला आयुक्त रहते हुए बनाए गए गन लाइसेंस के बारे में जानकारी हासिल की गई। जावेद कुछ समय पूर्व बागवानी विभाग के आयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।

फकीर चंद भगत : राजौरी के पूर्व जिला आयुक्त फकीर चंद भगत के जम्मू के ग्रेटर कैलाश आवास में भी सीबीआइ की टीम पहुंची। टीम ने नागरिक सचिवालय में तैनात अधिकारी से भी फर्जी गन लाइसेंस बनाने के बारे में पूछताछ की।

इनके आवास की भी जांच : कुपवाड़ा के पूर्व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इतरत हुसैन, किश्तवाड़ के पूर्व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सलीम मोहम्मद, किश्तवाड़ और डोडा के पूर्व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फारूक अहमद खान और पुलवामा के पूर्व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहांगीर अहमद के घरों पर भी सीबीआइ ने दबिश दी।

प्रशिक्षण लेकर ही इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ा सकेंगे प्रोफेसर

नईदुनिया, भोपाल

देश के सरकारी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाने से पहले अब प्रोफेसरों को विशेष प्रशिक्षण लेना होगा। यह विशेष प्रशिक्षण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च (एनआइटीटीटीआर) देगा। इस संबंध में ऑल इंडिया कॉउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआइसीटीई) ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इस विशेष प्रशिक्षण को लिए बिना कोई प्रोफेसर अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा। प्रशिक्षण की पूरी रूपरेखा तय करने के लिए एनआइटीटीटीआर की तीन जनवरी को भोपाल में बैठक भी होगी।

इंजीनियरिंग कॉलेजों में लगातार गिरती शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की कवायद करते हुए एआइसीटीई ने यह पहल की है। इसी आधार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी भोपाल के एनआइटीटीटीआर को दी गई है।

आठ और दो चरण रहेंगे : एआइसीटीई के निर्देशों के मुताबिक सीनियर प्रोफेसरों और जूनियर प्रोफेसरों को अलग अलग प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो प्रोफेसर पिछले पांच साल में नियुक्त हुए हैं, उन्हें जूनियर प्रोफेसर की श्रेणी में रखा जाएगा। जबकि, पांच साल से ज्यादा अध्यापन कार्य करने वाले प्रोफेसरों को सीनियर प्रोफेसर की श्रेणी में रखा जाएगा। सीनियर प्रोफेसरों को दो चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। जबकि, जूनियर प्रोफेसरों को आठ चरण में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें सरकारी के अलावा अनुदान प्राप्त और निजी कॉलेजों के असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसर के साथ प्रोफेसरों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण लेने के लिए असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का यूनिक आइडी के तौर पर पंजीयन कर एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसके बाद वे देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अध्यापन कार्य करा पाएंगे।

40 घंटे ऑनलाइन प्रशिक्षण : यह निर्देश एआइसीटीई के उप सचिव राजेश कुमार की तरफ से जारी किए गए हैं। पहला प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रणाली से दिया जाएगा। इसमें असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसर को 40 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण लेना होगा।

मुखबिर होने के शक में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच को मारी गोली

नईदुनिया, बीजापुर : छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच बोटी लेकाम (55 वर्ष) को गोली मार दी। नक्सलियों ने पुलिस का मुखबिर होने के शक में गोली मारी है। गंभीर स्थिति में उसे बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने लेकाम के शरीर से गोली निकाल दी है।

बीजापुर एसपी दिव्यांग पटेल के मुताबिक लेकाम को जांघ और कमर में गोली लगी। समाचार लिखे जाने तक उसकी स्थिति खतरे से बाहर थी। इस मामले में अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है।

बौखलाहट निकाल रहे नक्सली: एसपी दिव्यांग पटेल के मुताबिक बीजापुर समेत बस्तर के सभी जिलों में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों की सख्ती के चलते नक्सली अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। पुलिस का दबाव लगातार नक्सलियों पर बढ़ रहा है। इससे नक्सली बौखला गए हैं और मासूम ग्रामीणों को अपना निशाना बना रहे हैं।

बीएचयू में बिना डोनर और प्रोसेसिंग फीस के मिलेगा मरीजों को खून

- योजना आज से शुरू, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा फंड
- इसे लागू करने के बाद संस्थान को 22 लाख रुपये खर्च करने होंगे

जागरण संवाददाता, वाराणसी: बीएचयू स्थित सर सुंदर लाल चिकित्सालय और ट्रामा सेंटर में अब नए साल पर भर्ती मरीजों से रक्त, फ्रेश फ्रोजेन प्लाज्मा और रैंडम डोनर प्लेटलेट्स की प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही अब ब्लड के जरूरतमंदों को डोनर लेकर आने की भी जरूरत नहीं होगी। इससे मरीजों को काफी राहत मिल सकती है। उन्हें परेशानियों से कम जूझना पड़ेगा। पहले हास्पिटल में ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो आप काउंटर पर जाइए, बिना 850 रुपये भुगतान किए सीधे काउंटर पर जाइए, बिना 850 रुपये भुगतान किए सीधे काउंटर पर जाइए... कराया लीजिए। इसके बाद मरीज को जितने भी यूनिट ब्लड की जरूरत होगी, वह तत्काल मुहैया कराई जाएगी। इसकी शुरुआत 31 दिसंबर से ही हो जाएगी।

यह जानकारी बीएचयू में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दी गई। मालूम हो कि रक्त के लिए पहले 850 रुपये व फ्रेश फ्रोजेन प्लाज्मा और रैंडम डोनर प्लेटलेट्स के लिए 400 रुपये फीस देनी पड़ती थी। इस व्यवस्था को लागू करने के बाद संस्थान को 22 लाख रुपये खर्च करने होंगे, जिसके कोष की व्यवस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा की जाएगी।

नए साल में मरीजों को सौगातें : प्रेस कांफ्रेंस के दौरान ट्रामा सेंटर के इंचार्ज प्रो. संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि समस्त उत्तर व पूर्वी भारत से मरीज नेपाल से भी लोग इलाज के लिए यहां आते हैं। इनमें गरीब मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिन्हें अब राहत मिलने वाली है। उन्होंने बताया कि दोनों हास्पिटल में भर्ती मरीजों पर 27000 यूनिट रक्त व उनके अवयवों की जरूरत होती है।

हालांकि गरीबी रेखा से नीचे वालों को संस्थान द्वारा हर वर्ष 5500 यूनिट रक्त बिना किसी चार्ज व डोनर के दिया जाता रहा है। रक्तकोष प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. एसके सिंह ने बताया कि एक अप्रैल से जननी सुरक्षा योजना लागू है, जिसके बाद 90 महिलाओं की जान बचाई गई है। इससे यहां पर मातृत्व मृत्यु दर में ढाई गुना की कमी आई है।

कार्बेट क्षेत्र के होटल व रिसॉर्ट में तेज आवाज डीजे पर प्रतिबंध

संवाद सहयोगी, रामनगर (नैनीताल) : नए साल के जश्न के मौके पर रामनगर के रिसॉर्ट व होटलों में तेज आवाज में डीजे नहीं बज सकेंगे। शासन द्वारा गठित साइलेंस जोन की टीम रात में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम के साथ रिसॉर्ट व होटलों पर नजर रखेगी। इसके लिए एसडीएम के निर्देश में तीन टीमें गठित की गई हैं।

कार्बेट पार्क की 500 मीटर की परिधि में शासन द्वारा साइलेंस जोन घोषित किया गया है। साइलेंस जोन कमेटी में एसडीएम अध्यक्ष, कार्बेट के वार्डन सचिव, उस संस्थान, सिंचाई विभाग, पुलिस, वन प्रभाग व प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। इस परिधि के अंतर्गत आने वाले रिसॉर्ट व होटलों में तेज साउंड के अलावा तेज रोशनी भी नहीं की जा सकती है। दिन में सुबह छह बजे से रात दस बजे तक केवल 50 डेसीबल व रात दस बजे से सुबह छह बजे तक 40 डेसीबल ही साउंड की जा सकती है। एसडीएम हरगिरि गोस्वामी ने साइलेंस जोन के नियमों का पालन करने के लिए रिसॉर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बीते दिनों बैठक की थी।

पहल

बारूदी सुरंगों की सरजमीं पर लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने दिखाई जाएंगी विकासपरक-देशभक्तिपूर्ण फिल्में

छग के नक्सल क्षेत्र में जवानों ने बनाया ओपन थियेटर

नईदुनिया, बीजापुर

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का बीजापुर जिला लाल आतंक (नक्सलवाद) के लिए कुख्यात है। नक्सली फोर्स को निशाना बनाने के लिए आए दिन आइईडी ब्लास्ट करते रहे हैं। इसी बारूदी सुरंगों की सरजमीं के लोगों को देश-दुनिया के साथ मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सुरक्षाबलों ने एक ओपन थियेटर बनाया है। इसका नव वर्ष के मौके पर बुधवार को उद्घाटन होगा।

इस ओपन थियेटर में रोज विकासपरक और देशभक्तिपूर्ण फिल्में दिखाई जाएंगी। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार योजनाओं की जानकारी भी टेलीफिल्म और डॉक्यूमेंट्री माध्यम से दी जाएगी। एसपी दिव्यांग पटेल के अनुसार इसका उद्देश्य लोगों को नक्सलवाद से दूर रखना और स्थानीय हकीकत से रूबरू कराना है। यह ओपन थियेटर तर्रेम मार्ग पर सारकेगुड़ा के पास स्थित सीआरपीएफ कैंप के ठीक सामने बनाया गया है। यहां यह बताना भी लाजिमी होगा कि इस जिले में एक भी थियेटर या टॉकीज नहीं है।

चर्चा में रहा सारकेगुड़ा: यह पूरा इलाका

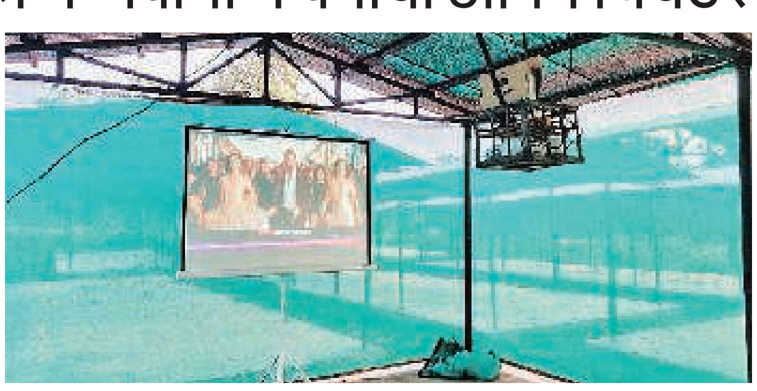

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के सारकेगुड़ा में सुरक्षाबलों द्वारा ग्रामीणों के लिए बनाया गया ओपन थियेटर। नईदुनिया

नक्सलियों के आतंक के नाम पर पहचाना जाता है। एक कथित मुठभेड़ में 17 लोगों की मौत के बाद सारकेगुड़ा काफी चर्चा में आया था। इसके बाद बासागुड़ा को जगरगुंडा से जोड़ने के लिए, पक्की सड़क का निर्माण भी शुरू किया गया है। इस दौरान जवानों को नुकसान उठाना पड़ा।

माड़ में सफल रहा है प्रयोग: बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में स्कूलों में पढ़ाने से लेकर ग्रामीणों के लिए हैल्थ कैंप लगाने, उनके सामग्री बांटने जैसे कई काम फोर्स कर रही है। दो साल पहले नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके के बासिंग में ऐसा ही एक थियेटर खोला गया था। इस थियेटर से ग्रामीणों को बाहरी दुनिया को समझने का मौका मिला।

मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने को नए तरीकों पर होगा शोध

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए वन अनुसंधान वृत्त अब उन पारंपरिक व जैविक तरीकों पर रिसर्च करेगा, जिनके इस्तेमाल से वन्यजीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वन अनुसंधान के इस प्रस्ताव को प्रमुख वन संरक्षक से मंजूरी मिल चुकी है। हरिद्वार और लालकुआं को ट्रायल के लिए चुना गया है। यहां हाथी प्रभावित क्षेत्र में जैविक तरीकों को अपनाकर तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष थामने की चुनौती बनी है। अब तक वन विभाग हाथियों को आबादी क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिए हाथी दीवार, खाई खुदवाकर व फेंसिंग पर करंट छोड़ने के साथ पटाखे फोड़ने के तरीके अपनाता था। फेंसिंग करंट पर अब प्रतिबंध लग चुका है। ऐसे में वन अनुसंधान ने प्रस्ताव तैयार कर उन तरीकों पर बढ़े पैमाने पर रिसर्च करने की अनुमति मांगी, जो उपाय प्रभावी साबित हो सकते हैं।

बिल पास कराने को एक लाख की घूस लेते धरा गया आइएएस अफसर

- ओडिशा में उद्यान विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं विजय केतन उपाध्याय
- सतर्कता विभाग ने रंगे हाथ पकड़ा, राज्य सरकार ने किया निलंबित

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

ओडिशा में सतर्कता विभाग ने सोमवार को राज्य के उद्यान विभाग के निदेशक विजय केतन उपाध्याय को एक लाख रुपये घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया।

बताया जा रहा है कि कार्य भुगतान बिल पास कराने के एवज में उक्त रकम घूस के रूप में ली जा रही थी। राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विजय केतन को निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार की 'मेरी सरकार' योजना के तहत आम लोगों की विभिन्न विभागों के बारे ली गई राय में पता चला था कि उद्यान विभाग में बड़े पैमाने पर घूसखोरी की जा रही है।

यहां तक कि इसमें खुद निदेशक के भी शामिल होने की सूचना थी। इसके बाद से ही सतर्कता विभाग को उचित कदम उठाने के लिए निर्देश दिया गया था। इसी के तहत सतर्कता विभाग पिछले 10 दिन से कृषि विभाग के अंतर्गत आने वाले उद्यान निदेशालय पर पैनी नजर रख रहा था।

सतर्कता विभाग की टीम ने उक्त आइएएस अधिकारी के आवास समेत अन्य ठिकानों पर भी इसी क्रम में छापामारी की। विजय केतन के बालासोर स्थित घर और दफ्तर पर एक साथ छापामारी की गई।

साथ ही उनके ससुर एवं भाई के घर पर भी सतर्कता विभाग ने छापामारी की। 2009 बैच के आइएएस अधिकारी विजय केतन उपाध्याय इससे पहले कालाहांडी, जगतसिंहपुर का जिलाधीश एवं जल संसाधन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव के तौर पर अपना दायित्व निभा चुके हैं।

दैनिक जागरण

समय मूल्यवान है, लेकिन सत्य समय से भी ज्यादा मूल्यवान है

एक बड़ा बदलाव

देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस को हरी झंडी मिलना एक और बड़े बदलाव की आधारशिला ही नहीं, बल्कि एक जरूरी काम को उसके अंजाम तक पहुंचाना भी है। चूंकि सीडीएस का फैसला तीनों सेनाओं के हित में है इसलिए यह देशहित में एक बड़ा फैसला है। सीडीएस महज एक और पद का सृजन नहीं है। यह प्रतिरक्षा मोर्चे को और दुरुस्त करने का उपाय भी है। सैन्य मामलों के प्रमुख के रूप में सीडीएस की नियुक्ति कितनी अहम है, यह इससे समझा जा सकता है कि इस पद पर आसीन होने वाले केवल तीनों सेनाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के तौर पर ही काम नहीं करेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के सदस्य भी होंगे। इस सबके बाद भी सीडीएस की नियुक्ति से तीनों सेनाओं के प्रमुखों के अधिकारों में कहीं कोई कटौती होने नहीं जा रही है। वे पहले की तरह रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करते रहेंगे। सीडीएस सरीखे किसी पद की आवश्यकता एक लंबे अर्से और खासकर कारगिल संघर्ष के बाद से ही महसूस की जा रही थी, लेकिन इस आवश्यकता की पूर्ति अब जाकर हो सकी। कारगिल संघर्ष के बाद यह पाया गया था कि तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की कमी के चलते सेना को कहीं अधिक नुकसान उठाना पड़ा। कारगिल संघर्ष के अलावा अन्य अवसरों पर भी तीनों सेनाओं में तालमेल की कमी दिखाई दी।

एक ऐसे समय जब रक्षा मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ती जा रही हों तब सेनाओं में तालमेल की कमी के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहने देनी चाहिए। सीडीएस की जरूरत केवल इसलिए नहीं थी कि दुनिया के सभी प्रमुख देशों ने यह पद बना रखा है, बल्कि इसलिए भी थी कि तीनों सेनाओं की समस्याओं का समाधान तेजी से करने का काम ऐसे किसी सैन्य अफसर के जरिये ही हो सकता है। सैन्य मामलों में तकनीक की महत्ता जिस तरह बढ़ती जा रही है उसकी अनदेखी एक दिन भी नहीं की जा सकती। उम्मीद की जानी चाहिए सीडीएस की नियुक्ति से केवल सेनाओं के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को ही गति नहीं मिलेगी, बल्कि उनकी रक्षा आवश्यकताएं भी समय से पूरी होंगी। निःसंदेह यह भी उम्मीद की जाती है कि सेनाओं के हितों की अनदेखी नहीं होगी और सेना के तीनों अंगों में जरूरी सुधार की प्रक्रिया तेज होगी। यह होनी भी चाहिए, क्योंकि आज के समय में सेनाओं का बड़ा होना उतना महत्वपूर्ण जितना कि उनका सक्षम होना। इस तरह की तमाम उम्मीदों के पूरा होने की संभावना के कारण ही सीडीएस के सृजन को एक संस्था के निर्माण के तौर पर देखा जा रहा है।

युवाओं की उम्मीद

केंद्र सरकार की हिमायत योजना बेरोजगारी से जूझ रहे जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण है। योजना के तहत यहां के युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार मिल रहा है। राज्य में बेरोजगारी की समस्या किसी से भी नहीं छुपी है। एक लाख युवाओं ने जहां रोजगार केंद्रों में अपने नाम दर्ज करवाएं हैं, वहीं छह लाख के करीब बेरोजगार युवा रोजगार के लिए सरकारी एवं निजी कंपनियों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए शेर-ए-कश्मीर रोजगार योजना, ओवरसीज कॉरपोरेशन जैसे कई कदम उठाए, मगर इनमें से कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सका। युवाओं को इस काबिल नहीं बनाया गया कि वह प्रशिक्षण हासिल कर निजी क्षेत्र में भी अपना कौशल दिखा सकें। करीब सात वर्ष पूर्व जम्मू-कश्मीर में शुरू हुई केंद्र की हिमायत और उड़ान योजनाओं से युवाओं को रोजगार देने के लिए उठाए गए कदमों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। साठ हजार के करीब युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अच्छे पैकेज पर नौकरियां दिलाई गई हैं। यह अच्छी बात है कि युवा भी यह समझ रहे हैं कि सरकार के लिए हर किसी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। ऐसे में कौशल विकास की ट्रेनिंग लेकर युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। वहीं युवाओं के लिए अच्छी बात यह भी है कि अब कई औद्योगिक घरानों ने भी जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिए रूचि दिखाई है। उन्होंने राज्य प्रशासन से संपर्कभी किया है। अगर यह औद्योगिक घराने भी यहां पर आकर बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं तो इससे भी हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। इसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करने की जरूरत है। इसी वर्ष पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया गया है और उसके बाद से ही अन्य राज्यों के लोगों के लिए जम्मू-कश्मीर में निवेश के रास्ते खुले हैं। ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि केंद्रीय योजनाओं के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलने से बेरोजगारी की समस्या पर जम्मू-कश्मीर में अंकुश लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से ही अन्य राज्यों के लोगों के लिए जम्मू-कश्मीर में निवेश के रास्ते खुले हैं। केंद्रीय योजनाओं के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलने से बेरोजगारी की समस्या पर जम्मू-कश्मीर में अंकुश लगाया जा सकता है

आम आदमी की जेब काटने वाला साल

विवेक कौल

सरकार लोगों से विभिन्न मदों में वसूले 2,66,000 करोड़ रुपये बदहाल बैंकों पर खर्च नहीं करती तो इस पैसे से वह 26,600 किमी हाईवे बना सकती थी

अर्थशास्त्र में एक पुरानी कहावत है, 'देयर इज नो फ्री लंच।' इसका मतलब यही है कि किसी न किसी को तो बिल भरना ही पड़ता है। अब भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को ही ले लीजिए। वर्ष 2019 में रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 135 आधार अंकों की कटौती की। साल के आरंभ में रेपो दर 6.5 प्रतिशत थी और साल के अंत में यह 5.15 प्रतिशत तक आ गई थी। रिजर्व बैंक जिस दर पर बैंकों को कर्ज देता है उस दर को रेपो दर कहते हैं। एक आधार अंक एक प्रतिशत का सौवां हिस्सा होता है। इस कटौती के पीछे क्या सोच थी? रिजर्व बैंक का मानना था कि जैसे-जैसे वह रेपो दर में कमी करेगा वैसे-वैसे बैंक जिस दर पर उधार देते हैं उस दर को घटाएंगे। जब बैंक उधार दर को घटाएंगे तो ज्यादा लोग उधार लेकर पैसा खर्च करेंगे। इससे आर्थिक सुस्ती थोड़ी बहुत-दूर होगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। दिसंबर 2018 में बैंकों की भारित औसत उधार दर 10.35 प्रतिशत थी। अक्टूबर 2019 में यह बढ़कर 10.40 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। साफ है कि बैंकों की उधार दर घटने की जगह बढ़ गई। इससे यह पता चलता है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति 2019 में पूरी तरह से विफल हो गई है।

अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? एक नजर बैंकों की भारित औसत सावधि जमा दर (वेटेड एवरेज फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट) पर डालें। दिसंबर 2018 में यह दर 6.87 प्रतिशत पर थी। अक्टूबर 2019 आते-आते यह दर केवल 12 आधार अंकों से गिरकर 6.75 प्रतिशत पर आ गई थी। 2019 में रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 135 आधार अंकों की कटौती की थी, जबकि बैंकों की भारित औसत सावधि जमा दर में केवल 12 आधार अंकों की कमी आई। बैंकों ने इस गिरावट का भी फायदा उधारकर्ताओं को नहीं दिया। सवाल है कि ऐसा क्यों? पिछले कई वर्षों से भारतीय बैंक और विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक खराब ऋण की समस्या से जूझ रहे हैं। इसलिए सावधि जमा दर गिरने का थोड़ा बहुत फायदा भी उधारकर्ताओं के पास नहीं पहुंचा। इससे बैंकों ने अपना मुनाफा बढ़ाया या फिर घाटे को कम किया, पर बैंकों की उधार दर नहीं घटने की केवल यही एक वजह नहीं है। निजी खपत का भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 60 प्रतिशत हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में निजी खपत की बढ़त दो कारणों से हुई है। पहला, लोग अपनी आय का ज्यादा हिस्सा खर्च कर रहे हैं। दूसरा, लोग पहले से ज्यादा उधार लेकर पैसा खर्च कर रहे हैं। इसकी मुख्य वजह यह रही कि पिछले कुछ वर्षों में लोगों की आय में पहले की तरह बढ़ोतरी नहीं हुई है। आय इसलिए पहले की तरह नहीं बढ़ रही है, क्योंकि पर्याप्त नौकरियां नहीं पैदा हो रही हैं।

जब लोग उधार लेकर पैसा खर्च करते हैं और अपनी आय का ज्यादा हिस्सा खर्च करते हैं तो फिर बचत कम होती है। पिछले कुछ वर्षों में घरेलू वित्तीय बचत में गिरावट आई है। 2010-11 में घरेलू वित्तीय बचत सकल डिस्पोजेबल आय (ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम) के करीब 10 प्रतिशत से कुछ ज्यादा थी। वर्ष 2017-18 में यह गिरकर 6.5 प्रतिशत तक आ गई थी। इस माहौल में जब पूरे देश की घरेलू वित्तीय बचत कम हो गई है, बैंकों के लिए ब्याज दरों को घटाना काफी मुश्किल हो गया है। सवाल है कि इसका नुकसान किसको भुगतना पड़ रहा है? दरअसल खराब ऋण से न केवल बैंकों का नुकसान हो रहा है, बल्कि इससे ग्राहकों का भी नुकसान हो रहा है। यहां तक कि इससे पूरे देश का नुकसान हो रहा है। पिछले दो वित्तीय वर्षों में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को डूबने से बचाने के लिए 1,96,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस साल भी सरकार 70,000 करोड़ रुपये इन बैंकों को चालू रखने के लिए खर्च करेगी। आगे बढ़ने से पहले यहां यह समझना जरूरी है कि एक बैंक चलता कैसे है? लोग बैंक में अपनी बचत को जमा करते हैं। इस जमा पूंजी पर बैंक ब्याज देता है। इस पैसे को लेकर बैंक फिर उधार देता है। उधार पर ली गई ब्याज दर, जमा पूंजी पर दी गई ब्याज दर से ज्यादा होती है। इसके अलावा यह जरूरी होता है कि उधार लौटाया जाए। अगर उधार नहीं लौटाया जाएगा तो कोई भी बैंक लोगों की जमा पूंजी को नहीं लौटा पाएगा और बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगा। ऐसी समस्या न पैदा हो इसके लिए सरकार हर साल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पैसा निवेश करती है। इसलिए वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2019-20 तक सरकार इन बैंकों में करीब 2,66,000 करोड़ रुपये निवेश कर चुकी होगी। यह पैसा कहीं और भी लगाया जा सकता था।

अवधेश राजपूत

अपनी नई किताब इन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक में विजय केलकर और अजय शाह यह बताते हैं कि 10,000 किलोमीटर का चार लेन वाला हाईवे बनाने में करीब एक लाख करोड़ रुपये खर्च होता है तो अगर सरकार 2,66,000 करोड़ रुपये इन बैंकों पर खर्च नहीं करती तो इस पैसे से वह 26,600 किलोमीटर के हाईवे बना सकती थी। इसका यह मतलब कतई नहीं कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बचाना नहीं चाहिए था, पर इस खर्च की वजह से कई और महत्वपूर्ण खर्चे नहीं हो पाए।

अब इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। वर्ष 2017-18 और वर्ष 2019-20 के बीच सरकार जो 2,66,000 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों पर खर्च कर रही है, वह पैसा कहां से आ रहा है? वर्ष 2013-14 में डीजल और पेट्रोल पर लगे उत्पाद शुल्क से सरकार ने 46,386 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वर्ष 2018-2019 आते-आते यह कमाई 2,13,400 करोड़ रुपये तक बढ़ गई थी। ऐसा कैसे हुआ? पेट्रोल और डीजल के प्रति लीटर पर एकत्र किए गए केंद्र सरकार के कुल उत्पाद शुल्क में तब और अब के बीच में काफी वृद्धि हुई है। अब कोई पूछ सकता है कि इसका भुगतान कौन करता है? जवाब साफ है-आप और हम, जब हर बार पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं।

अगर अर्थशास्त्र का कोई एक सिद्धांत है जिसे सभी भारतीयों को समझना चाहिए तो वह यह कि किसी न किसी को तो बिल भरना ही पढ़ता है। अमूमन बिल भरने वाले लोग हम और आप ही होते हैं। अर्थशास्त्र का हमारी जिंदगी में अलग-अलग तरीकों से असर पड़ता है और हर साल असर पड़ता है। हां, अक्सर हम लोगों को पता नहीं होता कि हमारी जेबें काटकर कर बिल भरा जा रहा है। गुजरता साल 2019 भी एक ऐसा ही वर्ष था।

(स्तंभकार इजी मनी ट्राइलॉजी के लेखक एवं अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

नैतिकता के संकट से घिरी राजनीति

गिरीश्वर मिश्र

विदा होता वर्ष बता गया कि राजनीतिक नेतृत्व में व्याप्त विकृति समाज और राजनीति के लिए कितनी घातक हो सकती है?

देश में छोटी-बड़ी अनेकानेक राजनीतिक पार्टियों और उनसे जुड़े और साथ ही स्वयंभू नेताओं की भीड़ देखकर यही लगता है कि भारत में राजनीतिक चेतना का तीव्र विकास हो रहा है। दूसरी ओर जब राजनीति के इन किरदारों की भूमिका और आचरण पर गौर करते हैं तो आम आदमी चिंतित हो उठता है। उसका मन इस बिरादरी के प्रति सशंकित होता जाता है। कई नेताओं के देश, समाज और विश्व के इतिहास और वर्तमान परिस्थिति से अपरिचय, सामान्य शिष्टाचार की कमी और किसी तरह के भरोसेमंद प्रामाणिक संचार कर पाने की मुश्किल उन्हें आए दिन उपहास का पात्र भी बनाती रहती है। टीवी और ऑनलाइन मीडिया के चलते पूरा देश इस तरह की घटनाओं का साक्षी होता है। चूंकि देश का नागरिक होना ही नेतृत्व करने के लिए पात्रता के लिए पर्याप्त है इसलिए उसके किरदार लोकतंत्र के प्रपंच के चलते (चुनाव लड़े बगैर भी) प्रदेश और देश के लिए फैसले लेने की स्थिति में भी पहुंच जाते हैं। राजनीति में सफलता पाने की अनेक युक्तियां हैं जो खास-खास मुहूर्त पर आजमाए जाते हैं। ये सारे पैंतरे सत्ता पाने और उसे बनाए रखने की हिकमत से जुड़े होते हैं। समाज के लिए चिंतन का समय ही नहीं बचता। शेष समय आलाप और प्रलाप को समर्पित हो जाता है। टीवी चैनल इतनी संख्या में हो चुके हैं कि नाना प्रकार के विमर्श राजनीतिक युद्ध के रूप में चलते ही रहते हैं।

आजकल राजनीतिक विमर्श के दौरान एक पक्ष के कथन और दूसरे पक्ष के अनर्गल कथन का अंतहीन सिलसिला ही भरा पड़ा होता है। बातचीत सतही वाचालता और अवांछित आक्रोश पर जोर देती है। आग्रही राजनेता रूढ़िबद्ध होकर किसी अन्य दृष्टि-विचार को देखना-सुनना ही नहीं चाहते। वे किसी भी तरह के परिवर्तन के प्रतिगामी ही रहते हैं और गति की जगह यथास्थिति को ही सुविधाजनक पाते हैं। नेताओं को यह भी अहसास नहीं होता कि उनके बेबुनियाद बयानों के क्या परिणाम होंगे? पिछले वर्षों में बड़े-बड़े नेता अपनी इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के लिए अदालतों में माफी मांग चुके हैं, लेकिन सब कुछ यथावत चालू है। पिछले दिनों तथ्यों की मनमानी और भड़काऊ व्याख्या पेशकर एक कल्पित आख्यान से देश में अस्थिरता लाने की कोशिश की गई। इसके चलते आगजनी, पथराव और हिंसा ने अनेक क्षेत्रों को अपने आगोश में ले लिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर राजनीति किस तरह देश के लिए आत्महंता

हो सकती है, इसका उदाहरण इस गुजरते वर्ष के आखिरी समय में सभी ने देखा। विदा होता वर्ष एक बार फिर से यह भी बता रहा कि राजनीतिक नेतृत्व में व्याप्त विकृति समाज और राजनीति के लिए कितनी घातक हो सकती है?

एक जमाना था जब नेता विश्वास का स्रोत होता था और उसकी बात का भरोसा रहता था। नेता होना भी आसान न था। उसे अर्जित किया जाता था। अब की बात ही कुछ और है। आज पार्टी हाईकमान किसी भी ज्ञात-अज्ञात व्यक्ति को कहीं से लाकर नेता के रूप में प्रतिष्ठित कर देता है और जनता को उसे स्वीकारने का ही विकल्प रहता है। कभी नेता को परिश्रमशील और रूखा जीवन बिताना पड़ता था, क्योंकि उसका एक मात्र लक्ष्य जन सेवा होता था। तब नेता और आम आदमी एक-दूसरे के करीब भी रहते थे। नेतागिरी के प्रति आकर्षण आज भी बरकरार है, उसके कारण जरूर भिन्न हो रहे हैं। बहुत से युवा जन नेता बनने को आतुर हैं। यह प्रवृत्ति किस कदर तेजी से बढ़ी है, इसका अनुमान निगम-पार्षद से लेकर संसद तक के चुनावों में भाग लेनेवाले प्रत्याशियों की बढ़ती संख्या से लगाया जा सकता है। नेतागिरी के प्रति आकर्षण का कारण उससे मिलनी वाली विभिन्न सिद्धियां हैं। लोग नेता की तलाश में रहते हैं, क्योंकि उनके मन में नेता की जो छवि है उसमें जनता की सेवा (सर्विस) और कल्याण (वेलफेयर) की प्रमुखता के भाव ही प्रमुख होते हैं। दुरूह होती व्यवस्था के मकड़जाल से मध्य और निम्न सामाजिक वर्ग के लोग त्रस्त हो रहे हैं। इसलिए आज कोई भी शख्स सड़क पर आसानी से मजमा जुटा सकता है और नेतागिरी कर सकता है।

नेता बनने का यह आकर्षण क्यों बढ़ा है, इसके कई कारण हैं। प्रमुख कारण है स्वच्छंदतापूर्वक आचरण की छूट और उसके साथ मिलने वाली सुरक्षा और अन्य सुविधाएं। कुल मिलाकर नेता बनना एक निहायत फायदे का सौदा है जिसमें लागत के मुकाबले कई गुना ज्यादा लाभ की गारंटी है। अधिकांश नेताओं की धन-संपदा का ग्राफ कितना बढ़ा और किस तरह बढ़ा, यह सबकी आखों के सामने है। आज धन बल और बाहुबल का ही जय घोष है। आज नेतृत्व में गहरी नैतिक त्रासदी छा रही है। इसकी पीड़ा सभी महसूस कर रहे हैं।

निजी तौर पर हर आदमी अकेले या सामूहिक तौर पर न्याय, ईमानदारी, भरोसा और प्रतिबद्धता जैसे मूल्यों को महत्व देता है, लेकिन मीडिया में नेताओं के अनैतिक आचरण की गाथाएं दिन-प्रतिदिन गूंजती रहती हैं। नफा या फायदा उठाना ही राजनीति का खास मकसद दिख रहा है। जनता नेताओं से जिम्मेदारी की अपेक्षा करती है। ध्यान रहे कि चरित्र, नैतिकता और आचार के प्रश्न से विरत होने पर राजनीति लोक क्षेम के गंतव्य से भी विरत होने लगती है। राजनीति कोई व्यापार नहीं है जिसका उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना होता हो। आर्थिक साम्राज्यवाद और स्वार्थ के इस दौर में आत्म तुष्टि ही व्यावहारिक नैतिक नियम बन चुका है। घूस, मिलावट और प्रदूषण के माहौल में नैतिक व्यक्ति ही नैतिक परिवेश का निर्माण में सहायक हो सकेगा। तभी आक्रोश, प्रतिशोध, अविश्वसनीयता, स्वार्थपरता, असंवेदनशीलता और अराजकता से मुक्ति मिल सकेगी। ऐसे कठिन काल में राजनीति को नए वर्ष के संकल्प के रूप में नैतिकता से दिशा लेनी की कोशिश करनी चाहिए। भारतीय समाज में नेता की भूमिका प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण रही है। देश का लोक मानस आज भी उसकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता है। नेतृत्व समाज के नैतिक संस्कार को प्रभावित करता है। नैतिक मूल्यों की उपेक्षा सिर्फ भौतिक नुकसान ही नहीं पहुंचाती। वह समाज के नैतिक परिवेश को भी कमजोर करती है।

(लेखक पूर्व कुलपति एवं शिक्षाविद् हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आज में रखें आस्था

समय का आभास हम दिन, महीना, साल के रूप में करते हैं। सूर्य और चंद्रमा समय मापन के महत्वपूर्ण घटक हैं। इन्हीं पर हमारा दिन और रात आश्रित होता है। समय का प्रवाह अविरल, शाश्वत और सार्वकालिक है। अतः समय ही नियति है और सतत चलायमान रहना ही समय की प्रकृति है। बीता समय हमारा अतीत है, चल रहा समय हमारा वर्तमान है और आने वाला समय हमारा भविष्य है। समय बंद मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता जाता है। इसलिए समय की हर घड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। समय के साथ परिवर्तन संसार का नियम है। समय कभी खराब नहीं होता। वह सभी के साथ न्याय करता है। समय को खराब बताने वाले अपने दूषित कर्मों से अनभिज्ञ रहते हैं। और अपना भी समय आएगा कहने वाले भविष्य की चिंता में वर्तमान के साथ छल करते हैं। समय न तो आता है और न ही आएगा। तारीखों के भरोसे तकदीर नहीं बदलती। कल हमेशा कल ही रहता है। अतः हमारी आस्था आज में होनी चाहिए। आज को जी भर के जीने वाले ही समय का पूर्णतः सदुपयोग कर पाते हैं। बीते कल को याद करने वालों के पास दुख और आने वाले कल को याद करने वालों के पास चिंता के सिवाय कुछ नहीं होता। भूत और भविष्य में जीने वाले ऐसे लोग वर्तमान के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं।

नवीनता तारीखों के इशारों पर चलने वाले नववर्ष से अधिक स्वयं में नवीन परिवर्तन लाने में है। स्वयं का बदलाव ही सृष्टि को बदलने का माद्दा रखता है। ये बदलाव अपनी हानिकारक वृत्तियों को त्यागने एवं लाभकारी प्रवृत्तियों के प्रति उन्मुख होने के अटल संकल्प के साथ ही संभव है। समय के साथ हमें स्वयं को हर पल मांजना चाहिए। क्योंकि स्वयं को मांजने से ही हमारे चरित्र में उज्ज्वलता और निखार आता है। अतः परिवर्तन समय में नहीं, स्वयं में संभव है। स्वयं में परिवर्तन ही बुद्ध और महावीर बनने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और हमारी समस्त पीड़ाओं को हरकर हमें परम शांति दे सकता है।

देवेंद्रराज सुथार

जो बीत गया उसे बीत जाने दें

अंशुमाली रस्तोगी

जो बीत गया सो बीत गया, जो आने वाला है उसी के साथ हमें अपना तारतम्य बनाना है

बस एक दिन और फिर साल 2019 भी हमसे विदा ले लेगा। विदाई में कुछ अच्छी तो कुछ मीठी यादें साथ रहेंगी। साल भर में हमने क्या खोया, क्या पाया का आंकलन जारी रहेगा। लेकिन हममें से शायद ही कोई इस बात पर पुनर्विचार करेगा कि साल के शुरुआत में जो छोटे या बड़े संकल्प लिए थे, उनका क्या हुआ? अंत तक हम उन पर डटे रहे या बीच में ही छोड़ उनसे मुक्ति पा ली। अक्सर ही यह ध्यान में आया है कि जब नया साल शुरू होता है, तब हम किस्म-किस्म के संकल्प लेते हैं। संकल्पों की ये लौ हफ्ते-दो हफ्ते तक तो बढ़िया जलती है किंतु समय बीतते ही लौ धीमी पड़ने लग जाती है। और अंत तक हम ही उसे बुझा देते हैं। अपने लिए संकल्प हमें बोर और बोझ लगने लगते हैं। आज और कल की रस्साकशी में ही साल बीतता चला जाता है।

संकल्पों पर टिके न रहना बताता है कि हममें आत्मविश्वास और दृढ़ता की कमी है। यों भी, अपनी कही बात से मुकर जाना इंसान की सदियों पुरानी फितरत है। संकल्पों की इस यात्रा के बीच हम खुद को कितना बदल पाए हैं, इस पर भी हमें थोड़ा ठहरकर सोचने की जरूरत है। एक बात और, हम अपनी किसी भी अच्छी या बुरी बात का बोझ साल पर नहीं डाल सकते। हमेशा साथ रहने वाला और आगे आता हुआ साल हमें जीवन को जीने का फलसफा देता है। हमारा संघर्ष सही और गलत का साक्षी बनता है। साल कुछ नहीं करता, जो करता है वह इंसान ही करता है। दरअसल साल एक सूरज की मानिंद होता है। जिसका एकमात्र काम प्रकाश फैलाना होता है। यह निर्भर हम पर करता है कि हम उस प्रकाश को अपने जीवन में कितनी जगह देते हैं और कितना उससे दूरी बनाकर रखते हैं। समय की रेत पर हम निरंतर कुछ न कुछ लिखते-मिटाते रहते हैं। यह जरूरी भी है। ऐसा अगर नहीं करेंगे तो बहुत कुछ हमारे बीच से और बीच का ठहर जाएगा। बस ठहरने ही तो नहीं देना है कुछ भी। विकास, सोच, विचार, अहसास की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। साल हमें यही मौके हर बार देता है कि हम कुछ अच्छा बुनें, कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अविस्मरणीय यादें संजोएं रहें। नकारात्मकता को न केवल खुद से, बल्कि अपने जीवन से भी दूर, बहुत दूर रखें।

अच्छा लगेगा अगर साल 2020 में हम धर्म और जाति की जड़ताओं और भेदभाव से मुक्ति पाएं। अगर साल 2020 में हम राजनीतिक बहसों में सोशल या निजी प्लेटफॉर्म पर अपनी दोस्तियां न तोड़ें, उन्हें बरकरार रखें। मतभेद को मनभेद न बनाएं। अगर साल 2020 में हम कुछ देर के लिए मोबाइल का साथ छोड़, घर के किसी बुजुर्ग या बच्चे का हाथ पकड़ें, उनका स्नेह लें, अपना स्नेह उन्हें दें। अगर साल 2020 में हम स्त्री को इज्जत दें, उन्हें प्रताड़ित न करें। अगर साल 2020 में किसी अनजान व्यक्ति के साथ चाय-कॉफी पिएं, कुछ उससे अपनी कहें, कुछ उसकी सुनें। अगर साल 2020 में हम अपनों को हाथ से कभी-कभार पत्र लिखें।

हालांकि ये बहुत छोटी व्यवहार-गत बातें हैं, जिन्हें किन्हीं संकल्पों में बांधने की आवश्यकता नहीं। इन्हें तो बैठे-ठाले भी किया जा सकता है। यह तो जीवन का संगीत है, जिसे सुनने के लिए ईयर-बड नहीं चाहिए होते।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

एकपक्षीय विचार

संवैधानिक मूल्यों को बचाने का समय शीर्षक से लिखे अपने लेख में पी चिदंबरम ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उठाए गए तमाम महत्वपूर्ण कदमों जैसे-तत्काल तीन तलाक कानून, नागरिकता संशोधन कानून, प्रस्तावित एनआरसी, एनपीआर एवं अनुच्छेद 370 की समाप्ति की आलोचना की है। उन्होंने बताया है कि इन मुद्दों का आम आदमी से कोई खास सरोकार नहीं है। उल्लेखनीय है कि तत्काल तीन तलाक कानून ने देश की करीब दस करोड़ महिलाओं को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। जाहिर है कि इस मुद्दे का सरोकार सीधे-सीधे आम आदमी से जुड़ा हुआ है। नागरिकता संशोधन कानून का आधार भी शुद्ध रूप से मानवीय है, न कि धार्मिक। इस कानून में अधिसूचित धर्म समूहों से जुड़े लोग संबंधित देशों में अपनी आस्था और विश्वासों के कारण लंबे समय से प्रताड़ित होते रहे हैं। इन लोगों को यदि उदारतापूर्वक देश की नागरिकता देने का प्रस्ताव किया गया है तो यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुकूल ही है। रही बात श्रीलंका के तमिलों को नागरिकता कानून में शामिल न करने की तो सच्चाई यह है कि श्रीलंका के तमिलों की समस्या का स्वरूप राजनीतिक है, न कि धार्मिक। वहां उन्हें अपनी आस्था एवं विश्वास के कारण प्रताड़ित किया जाता हो, इसका कोई सुबूत नहीं है। यही बात भूटान के ईसाइयों के मामले में भी कही जा सकती है। लेखक ने केंद्र सरकार द्वारा एनपीआर के लिए डाटा संग्रह की कवायद की भी आलोचना की है। क्या वह यह कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार के समय यह काम संविधान की भावना के अनुरूप था, लेकिन यदि उसी काम को भाजपा सरकार ने आगे बढ़ाया है तो वह संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। ध्यातव्य है कि किसी भी देश की सरकार को इसका पूरा अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों की पूरी जानकारी रखे। यह उस देश की सुरक्षा और उसकी सरकार की विकास योजनाओं और कल्याणकारी नीतियों के लिए आवश्यक डाटा प्रदान करती है। वैसे भी एनपीआर किसी तरह से नागरिकता को परिभाषित नहीं करता। लगता है कि लेखक ने एक दल के राजनीतिक नेता के तौर पर उक्त लेख को लिखा है। इसलिए उनका दृष्टिकोण एकपक्षीय हो गया है।

chandankarn9470@gmail.com

एक गलत परिपाटी

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ सार्वजनिक दुर्व्यवहार के बाद केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान के साथ भी दुर्व्यवहार न केवल शर्मनाक है अपितु संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के अपमान की नई अवांछित परिपाटी शुरू हो रही है। सत्तासीन पार्टी निश्चित रूप से अपनी पार्टी के लोगों को राज्यपाल और राष्ट्रपति पद पर आसीन करती रही है और इसे यह केवल भाजपा ने शुरू नहीं किया है, कांग्रेस ने भी ऐसा खूब किया है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि विपक्षी दलों और भिन्न विचारधारा के लोग उनका अपमान करें। कल को तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी दुर्व्यवहार हो सकता है क्योंकि वे सरकार के हर अच्छे तथा अलोकप्रिय फैसलों की प्रशंसा करते हैं। ये कैसा चलन प्रारंभ किया जा रहा है? विपरीत विचारधारा के बावजूद कम से कम संवैधानिक पदों का सम्मान तो होना ही चाहिए अन्यथा संविधान के सम्मान पर प्रश्नचिह्न लगना निश्चित है।

सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी

न फैलाएं भ्रम

पी चिदंबरम के 'संवैधानिक मूल्यों को बचाने का समय' में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बहुत ही अंतर्विरोध नजर आता है। ये दिग्भ्रमित नेता अपने समर्थकों को भी भ्रमित कर देश अहित में ही कार्य कर रहे हैं। मोदी सरकार की प्रचंड बहुमत से वापसी को ये समझ नहीं पा रहे हैं। यदि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अच्छे काम नहीं हुए तो दोबारा उनको प्रचंड बहुमत नहीं मिलना चाहिए था। मुख्य विरोधी पार्टी अभी भी तीन तलाक, 370, नागरिकता कानून आदि प्रत्येक बात को गलत बता रही है। अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए ये किसी भी हद तक जाने को प्रयासरत दिखाई देते हैं। एनपीआर को भी ये शंका की नजर से देखने का प्रयास कर अपने समर्थकों को भी भ्रमित कर रहे हैं। भविष्य में इतिहास के पन्नों पर इन नेताओं के नाम किस तौर पर दर्ज किया जाए इस बात को तो ये लोग खुद ही तय कर रहे हैं।

bailwalbp@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

समुदाय विशेष को गुमराह कर रहा विपक्ष

नागरिकता संशोधन कानून की समीक्षा सामान्य एवं प्रचलित अवधारणाओं की दृष्टि से की ही नहीं जा सकती। इसकी एक विशिष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। यह इतिहास मात्र भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का इतिहास है। इन्हीं चारों राष्ट्रों के इर्द-गिर्द घूमनेवाला नागरिकता संशोधन कानून भारत राष्ट्र को बचाने की ऐतिहासिक मजबूरी है, जो विभाजन की त्रासदी से उत्पन्न होनेवाली अमानवीय स्थितियों के निराकरण के लिए प्रकट हुई है। इसे इस विचारधारा या उस विचारधारा, हमारी पार्टी की नीति या उनकी पार्टी की नीति की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। यह कानून अंधकार के विरुद्ध प्रकाश की यात्रा है। आतंकवादी दानवता के विरुद्ध मानवता के संघर्ष की एक कड़ी है। विश्व मानवता के समर्थन में यह सनातन मूल्यों की रक्षा का संघर्ष भी है

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में नई दिल्ली में बीते दिनों उपद्रव व तोड़-फोड़ करते प्रदर्शनकारी। फाइल फोटो

आजकल

कुमुद शर्मा
प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय

नागरिकता संशोधन कानून की आड़ में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष अपनी मिथ्याभिमानी ढोंगी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को देशद्रोह की सीमा तक घसीट लाया। विपक्षी दलों ने इस संशोधित कानून में अपने निहित स्वार्थों के चलते आधारहीन मुस्लिम विरोधी मिथ को आरोपित कर दिया और इसी आधार पर कुछ प्रदेशों में राष्ट्र विरोधी हिंसक दंगे भड़काए गए। आगजनी और पत्थरबाजी से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंची। विपक्ष के इस विध्वंसक आचरण के साथ जिन सिमी (स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया), पीएफआइ, एसडीपीआइ जैसी मुस्लिम संस्थाओं ने इसमें साझेदारी की, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही इन संस्थाओं पर विभिन्न धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन संस्थाओं और कांग्रेस के बीच एक साझे उद्देश्य की प्रेरणा काम कर रही है।

सोनिया गांधी ने नागरिकता संशोधन कानून को नाइंसाफी बताया है। उन्होंने देश को आह्वान किया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार रहें। वैसे यहां लोकतंत्र कहां से आ गया? यह कानून तो विशुद्ध लोकतंत्र की ही देन है जिसे पूरे देश के चुने हुए प्रतिनिधियों ने संसद में पारित किया है। खैर कांग्रेस के हास्यास्पद बयानों की तो कभी कमी नहीं रहती। मगर चिंता की बात यह है कि इस तरह के बयानों में प्रायः नफरत के संदेश छिपे रहते हैं। गहराई से देखा जाए तो कांग्रेस के इस तरह के बयानों में एक निश्चित और निर्धारित पैटर्न मिलेगा जो जिहादी और अलगाववादी मुस्लिमों की भाषा से मेल खाता है।

कांग्रेस के बयानों में इस तरह का पैटर्न इधर कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से 2014 में भाजपा की मोदी सरकार आने के बाद। कांग्रेस के इस परिवर्तन को लोग अलग-अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जो दृष्टिकोण सबसे ज्यादा चर्चा में है उसके अनुसार कांग्रेस की लीडरशिप ऐसे हाथों में चली गई है जिनकी तैयार की गई नीतियां एवं कार्यक्रम ऐसे कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय से मेल खाते हैं जो अभी भी द्विराष्ट्र सिद्धांत (जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वह मुस्लिम राष्ट्र का हिस्सा है) पर काम कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के पीछे इसी दर्शन की प्रेरणा बताई जा रही है।

मोदी सरकार के कार्यकाल में जितने भी बिल पारित हुए और कानून बने, उन सभी के विरोध में कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बयान अशिष्ट, अनैतिक और सांप्रदायिक रहे हैं। इन सभी बिलों को संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से पारित किया गया। प्रक्रियाएं संवैधानिक थीं, पर संविधान मात्र अर्थविज्ञान का मुद्दा नहीं है, वह देश के नागरिकों की राष्ट्रीय आस्था की अभिव्यक्ति है। इसकी अवहेलना करते हुए प्रत्येक मुद्दे पर कांग्रेस समेत अनेक विपक्षी दलों ने इतना विष-वमन किया कि उससे पाकिस्तान और वहां के जिहादियों को भरपूर खुराक मिलती रही।

अब तक की उपलब्धियों से भारत में राष्ट्रीय चेतना जगाने वाली मोदी सरकार का कार्यकाल भारतीय राजनीति का असाधारण काल कहा जाएगा। यह मोदी सरकार की ऐसी लोकतांत्रिक मोर्चाबंदी है जिससे बिखरते हुए भारत राष्ट्र का दुर्गीकरण हो रहा है। तीन तलाक, 370 का निरस्तीकरण तथा नागरिक संशोधन कानून के माध्यम से राष्ट्रीय अस्मिता की निर्मिति हो रही है।

राष्ट्र निर्माण की दिशा में क्रियान्वित नीतियों और कार्यक्रमों को प्रत्येक देश में जनता का भारी समर्थन मिलता है। मगर कांग्रेस के नेतृत्व में देश का अधिकांश मुस्लिम समुदाय मोदी सरकार की सभी नीतियों का विरोध कर रहा है। अक्सर देखा यह भी गया है कि यह समुदाय राष्ट्रीय प्रतीकों या अभियानों के विरोध में उठ खड़ा होता है। उदाहरण के लिए भारत में आजादी का मंत्र फूंकनेवाले 'वंदे मातरम' का मुसलमानों ने विरोध किया। 'मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' ने तो इसके विरोध में मुस्लिम स्कूली बच्चों के अभिभावकों को पत्र तक लिखे। बांग्ला साहित्यकार एवं समीक्षक रियाजुल करीम ने लिखा कि 'वंदे मातरम' के विरोध का प्रमुख उद्देश्य भारतीय मुसलमानों को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग करना था। यह अलगाववादी जिन्ना की चाल थी।

इसी तरह शाहबानों को मुआवजा देने के मामले में कट्टरपंथी मुस्लिमों ने यह कहकर विरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट का मुआवजा देने का फैसला शरीयत कानून में दखलंदाजी है। उन्होंने संसद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए कांग्रेस पर दबाव डाला। कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस फैसले को पलटवाकर इसे संसदीय कानून बनवा दिया जो पहले मात्र शरीयत का कानून था। संसदीय रिकार्ड में सांप्रदायिकता का ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता।

यह एक विचित्र स्थिति है कि धर्म को अफीम मानकर अपने ही प्राचीन धर्म का विरोध करनेवाला वामपंथ मुस्लिम धर्मांधता से विरोध नहीं करता। बंगाल से लेकर केरल तक अपनी छत्र-छाया में इसे पालता है। कभी अल्पसंख्यक के नाम पर, कभी सेक्युलरिज्म की दुहाई देकर या फिर कभी मानवाधिकार का करुण प्रलाप करके वह मुस्लिम समुदाय का समर्थन करता रहता है। और इस समर्थन की छत्र-छाया में जिहादी मुस्लिम अपने मंसूबों को अंजाम देते रहते हैं। सीएए के विरोध में जिहादियों का हिंसक कृत्य एक ऐसा ही उदाहरण है। यह हिंसा चलती रहेगी, क्योंकि वोट प्राप्त करने के लिए और अपनी कायरता के कारण ना तो वामपंथ व कांग्रेस अपना रास्ता बदलेंगे और ना ही जिहादी मुस्लिम अपना मंतव्य छोड़ेंगे। इन सभी की समस्या यह है कि मोदी व शाह ने इनकी वह नस दबाई है जहां सबसे अधिक दर्द होता है। जबकि ये दोनों नेता अपने वृहत्तर राष्ट्रीय सरोकारों का परिचय दे रहे हैं। वे पिछली सरकारों की उन गलतियों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं जिनसे भारत की आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। कल्पना कीजिए कि जिस देश के पड़ोसी चीन व पाकिस्तान जैसे देश हों, उस देश की कांग्रेस सरकार ने अपने पिछले दस वर्षों के कार्यकाल में बड़े हथियारों की खरीदारी न करके डिफेंस को खोखला कर दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला। देश को हतप्रभ करनेवाले उनके अनेक घोटाले जरूर उजागर हुए।

कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही अपने प्रशासनिक कार्य निष्पादन से यह सिद्ध किया है कि वह अपनी मूल प्रकृति में पलायनवादी, भीरुता एवं सुविधापरस्ती की प्रवृतियों से ग्रस्त रही है। यही कारण है कि पड़ोसी देशों से घुसपैठियों की समस्या, गैर बराबरी पर आधारित धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिक कानून न होने की समस्या, चीन से पराजय एवं सीमाओं की समस्या, कश्मीर समस्या, श्रीलंका में सेना भेजने का विवेकहीन फैसला, आंतरिक सुरक्षा की उपेक्षा, पुराने ढर्रे पर चलाई जा रही अंतरराष्ट्रीय कूटनीति जैसी संचित समस्याएं इतना विकराल रूप धारण करती चली गईं कि इन्हें सुधारने और ठीक करने के लिए मोदी सरकार को अपनी सारी शक्ति लगानी पड़ रही है।

मोदी सरकार राष्ट्र की जड़ों को सींच रही है। जनता की उम्मीदें भी सरकार पर टिकी हैं। मगर देश की अधिकांश अल्पसंख्यक आबादी मोदी सरकार से खुश नहीं है। आज जबकि विश्व परमाणु युग के उस दौर में पहुंच गया है, जब देश के वृहत्तर राष्ट्रीय और सांस्कृतिक आयामों का मार्ग प्रशस्त करने की जरूरत है, ताकि राष्ट्रीय हितों के अनुरूप वैश्विक प्रणाली में सत्ता एवं ताकत के नए रचना विन्यास से देश को सुरक्षित घेरे में लाया जा सके। राष्ट्रीयता कभी भी व्यतीत मूल्य नहीं हो सकती। यह मनुष्य की मूलभूत प्रकृति में अंतर्भूत है। जो लोग इसे कमजोर करने की बात करते हैं, वे वस्तुतः अपनी आदर्शवादी मिथ्या परिकल्पना से जूझ रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून एवं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को इन्हीं संदर्भों में देखा जाना चाहिए। राष्ट्रीयता की भावना दृढ़ होगी तो आनेवाली पीढ़ियां भी मजबूत होंगी चाहे वे अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक।

कट्टरपंथ को हवा देने की कोशिश

कुछ दशक पहले गांवों से उजड़कर मुस्लिम परिवार रोजी रोटी की तलाश में जामिया नगर बसने लगे। यह देखकर एक दर्जन से अधिक मुस्लिम संगठनों ने यहां अपने कार्यालय स्थापित कर लिए जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम मजलिसे-मुशावरत और जमाते-इस्लामी जैसे संगठन भी थे। मुस्लिम धर्म और अस्मिता पर खतरा दिखाकर ये संगठन गरीब मुसलमानों को बहकाकर जुलूस एवं प्रदर्शन आदि करने लगे। इन लोगों ने जामिया मिल्लिया के छात्रों को भी प्रभावित करने का प्रयास किया। जमाते-इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने एक बार आरिफ मोहम्मद खां को लोहे की रॉड से हमला करके घायल कर दिया, क्योंकि उन्होंने शाहबानो मामले में प्रगतिशील एवं आधुनिक मुसलमानों का नेतृत्व किया था (टेक्स्ट एंड कन्टेक्स्ट-आरिफ मोहम्मद खां)। यह आरोप है कि ये वही तत्व थे जिन्होंने कुछ कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जामिया के छात्रों के जुलूस में शामिल होकर उन्हें आगजनी, पत्थरबाजी और दंगा-फसाद के लिए उकसाया। ऐसा प्रतीत होता है कि ये संगठन एवं उनके कार्यकर्ता इस देश के नहीं, बल्कि किसी पराये देश के नागरिक हैं। नागरिकता कानून का निराधार विरोध करके दंगा-फसाद और आगजनी करनेवाला समुदाय स्वयं ही तय करे कि एक सच्चा नागरिक कहलाने के लिए वह किस विशेषता का दिग्दर्शन करा रहा था? किन राष्ट्रीय सरोकारों का परिचय दे रहा था? जिस कांग्रेसी शासन के मात्र सात वर्षों के दौरान वर्ष 1964 से 1970 के बीच 425 सांप्रदायिक दंगे हुए और जिसमें लगभग 3,300 लोग मारे गए (इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, डॉ. बीएल फाडिया) उसी कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व द्वारा आज पुनः देशवासियों से कुर्बानी का आह्वान किया जा रहा है, क्योंकि यही कुर्बानियां तथाकथित सेक्युलर पार्टियों के लिए सत्ता का रास्ता तैयार करती हैं।

आतंकी हरकतों पर वामपंथी दलों की चुप्पी

भारतीय मुस्लिम समाज प्रायः पाक एवं उसके प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों पर एक शब्द भी नहीं बोलता। वह एक उल्टा ही विमर्श चलाता है कि सुरक्षा बल कश्मीर में मुसलमानों पर ज़ुल्म ढा रहे हैं। उसकी समस्या यह है कि वह जिस देश में रहता है उसी देश के धर्म, प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति का धार्मिक कारणों से विरोध करता है। विश्व के दर्जनों देशों में अल्पसंख्यक या शरणार्थी होने के बावजूद मुस्लिम शक्ति कैसे ग्रहण कर लेते हैं? इसको भी समझना जरूरी है। ये मूलतः वामपंथ और मानवाधिकार केंद्रित उदारवादी मध्यमार्गी व्यवस्थाओं की छाया में शक्ति ग्रहण करते हैं। जिहादी मुस्लिम समाज स्थानीय धर्म और संस्कृतियों का विरोध इसलिए करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य उसे इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील करना होता है। लेकिन वामपंथ स्थानीय संस्कृतियों का विरोध इसलिए करता है, क्योंकि वह उसे प्रतिक्रियावादी और प्रतिगामी मानता है। स्थानीय धर्म और संस्कृतियां वामपंथ और जिहादी इस्लाम दोनों के निशाने पर रहते हैं।

खरी-खरी

डर की डुगडुगी से उपजा बेसुरा राग

ललित शौर्य

वो पिछले कुछ दिनों से डर से लगातार दबे जा रहे हैं। बल्कि यूं कहें कि डर के नीचे कुचले जा रहे हैं। आलम यह है कि डर ने उनकी सांसें ऊपर-नीचे कर दी हैं। डर उनके सीने में चढ़ बैठा है। देश में बदला अब भी कुछ नहीं है, लेकिन वो अचानक अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसमें सबसे मजे की बात ये है उन्हें यही पता नहीं कि आखिर डर किस बात से है?

डराने का व्याकरण बड़ा अजीब है। किसी को सामने से नहीं, बल्कि परदे के पीछे से डराया जाता है। परदे के सामने बंदा डरता है। डरने-डराने की यह प्रक्रिया चलती रहती है। आखिरकार डर इस कदर हावी हो जाता है कि डरने वाले परदे को ही जलाकर फूंक डालते हैं।

इन दिनों देश की सड़कों पर भी फूंका-फूंकी का खेल चल रहा है। कहीं-कहीं तो डर से डरा हुआ इंसान बेखौफ खाकी को भी डराने से बाज नहीं आ रहा है। पहली बार डर के दर्दनाक दर्शन हो रहे हैं। कानाफूसी हो रही है कि डरा हुआ इतना तांडव कर सकता है, तो बेडर के हाल क्या होंगे? अहिंसा के पाठ पढ़ाने वाले डर से उत्पन्न हिंसा को हिंसा मानने को तैयार नहीं हैं। वो तो आजकल हिंसा को नई परिभाषा देने की जुगत में लगे हुए हैं। उनका मानना है कि डरा हुआ सिर्फ डर सकता है। वो ना तो किसी को डरा सकता है, ना ही किसी तरह कि हिंसा के गोलगप्पे निगल सकता है। वो तो बस डर की डकार लेने में सक्षम है।

लेकिन सड़कों, गलियों के नजारे कुछ और ही बयां कर रहे हैं। हाथ में तिरंगा लिए हुए डरा हुआ इंसान सरकारी संपत्ति का मलीदा बना रहा है। सरेआम, सरेराह मलीदा का कारोबार चल निकला है।

बुद्धि, विवेक को सात तालों में कैद कर अफवाह की चटनी चाटने वालों को कोई भी कबूतर बनाकर नचा सकता है। दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बजाय कोई सड़क पर पत्थर लेकर दौड़ेगा, तो अंजाम घातक ही होगा।

अब समय आ गया है कि डर की वैलिडिटी को खत्म कर सौहार्द और भाईचारे का रिचार्ज करवाया जाए। डर की डुगडुगी बजाकर सड़कों पर रिले रेस निकालकर कुछ नहीं होने वाला। इससे बेहतर है कि हम भारत के विकास के लिए जलेबी दौड़ करते नजर आएं।

ट्वीट-ट्वीट

अजित दादा पवार 'गहन शोध' का विषय हैं। भारत गणराज्य में 'लोकतांत्रिक मूल्यों' को समझने हेतु वह एक उपयुक्त राजनीतिज्ञ हैं। विश्वविद्यालयों के राजनीति शास्त्र विभाग इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करें।
ब्रजेश मिश्रा@brajeshlive

सीडीएस की नियुक्ति की खबर सुखद है। इससे भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होगा। सेना के तीनों अंगों में बेहतर तालमेल, समन्वय देखने को मिलेगा। नागरिक-सेना के रिश्ते भी अच्छे होंगे। सेना के तीनों अंगों से जुड़े फैसले एक ही जगह होने से रक्षा संबंधी नीतियों को लागू करने में सीडीएस की भूमिका प्रभावी होगी।
वेद मलिक@Vedmalik1

मैं अपने अनुभव से बताता रहा हूं (क्योंकि मैंने वामपंथियों के साथ काम भी किया है) कि वामपंथियों से ज्यादा असहनशील, संविधान विरोधी, दूसरों की आवाज दबानेवाला, मौकापरस्त कोई नहीं होता। आरिफ मोहम्मद खान के साथ जो हुआ वह इसी की बानगी है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता उनका मूल मंत्र है।
सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

जागरण जनमत

कल का परिणाम

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ फैले भ्रम को दूर करने में मोदी सरकार सफल रही है?

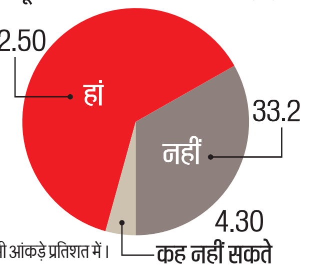

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या सीएए का विरोध वोट बैंक की राजनीति का नतीजा है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

बेटा मंत्री कैबिनेट मुख्यमंत्री बाप,
वंशवाद का डस रहा भारत को अभिशाप।
भारत को अभिशाप तमाशा सब देखेंगे,
कांग्रेस के साथ और वे क्या सीखेंगे!
बालासाहब आप रहे बिन कुर्सी नेता,
अब बेटे संग राज करे कुर्सी पर बेटा।
- ओमप्रकाश तिवारी

मध्य प्रदेश डायरी

राष्ट्रीय बहस में शामिल हो गया मध्य प्रदेश

आशीष व्यास
संपादक, नई दुनिया, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में भाजपा-कांग्रेस इस बार राष्ट्रीय बहस को लेकर आमने-सामने हैं। मुख्यमंत्री कमल नाथ ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस इस कानून का विरोध जारी रखेगी। भोपाल में विरोध-प्रदर्शन के बीच कांग्रेस ने 'संविधान बचाओ- न्याय शांति यात्रा' भी निकाली। भीड़ के उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री यह कहने से भी नहीं चूके कि इस रैली के जरिये कांग्रेस देश के दिल से यह बताना चाहती है कि केंद्र सरकार देश को तोड़ना चाहती है, लेकिन हम भारत के संविधान और संस्कृति का सम्मान करते हुए इस कानून का पालन नहीं करेंगे।

दरअसल, मध्य प्रदेश में अपना एक साल पूरा कर चुकी कमल नाथ सरकार के लिए यह अवसर शक्ति-प्रदर्शन का भी था। सरकार के साथ कांग्रेस भी यह चाहती थी कि शांति मार्च के जरिये मध्य प्रदेश में पार्टी की उपस्थिति का संदेश पूरे देश में जाए। इस रणनीति पर काम करने के लिए वरिष्ठ नेताओं की पूरी टीम काफी समय पहले से सक्रिय हो गई थी। राजधानी में हुई पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक में क्षेत्रीय स्तर के अनेक नेताओं को भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी। पार्टी का प्रयास यह भी था कि प्रदेश के अलग-अलग इलाकों से पुराने कांग्रेसी इस शांति मार्च में भागीदारी करें। इसके पीछे पार्टी की सोच थी कि कांग्रेसी विचारधारा का प्रचार-प्रसार पूरे प्रदेश में किया जा सके। स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला संगठनों से लेकर प्रदेश के बड़े सामाजिक संगठनों को भी भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया था। इससे कुछ दिन पहले भी राजधानी के इकबाल मैदान में धरना-प्रदर्शन किया जा चुका है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि जो भारतीय संविधान को मानते हैं, वे इस कानून को लागू नहीं होने देंगे।

कांग्रेस के इस आक्रामक रवैये के जवाब में भाजपा भी मैदान संभालते नजर आ रही है। इस बार नई रणनीति यह है कि योजनाबद्ध तरीके से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि तार्किक रूप से अपनी बात जनता तक पहुंचाई जा सके। जन-जुड़ाव की इस नई कोशिश को एक जनवरी से अभियान के रूप में शुरू किया जा रहा है और आगामी पखवाड़े में प्रदेश के पांच लाख परिवारों से सीधे जुड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि सीएए पर जिस तरह भ्रम फैलाया जा रहा है उसे दूर करने के लिए भाजपा प्रदेश में घर-घर जाकर जनजागरण करेगी। भाजपा के इस वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस को जवाब देते हुए इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून बनाकर बापू का सपना साकार किया। देश विभाजन के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख और अन्य अल्पसंख्यक अगर वहां न रहना चाहें, तो भारत आ सकते हैं। माना जा सकता है कि प्रादेशिक मुद्दों पर एक दूसरे का विरोध कर रहे दोनों प्रमुख दल आने वाले समय में राष्ट्रीय बहस पर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे।

क्या राम से रूठ गया है राज : लगता है राम वन गमन पथ भी अब राजनीतिक वादों-इरादों पर निर्भर हो गया है। भगवान राम 14 साल के वनवास के दौरान मध्य प्रदेश में जहां-जहां से गुजरे थे, भाजपा और कांग्रेस की सरकारें पिछले 16 वर्षों में उन्हें चिन्हित करने और खोजने में विफल रही है। पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने विस्तृत योजना बनाकर इसे अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल किया था, लेकिन निर्णायक परिणाम सामने नहीं आ पाए। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी अपने वचन-पत्र में राम वन गमन पथ खोजने का एलान किया था। लेकिन अब तक कागजों में भी कोई कार्ययोजना नहीं बनी है। पौराणिक मान्यता है कि हजारों साल पहले त्रेता युग में 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ मौजूदा मध्य प्रदेश में सतना जिले के चित्रकूट से दाखिल होकर अमरकंटक और छत्तीसगढ़ होते हुए रामेश्वरम की ओर रवाना हो गए थे। इस दौरान वे सतना, रीवा, पन्ना, छतरपुर, शहडोल और अनूपपुर जिलों की सीमा से निकले थे। प्रदेश सरकार यह दावा कर रही है कि पर्यटन विकास के लिए इस योजना पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। 'थीम पार्क' और कार्ययोजना का निर्माण अंतिम दौर में है। अब देखना केवल यह बाकी है कि बजट की कमी का सामना कर रही कांग्रेस सरकार कब तक और कितना पैसा राम के नाम पर खर्च करेगी?

समस्या- समाधान

मंदी की मुश्किल का हल

देश के वर्तमान आर्थिक हालात को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यदि बैंकिंग ढांचा पटरी पर आ गया तो अर्थव्यवस्था की गाड़ी को रफ्तार पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी

प्रणव सिरोही
pranav.sirohi@nda.jagran.com

अब इसमें शायद ही कोई संदेह रह गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही है। तमाम आंकड़े इसकी पुष्टि कर ही रहे हैं, बीते सप्ताह आइएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी इस आर्थिक फिसलन को रोकने के लिए सरकार से अविलंब कुछ कदम उठाने के लिए कहा है। इससे पहले 12 दिसंबर की देर रात क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एसएंडपी) के एक नोट ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की नींद जरूर उड़ा दी होगी जिसमें एजेंसी ने कहा कि यदि समय रहते सरकार ने उचित कवायद नहीं की तो उसे भारत की रेटिंग घटाने से गुरेज नहीं होगा। मौजूदा माहौल में किसी भी रेटिंग एजेंसी की ऐसी कार्रवाई बुरे हालात को और बदतर बनाने का ही काम करेगा, क्योंकि तमाम निवेशक संस्थाएं इन्हीं एजेंसियों की रेटिंग के आधार पर अपने निवेश का निर्णय करती हैं।

चूंकि किसी भी मर्ज के उपचार के लिए पहले-पहल उसकी पड़ताल अपरिहार्य हो जाती है यानी इस आर्थिक सुस्ती के स्वरूप को समझना होगा। बीमारी के संकेत बताने वाले मुद्रा कोष और एसएंडपी की नसीहतों पर गौर करते हैं। वैसे उनका निचोड़ कुछ राहत देने वाला है। उनका मानना है कि भारत की आर्थिक सुस्ती ढांचागत नहीं, बल्कि चक्रीय है और उसकी बुनियाद इतनी मजबूत है कि वह जल्द ही जोरदार वापसी करने में पूरी तरह सक्षम भी है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अर्थव्यवस्था किसी मौसमी संक्रामक बीमारी से जूझ रही है और उसमें किसी असाध्य बीमारी के लक्षण नहीं दिख रहे।

आंकड़े खुद इसकी पुष्टि करते हैं। मसलन वाहन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों के आंकड़े बताते हैं कि ये मांग की भारी कमी से जूझ रहे हैं। यानी मंदी मांग जनित अधिक है। अब जब मांग का मुद्दा उठता है तो हमें चार पहलुओं- निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग, सकल पूंजी निर्माण और निर्यात पर गौर करना होगा। इनमें केवल सरकारी उपभोग को छोड़ दिया जाए तो तीनों पहलू फिलहाल पस्त पड़े दिखाई देंगे। वर्ष 2011-12 में जिस पूंजी निर्माण की दर 34.3 प्रतिशत थी वह चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सिकुड़कर 27.8 प्रतिशत रह गई। केवल यही पहलू जीडीपी वृद्धि दर को तकरीबन डेढ़ प्रतिशत तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। वैश्विक बाजारों में मंदी और भारतीय उद्योगों की अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिस्पर्धा क्षमता के चलते निर्यात से भी ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा सकतीं।

अभी अर्थव्यवस्था सरकारी उपभोग के भरोसे चल रही है, लेकिन उसकी एक सीमा है जिसे जरूरत से ज्यादा बढ़ाना राजकोषीय घाटे की सूरत बिगाड़ेगा। हालांकि अनेक अर्थशास्त्री सरकारी खर्च को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और इसके लिए 2008 की आर्थिक मंदी से निपटने के उपायों की ओर भी ध्यान दिलाया जा रहा है, लेकिन मनमोहन सरकार के दौरान लिए गए उन फैसलों का असर ऐसा हुआ था कि राजकोषीय घाटा 2009-10 के दौरान बढ़कर जीडीपी के 6.6 प्रतिशत तक पहुंच गया था जो राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित सीमा के दोगुने से भी अधिक था। वैसे भी सरकारी हस्तक्षेप गड्ढे में पड़ी गाड़ी को निकाल जरूर सकता है, पर रफ्तार केवल निजी निवेश से प्रेरित आर्थिक गतिविधियों के ईंधन से ही दी जा सकती है।

ऐसे में निजी निवेश के लिए सस्ते कर्ज की उम्मीद से निगाहें रिजर्व बैंक की ओर टिकती हैं, लेकिन महंगाई ने इस मामले में केंद्रीय बैंक के हाथ और बांध दिए हैं। हालांकि आरबीआइ इस वर्ष फरवरी से अब तक नीतिगत दरों में 135 आधार अंकों की कटौती कर चुका है, मगर उसका फायदा भी अभी तक जमीनी स्तर पर मिलता नहीं दिख रहा। एक हालिया रपट के अनुसार साल की पहली छमाही में कंपनियों को मिलने वाले कर्ज में लगभग 60 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। असल में गैर निष्पादित आस्तियों यानी एनपीए से कराह रहे बैंक इस कारण नए कर्ज देने को लेकर शंकालु बने हुए हैं। संकट से जूझ रहे एनबीएफसी के चलते यह स्थिति और जटिल होती गई। इसी कारण कर्ज की यह धारा सूख गई है। हालांकि अनेक नए प्रयासों से फंसे हुए कर्जों की वसूली में आई तेजी से बैंकों की दशा सुधरी है जिसका लाभ निजी क्षेत्र को नए कर्जों के प्रवाह में मिल सकता है।

हालांकि सरकार ने मुश्किलों से जूझते बैंकों को पुनर्पूंजीकरण की मदद मुहैया कराई है, लेकिन यही काफी नहीं होगा। बैंकिंग क्षेत्र व्यापक एवं ढांचागत सुधारों की बाट जोह रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधार से ही देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकती है। सरकार ने हाल में आइबीसी में सुधार को लेकर भी सराहनीय कदम उठाया है जिसमें पुरानी कंपनी के प्रबंधन के किसी कृत्य को लेकर बोली में सफलता हासिल करने वाली नई कंपनी को किसी आपराधिक कार्रवाई से नहीं जूझना होगा। इसके चलते इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया में शामिल होने की इच्छुक तमाम कंपनियां भयाक्रांत थीं, जो डर अब सरकार ने दूर कर दिया है। इसके अलावा मौजूदा सुस्ती को दूर करने के लिए मोदी सरकार की निवेश एवं वृद्धि पर नवगठित समिति की भी गत सप्ताह की शुरुआत में बैठक हुई। फिर भी तमाम ऐसे सुधार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं जो आर्थिक मोर्चे पर 'एनिमल स्पिरिट' यानी धारणा और माहौल को बदलने का माद्दा रखते हैं। क्या अपने राजनीतिक एवं सामरिक एजेंडे पर पर्याप्त दमखम दिखाने वाली मोदी सरकार ढांचागत आर्थिक सुधारों को मूर्त रूप देने का साहस दिखा पाएगी? अर्थव्यवस्था को इस फौरी सुस्ती से निकालने और पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य काफी कुछ इस सवाल के जवाब पर निर्भर करेगा।

48.46 प्रतिशत युवतियां हैं देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। वहीं पुरुषों का प्रतिशत 51.36 है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (एआइएसएचए) 2018-19 की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में उच्च शिक्षा में कुल अनुमानित छात्र नामांकन 3,73,99,388 हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 31 दिसंबर 2019

झारखंड

नई सरकार से उम्मीदें

दूसरी बार सत्ता की कमान संभालने के तुरत बाद जिस तरह राज्य के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्तियों के दरवाजे खोलकर विभिन्न विभागों की रिक्तियों को शीघ्र भरने की बात कही है, उससे युवाओं में नई उम्मीद जगी है। युवा मुख्यमंत्री ने शपथग्रहण के ही दिन कैबिनेट की पहली बैठक में इस विषय को रखकर युवाओं और बेरोजगारों के प्रति अपनी प्राथमिकता को भी स्पष्ट कर दिया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार नवंबर में झारखंड में शहरी बेरोजगारी की दर 17.4 फीसद थी। यह राष्ट्रीय औसत से करीब दोगुनी है। झारखंड की विडंबना यह रही है कि राज्य गठन के दो दशक बाद भी यहां न तो अपेक्षा के अनुरूप नियुक्तियां हो सकी हैं ना ही विभागों के रिक्त पदों को भरा जा सका है। नियुक्ति के लिए ली गई जेपीएससी की प्रशासनिक सेवा समेत तमाम प्रतियोगिता परीक्षाएं लगातार विवादों में रहने के कारण रद होती रहीं। अस्थिर सरकारों से लेकर स्पष्ट नीति, विजन का अभाव और गड़बड़ी, भ्रष्टाचार एवं तकनीकी उलझनें इसकी मुख्य वजह रहीं। अब नए मुख्यमंत्री ने नियुक्तियों के प्रति गंभीरता दिखाते हुए चुनाव पूर्व अपने किए गए वादे पर अमल करने का संकेत दिया है। हेमंत अगर इसे त्वरित गति से कार्यरूप देते हैं तो यह उनकी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। किसी भी राज्य के विकास में वहां के मानव संसाधन का अहम योगदान होता है। सशक्त, सक्षम और समृद्ध वर्कफोर्स राज्य के विकास को गति दे सकती है। इसलिए जितनी जल्द हो सके, इसकी कमी को दूर कर लेना चाहिए। इसके अलावा नई सरकार को वेतन व प्रोन्नति संबंधी विसंगतियों को भी जितनी जल्दी हो सके दूर कर लेना चाहिए। इन विसंगतियों के कारण पिछले वर्षों में तेजी से इस राज्य से प्रतिभाओं का पलायन हुआ है। योग्य अफसर यहां से दूसरे राज्य चले गए हैं। इस स्थिति को बदलना होगा। पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और रसोइया समेत विभिन्न सेवा संवर्गों के कर्मचारी भी नई सरकार से उम्मीद लगाए हैं कि उनकी वर्षों से चली आ रही मांगें पूरी होंगी। सरकार को जितनी जल्दी हो सके इनकी समस्याओं का भी कोई ठोस हल निकाल लेना चाहिए। वहीं नक्सलवाद से निपटना एक और बड़ी चुनौती है, जिसके लिए सरकार को हर हाल में निर्णायक जंग छेड़कर राज्य में भयमुक्त वातावरण बनाना चाहिए। पिछली सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई छेड़ी थी। हेमंत सरकार को इस जंग को और प्रखर करने पर विचार करना चाहिए।

युवा मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही राज्य में रिक्त पदों को भरने की बात कह यह स्पष्ट कर दिया है कि युवा उनकी प्राथमिकता में हैं।

आर्थिक मोर्चे पर भी राज्य कई चुनौतियों से जूझ रहा है। आज झारखंड के पास देश की चालीस फीसद खनिज संपदा और 29 फीसद कोयला का भंडार है। इससे स्पष्ट है कि प्राकृतिक संसाधनों से राज्य काफी समृद्ध है। बावजूद इसके राज्य पर इस समय 85 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। यही नहीं झारखंड में गरीबी भी चरम पर है। वहां की 37 फीसद आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने को मजबूर है। जाहिर है यदि हेमंत सोरेन राज्य को इन समस्याओं से बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं तो उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा।

बंगाल

विश्वविद्यालय में छात्र और राजनीति

आमतौर पर यह माना जाता रहा है कि छात्र देश की राजनीति को नई दशा-दिशा देने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों ने अब तक छात्रों को इस मामले में अपने-अपने हिसाब से उपयोग किया है। कोलकाता दौरे पर आए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को राजनीति से दूर रखने का आह्वान किया है। वह भी उस राज्य में जहां शायद ही एक दिन भी शिक्षण संस्थानों में सियासत को लेकर हंगामा नहीं होता हो। ऐसे में केंद्रीय मंत्री के बयान पर चर्चा छिड़ना लाजिमी है।

केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का जादवपुर विश्वविद्यालय का दौरा हो या राज्यपाल जगदीप धनखड़ से सवालों की झड़ी, विश्वविद्यालय के छात्रों ने निरंतर विरोध के सुर बुलंद किए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी छात्रों के पक्ष में हैं और उन्होंने दो टूक कह दिया कि छात्रों के वोट से सरकार बन सकती है तो उन्हें सवाल करने का अधिकार क्यों नहीं है? दरअसल देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों को राजनीतिक दल ही अपना हथियार बना रखे हैं। किसी एक दल या एक विचारधारा को दोषी ठहराया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जब सभी राजनीतिक दलों की छात्र शाखाएं हैं तो जाहिर है कि उनकी राजनीतिक भागीदारी भी रहेगी। निशंक ने तो यहां तक कह दिया है कि राजनीतिक केंद्रों में तब्दील हो रहे शैक्षणिक संस्थानों को केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। उनकी इस चेतावनी का कितना असर होगा, यह तो आगे पता चलेगा, लेकिन नियंत्रण संभव नहीं है।

प्रतीकात्मक।

पोखरियाल की मंशा चाहे जितनी मजबूत हो, लेकिन पंचायत, निकाय और विधानसभा से लेकर लोकसभा के हर चुनाव की भागमभाग में छात्रों को हर दल अपना हथियार बनाते रहते हैं। फिर शिक्षा कैंपस में राजनीतिक गतिविधि रोकने का मापदंड क्या होगा? यह भी तो साफ होना चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के मुद्दे पर भी तो छात्रों ने खूब हंगामा किया। देश भर में विरोध की जो लहर उठी उसके सुर तो उन्हीं दलों और नेताओं से मिल रहे हैं और इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं।

हालांकि देश भर में हाल के दिनों में विपक्षी दलों द्वारा उकसाए जाने के कारण विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा अनेक शैक्षणिक संस्थानों में जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन किए गए हैं, उन सबकी पृष्ठभूमि में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने चेतावनी भी दे डाली है कि नरेंद्र मोदी सरकार इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाली है। तो क्या ऐसे संस्थानों में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है, यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है। नई दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर जादवपुर और प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय तक तो सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक पंजी पर विरोध के सुर निरंतर तेज हुए हैं। अब सत्ताधारी दल के पास चेतावनी के साथ ही विपक्ष को कोसने का भी मुद्दा मिल गया है। अब असली जरूरत इस बात की है कि छात्र राजनीतिक दलों के औजार न बनें और उन्हें कोई बहका न सके। इसके लिए हर दल को आइने में झांकने की जरूरत है।

पंजाब

डोर पर नहीं कोई जोर

इसे जागरूकता की कमी कहें या फिर सरकारी स्तर पर इच्छाशक्ति की कमी कि पंजाब में प्रतिबंध होने के बावजूद पतंगों को उड़ाने के लिए चाइनीज डोर इस्तेमाल हो रही हैं। नतीजतन पंजाब भर में इसका कहर बरप रहा है। हर वर्ष हजारों लोग, पशु एवं पक्षी हादसों का शिकार हो रहे हैं। कुछ तो इसके कारण जान तक गंवा चुके हैं, फिर भी न तो पतंगबाजी के शौकीन लोग चेते हैं और न ही प्रशासन इस ओर गंभीर है। इस साल भी लोहड़ी के नजदीक आते ही बाजारों में चाइनीज डोर बेशक चोर दरवाजे से ही सही, लेकिन धड़ल्ले से बिकने लगी है। शायद ही पंजाब में कोई ऐसा शहर, कस्बा या गांव हो जहां इसकी उपलब्धता न हो। यहां तक कि कुछ लोग इसे ऑनलाइन साइटों से सीधे घर पर ही मंगवा रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि लोगों ने पुराने हादसों से सबक नहीं सीखा है।

रविवार को भी लुधियाना के जगराओं पुल पर एक व्यक्ति चाइनीज डोर की चपेट में आ गया और बुरी तरह से जख्मी हो गया। राहगीरों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसे चिकित्सकों को बारह टांके लगाने पड़े। अकेले लुधियाना में ही अभी तक पैंसठ लोग चाइनीज डोर से कट चुके हैं, जबकि पिछले साल दो लोगों की इस डोर ने जान ले ली थी। इसके अलावा अमृतसर, पठानकोट और गुरदासपुर में भी यह डोर पिछले वर्षों के दौरान कई लोगों की जानें लील चुकी है। तीखी, मजबूत और मेटल कोटेड होने के कारण अच्छी विद्युत सुचालक चाइनीज डोर के कारण लोग कटते तो हैं ही साथ ही यह बिजली की तारों के साथ छू जाने पर झटका भी देती है। इसे बनाने में अधिकतर केमिकल और दूसरी धातुओं का इस्तेमाल होता है। इनमें शीशा, गोंद, एल्युमीनियम ऑक्साइड शामिल हैं। इससे यह आसानी से टूटता नहीं है। इसमें ब्लेड जैसी धार होती है। बाजार में मिलने वाली सभी डोर घातक होती हैं, लेकिन इनमें चाइनीज सबसे खतरनाक होती हैं। पतंगबाजी के दौरान डोर में करंट के कारण भी कई हादसे पूर्व में पेश आ चुके हैं।

प्रतीकात्मक।

इस डोर पर तो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुका है और सरकार ने भी इस डोर को कोर्ट के आदेश के बाद ही प्रतिबंधित किया था, परंतु हैरानी की बात है कि इसका चलन बंद नहीं हुआ है। पुलिस और प्रशासन को चाहिए कि वह इस जानलेवा डोर को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की तरफ गंभीरता दिखाए। सिर्फ इसे बेचने वालों पर ही नहीं, बल्कि इसका प्रयोग करने वालों पर भी कठोर कानूनी कार्रवाई करे।

उत्तराखंड

हादसों पर अंकुश की कवायद

उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार की चिंता उचित ही है। विशेषकर पहाड़ की सर्पीली सड़कों पर स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। आमतौर पर हादसों के लिए मानवीय चूक को जिम्मेदार माना जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मानवीय चूक हादसों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन अन्य कारकों को भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता। मसलन इन दिनों सड़कों पर जमा पाला दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण बन रहा है, लेकिन हैरत यह है कि सिस्टम ने अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। रविवार को टिहरी के गजा क्षेत्र में एक वाहन के खाई में गिरने से एक जान चली गई। तब अफसरों का ध्यान इस ओर गया। अब कहा जा रहा है कि जल्द ही ऐसे स्थानों पर चूना डलवाने का काम शुरू किया जाएगा।

विचारणीय पहलू यह है कि आखिर हादसे के बाद ही जिम्मेदारों की नींद क्यों टूटती है। दूसरा सड़कों पर बने गड्ढे हादसों को अक्सर ही न्योता देते हैं। फिर बात चाहे पहाड़ की हो या मैदान की। कुछ साल पहले पौड़ी गढ़वाल जिले के धूमाकोट में हुआ बस हादसा इसकी एक बानगीभर था। इस हादसे में करीब 50 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद कार्रवाई के नाम पर कुछ अफसरों पर गाज तो गिरी, लेकिन समय बीतने के साथ सब कुछ मानो भुला दिया गया। इतना ही नहीं, प्रदेश में हर साल डेंजर जोन और ब्लैक स्पॉट पर चर्चा की जाती है। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में यह हकीकत सामने आई कि डेजर जोन और ब्लैक स्पॉट के ट्रीटमेंट की रफ्तार बेहद सुस्त है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 139 ब्लैक स्पॉट (ऐसे क्षेत्र जहां लगातार हादसे हो रहे हैं) चिह्नित हैं। इनमें से अभी तक 37 में ही सुधार हो पाया है। वहीं 89 में तात्कालिक कार्य ही किए गए। दुर्घटना संभावित स्थल (डेंजर जोन) के बारे में बताया गया कि राज्य में 1500 ऐसे स्थल चिह्नित हैं। इनमें से केवल 107 में ही सुधार हो पाया है। आलम यह है कि इस स्थिति पर परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने यहां तक कहा कि इस बारे में निर्देशित करने के बावजूद प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। जाहिर है अफसर मंत्री के आदेशों को भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं।

उत्तराखंड में हादसों पर अंकुश के लिए सरकार के स्तर पर कवायद जारी है, लेकिन यह तभी संभव है जब अफसर संवेदनशीलता से कार्य करें।

यह सही है कि सरकार दुर्घटनाओं को लेकर चिंतित है। अनुपूरक बजट में इसके लिए एक करोड़ रुपये की धनराशि का प्रविधान किया है। इस राशि से दुर्घटना में कमी लाने के लिए उपाय किए जाएंगे। बावजूद इसके यह तब तक संभव नहीं है जब तक अफसर संवेदनशील नहीं होंगे।

सड़क दुर्घटना एक राष्ट्रव्यापी समस्या है। द लांसेंट पब्लिक हेल्थ जर्नल के अनुसार भारत में हर रोज 600 लोगों की मौत सड़क हादसे में होती है। वर्ष 2017 में देशभर में कुल 2.19 लाख लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए साल से हादसों पर आशा के अनुरूप अंकुश लग सकेगा।

अंतरिक्ष में रुकने के रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं वैज्ञानिक

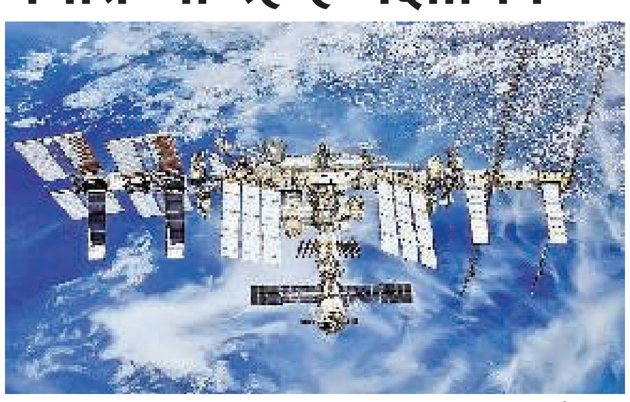
प्रतीकात्मक

अंतरिक्ष यात्रा के जिक्र भर से ही व्यक्ति रोमांच और कल्पना के सागर में गोते लगाने लगता है, लेकिन वहां पहुंचना और अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आइएसएस) में काम करना दुरूह कार्य है। इसके बावजूद अनंत आकाश के रहस्यों को जानने-समझने की जिज्ञाषा में वैज्ञानिक वहां पहुंचते हैं। खोज कर रहे वैज्ञानिक अपने शोध कार्य में इतना रमे हुए हैं कि वह वहां रुकने के रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं।

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

नासा की अंतरिक्ष यात्री 40 वर्षीय क्रिस्टीना कोच ने इसी सप्ताह अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने नासा की ही अंतरिक्ष यात्री पेगी व्हिट्सन (2016-17) का आइएसएस में 288 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड तोड़ा है। इतना ही नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोच अपने नए रिकॉर्ड को और भी विस्तार दे रही हैं। इसी वर्ष मार्च में आइएसएस पहुंची कोच को फरवरी 2020 में लौटना है। तब तक वह अंतरिक्ष में 328 दिन बिता चुकी होंगी। कोच का मिशन यूं तो छह माह का था, लेकिन नासा ने उनके मिशन को बढ़ाने का फैसला लिया। उनके नाम अंतरिक्ष का एक और रिकॉर्ड है। वह अक्टूबर 2019 में आइएसएस से बाहर आकर अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली महिलाओं की टीम में भी शामिल थीं। इसमें उनके साथ जेसिका मीर भी शामिल थीं।

हालांकि कोच ने पेगी व्हिट्सन का एक बार में सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रुकने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन कई उड़ानों के दौरान अंतरिक्ष में बिताए गए समय में पेशे से बॉयोकेमिस्ट व्हिट्सन अभी भी आगे हैं। 2002 से 2017 तक की कई उड़ानों में उन्होंने कुल 665 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं, जो किसी भी महिला द्वारा अंतरिक्ष में बिताया गया सबसे लंबा समय है। 59 वर्षीया व्हिट्सन अब रिटायर हो चुकी हैं।

वहीं महिला और पुरुष दोनों में रूस के गेनेडी पडल्का के नाम कई उड़ानों में सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रुकने का रिकॉर्ड है। 1998 से 2015 तक की कुल पांच उड़ानों में उन्होंने अंतरिक्ष में 878 दिन (लगभग ढाई वर्ष) बिताए।

सबसे लंबे समय तक एक उड़ान में आइएसएस में रुकने का रिकॉर्ड

स्काट केली	342 दिन
क्रिस्टीना कोच	290 दिन
पेगी व्हिट्सन	289 दिन
माइकल लोपेज	215 दिन
माइकल बैरट	199 दिन
टी डब्ल्यू वर्ट्स	199 दिन

भविष्य के कार्यक्रम बनाने में मिलेगी मदद : कोच के इस लंबे मिशन से नासा को लंबी अंतरिक्ष यात्राओं से होने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके माध्यम से भविष्य में और लंबे समय तक के शोध कार्यक्रम चलाए जा सकेंगे।

स्कॉट केली ने बिताए थे 340 दिन : महिला और पुरुष दोनों अंतरिक्ष यात्रियों में देखें तो आइएसएस पर सबसे ज्यादा दिन रुकने का रिकॉर्ड स्कॉट केली के नाम है, जिन्होंने 2015-16 के दौरान अंतरिक्ष में 340 दिन बिताए थे।

वालेरी पोलाकोव ने अंतरिक्ष में बिताए थे 438 दिन : अंतरिक्ष में एक उड़ान में सबसे ज्यादा दिन तक रुकने का रिकॉर्ड अभी भी रूस के वालेरी पोलाकोव के नाम है। जनवरी 1994 से मार्च 1995 तक वह रूस के मीर स्पेस स्टेशन पर रहे थे।

बाल विवाह निरस्ती में राजस्थान बना सिरमौर

संवाद सूत्र, जोधपुर

- **देश में जहां कुल 47 विवाह निरस्त हुए हैं, उसमें अकेले राजस्थान के हैं 43 मामले**
- **बाल विवाह से बदनामी का दंश झेल रहे राज्य की बदल रही तस्वीर**
- **'बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006' के तहत की जा रही है कार्रवाई**

एक समय था जब बाल विवाह का नाम आते ही सभी की नजरें राजस्थान की ओर होती थीं और प्रदेश को देशभर में शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी। सरकारी प्रयासों के बावजूद प्रदेश में बाल विवाह रोकने में कामयाबी नहीं मिल रही थी, लेकिन बीते कुछ सालों में ही राज्य बाल विवाह निरस्त कराने के मामले में सिरमौर बन गया है। इसकी वजह है बाल विवाह निरस्त करने के कानून का सख्ती से पालन करना है। देशभर में कुल 47 बाल विवाह निरस्त किए गए हैं। 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006' के तहत अकेले राजस्थान में ही 43 विवाह निरस्त हुए हैं। दर्जनों रद होने की प्रक्रिया में हैं।

देश की जनगणना-2011 के मुताबिक करीब 1.21 करोड़ बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। इसमें 57 फीसद लड़के और 43 फीसद लड़कियां हैं। राजस्थान में बाल विवाह के कलंक को मिटाने के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठन भी भरसक प्रयास कर रहे हैं। सूर्यनगरी जोधपुर का सारथी ट्रस्ट भी इसमें अहम भूमिका निभा रहा है।

पहला विवाह जोधपुर का निरस्त हुआ था : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू होने के बाद देश में बाल विवाह निरस्ती की पहली कार्रवाई राजस्थान के जोधपुर में ही हुई थी। यही नहीं देश और प्रदेश में सर्वाधिक बाल विवाह जोधपुर में ही निरस्त हुए हैं। जोधपुर में 40 विवाह निरस्त हुए हैं।

लिम्का बुक में दर्ज हुआ जोधपुर का रिकॉर्ड : देश का पहला बाल विवाह जोधपुर में निरस्त होने का रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। वहीं वर्ष 2015 में जोधपुर पारिवारिक न्यायालय से महज तीन दिन की न्यायिक प्रक्रिया से विवाह निरस्त करवाने की मुहिम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई हैं। जन चेतना से जुड़ा बाल विवाह निरस्ती विषय सीबीएसई की पुस्तकों में भी शामिल किया जा चुका है।

अहम तथ्य

- 15 साल से कम उम्र की सात फीसद लड़कियों का देश में बाल विवाह।
- 18 साल से कम उम्र की 27 फीसद लड़कियों का बाल विवाह हो जाता है।
- 18 साल से कम उम्र के चार फीसद लड़कों का बाल विवाह होता है।
- विश्व की तीन में से एक बालिका वधु भारत में रहती है।
- राजस्थान में 36 फीसद बालिकाओं का विवाह 18 साल की वैधानिक उम्र से पहले होता है।
- राजस्थान में 6.3 फीसद बालिका वधुएं 18 साल से कम उम्र में मां बन जाती हैं।

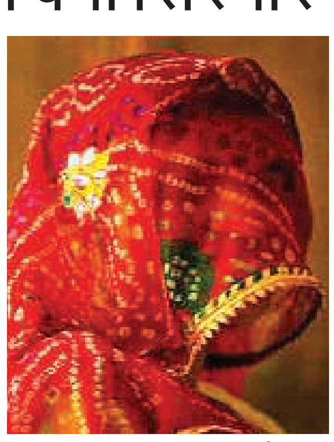
प्रतीकात्मक

कई सालों से राजस्थान बाल विवाह को लेकर शर्मसार होता रहा है। अब इसी कलंक को मिटाने के लिए बाल विवाह निरस्ती एक मुहिम बन गई है।
-डॉ.कृति भारती, मैनेजिंग ट्रस्टी सारथी ट्रस्ट, जोधपुर

उत्तराखंड के 35 ब्लाकों से पलायन थामने को कार्ययोजना

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- **पलायन आयोग यह कार्ययोजना 10 दिन में सरकार को सौंपेगा**
- **सभी विभाग इन ब्लाकों में विभिन्न योजनाओं पर करेंगे फोकस**

पलायन की मार से त्रस्त पौड़ी, अल्मोड़ा जिलों के लिए कार्ययोजना तैयार करने के बाद ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग अब ब्लाक स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने में जुट गया है। प्रदेश के 95 ब्लाकों में 35 ऐसे हैं, जहां पलायन अधिक हुआ है। इन ब्लाकों के गांवों में लोगों को थामे रखने को विभागवार क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसकी कार्ययोजना बनाई जा रही है। 10 दिन में आयोग इसे राज्य सरकार को सौंप देगा।

अल्मोड़ा और पौड़ी जिलों में पलायन के कारण जनसंख्या में गिरावट आई है, लेकिन अन्य जिलों के तमाम ब्लाकों में भी जनसंख्या घटी है। हालांकि, इन जिलों में ओवरआल जनसंख्या का आंकड़ा शहरों के कारण ठीक है, लेकिन गांव खाली हो रहे हैं। नतीजतन ब्लाकों के गांवों में जनसंख्या सिमट रही है। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ.एसएस नेगी के मुताबिक इस सबको देखते हुए ब्लाक को इकाई मानकर कार्ययोजना बनाने के लिए विश्लेषण शुरू कर दिया गया है।

डॉ.नेगी बताते हैं कि सभी ब्लाकों का गहन सर्वेक्षण हो चुका है। इसमें ये बात सामने आई है कि 35 ब्लाकों में पलायन ज्यादा हुआ है। लिहाजा, पहले चरण में सभी विभागों का फोकस इन ब्लाकों के गांवों पर होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ब्लाकों के लिए विभागवार कार्ययोजना बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसमें पूर्व में हुए सर्वे में ग्रामीणों के बीच से आए सुझावों को शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 10 दिन में कार्ययोजना सरकार को सौंप दी जाएगी। साथ ही आग्रह किया जाएगा कि अगले पांच साल तक सबसे पहले इन विकासखंडों के गांवों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

पलायन से खाली पड़े गांव (फाइल फोटो)

बैठकों के नाम पर अफसरों की लखनऊ दौड़ पर रोक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- **मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करें समीक्षा**
- **जरूरत पर अधिकतम दो माह में एक बार जिलों से बुलाए जाएं अफसर**

तकनीक के इस सुविधायुक्त युग में भी समीक्षा बैठकों के नाम पर उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की लखनऊ दौड़ और सरकारी धन की बर्बादी रुकने की अब पूरी उम्मीद है। इस ढर्रे को बदलते हुए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समीक्षा ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और व्हाट्सएप से करें। जिलों से अधिकारियों को अधिकतम दो माह में सिर्फ एक बार ही बुलाया जाए।

मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को पत्र जारी कर यह निर्देश सोमवार को दिए। उन्होंने पत्र में लिखा है कि स्थानीय स्तर पर सरकारी कार्यों में होने वाली देरी को रोकने के लिए शासन और मुख्यालय स्तर पर होने वाली बैठकों की व्यवस्था बदलनी होगी। जिलों में तैनात अधिकारियों को समीक्षा बैठक के लिए आवश्यकता होने पर ही बुलाया जाए। इतना ही नहीं ज्यादा से ज्यादा दो माह में एक बार ही अफसरों को आने को कहा जाए। पत्र में कहा गया है कि अधिकारियों को बार-बार राजधानी में यहां बुलाने से काम प्रभावित होता है।

अधिकतम तीन दिन में हो जाए फाइल का निस्तारण

मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को फाइलों के निस्तारण को लेकर भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शासन व विभागों की पत्रावलियां विभिन्न स्तरों पर लंबे समय तक अटकी रहने से मामलों के निस्तारण में बेवजह देरी होती है। तय करें कि हर फाइल उसी दिन या अधिकतम तीन दिन में निस्तारित कर आगे बढ़ा दें। ऐसा न करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि इन निर्देशों का पालन कड़ाई से कराया जाए। उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

शोधगंगा पर पीएचडी थीसिस के मामले में काशी हिंदू विश्वविद्यालय फिसड्डी

हिमांशु अस्थाना, वाराणसी

काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने इस वर्ष 23 व 24 दिसंबर को दीक्षा समारोह में पीएचडी की 732 व एमफिल की 12 उपाधियां प्रदान कीं। हर साल अगर इतने मान लिए जाएं तो अब तक कई हजार पीएचडी उपाधियों का आवंटन बीएचयू ने कर दिया है, लेकिन पीएचडी थीसिस के डिजिटल प्लेटफार्म शोधगंगा इंफ्लिबनेट पर मात्र 254 शोध ही उपलब्ध हैं, जबकि हर मामले में बीएचयू से कनिष्ठ वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 8132 थीसिस शोधगंगा पर उपलब्ध हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 8147, जेएनयू के 4721, जामिया मिलिया इस्लामिया के 461 व कलकत्ता विश्वविद्यालय के 11908 शोध वेबसाइट पर अपलोड हैं। 2700 एकड़ में फैले देश के पांच इंस्टीट्यूट आफ एमिनेंस में से एक बीएचयू में तीन बड़े संस्थान,14 संकाय व 140 विभाग हैं। इतना बड़ा दायरा जिस विश्वविद्यालय का हो और आनलाइन मंच पर पीएचडी की थीसिस मात्र 254 ही उपलब्ध हो, तो इससे साबित होता है कि बीएचयू इस मामले में कई संस्थानों के मुकाबले फिसड्डी है।

- **शोधगंगा इंफ्लिबनेट पर बीएचयू के मात्र 254 शोध ही हैं उपलब्ध**
- **पूर्वांचल, एएमयू, जेएनयू जैसे संस्थानों से पिछड़ा बीएचयू**

काशी हिंदू विश्वविद्यालय (फाइल फोटो)

अपलोड को लेकर हुआ है एमओयू

बीएचयू और यूजीसी के इंफ्लिबनेट के बीच 2015 में एक एमओयू हुआ था, जिसके तहत पीएचडी अवार्ड किए जाने वाले अभ्यर्थियों के शोध को इंफ्लिबनेट में भेजा जाएगा, जिसे शोधगंगा पर अपलोड किया जाएगा।

बीएचयू के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 2017 में हमें यूजीसी ने थीसिस नकल पर नकेल कसने वाला प्लेगरिजम साफ्टवेयर उपलब्ध कराया है। इससे थीसिस को चेक करने के बाद ही इंफ्लिबनेट को भेजा जाता है, जिसके बाद वे तमाम मानकों को पूरा करने के बाद अपलोड करते हैं। विवि रोज 10 थीसिस अपलोड करता है, वहीं हमारे पांच हजार शोध अपलोड होने को तैयार हैं। अगले एक-दो महीने के भीतर कार्य संपन्न हो जाएगा।

यूजीसी का नियम : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विनियम 2016 के मुताबिक एम फिल व पीएचडी उपाधि प्रदान किए जाने की घोषणा से पूर्व शोध की एक इलेक्ट्रानिक प्रति इंफ्लिबनेट के पास जमा करनी होगी, ताकि सभी विश्वविद्यालयों तक इसकी पहुंच बनाई जा सके।

24.49 प्रतिशत हिस्सा भारत के भौगोलिक भूभाग का वनों से आच्छादित है। यह आकलन फारेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है, जिसकी अंतिम रिपोर्ट 2017 में आई थी। देश में सबसे कम वृक्षों का आवरण हरियाणा में है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 6.79 प्रतिशत है। वहीं 97 फीसद के साथ केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप शीर्ष पर कायम है।

लोहे से लड़ रणजीत ने बदल दी दो पीढ़ियों की तकदीर

पंजाब में गुरदासपुर जिले के कस्बे कलानौर में अपना काम संभालतीं 60 वर्षीय रणजीत कौर (दाएं)। जागरण

महिंदर सिंह अर्लीभन्न, गुरदासपुर

- 24 साल पहले पति की मौत के बाद संभाला पुश्तैनी काम, बेटियों को एमए तक पढ़ाया
- 60 साल की उम्र में भी खुद बनाती हैं लोहे के औजार, परिवार के सामने खड़ी मुसीबतों को अपने हौसले से बौना साबित कर दिया

नारी सशक्तीकरण

लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी जज्बे और हिम्मत की मिसाल हैं पंजाब के गुरदासपुर जिले के छोटे से कस्बे कलानौर की 60 वर्षीय रणजीत कौर। उन्होंने 24 साल पहले पति की मौत के बाद परिवार के सामने खड़ी मुसीबतों को अपने हौसले से बौना साबित कर दिया।

रणजीत ने चार बच्चों की परवरिश के लिए न कभी किसी के सामने हाथ फैलाया और न दुखड़ा रोया। परिवार की पुश्तैनी लोहे के कृषि औजारों की दुकान खुद संभाली और अपनी दो पीढ़ियों की तस्वीर बदल दी।

वर्ष 1995 में रणजीत कौर के पति जसविंदर सिंह की रक्त कैंसर से मौत हो गई थी। जसविंदर लोहे के कृषि औजार बनाकर कलानौर बाजार में दुकान पर बेचते थे। जसविंदर की मौत के बाद परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था। बेटा अवतार सिंह (12 वर्ष), बेटी गुरजिंदर कौर (10 वर्ष), हरप्रीत कौर आठ वर्ष और सतिंदर कौर तीन वर्ष की थीं। तीन बेटियों और एक बेटे की जिम्मेदारी रणजीत कौर ने अपने कंधों पर उठा ली। उन्होंने दिन में दुकान पर अपना पुश्तैनी काम और रात को घर पर सिलाई का काम भी किया। बेटियों को एमए तक पढ़ाया। तीनों की शदियां कीं।

जिंदगी ने एक बार फिर रणजीत के सामने बड़ी चुनौती रख दी। बेटे अवतार की 2012 में मौत के बाद आखिरी सहारा भी टूट गया। अब बहू, दो पोतियों और एक पोते की जिम्मेदारी फिर उन पर आ गई। रणजीत ने ऐसे वक्त में भी हिम्मत नहीं हारी और मुश्किलों से संघर्ष जारी रखा। बहू को बीएड कराने के बाद अब तीनों बच्चों को एक अच्छे निजी स्कूल में पढ़ाकर उनका भविष्य संवार रही हैं। रणजीत दातर, छुरियां, लकड़ी के औजार, चौकी-बेलन, कैंची, तेजधार हथियार खुद तैयार करती हैं। वे रोजाना 1500 से 2000 रुपये तक कमा लेती हैं।

हाथ फैलाकर नहीं, मेहनत कर बच्चों को रोटी खिलाऊंगी

रणजीत कौर कहती हैं कि वे और उनकी बहू विधवा हैं, इसलिए कई बार समाजसेवी संगठन उन्हें मुफ्त में राशन देने की पेशकश करते हैं। वे उन्हें मना कर देती हैं। वह कहती हैं, हाथ फैलाकर नहीं मेहनत कर अपने बच्चों को रोटी खिलाऊंगी। जिंदगी का मजा मेहनत में ही है।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/positive-news

अनसुलझी पहेली! शीला की जुबानी पूरी कहानी...

दैनिक जागरण से कहा- मैं ओशो को मरने नहीं देना चाहती थी, लेकिन वह मुझे ही दुश्मन मान बैठे...

भगवान रजनीश उर्फ ओशो का इतिहास अनसुलझी पहेली है। मानो रहस्य-रोमांच से भरी कोई अधूरी कहानी। कहानी में ओशो के साम्राज्य की 'साम्राज्ञी', उनकी सबसे करीबी और 'सबसे विद्रोही' शिष्या मां आनंद शीला की भूमिका उतनी ही अहम, जितनी खुद ओशो की। मानो एक सिक्के के दो पहलू। शीला को इस कहानी में से हटा दें, तो मानो कुछ नहीं। इसी रहस्य और रोमांच को फिल्म जगत पूरी तरह भुना लेने को आतुर है। शीला के जीवन पर फिल्म और सीरीज बनने जा रही हैं। शीला, और शीला के बहाने ओशो, दुनियाभर में चर्चा में हैं। स्विटजरलैंड के बेसल से फोन पर अतुल पटैरिया को दिए इंटरव्यू में मां आनंद शीला की जुबानी वह पूरी कहानी...

जागरण विशेष

बीती सदी के उत्तरार्द्ध की यह कहानी, जिसने दुनिया को सम्मोहित किया, आज भी कई रहस्य समेटे है- ओशो और शीला की कहानी। ओशो नायक, तो शीला नायिका। दोनों अपनी-अपनी जगह और बिलकुल जुदा व्यक्तित्व, लेकिन दोनों ने मिलकर जो चमत्कार किया, दुनिया हैरत से भर नतमस्तक हो गई। विश्वशक्ति अमेरिका के खिलाफ उसी के घर में 'अघोषित लड़ाई' लड़ने वाली शीला कहती हैं कि उन्होंने फकीर ओशो को 'किंग' बनाया, तो ओशो ने कहा कि उन्होंने साधारण होटल परिचारिका को 'क्वीन' बनाया। सच यह भी कि इस जोड़ी के टूटते ही वह पूरा साम्राज्य तिनकों में बिखर गया।

शीला पर एक डॉक्टर और अमेरिकी अटॉर्नी की हत्या की साजिश रचने, काउंटी इलेक्शन को प्रभावित करने और अमेरिकी इतिहास का इकलौता 'बायो टेरर अटैक' करने जैसे गंभीर आरोप लगे। किसी और ने नहीं, ओशो ने लगाए। शीला को साढ़े तीन साल की जेल हुई। मुकदमे अब भी लंबित हैं और शीला स्विटजरलैंड में हैं, जिसकी अमेरिका से प्रत्यर्पण संधि नहीं है। इधर, ओशो को भी 1986 में अमेरिका से खदेड़ दिया गया। 1990 में वह पुणे में चल बसे। कहा गया कि अमेरिका ने उन्हें जहर दिया था। वहीं, शीला कहती हैं कि अमेरिका ने नहीं, ओशो को ओशो ने ही मारा और वह ओशो को मरने देना नहीं चाहती थीं।

1982 में ओशो के साथ मां आनंद शीला (बाएं)। (फाइल) सौ. शीला

ओशो को किसने मारा? शीला ने कहा, उसी ने जिससे मैं उन्हें बचाना चाहती थी। डॉक्टर देवराज उर्फ अमृतो के साथ उनकी बढ़ती 'रिलेशनशिप' पर मुझे ऐतराज था...। कैसी रिलेशनशिप? थोड़ा ठिठक कर कहती हैं- जैसी ड्रग डीलर और ड्रग एडिक्ट के बीच होती है...। शीला आरोप लगाती हैं कि डॉ. देवराज ड्रग का अधिक डोज देकर ओशो को गुलाम बना चुका था। वह तिल-तिल कर मर रहे थे। मैं उन्हें इस तरह मरने देना नहीं चाहती थी। देवराज के पीछे कौन था? इस पर शीला कुछ बताते बताते रह गईं। हालांकि उनका इशारा कुछ लोगों की ओर था। कहा- उन लोगों के प्रति मेरा विरोध ही ओशो और मेरे बीच के अलगाव का एकमात्र कारण बना।

कहती हैं, ओरेगॉन, अमेरिका में 64 हजार हेक्टेयर में फैले रजनीशपुरम, जिसमें दुनियाभर के हजारों उच्चशिक्षित, पेशेवर और धनकुबेर ओशो के चरणों में पड़े रहते थे, मेरे छोड़ते ही तिलस्म खत्म हो गया। अमेरिकी सरकार की भूमिका पर शीला ने कहा, अमेरिका को ओशो ने ही इसका मौका दिया। अमेरिकी सरकार नहीं चाहती थी कि हमारा वर्चस्व और बढ़े। उसने लोगों को भड़काया। लेकिन मैंने उनका सामना किया।

शीला ने ओशो और अपने रिश्ते के बारे में स्पष्ट किया कि वह रिश्ता न तो गुरु और शिष्या की तरह का था और ना ही उसमें कुछ भी गलत था। मेरे पिता ओशो के करीब थे। तब मैं 16 साल की थी, जब ओशो मेरे घर आए और मैं उनसे मिली। उनके सम्मोहन में मैं अमेरिका तक जा पहुंची। मैं उनके प्रेम में पागल हो चुकी थी। लेकिन प्रेम के रिश्ते की बुनियाद न तो अध्यात्म था और ना ही सेक्स। यह तो कुछ और ही था...। कहा- ओशो की महत्वाकांक्षाओं और सपनों को मैं यथार्थ में परिणत करती गई। वह अपना काम करते थे और मैं अपना। जब उन्होंने मुझे वहां से निकाला, तो जन्नत को वीरान होते समय नहीं लगा। दिलचस्प यह कि स्विटजरलैंड के बेसल स्थित आवास की दीवारों पर शीला ने अब भी ओशो की तस्वीरें सजा रखी हैं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/jagran-special

सांसद-विधायक और मंत्री भी पहनेंगे कादीपुर की चप्पल

मिली ख्याति ▸ 'मन की बात' में जिक्र होने के बाद बढ़ी मांग

नौ हजार का एक ही दिन में मिला आर्डर, एक हजार विकास भवन के अफसर व कर्मचारियों ने मंगाए

ज्ञानेन्द्र सिंह, प्रयागराज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' कार्यक्रम में फूलपुर के कादीपुर गांव के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के कार्य की सराहना क्या की, समूह की तो मानो चांदी हो गई। यह समूह चप्पल बनाता है और अब मंत्री, सांसद और विधायक भी समूह की चप्पलें पहनेंगे। इतना ही नहीं, प्रोत्साहन के लिए जिले के बड़े अफसर भी समूह की ही चप्पल पहनेंगे। बात इससे भी आगे पहुंच गई है। कई बड़े समूहों, विभागों और निजी कंपनियों ने अपने स्टॉफ के लिए इन चप्पलों को खरीदने के लिए आर्डर दिए हैं। कादीपुर गांव की महिलाओं के जज्बात और जज्बे ने उन्हें देशभर में सुर्खियों में ला दिया। यहां की महिलाओं ने 'ज्वाला प्रेरणा ग्राम संगठन' नामक महिला स्वयं सहायता समूह बनाया। समूह ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन की सहायता से चप्पल बनाने का प्लांट लगाया। कुछ दिन तो चप्पलों की बिक्री कम थी, मगर मिशन ने प्रोत्साहित किया तो महिलाओं ने बाजार पकड़ना शुरू किया। कुछ माह बाद उनकी मेहनत ने रंग लाना शुरू किया। पुलिसकर्मियों से लेकर आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, स्वच्छाग्रहियों, छात्राओं ने चप्पलें खरीदनी शुरू कीं। देखते ही देखते चप्पलों की मांग बढ़ने लगी।

महिलाओं की जीवटता पीएम तक पहुंची : दैनिक जागरण ने इसी साल 19 नवंबर के अंक में इस समूह के कार्य को लेकर समाचार प्रकाशित किया तो समूह की महिलाओं की जीवटता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में उल्लेख कर पूरे देश में उनका सम्मान बढ़ा दिया। इसी के साथ समूह के कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि अब इस समूह की चप्पल कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, फूलपुर की सांसद केसरी देवी, शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेई, फूलपुर के विधायक प्रवीण पटेल, पूर्व विधायक दीपक पटेल, पूर्व विधायक गुरु प्रसाद मौर्य आदि भी पहनेंगे।

समूह की अध्यक्ष पल्लवी परमार और सचिव अनीता देवी ने बताया कि रविवार से लेकर सोमवार की शाम तक नौ हजार से ज्यादा चप्पलों के आर्डर मिल गए हैं।

नेपाल की धरोहरों के संरक्षण का खाका तैयार करेगा इंटेक

डॉ. राकेश राय, गोरखपुर

2015 में भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गई थीं नेपाल की 11 पुरातात्विक धरोहरें

- इंटेक के गोरखपुर चैप्टर को सौंपी गई है खाका तैयार करने की जिम्मेदारी

चार साल पहले आए भूकंप से क्षतिग्रस्त नेपाल की धरोहरों के पुनर्निर्माण और संरक्षण का प्रारूप इंटेक (इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज) तैयार करेगा। नेपाल के भारतीय दूतावास में इसको लेकर दूतावास और इंटेक के बीच करार हुआ है। नेपाल के चार जिलों में 11 धरोहरों के संरक्षण का खाका तैयार करने की जिम्मेदारी इंटेक ने गोरखपुर अध्याय (चैप्टर) को सौंपी है। अध्याय की टीम ने तैयारी शुरू कर दी है।

11 दिसंबर को काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में संरक्षण को लेकर तैयार करारनामे पर भारत की ओर से भारतीय मिशन दूतावास के उप प्रमुख अजय कुमार और इंटेक के राष्ट्रीय सचिव सीटी मिश्रा ने हस्ताक्षर किया। करारनामा नेपाल में भारत के राजदूत मनजीव सिंह पुरी और नेपाल के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के संयुक्त सचिव गोपाल प्रसाद अर्याल की मौजूदगी में हुआ। इंटेक के गोरखपुर अध्याय के पदाधिकारियों ने बताया कि करार के तहत उनकी संस्था नेपाल के काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर और सोलखुंभू में सांस्कृतिक विरासत वाले स्थलों के पुननिर्माण के लिए डिजाइन और परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं देगी। ये स्थल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए थे। इंटेक यह कार्य नेपाल के संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य करेगा।

> इंटेक ने नेपाल के 11 पुरातात्विक धरोहरों के पुनर्निर्माण और संरक्षण को लेकर परामर्श देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। गोरखपुर अध्याय को सर्वे करके प्रारंभिक खाका तैयार करने को कहा गया है। इस क्रम में धरोहर स्थलों की सूची मांगी गई है। सूची मिलते ही करार के मानक पर नेपाल के पुरातात्विक विभाग से मिलकर सर्वे का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
>
> **-ई. महावीर प्रसाद कंडोई, संयोजक इंटेक**

आज 104 साल की हो जाएंगी ब्रह्माकुमारी की दादी जानकी

जागरण संवाददाता, जयपुर

दादी जानकी। फाइल

- विश्वविद्यालय की हैं मुख्य प्रशासिका, 100 देशों में दे चुकी हैं संदेश
- प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का बनाया है ब्रांड एंबेसडर

140 देशों में फैले प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी मंगलवार को 104 वर्ष की हो जाएंगी। एक साल में 72 हजार किलोमीटर की यात्रा कर चुकी दादी जानकी ने 100 देशों में अकेले ही राजयोग का संदेश पहुंचाया।

वर्ष 1916 में जन्मी दादी जानकी 21 साल की उम्र में संस्थान से जुड़ी थीं। मात्र चौथी कक्षा पास दादी जानकी 2007 में विवि की मुख्य प्रशासिका बनी थीं। उनके संस्थान से दुनिया के 20 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। ब्रह्माकुमारी विश्व की एकमात्र ऐसी संस्था है, जो नारी शक्ति द्वारा संचालित है।

संस्थान के प्रवक्ता बीके कोमल ने बताया कि दादी जानकी अब भी सुबह चार बजे उठ जाती हैं। राजयोग मेडिटेशन के साथ आध्यात्मिक मूल्यों का मंथन, लोगों से मिलना-जुलना आदि अपने तय समय पर ही करती हैं। उनकी यह दिनचर्या रात 10 बजे तक चलती है । ब्रह्माकुमारी की पूरे विश्व में साफ-सफाई और स्वच्छता को लेकर विशेष पहचान रही है। देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादी जानकी को स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एंबेसडर भी नियुक्त किया है। दादी जानकी के नेतृत्व में संस्थान के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में हर वर्ष राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसमें दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

लाखों की दमकल गाड़ी बनी कबाड़

हरियाणा राज्य के यमुनानगर में चुहड़पुर कला स्थित हर्बल पार्क में खड़ी दमकल गाड़ी की यह तस्वीर लापरवाही और सरकारी धन की बर्बादी का जीता-जागता उदाहरण है। हर्बल पार्क में आग बुझाने के लिए लाखों रुपये खर्च करके खरीदी गई यह गाड़ी कबाड़ में तब्दील चुकी है। इसके आसपास पेड़-पौधे उग आए हैं। कोई नहीं जानता इसकी जवाबदेही किसकी है। 184 एकड़ में बने हर्बल पार्क का उद्घाटन 19 अप्रैल 2003 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजी अब्दुल कलाम ने किया था। यहां 350 से भी अधिक जड़ी-बूटियों के पौधे मौजूद हैं। पोपीन पंवार

अरे वाह! 'बैग' में बिकेगी चाय

विक्सन सिक्रोड़िया, कानपुर

- चार छात्रों ने बनाया सस्ता और हल्का फ्रंट पैक टी-बैग
- लैपटॉप बैग की तरह आगे लटकाकर एक हाथ से कर लेंगे सारे काम

टी-बैग में चाय की पत्ती तो सभी देखते हैं, लेकिन अब बैग में गरमागरम चाय भी दिखेगी। यह कमाल है, आइआइटी से इंजीनियरिंग कर चुके चार छात्रों का। उन्होंने ट्रेन में स्टील या पीतल के भारी भरकम टी-कंटेनर लेकर चल रहे वेंडर को चाय बेचने में आने वाली दिक्कत और यात्रियों को होने वाली परेशानी देखते हुए स्मार्ट टी कंटेनर बना दिया। इस स्मार्ट टी कंटेनर को लैपटॉप बैग की तरह लटकाकर वेंडर आसानी से चाय निकाल और सर्व कर सकते हैं।

आइआइटी के पूर्व छात्र अलकेश सिन्हा, अश्विनी रॉय, कार्तिक और आशीष मोहनदास ने इस 'फ्रंट पैक बैग' को ह्यूमेनिटीज एंड सोशल साइंस विभाग के प्रो. सात्यकि रे व इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग के प्रो. दीपू फिलिप के निर्देशन में तैयार किया। इसे बनाने से पहले छात्रों ने ट्रेन में चाय व कॉफी बेचने में आने वाली समस्याओं को भी जाना। आगे लटकाने वाले इस फ्रंट पैक बैग का वजन महज ढाई किलो है। इसमें छह लीटर चाय या कॉफी भरी जा सकती है, जो छह घंटे तक गर्म रहेगी। फ्रंट बैक के अंदर स्टेनलेस स्टील की लेयर है। बाहरी हिस्से पर इंसुलेटिंग मैटीरियल पॉलीपबलीन की कोटिंग की गई है, जिससे चाय की गर्माहट बाहर नहीं निकलती।

एक हाथ से हो जाएंगे सारे काम : कानपुर आइआइटी से मास्टर इन डिजाइन करने वाले आशीष मोहनदास बताते हैं कि इस फ्रंट पैक बैग के कारण, गिलास व चाय निकालना, सर्व करना जैसे सभी काम एक हाथ से ही हो जाएंगे। पैक के साइड में पेपर गिलास को स्लाइड स्टाइल में रखने की जगह है। एक गिलास निकालने पर दूसरा अपने आप वहां आ जाएगा। टोटी की जगह प्रेस बटन है, जिसे दबाने पर चाय या कॉफी निकलेगी। इस बैग से चाय सर्व करने के बाद यात्रियों और वेंडरों का फीडबैक लिया। सभी ने इसे बेहद आसान और सुविधाजनक बताया। तब इसे तैयार किया गया। एक वर्ष के शोध में तैयार इस टी-कंटेनर का पेटेंट फाइल हो गया है। जल्द ही इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा। इसकी कीमत स्टील या पीतल के ब्रांडेड टी कंटेनर के मुकाबले आधी हो होगी।

नारियल के रेशों से बना जाल दोगुनी कर देगा सड़क की उम्र

मिलेगी मजबूती

केंद्र सरकार के कॉयर बोर्ड ने रिसर्च के बाद तैयार किया जियो टैक्सटाइल, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सड़क निर्माण एजेंसियों को इस्तेमाल करने की दी हिदायत

मनीष शर्मा, जालंधर

नारियल के जिस छिलके को हम बेकार समझकर जला देते हैं, उसके रेशों से बना जाल सड़कों की उम्र दोगुनी कर देता है। यह साबित हुआ है केंद्र सरकार के कॉयर बोर्ड मंत्रालय की रिसर्च में। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन आते बोर्ड ने नारियल के रेशों से बने जाल के व्यवसायिक उत्पादन के लिए उद्योगपतियों को दे दिया है।

केरल में इसका उत्पादन शुरू हो गया है। इसके इस्तेमाल की शुरुआत कम भारी वाहनों वाली गांव की सड़कों से करने की तैयारी है। इस संबंध में कुछ माह पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण वाली केंद्रीय एजेंसियों से बैठक भी की है। यह जानकारी कॉयर बोर्ड के जोनल डायरेक्टर जेके शुक्ला ने दी।

यहां देशभगत यादगार हाल में संपन्न हुई हैंडीक्रॉफ्ट एक्सपो में पहुंचे जेके शुक्ला ने कहा कि अभी सड़क बनाने में मिट्टी के ऊपर डामर और फिर प्रीमिक्स बिछा दिया जाता है। जब गाड़ी चलती है तो भार से सड़क पर जोर पड़ता है और वो बाहर की तरफ खिसक जाती है, जिससे उसमें गड्ढा पड़ जाता है। सड़क जल्दी टूट जाती है। अगर मिट्टी के ऊपर यह जियो टैक्सटाइल यानि जाल बिछा दें तो वो मिट्टी व डामर की पकड़ को मजबूत रखेगा और भार को भी संतुलित करेगी। इससे सड़कों की उम्र दोगुनी हो जाएगी। अब इसे सड़क निर्माण एजेंसियों की कुछ चिंताओं के मद्देनजर फिर से रिसर्च टीम को दिया जा रहा है। उम्मीद है उसके बाद इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा।

.. तो पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे

कॉयर बोर्ड की तरफ से कॉयरवुड यानि लकड़ी भी बनाई गई है। नारियल के रेशों से बनी इस लकड़ी पर दीमक नहीं लगती। दूसरी लकड़ियों की तरह यह पानी पड़ने से खराब नहीं होती। अगर यह खराब हो जाए तो भी उसे मिट्टी में डालने पर वह वहीं नष्ट हो जाती है। अभी दरवाजे, खिड़की व अन्य फर्नीचर और दूसरी जिन चीजों को बनाने में लकड़ी इस्तेमाल होती है, उसमें यह काम आ सकती है। जोनल डायरेक्टर जेके शुक्ला कहते हैं कि अगर लोग इसका इस्तेमाल करें तो हमें पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सड़क बनाने में इस्तेमाल होने वाली जियो टैक्सटाइल दिखाते कॉयर बोर्ड के जोनल डायरेक्टर जेके शुक्ला (दाएं) और कॉयर बोर्ड चंडीगढ़ की मैनेजर मनजीत कौर (बाएं)। जागरण

मंदी में दोगुना निर्यात, घरेलू मार्केट में मांग कम

जोनल डायरेक्टर जेके शुक्ला ने कहा कि बाकी चीजों के कारोबार में भले ही मंदी की बात कही जा रही हो लेकिन नारियल के रेशों से बने लगभग 60 उत्पादों का निर्यात पिछले वित्त वर्ष में दोगुना हुआ है। 2018-19 में कारोबार 2600 करोड़ पहुंचा, जिसके 2019-20 में तीन हजार करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। हॉलैंड के अलावा अमेरिका, यूरोप व रूस में इनका खूब इस्तेमाल होता है क्योंकि वहां के लोग पर्यावरण संरक्षण को तरजीह देते हुए प्लास्टिक की जगह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में इसका सालाना बाजार दस हजार करोड़ का है, जिसे बढ़ा 50 हजार करोड़ करने की कोशिश है। देश में जागरूकता की कमी के चलते इनका इस्तेमाल थोड़ा कम है।

बुरादा बना खाद, हॉलैंड हुआ मुरीद

नारियल को छीलते वक्त उससे रेशों के साथ कुछ बुरादा निकलता है। अमूमन इसे लोग जला देते हैं, लेकिन कॉयर बोर्ड ने इसे खाद जैसी मिट्टी का रूप दे दिया है। इसमें कोई पौधा लगाने पर उसका विकास दोगुना होता है। फल या सब्जी वाला पौधा हो तो वो दोगुना उत्पादन देता है। बागवानी के लिए मशहूर हॉलैंड के एम्सटर्डम में इसकी खासी मांग है।

नववर्ष में शिफ्ट होगी ताज की टिकट विंडो

जासं, आगरा : ताजमहल की पश्चिमी गेट स्थित टिकट विंडो नववर्ष में ही शिफ्ट हो सकेगी। इन दिनों टिकट विंडो को शिफ्ट किए जाने का काम किया जा रहा है। टिकट काउंटर बन गए हैं, लेकिन लीज लाइन शिफ्टिंग, सर्वर केबिल समेत अन्य काम अभी किए जाने हैं। इनमें अभी समय लग सकता है।

ताज पश्चिमी गेट पर टिकट विंडो सती उन्निसा के मकबरे (सहेली बुर्ज) में संचालित है। इसके नजदीक ही टर्न सिस्टम गेट लगे हुए हैं। यहां केवल छह टिकट काउंटर हैं। वीकेंड व छुट्टियों में भीड़ उमड़ने पर यहां लंबी लाइनें लग जाती हैं। इससे पर्यटकों को टिकट प्राप्त करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके चलते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) टिकट विंडो को फतेहपुरी मस्जिद में शिफ्ट कर रहा है। यहां वर्ष के अंत तक टिकट विंडो शिफ्ट होने की उम्मीद थी, लेकिन यहां केवल टिकट काउंटर बन सके हैं। एएसआइ ने यहां पर 14 टिकट काउंटर बनाए हैं। टिकट विंडो शिफ्ट होने से पर्यटकों की परेशानी दूर होगी।

पैन और आधार की लिंकिंग अब 31 मार्च तक

नई दिल्ली : सीबीडीटी ने पैन और आधार की अनिवार्य लिंकिंग की 31 दिसंबर की वर्तमान समय-सीमा बढ़ा दी है। अब परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) और आधार को मार्च, 2020 तक लिंक किया जा सकेगा। गौरतलब है कि पैन और आधार को जोड़ने की समय-सीमा पहले भी सात बार बढ़ाई जा चुकी है। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार को संविधान सम्मत ठहराए जाने के बाद सरकार की आधार योजना पर मुहर लग गई थी। (प्रेट्र)

अगले वर्ष टाटा ग्रुप के सामने कई चुनौतियां हैं। लेकिन ग्रुप ज्यादा जीवंतता के साथ भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है।
— एन. चंद्रशेखरन
चेयरमैन, टाटा संस

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)
41,558 ▼ 17.14	12,255.85 ▲ 10.05	₹ 39,882 ▼ ₹73	₹ 47,910 ▼ ₹156	₹71.31 ▼ ₹0.04	$ 68.80

सतर्कता ▸ राजकोषीय घाटे की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए खर्च की नई सीमा तय

खजाने पर दबाव के चलते सरकार घटाएगी खर्च

मंत्रालयों को नए नियमों के मुताबिक खर्च करने का निर्देश दिया गया है

नितिन प्रधान, नई दिल्ली

रेवेन्यू कलेक्शन की धीमी रफ्तार के बाद खजाने पर बन रहे दबाव ने सरकार को व्यय नीति में बदलाव करने को बाध्य कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों के लिए चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में खर्च की नई सीमा तय की है। इसके तहत मंत्रालय चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2020) में बजट अनुमान का केवल 25 परसेंट ही खर्च कर पाएंगे। अभी तक खर्च की सीमा 33 परसेंट थी।

वित्त मंत्रालय के बजट डिवीजन की तरफ से जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम में खर्च की सीमा के दोबारा निर्धारण का पूरा खाका जारी किया गया है। इसके मुताबिक वित्त वर्ष के आखिरी महीने यानी मार्च 2020 में बजट अनुमान का केवल 10 परसेंट ही खर्च किया जा सकेगा। वर्तमान में इसके लिए 15 परसेंट की सीमा तय है। इसी तरह जनवरी और फरवरी, 2020 के लिए पुरानी 18 परसेंट की सीमा को घटाकर 15 परसेंट कर दिया है।

प्रतीकात्मक

मेमोरेंडम में चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में खर्च बारे में अन्य दिशानिर्देश भी दिए गए हैं। मसलन, यदि खर्च की नई सीमाओं के मुताबिक बजट अनुमान के मुकाबले संशोधित अनुमान तय किया जाता है तो मंत्रालयों को वित्त वर्ष के आखिरी महीने में उस संशोधित अनुमान का ही 10 परसेंट खर्च करना होगा, न कि बजट अनुमानों का। यदि अनुदान के जरिये बचत को पुनः आवंटित किया जाता है तो उसे भी अनुदान की पूरक मांगों के जरिये संसद से पारित कराने के बाद ही खर्च किया जा सकेगा। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को नए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

गौरतलब है कि व्यय संबंधी दिशानिर्देशों में बदलाव इससे पहले साल 2017 में किया गया था। उस वर्ष आखिरी तिमाही के लिए बजट अनुमान का 33 परसेंट और वित्त वर्ष के आखिरी महीने में 15 परसेंट की व्यय सीमा निर्धारित की गई थी।

व्यय सीमा में यह बदलाव ऐसे वक्त में किया गया है जब राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष के पहले सात महीने (अप्रैल-अक्टूबर) में ही बजट अनुमानों से ऊपर चला गया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ एकाउंट्स (सीजीए) के आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में राजकोषीय घाटा 7.20 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह 7.03 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमानों का 102.4 परसेंट है। बजट में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3 परसेंट पर रखने का लक्ष्य तय किया गया था।

दरअसल सरकार को चालू वित्त वर्ष में टैक्स और नॉन -टैक्स, दोनों मोर्चे पर रेवेन्यू के कलेक्शन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वित्त वर्ष के शुरुआती आठ महीने (अप्रैल से नवंबर) में प्रत्यक्ष कर संग्रह महज 5.56 लाख करोड़ रुपये रहा है। हालांकि यह पिछले साल की इसी अवधि के 5.47 लाख करोड़ रुपये से कुछ अधिक है। लेकिन 13.35 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले इसकी वृद्धि दर कम है। जहां तक जीएसटी कलेक्शन का प्रश्न है इस अवधि में सरकार को 3.98 लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। जबकि पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर की अवधि में कलेक्शन 5.82 लाख करोड़ रुपये रहा था। चालू वित्त वर्ष के लिए इस मद में 6.63 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया है।

यहां तक कि नॉन-टैक्स कलेक्शन के मद में विनिवेश के नतीजे बहुत उत्साहजनक नहीं रहे हैं। अभी तक विनिवेश से 17,364.26 करोड़ रुपये ही जुटाए जा सके हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए विनिवेश के माध्यम से 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष की शेष अवधि में बीपीसीएल, एयर इंडिया और दो बिजली कंपनियों को एनटीपीसी को बेचने की योजना है। लेकिन बीपीसीएल और एयर इंडिया के विनिवेश पर अभी भी कई सवाल हैं।

बजट में स्टार्ट-अप्स को टैक्स प्रोत्साहन संभव

नई दिल्ली, प्रेट्र : रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार आगामी बजट में स्टार्ट-अप कंपनियों को टैक्स प्रोत्साहन दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक उद्योग एवं आंतरिक कारोबार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) ने आगामी बजट के लिए स्टार्ट-अप्स से संबंधित कई सुझाव दिए हैं। इनमें अटल इनोवेशन मिशन के तहत आने वाले इंक्यूबेटर्स को टैक्स प्रोत्साहन, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (एआइएफ) मैनेजमेंट के लिए जीएसटी में कटौती और इंप्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्रोग्राम (ईएसओपी) पर टैक्स लाभ जैसे सुझाव शामिल हैं।

प्रतीकात्मक

- डीपीआइआइटी ने इन उभरती कंपनियों के संबंध में वित्त मंत्रालय को दिए सुझाव
- स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है

जानकारों के मुताबिक स्टार्ट-अप्स को प्रतिभावान लोगों की जरूरत होती है और कंपनी में शेयरधारिता देकर ऐसे लोगों को आसानी से आकर्षित किया जा सकता है। स्टार्ट-अप्स द्वारा कर्मचारियों को अधिक वेतन देने से उनका बोझ क्षमता से अधिक बढ़ जाता है, जिससे उनकी सफलता की संभावनाएं कमजोर होती है। चायोस के संस्थापक नितिन सलूजा ने कहा कि ईएसओपी के मामले में टैक्स छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टार्ट-अप्स के लिए ईएसओपी एक बेहतर विकल्प है। ईएसओपी, कंपनी द्वारा स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली योजना है। इसके तहत कंपनी अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन की जगह कंपनी में हिस्सेदारी देती है।

देश में स्थित एआइएफ फंड मैनेजर पर 18 परसेंट जीएसटी देय होता है, इसे घटाने की मांग की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी दरों में कटौती से देश को इन्वेस्टमेंट हब बनाने में मदद मिलेगी। स्टार्ट-अप इंडिया के जरिये सरकार देश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश कर रही है।

स्टार्ट-अप इंडिया एक्शन प्लान के तहत 19 कंपोनेंट को शामिल किया गया है। इनमें फंड में सहायता और प्रोत्साहन देना, उद्योग और अकादमी की भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे कंपोनेंट शामिल हैं। अभी तक सरकार ने 26,619 स्टार्ट-अप्स की पहचान की है। इनमें से अधिकतर आइटी सेवाओं के क्षेत्र में हैं। इसके अलावा हेल्थकेयर, लाइफ साइंसेज और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी संख्या में स्टार्ट-अप्स सक्रिय हैं।

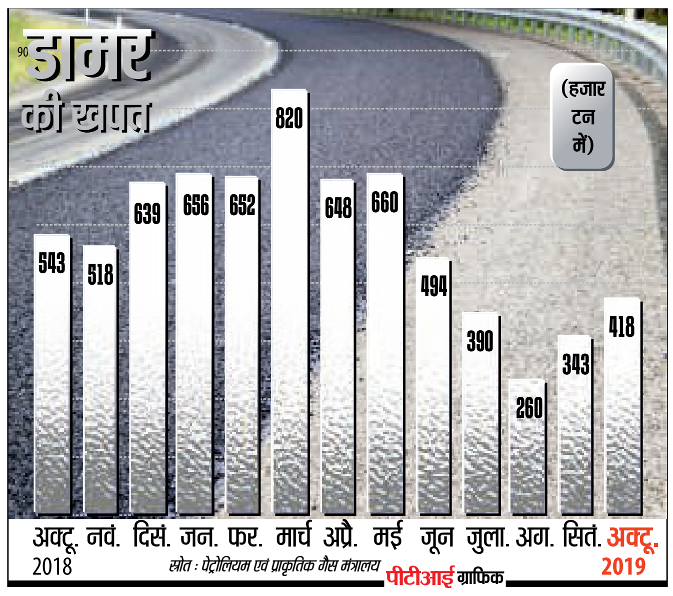

स्रोत : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय पीटीआई ग्राफिक

न्यूज गैलरी

डीएचएफएल के रिजॉल्यूशन प्लान पर हुई चर्चा

मुंबई : डीएचएफएल की रिजॉल्यूशन प्रक्रिया के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। कर्ज संकट से जूझ रही इस कंपनी के लिए आरबीआइ द्वारा नियुक्त प्रशासक और कंपनी के कर्जदाताओं ने इसके रिजॉल्यूशन प्लान पर बातचीत करने के लिए सोमवार को बैठक आयोजित की। इस दौरान डीएचएफएल पर इसके कर्जदाताओं, कर्मचारियों और अन्य साझेदारों द्वारा किए गए 87,905.6 करोड़ रुपये के दावों पर चर्चा हुई। दो दिसंबर को इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू होने के बाद कंपनी के प्रशासक आर. सुब्रमन्यकुमार की इसके कर्जदाताओं के साथ यह पहली बैठक थी। कंपनी पर एसबीआइ सहित कई बड़े बैंकों का कर्ज है। इसके कुल कर्ज में एसबीआइ की हिस्सेदारी 10,082.90 करोड़ रुपये है। (प्रेट्र)

गैर-जरूरी उत्पादों के लिए आयात नियम बनाने की तैयारी

नई दिल्ली : सरकार गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात को कम करने के लिए सरकार नियम लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 350 से अधिक उत्पादों के आयात नियमन की तैयारी चल रही है। इसमें इन उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता मानक भी शामिल किए हैं। इसके लिए इसी महीने एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें संबंधित मामलों के मंत्रालयों ने भाग लिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस नियमन के अंतर्गत करीब पांच हजार उत्पादों को लाने की योजना है। लेकिन फिलहाल 371 उत्पादों को केंद्र में रखकर इस योजना पर चर्चा हो रही है। (प्रेट्र)

खरीदार नहीं मिला तो छह महीने में बंद होगी एयर इंडिया

मुंबई : संकट से जूझ रही सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया को खरीदार नहीं मिलने पर छह महीनों के भीतर बंद करना पड़ सकता है। कंपनी के एक उच्च अधिकारी के मुताबिक इसके परिचालन संबंधी कार्यों के लिए फंड जुटाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कंपनी छह महीनों से अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगी। कर्मचारी का कहना था कि अब टुकड़ों में कोई भी मदद एयर इंडिया को बचाने में नाकाम साबित होगी। 60,000 करोड़ रुपये के कर्ज से जूझ रही इस कंपनी को बेचने की तैयारी चल रही है। एयर इंडिया को बचाने और बेचने का सरकार का पिछला प्रयास भी विफल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2011-12 से लेकर इस वर्ष दिसंबर तक सरकार इसे 30,520.21 करोड़ रुपये का फंड दे चुकी है। (प्रेट्र)

एसबीआइ ने लोन ग्राहकों को दिया नए साल का तोहफा, ब्याज दरें घटाईं

- एमएसएमई और होम लोन ग्राहकों के लिए ब्याज दरें चौथाई फीसद घटाईं
- नए घर खरीदारों को अब 7.90 परसेंट सालाना की दर से ही देना होगा ब्याज

मुंबई, प्रेट्र : भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने खुदरा लोन समेत एमएसएमई सेक्टर के ग्राहकों को नए साल का तोहफा दिया है। देश के इस सबसे बड़े कर्जदाता ने एक्सटर्नल बेंचमार्क-बेस्ड रेट (ईबीआर) को 8.05 परसेंट से घटाकर 7.80 परसेंट प्रतिवर्ष कर दिया है। नई ब्याज दरें बुधवार से प्रभावी होंगी। बैंक ने बताया कि नए घर खरीदारों को अब 8.15 परसेंट की जगह सिर्फ 7.90 परसेंट सालाना की दर से ब्याज देना होगा।

एसबीआइ द्वारा ब्याज दरों में इस कटौती से उन ग्राहकों को फायदा मिलेगा, जिन्होंने फ्लोटिंग रेट की शर्तों पर लोन लिया है। एमएसएमई सेक्टर को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। एसएमई सेक्टर के लिए यह राहत इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेक्टर को पूंजीगत दबाव से उबारने के लिए सरकार विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रही है।

एसबीआइ ने होम लोन के लिए फ्लोटिंग रेट इस वर्ष जुलाई से शुरू किया था और अक्टूबर से फ्लोटिंग रेट तय करने के लिए रेपो-रेट को एक्सटर्नल बेंचमार्क के रूप में चुना था। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने सभी बैंकों को निर्देश दिया था कि वे अपने होम, रिटेल और एमएसएमई सेक्टर को दिए जाने लोन एक्सटर्नल-बेंचमार्क से जोड़ें। आरबीआइ द्वारा रेपो-रेट में कटौती का फायदा बैंकों द्वारा ग्राहकों को नहीं देने के चलते केंद्रीय बैंक ने यह निर्देश जारी किए थे।

बैंक ने होम लोन पर फ्लोटिंग रेट जुलाई में शुरू किया था। प्रतीकात्मक

इंडियन बैंक ने की एमसीएलआर में कटौती

चेन्नई, प्रेट्र : इंडियन बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स (एमसीएलआर) में कटौती करने की घोषणा की है। बैंक ने शेयर बाजारों को बताया कि नई ब्याज दरें तीन जनवरी से प्रभाव में आएंगी। एक दिन के लोन पर नई एमसीएलआर दर 7.90 परसेंट होगी, जो इस समय 7.95 परसेंट है। इसके अलावा एक महीने की अवधि वाले लोन पर ये ब्याज दर 8.05 परसेंट, तीन महीने वाले लोन पर 8.15 परसेंट, छह महीने वाले लोन पर 8.20 परसेंट और एक वर्ष की अवधि वाले लोन पर 8.30 परसेंट की दर से ब्याज देय होगा।

निर्यातकों को 1.12 लाख करोड़ का आइजीएसटी रिफंड का भुगतान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने कहा है कि निर्यातकों को अब तक 1.12 लाख करोड़ रुपये के आइजीएसटी रिफंड का भुगतान किया जा चुका है। इसका लाभ 83,500 निर्यातकों को मिला है। अब निर्यातकों का सीमा शुल्क विभाग के पास 3,604 करोड़ रुपये का रिफंड बकाया है। सीबीआइसी के एक बयान के मुताबिक कुल 1,85,000 निर्यातकों में से केवल 6,421 निर्यातकों की पहचान ही रिस्की एक्सपोर्टर के तौर पर की गई है। यह कुल निर्यातकों का केवल 3.4 परसेंट है। हालांकि इनमें कुछ स्टार एक्सपोर्टर भी शामिल हैं। सीबीआइसी का कहना है कि कुछ स्टार एक्सपोर्टर अपने निर्धारित पते पर भी नहीं मिले हैं। जिन निर्यातकों को टैक्स अधिकारी नहीं तलाश पाए हैं उनकी संख्या 1,241 है। इनमें आठ स्टार एक्सपोर्टर हैं। साथ ही 399 निर्यातकों के खिलाफ सत्यापन संबंधी विपरीत रिपोर्ट मिली है।

बद्दी में फर्जी जीएसटी नंबर से 107 करोड़ रुपये का घोटाला

संवाद सहयोगी, बद्दी

- पंजाब निवासी आरोपित ने हिमाचल के उद्योगों को बेचा माल
- विभाग ने समय रहते वसूल किया 19 करोड़ का टैक्स

सोलन जिले के बद्दी में फर्जी जीएसटी नंबर के जरिये करोड़ों रुपये के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। विभिन्न कंपनियों के नाम पर करीब 107 करोड़ रुपये के टैक्स का घोटाला किया गया है। जीएसटी डायरेक्टरेट इंटेलीजेंस विभाग शिमला जोन ने सारे प्रकरण का भंडाफोड़ किया है। विभाग ने इसमें से 19.20 करोड़ रुपये की वसूली कर ली है।

जांच में सामने आया है कि पंजाब के एक व्यक्ति ने देश के अलग-अलग हिस्सों में कंपनियां बनाकर हिमाचल के उद्योगों को कच्चा माल बेच दिया। इन उद्योगों ने उसका रिफंड भी ले लिया, लेकिन कंप्यूटर में जब जीएसटी नंबरों का मिलान किया गया तो ये नंबर फर्जी निकले। डायरेक्टरेट ने आरोपितों पर सौ फीसद जुर्माना भी किया है। नाम न छापने की शर्त पर विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि आरोपित व्यापारी निवासी मंडी गोबिंदगढ़, पंजाब ने 12 अलग-अलग कंपनियां बनाई थीं। इसमें से छह का वह खुद डायरेक्टर था व छह किसी और नाम से चला रहा था। मामला जाहिर होने के बाद पता चला कि आरोपित ने 107 करोड़ रुपये के जाली बिल पंजाब, दिल्ली व हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग नाम से काटे। उसने हिमाचल के बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, पावंटा साहिब, कालाअंब व परवाणू में भी कंपनियों के कार्यालय दर्शाए थे। उन ठिकानों पर जब अधिकारी पहुंचे तो कोई कंपनी नहीं पाई गई। छानबीन पर कंपनी मालिक द्वारा काटे बिल फर्जी निकले। अधिकारियों ने कंपनी संचालक को हिरासत में लेकर 19.20 करोड़ रुपये का टैक्स वसूल कर किया है। इसे आरोपित व परिवार की निजी संपत्ति को कब्जे में लेकर वसूला गया है। जीएसटी में हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा मामला सामने आया है। बताया जाता है कि इस मास्टमाइंड ने जो बिलिंग की है उसमें से बद्दी, बरोटीवाला, झाड़माजरी व नालागढ़ के अधिकांश लोहा उद्योग हैं। जांच में अभी कई और लोगों के नाम सामने आने की बात कही गई है।

एक लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनेगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्याज के मौजूदा संकट जैसी स्थिति को भविष्य में टालने के लिए केंद्र सरकार ने अगले वर्ष एक लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया है। सरकार ने इस वर्ष के लिए 56,000 टन प्याज का बफर स्टॉक रखा था। लेकिन यह पर्याप्त साबित नहीं हुआ और पिछले लगभग दो महीनों से इसका भाव आम ग्राहकों की पहुंच से बाहर रहा है।

एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक मंत्रिसमूह की हाल ही में बैठक हुई थी। इसमें अगले वर्ष के लिए ज्यादा बफर स्टॉक रखने का फैसला किया गया। अधिकारी के मुताबिक को-ऑपरेटिव संस्था नैफेड को बफर स्टॉक तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। वह रबी सीजन के दौरान उत्पादित प्याज का मार्च से जुलाई के बीच किसानों से सीधे खरीद करेगी। इस सीजन के प्याज की शेल्फ लाइफ (खाने लायक स्थिति में होने वाली समय-अवधि) ज्यादा होती है। मानसून में देरी और बेमौसम बारिश के चलते इस वर्ष प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में प्याज की खेती, भंडारण और परिवहन पर बुरा असर पड़ा। इसके चलते इस वर्ष सितंबर से प्याज का भाव बढ़ने लगा था।

हुआवे को 5-जी ट्रायल की इजाजत देगी सरकार

- रवि शंकर प्रसाद ने कहा - ट्रायल के लिए सबको मिलेगा 5-जी स्पेक्ट्रम
- अमेरिका ने हुआवे को इजाजत नहीं देने का दुनियाभर से किया हुआ है आग्रह

नई दिल्ली, प्रेट्र : अमेरिका की सलाह को दरकिनार करते हुए भारत ने स्पष्ट किया है कि वह चीन की इक्विपमेंट निर्माता कंपनी हुआवे को 5-जी ट्रायल की अनुमति देगा। दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि सरकार हुआवे और अन्य टेलीकॉम इक्विपमेंट निर्माता समेत सभी टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों को 5-जी ट्रायल के लिए स्पेक्ट्रम मुहैया कराएगी। प्रसाद ने साफ किया कि भारत ने देश के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ट्रायल के लिए 5-जी स्पेक्ट्रम मुहैया कराने का फैसला किया है।

टेलीकॉम सेक्टर को लेकर हुए एक आयोजन के मौके पर प्रसाद का कहना था कि 5-जी का युग आ गया है। हमने सभी स्पर्धियों को ट्रायल के लिए 5-जी स्पेक्ट्रम मुहैया कराने का फैसला किया है। प्रसाद के इस बयान का सीधा मतलब यह है कि देश की टेलीकॉम कंपनियों को यह छूट दी गई है कि वे ट्रायल में जिस भी उपकरण निर्माता कंपनी के साथ गठजोड़ करना चाहती हैं, कर सकती हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने इस फैसले को अभी सैद्धांतिक मंजूरी दी है और टेलीकॉम विभाग इसके विभिन्न पहलुओं पर काम करेगा।

इससे भारत में 5-जी ट्रायल में शिरकत करने के लिए जी-तोड़ कोशिश कर रही हुआवे को निश्चित रूप से बड़ी राहत मिली है। हुआवे इंडिया के सीईओ जे चेन ने कहा कि कंपनी को यकीन है कि भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में नई जान फूंकने के लिए तकनीकी नवीनता और उच्च गुणवत्ता वाले नेटवर्क ही पैमाना होंगे। उन्होंने कहा कि हुआवे भारतीय बाजार को लेकर प्रतिबद्ध है।

अमेरिका ने 5-जी सेवा शुरू करने को तैयार देशों से आग्रह किया है कि वे चीन की हुआवे को इन गतिविधियों से दूर रखें। अमेरिका के मुताबिक हुआवे जासूसी करती है और सूचनाएं चीन की सरकार को मुहैया कराती है। अमेरिकी सरकार ने हुआवे को अपने देश में कारोबार से प्रतिबंधित किया हुआ है। लेकिन कई देशों ने अपनी टेलीकॉम कंपनियों को हुआवे के उपकरण का प्रयोग करने की छूट दी हुई है।

पशु चारे की कमी को पूरा करने पर जोर

प्रतीकात्मक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : देश में पशु चारे की भारी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय चारा नीति तैयार की है। इसके तहत घास के उन्नत बीज और टेक्नोलॉजी मुहैया कराई जाती है। डेयरी उद्यम के लिए यह नीति बहुत कारगर साबित हो सकती है। देश में पशु चारा वाली फसलों की खेती का रकबा केवल 5.23 फीसद है, जो बहुत कम है। इसे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को हर तरह की मदद मुहैया कराएगी।

देश में चार साल पहले 2015-16 के रबी सीजन में 1.02 फीसद यानी 3384 हेक्टेयर, खरीफ में 1.54 फीसद यानी 5113 हेक्टेयर और जायद सीजन में 0.78 फीसद रकबा यानी 2593 हेक्टेयर में चारे की फसल की खेती की गई थी। हरे चारे की उपलब्धता होने से दुधारू पशुओं में दूध की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों की ओर से उन्नत और हाइब्रिड प्रजाति का चारा बीज राज्यों को उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेयरी और पशुधन क्षेत्र सबसे अहम हो गया है। इसके लिए पर्याप्त पशु चारे की सख्त जरूरत है, जिसे पूरा करने को लेकर सरकार ने राष्ट्रीय चारा नीति तैयार की है। पौष्टिक हरे पशु चारे की उपलब्धता से डेयरी उत्पादकता में वृद्धि होती है। इस बारे में आइसीएआर के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्र ने बताया कि डेयरी सेक्टर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। हरे चारे की भारी कमी को पूरा करने के लिए साइलेज (प्रसंस्करित चारा) का बंदोबस्त करने की जरूरत है। चारा नीति को अब तक 10-12 राज्यों ने लागू कर अपनी नीति बनाई है।

सुस्त कारोबार

शेयर बाजार सेंसेक्स से दूर, निफ्टी के करीब रहे में निवेशक

सेंसेक्स गिरावट और निफ्टी बढ़त के साथ हुआ बंद, किसी बड़े आर्थिक संकेत के अभाव में दिशाहीन दिखे निवेशक

मुंबई, प्रेट्र : प्रमुख भारतीय शेयर बाजारों में सोमवार को निवेशकों का मिलाजुला रुख देखने को मिला। दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 17.14 अंकों की गिरावट के साथ 41,558 के स्तर पर थमा। वहीं, एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में 10.05 अंकों की तेजी देखी गई और यह 12,255.85 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबारी सत्र के दौरान काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

सेंसेक्स पैक में आइसीआइसीआइ बैंक के शेयरों में सबसे अधिक 0.99 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। एसबीआइ, टीसीएस, एचयूएल, एशियन पेंट्स और एक्सिस बैंक के शेयर भी गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं नेस्ले इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एयरटेल और टाटा स्टील के शेयरों में तेजी देखी गई।

बीएसई में सेक्टोरल इंडेक्स के मामले में आइटी, बैंक, फाइनेंस, टेक और ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स पर दबाव देखा गया। वहीं ऑटो, मेटल, टेलीकॉम इंडेक्स की कंपनियों के शेयर बढ़त दर्ज करने में सफल रहे। बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर के शेयरों में इस वर्ष दूसरी छमाही के दौरान कुछ ज्यादा ही अस्थिरता दिखी है। जानकारों के मुताबिक किसी बड़ी आर्थिक हलचल की अनुपस्थिति में शेयरों बाजारों में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। एशिया के अन्य बाजारों में भी निवेशक कुल मिलाकर दिशाहीन ही दिख रहे थे। इसलिए इन बाजारों में भी कुछ में गिरावट, तो कुछ में उछाल देखा गया। मिलाजुला रुख ही दिख रहा था।

प्रिंस पाइप्स के शेयरों में गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र : शेयर बाजारों में प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। सूचीबद्ध होने के बाद सोमवार को अपने पहले कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयरों को सात परसेंट तक की गिरावट का सामना करना पड़ा। बीएसई में कंपनी के शेयर 6.40 परसेंट की गिरावट के साथ 166.60 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। वहीं एनएसई में इनमें 7.30 परसेंट की कमी दर्ज की गई। यहां ये 165 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए। इस दौरान बीएसई में कंपनी के 20.37 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई। वहीं एनएसई में दो करोड़ शेयरों की ट्रेडिंग की गई।

प्रतीकात्मक

सोना-चांदी के भाव में नरमी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सोमवार को दिल्ली के प्रमुख सराफा बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान सोना 73 रुपये की गिरावट के साथ 39,882 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिका। वहीं चांदी भी 156 रुपये की गिरावट के साथ 47,910 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। जानकारों के मुताबिक घरेलू बाजारों में मांग में कमी और ग्लोबल मार्केट में सोने के भाव में नरमी का असर भारतीय सराफा बाजारों पर भी देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में सोना 1,513.50 डॉलर और चांदी 17.87 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) के हिसाब से बिके। इस वर्ष सोने के भाव में काफी अस्थिरता दिखी, जिसके अगले वर्ष जारी रहने की संभावना है। जानकारों का मानना है कि 2020 में पीली धातु 45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को छू सकती है। भू-राजनीतिक कारणों, आर्थिक चुनौतियों और डॉलर के मुकाबले रुपये में अस्थिरता को देखते हुए अगले वर्ष सोने के भाव में तेज उछाल देखा जा सकता है।

30 दिसंबर 2006 को बगदाद में फांसी दे दी गई सद्दाम हुसैन को अमेरिकी सैनिकों द्वारा एक बंकर से गिरफ्तार करने के बाद। सद्दाम पर आरोप था कि उन्होंने सैकड़ों शिया मुस्लिमों की हत्या करवाई और कुर्दों को भी नहीं बख्शा।

न्यूज गैलरी

तुर्की ने पकड़े इस्लामिक स्टेट के 100 आतंकवादी

इस्तांबुल : तुर्की के कई इलाकों में छापे के दौरान आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) के 100 सदस्य पकड़े गए हैं। तुर्की की सरकारी न्यूज एजेंसी के अनुसार, बीते कुछ दिनों में अंकारा, बरसा और बतमान प्रांतों में पुलिस की छापेमारी में बड़ी संख्या में आतंकी गतिविधियों में संलिप्त आइएस से जुड़े लोगों को पकड़ा गया है। इनमें 40 इराकी और 20 सीरियाई नागरिक हैं। तुर्की में पिछले हफ्ते भी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले भी इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कार्रवाई में कई आतंकियों को पकड़ा गया था। हालिया कार्रवाई के बाद तुर्की ने अपने यहां पकड़े गए आतंकियों को उनके मूल देश वापस भेजना शुरू किया है। गौरतलब है कि सीरिया में संघर्ष भड़कने के बाद पड़ोसी मुल्क तुर्की में शरणार्थियों के समूहों के साथ आतंकियों ने भी पनाह ले ली थी। इससे आशंका जताई जा रही है कि पहले भी आतंकियों ने इसी तरह की मदद खुद को छिपाने के लिए ली होगी। पिछले कुछ वर्षों से तुर्की भी आइएस के हमलों का शिकार रहा है। वर्ष 2017 में नए साल की पार्टी के दौरान इस्तांबुल के एक नाइट क्लब में आतंकियों के हमले में 39 लोग मारे गए थे। (एएफपी)

दक्षिण कोरिया में पांच हजार से ज्यादा लोगों को माफी

सियोल : दक्षिण कोरिया की सरकार ने विभिन्न मामलों में कानून का उल्लंघन करने वाले 5,147 लोगों को माफी देने का एलान किया है। मंगलवार से प्रभावी इस माफीनामे को दक्षिण कोरिया के न्याय मंत्रालय ने जारी कर दिया है। दक्षिण कोरियाई सरकार द्वारा क्षमा पाने वाले 5,147 लोगों में से 1,879 ऐसे युवक शामिल हैं जो देश में लागू अनिवार्य सैन्य सेवा ज्वाइन नहीं करने के कारण जेल की सजा काटने को बाध्य थे। अब सरकार ने इस कानून में ढिलाई के बाद इन युवकों को माफी देने की घोषणा की है। माफी पाने वाले लोगों में चुनाव से जुड़े कानून तोड़ने वाले 267 लोग, दो राजनेता और एक मजदूर कार्यकर्ता भी शामिल हैं। गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया में लागू कानून के तहत देश के प्रत्येक युवक को थलसेना में 21 माह के अलावा नौसेना में 23 माह या वायुसेना में 24 माह की सेवा देना अनिवार्य है। इस कानून का पालन नहीं करने पर 18 महीने की जेल की सजा का प्रावधान है। इन्हीं प्रावधानों के तहत इन युवाओं को सजा सुनाई गई थी। हालांकि, अब राष्ट्रपति मून जे इन की अगुआई वाली सरकार ने तीसरी बार सामूहिक माफी दी है। बता दें कि इससे पहले दक्षिण कोरिया की सरकार ने 2017 में छह हजार से ज्यादा और उसके बाद पिछले साल यानी 2018 के फरवरी में चार हजार से ज्यादा लोगों को माफी दी गई थी। (आइएएनएस)

भारत के साथ कालापानी पर बातचीत की तैयारी में जुटा है नेपाल

काठमांडू, प्रेट्र : भारत के साथ कालापानी सीमा मुद्दा सुलझाने के लिए नेपाल बातचीत की तारीख तय करने में जुटा है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने सोमवार को यह जानकारी दी। नेपाल ने भारत के अपडेट राजनीतिक मानचित्र पर आपत्ति जताई है। काठमांडू ने दावा किया है कि कालापानी और लिपुलेख क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में दिखाया गया है जबकि ये क्षेत्र नेपाल में हैं। भारत ने कहा है कि नया नक्शा उसके स्वायत्त क्षेत्र का सटीक चित्रण करता है। उसने किसी भी तरह से नेपाल के साथ अपनी सीमा को संशोधित नहीं किया है।

काठमांडू में विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री ग्यावाली ने कहा कि सीमा मुद्दा सुलझाने के लिए नेपाल सरकार वार्ता की तारीख तय करने में जुटी है। विदेश मंत्री ने दावा किया कि नेपाल ने भारत सरकार को 23 नवंबर को औपचारिक पत्र भेजा था। जवाब भेजकर भारत ने मुद्दे का समाधान करने में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि सीमा संबंधी समस्या के कारण भारत-नेपाल रिश्ते में प्रभावित हो रहे हैं।

चीन में डिजायनर बेबी के जन्म में शामिल तीन शोधकर्ताओं को जेल

- भ्रूण के जीन में बदलाव कर शिशुओं का कराया था जन्म
- चीन समेत दुनियाभर के वैज्ञानिकों ने की थी तीखी आलोचना

बीजिंग, एपी : चीन में डिजायनर बेबी के जन्म में शामिल तीन शोधकर्ताओं को चिकित्सा के क्षेत्र में अवैध तरीके से परीक्षण करने पर जेल की सजा सुनाई गई है। चीन में पिछले साल नवंबर में भ्रूण के जीन में बदलाव कर शिशुओं के जन्म का दावा किया गया था। इस तरीके से पैदा होने वाले ये पहले बच्चे बताए गए थे। इसकी चीन समेत दुनियाभर में खूब आलोचना हुई थी और इसे नैतिकता के खिलाफ बताया गया था।

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, इस विवादित परीक्षण के प्रमुख शोधकर्ता ही जियानकुई को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है। उन पर 30 लाख युआन (करीब तीन करोड़ रुपये) का जुर्माना भी लगाया गया है। इस शोध से जुड़े दो अन्य शोधकर्ताओं को कम सजा मिली है। झांग रेनली को दो साल और किन जिनझोउ को 18 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है। इन दोनों पर क्रमशः दस लाख युआन (करीब एक करोड़ रुपये) और पांच लाख युआन (करीब 50 लाख रुपये) का जुर्माना लगा है।

वैज्ञानिक हे जियानकुई।

वैज्ञानिक किन जिनझोउ। एपी

कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक, तीनों शोधकर्ता जीन परिवर्तित जुड़वां बहनों समेत तीन शिशुओं के जन्म में शामिल थे। इन शोधकर्ताओं ने प्रसिद्धि और फायदे के लिए ना सिर्फ चीनी नियमों बल्कि वैज्ञानिक और चिकित्सा शोध की नैतिकता का भी उल्लंघन किया। जियानकुइ ने अमेरिका में अध्ययन करने के बाद हांगकांग से सटे चीन के शेंझेन शहर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलाजी में अपनी लैब बनाई थी।

अपनाई गई थी यह तकनीक : जियानकुई ने जीन में बदलाव करने की तकनीक क्रिस्पर-केस9 का उपयोग किया था। उन्होंने दावा किया था कि जीन एडिटिंग तकनीक से शिशुओं को एचआइवी संक्रमण से बचाने में मदद मिल सकती है।

प्रोटेस्टेंट चर्च के पादरी को नौ साल कैद की सजा

- सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने का लगाया गया है आरोप
- अवैध व्यापार के संचालन का भी दोषी पाया गया, पिछले साल कार्रवाई हुई थी

बीजिंग, एजेंसियां : चीन में सोमवार को अनधिकृत प्रोटेस्टेंट चर्च के पादरी वांग यी को नौ साल जेल की सजा सुनाई गई। पादरी पर सरकार के खिलाफ आम लोगों को भड़काने का आरोप है। दक्षिण पश्चिम चीन के चेंगदू शहर की अदालत के फैसले के मुताबिक वांग को अवैध व्यापार संचालन का भी दोषी पाया गया है। पिछले साल भी वांग के रेन कान्वेंट चर्च पर कार्रवाई हुई थी। दिसंबर, 2018 में मारे गए छापे के दौरान वांग को हिरासत में ले लिया गया था जबकि उनके भूमिगत चर्च के दर्जनों सदस्य फरार हो गए थे।

कोर्ट के इस निर्णय पर चीन में एमनेस्टी इंटरनेशनल के शोधकर्ता पैट्रिक पून ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा, आज का फैसला चीन में कथित धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। वांग केवल अपने धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन कर रहे थे और देश में मानवाधिकार मूल्यों के लिए खड़े रहते थे। चीन का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन राष्ट्रपति शी चिनफिंग के सत्ता संभालने के बाद से स्थितियों में काफी परिवर्तन आया है। सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी को चुनौती देने वाले धर्मों पर प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है।

आधिकारिक तौर पर चीन की नास्तिक सरकार धार्मिक सहित अपने नियंत्रण से बाहर किसी भी संगठित आंदोलन पर हमेशा नजर बनाए रखने के साथ ही समय-समय पर उन पर कार्रवाई करती रहती है। चीन में पूरा ईसाई समुदाय दो हिस्सों में बंटा है। एक वे लोग हैं जो रेन कान्वेंट जैसे अनधिकृत चर्चों से जुड़े हैं और दूसरे वे हैं जो सरकार द्वारा स्वीकृत चर्चों में जाते हैं। खास बात यह है कि सरकार द्वारा स्वीकृत चर्चों में प्रार्थना के साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी के गीतों का नियमित गायन भी अनिवार्य है।

बाइबिल में पूरी श्रद्धा रखते हैं प्रोटेस्टेंट समुदाय के लोग

ईसाई धर्म में मुख्य रूप से तीन समुदाय हैं। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। कैथोलिक समुदाय में पोप को सर्वोच्च धर्मगुरु माना जाता है। ऑर्थोडॉक्स रोम के पोप को नहीं मानते, पर अपने-अपने राष्ट्रीय धर्मसंघ के पैट्रिआर्क को मानते हैं व परंपरावादी होते हैं। प्रोटेस्टेंट पोप को नहीं मानते। इसके बजाय वे पवित्र धर्मग्रंथ बाइबिल में पूरी श्रद्धा रखते हैं।

हिजबुल्ला के ठिकानों पर अमेरिकी हमले

कार्रवाई ▶ 25 की मौत, इराक और सीरिया में पल-बढ़ रहे आतंकियों को बनाया निशाना

ईरान समर्थित मिलिशिया ने हमलों का बदला लेने की कसम खाई

अमेरिकी सेना की एयर स्ट्राइक में कातिब हिजबुल्ला और हिजबुल्ला ब्रिगेड के हेडक्वॉर्टरों को तबाह कर दिया गया है। एपी

बगदाद, एजेंसियां : इराक और सीरिया में कातिब हिजबुल्ला और हिजबुल्ला ब्रिगेड के पांच ठिकानों पर अमेरिकी सेना के हमले में 25 लोग मारे गए। इन हमलों में हिजबुल्ला के 51 लड़ाकों के घायल होने की भी खबर है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। ईरान समर्थित मिलिशिया ने इन हमलों का बदला लेने की कसम खाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने कहा, हमले यह संदेश देने के लिए किए गए हैं कि अमेरिकियों के जीवन को खतरे में डालने वाली ईरान की किसी कार्रवाई को अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा।

इराक के किरकुक शहर स्थित सैन्य बेस के पास शुक्रवार को किए गए हमले में एक अमेरिकी ठेकेदार की मौत हो गई थी। अमेरिकी कार्रवाई को इसी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, इस हमले में 25 रॉकेट दागे गए थे। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता जोनाथन हॉफमैन ने कहा, हमने इराक में ईरान समर्थित शिया मुस्लिम मिलिशिया समूह के तीन और सीरिया में दो स्थानों को निशाना बनाया था। जिन स्थानों को निशाना बनाया गया, वहां हथियारों का भंडारण करने के साथ ही हमलों को संचालित करने काम किया जाता था। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि हमलों को एफ-15ई लड़ाकू विमानों द्वारा अंजाम दिया गया। अमेरिकी हमले के बाद रविवार आधी रात कातिब हिजबुल्ला ने एक बयान जारी किया। उसने कहा, 'अमेरिका और उसके भाड़े के लोगों के साथ हमारी लड़ाई अब किसी भी अंजाम तक जा सकती है। हमारे पास उनके हमलों का जवाब देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो इस अपराध का जवाब देने से हमें रोक सके।' बता दें कि ईरान समर्थित इराक की हिजबुल्ला ब्रिगेड लेबनानी आतंकी समूह हिजबुल्ला से पूरी तरह अलग है। इराक की हिजबुल्ला ब्रिगेड पॉपुलर मोबलाइजेशन फोर्सेस के एक घटक के तौर पर काम करती है।

ईरान ने अमेरिकी हमले को आतंकी कृत्य बताया : ईरान ने अमेरिकी हमलों को आतंकी कृत्य करार दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्बास मौसवी ने कहा, इराक और इराकी सुरक्षा बलों के खिलाफ अमेरिकी हमले आतंकवाद का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ईरान ना केवल इस कृत्य की निंदा करता है बल्कि अमेरिका पर इराक की संप्रभुता की अनदेखी करने का भी आरोप लगाता है।

पाकिस्तानी तालिबान कमांडर कारी सैफुल्ला महसूद ढेर

- टीटीपी ने कारी की हत्या में हक्कानी नेटवर्क का हाथ होने की जताई आशंका

कारी सैफुल्ला महसूद। फाइल

इस्लामाबाद, एएनआइ : तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के कमांडर कारी सैफुल्ला महसूद की अफगानिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कुछ हथियारबंद लोगों ने इस हमले को खोस्त प्रांत के गुलून शिविर के बाहर अंजाम दिया। टीटीपी के प्रवक्ता ने दावा किया है कि यह हमला हक्कानी नेटवर्क द्वारा अंजाम दिया गया है क्योंकि कुछ दिन पहले भी उसने इसी इलाके में टीटीपी के हकीमुल्ला महसूद समूह से जुड़े तीन आतंकियों को मार गिराया था।

आतंकी संगठन टीटीपी की स्थापना 2007 में बैतुल्ला महसूद ने की थी। वर्तमान में यह चार गुटों (स्वात समूह, महसूद समूह, बाजौर एजेंसी समूह और डेरा आदमखेल समूह) में विभाजित है। विभिन्न हमलों में शामिल होने के कारण कारी सैफुल्ला महसूद भी पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा वांछित आंतकियों में था। पूर्व में आए एक ऑडियो संदेश में महसूद ने दावा किया था कि उसके आतंकी गुट ने इस साल 75 हमले किए हैं। इनमें से ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान जिलों में किए गए। अधिकारियों ने हालांकि उसके इस दावे की पुष्टि नहीं की है।

विश्लेषकों का मानना है कि कारी महसूद की मौत टीटीपी के लिए बड़ा झटका है क्योंकि वह चारों गुटों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा था। पेशावर के एक वरिष्ठ पत्रकार साबूर खटक ने कहा, टीटीपी पहले ही कई गुटों में बंट चुका है और महसूद उन्हें फिर से एकजुट करने की कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं वह सबसे सक्रिय आतंकी था। महसूद ने कराची में 2015 में हुए बस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में 45 लोग मारे गए थे। खटक ने बताया कि 2016 में कारी को अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। उसे 14 महीने तक जेल में रखा गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया।

हांगकांग में विरोध-प्रदर्शनों के साथ होगा नए साल का अंत और आगाज

हांगकांग, रायटर : हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारी वर्ष के आखिरी दिन यानी मंगलवार को कई विरोध-प्रदर्शनों की योजना बना रहे हैं। वे नए साल के मौके पर भी बड़ा जुलूस निकालने की तैयारी को अंतिम रूप दे चुके हैं। इसके पीछे आंदोलनकारियों का मुख्य मकसद नए साल के उत्सव और खरीदारी को बाधित करना है।

सोशल मीडिया पर जारी एक नोटिस के अनुसार, नए साल की पूर्व संध्या पर विक्टोरिया हार्बर और कई शॉपिंग मॉल से विरोध प्रदर्शन निकाले जाएंगे। एक जनवरी को लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारियों द्वारा निकाले जाने वाले जुलूस को पुलिस की अनुमति मिल गई है और यह कॉजवे-बे स्थित बड़े पार्क से शुरू होगा। विरोध-प्रदर्शनों और नए साल पर जुलूस को देखते हुए पुलिस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। एक फेसबुक पोस्ट में पुलिस आयुक्त क्रिस टैंग ने हांगकांग की सुरक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति के अपने अधिकारियों को धन्यवाद दिया और प्रदर्शनकारियों को चेतावनी जारी की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से कहा है कि यदि आप हिंसा करेंगे तो आपको लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा। वहीं शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के आयोजक सिविल ह्यूमन राइट्स फ्रंट के नेता जिमी शाम ने कहा, नए साल के मौके पर हमें अपनी एकजुटता दिखाने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि हांगकांग के लोग हांगकांग के भविष्य के लिए सड़कों पर आएंगे।

हांगकांग में लोकतंत्र की मांग का आंदोलन अब आजादी की मांग की ओर मुड़ गया है। सोमवार को यहां प्रदर्शनकारियों ने अपने मोबाइल फोन्स की लाइट जलाकर चीन के खिलाफ विरोध जताया। रायटर

टेक्सास के चर्च में हुई गोलीबारी, दो लोगों की मौत

ह्यूस्टन, प्रेट्र : अमेरिका में टेक्सास राज्य के व्हाइट सेटलमेंट शहर के एक चर्च में एक बंदूकधारी ने लोगों पर गोलियां चलाईं जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। हालांकि बाद में प्रार्थना सभा के एक सशस्त्र सदस्य ने हमलावर को गोली मार दी।

यह घटना रविवार सुबह व्हाइट सेटलमेंट में वेस्ट फ्रीवे चर्च ऑफ क्राइस्ट में प्रार्थना के दौरान करीब 11.50 बजे हुई। इस प्रार्थना सभा की सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही थी। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि बंदूकधारी खड़ा हुआ है और पास ही खड़े एक व्यक्ति से बात कर रहा है जिसने एक दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया।

इसके बाद बंदूकधारी ने उस व्यक्ति पर गोली चला दी। फिर बंदूकधारी ने उस व्यक्ति पर भी गोली चला दी जिससे उसने बात की थी। हालांकि इसके बाद सुरक्षाकर्मी के तौर पर काम करने वाले एक व्यक्ति ने बंदूक से हमलावर पर गोली चलाई जिससे वह तुरंत नीचे गिर गया। अधिकारियों ने इस घटना के पीछे के मकसद के बारे में जानकारी नहीं दी है।

तालिबान ने अफगानिस्तान में संघर्ष विराम से किया इन्कार

- अमेरिका के साथ संभावित समझौते में संघर्ष विराम को शामिल करने की चर्चा पर लगाया विराम

काबुल, एएफपी : आतंकी संगठन तालिबान ने उन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि अमेरिका के साथ संभावित समझौते में संघर्ष विराम को भी शामिल किया जा रहा है। तालिबान ने स्पष्ट कहा कि अफगानिस्तान में संघर्ष विराम की उसकी कोई योजना नहीं है। संघर्ष विराम की खबरों से यह उम्मीद बढ़ी थी कि अफगानिस्तान में 18 साल से जारी खूनी संघर्ष में कमी आ सकती है।

तालिबान ने सोमवार को कहा, 'पिछले कुछ दिनों से मीडिया में संघर्ष विराम के संबंध में झूठी खबरें आ रही हैं। सच्चाई यह है कि संघर्ष विराम की कोई योजना नहीं है।' मीडिया में आई खबरों में दावा किया गया था कि अमेरिका और तालिबान शांति समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख का जल्द एलान हो सकता है। यह भी बताया गया था कि तालिबान के ज्यादातर आतंकियों ने अफगानिस्तान में संघर्ष विराम के पक्ष में सहमति दी है। लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला तालिबान के सरगना मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा को लेना है। तालिबान के पूर्व कमांडर सैयद अकबर आगा के हवाले से कहा गया था, 'संघर्ष विराम के दो हिस्से होंगे।

इसके पहले हिस्से का एलान अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर से पहले किया जाएगा। जबकि अफगानिस्तान और विदेशियों के साथ करार होने के बाद दूसरे भाग की घोषणा की जाएगी। मुझे लगता है कि संघर्ष विराम के पहले भाग को लेकर तालिबान सहमत नहीं है।' खबरों में यह भी बताया गया था कि अमेरिका और तालिबान के बीच कतर की राजधानी दोहा में संभावित अगले दौर की शांति वार्ता में इन मसलों पर सहमति बन सकती है।

ऑस्ट्रेलिया में गर्म हवाओं से भड़की आग

बढ़ा खतरा

विक्टोरिया प्रांत के पूर्वी गिप्सलैंड से तीस हजार लोगों को इलाका छोड़ने के निर्देश, जंगलों की आग से अभी तक नौ लोगों की जान जा चुकी है और हजारों घर राख में तब्दील हो चुके हैं

सिडनी, आइएएनएस : ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग गर्म हवाओं से और भड़क गई है। बिगड़े हालात को देखते हुए सोमवार को देश के चार राज्यों में आपात स्थिति की चेतावनी जारी कर दी गई। इन क्षेत्रों से पर्यटकों के अलावा आग बुझाने में जुटे अग्निशमन दस्तों को भी वापस लौटने को कहा गया है। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा के कारण विक्टोरिया प्रांत के पूर्वी गिप्सलैंड से तीस हजार लोगों को इलाका छोड़ देने के लिए कहा गया है। तेज आंधी और बिजली गिरने की संभावना के मद्देनजर आग की स्थिति और भयावह होने की संभावना जताई जा रही है।

ऑस्ट्रेलिया में इस आग से अभी तक नौ लोगों की जान जा चुकी है और हजारों घर राख में तब्दील हो चुके हैं। मरने वालों में दो दमकल कर्मी भी शामिल हैं। गर्म और तेज हवा को देखते हुए दावानल का दायरा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। न्यू साउथ वेल्स प्रांत के जंगलों में लगी आग से सिडनी शहर धुएं के गुबार से भरा है। आग से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए राजधानी कैनबरा में नए साल के मौके पर आतिशबाजी के उत्सव को स्थगित कर दिया गया है।

ऑस्ट्रेलिया की जंगलों में लगी आग बुझाता दमकलकर्मी। रायटर

हालात बिगड़ने की आशंका : सोमवार दोपहर को हवा के रुख में बदलाव के बाद स्थिति और भयावह होने की आशंका है। पूर्वी विक्टोरिया में लगी आग से राख का गुबार 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल गया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 16 दिसंबर से लगी इस आग की वजह से एक लाख 48 हजार हेक्टेयर का इलाका जलकर राख हो चुका है। इससे लोगों की जान और संपत्ति पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं, बॉक्सिंग डे के मौके पर लगी आग पर काबू पाने के लिए 200 दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उधर, न्यू साउथ वेल्स में लगी आग के पश्चिमी सिडनी की ओर लगातार बढ़ने से एक बार फिर पूरा शहर धुएं की चादर से ढक गया है।

डोनाल्ड ट्रंप का विवादित ट्वीट गायब, समर्थकों का फूटा गुस्सा

सैन फ्रांसिस्को, आइएएनएस : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से विवादित ट्वीट के गायब होने का मामला तूल पकड़ रहा है। पहले तो ट्रंप के 6.8 करोड़ फॉलोअर्स को लगा कि कथित व्हिसिलब्लोअर के नाम वाला ट्वीट कहीं ट्रंप ने ही तो नहीं हटाया है। लेकिन तकनीकी खराबी के चलते ट्वीट नहीं दिखाई देने के ट्विटर के बयान के बाद फॉलोअर्स ने सोशल मीडिया कंपनी की जमकर खबर ली। माना जाता है कि इसी कथित व्हिसिलब्लोअर की शिकायत पर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत हुई है।

ट्विटर ने रविवार को कहा, 'हमारे एक सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के कारण ट्रंप का ट्वीट सिर्फ कुछ लोगों को दिखाई दे रहा था। हम इस खराबी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की होने वाली परेशानी के लिए माफी चाहते हैं।' लेकिन कंपनी के इस बयान से यूजर्स का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने जमकर भड़ास निकाली। एक यूजर ने ट्विटर सेफ्टी को लिखा, 'मुझे यह सब बहुत अजीब लगता है। आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन औरों के लिए है। वास्तव में यह बहुत अजीब बात है कि ज्यादातर ट्रंप के ट्वीट गायब होते हैं।

एक अन्य ट्विटर यूजर ने कहा, हमेशा रिपब्लिकन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों के अकाउंट के साथ ही ऐसा क्यों होता है। यह अजीब सा नहीं लगता कि एक तकनीकी खराबी के चलते पूरा स्पेक्ट्रम प्रभावित हो गया। दरअसल, यूट्यूब और फेसबुक सहित कई तकनीकी कंपनियों ने अपने प्लेटफार्म पर कथित व्हिसिलब्लोअर का नाम नहीं दिया है। ट्विटर ने भी उसका नाम तो नहीं दिया है, लेकिन यह जरूर कहा है कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम देने से कंपनी की नीतियों का उल्लंघन नहीं होगा।

दुष्कर्म के झूठे मामले में ब्रिटिश युवती दोषी करार

लंदन, आइएएनएस: साइप्रस की एक अदालत ने दुष्कर्म मामले में झूठा आरोप लगाने वाली ब्रिटिश युवती को दोषी करार दिया है। द्वीपीय देश साइप्रस में बीते जुलाई में एक झूठे मामले में फंसाते हुए 19 वर्ष की इस युवती ने इजरायल के 12 युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। मामले की पुलिस छानबीन में पता चला कि युवती ने उन लोगों पर मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। इसके बाद युवती को गिरफ्तार कर लिया गया और झूठे आरोप में गिरफ्तार युवकों को रिहा कर दिया गया।

झूठे आरोप के मामले में अभियोजन पक्ष ने बताया कि युवती ने पूछताछ में खुद ही इस बात को स्वीकार कर लिया कि उसने उन युवकों के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए थे।

सोमवार को साइप्रस अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद युवती के वकीलों ने बताया कि वे कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूरोप की मानवाधिकार अदालत में अपील करेंगे।

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट जीतकर हमने एक नई शुरुआत की है और अब हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है।
— मार्क बाउचर, दक्षिण अफ्रीका टीम के कोच

मेलबर्न टेस्ट में वार्नर से मिले राशिद

नई दिल्ली, आइएएनएस : दो दोस्त अचानक मिल जाएं तो उनकी पहली प्रतिक्रिया कुछ खास ही होती है। कुछ ऐसा ही डेविड वार्नर और अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान के साथ हुआ। राशिद यहां मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट का लुत्फ लेने आए थे। जब वार्नर ने उन्हें देखा तो उन्होंने राशिद खान की अपने बल्ले से प्यार से पिटाई ही कर दी।

एक नजर में

हंपी ब्लिट्ज प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर

मास्को : भारतीय ग्रैंडमास्टर कोनेरू हंपी ने महिला विश्व रैपिड एवं ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में दूसरे खिताब के लिए दमदार शुरुआत की और वह ब्लिट्ज प्रतियोगिता के पहले दिन तीन अन्य के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर हैं। शनिवार को रैपिड खिताब जीतने वाली 32 वर्षीय हंपी ने दो दिवसीय ब्लिट्ज प्रतियोगिता में पहले पांच दौर में जीत से शुरुआत की और वह एक समय शीर्ष पर थीं। हंपी ने अपनी अगली दो बाजियां ड्रॉ कराईं और फिर आठवीं बाजी में मोनिका सैको को हराया। वह हालांकि पहले दिन के बाद शीर्ष पर चल रहीं रूस की कैटरीना लैगनो से दिन की अंतिम बाजी में नाटकीय तरीके से हार गईं। (प्रेट्र)

क्रैमनिक 14 भारतीय खिलाड़ियों को कोचिंग देंगे

चेन्नई : दिग्गज शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर क्रैमनिक विश्व के दूसरे सबसे युवा ग्रैंडमास्टर डी गुकेश और आर प्रग्नानंदा सहित 14 युवा भारतीय खिलाड़ियों को यहां आठ जनवरी से शुरू होने वाले 10 दिवसीय शिविर मे प्रशिक्षण देंगे। माइक्रोसेंस द्वारा आयोजित इस शिविर में पूर्व विश्व चैंपियन क्रैमनिक के अलावा एक अन्य दिग्गज बोरिस गेलफेंड भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे। शिविर में दो महिला खिलाड़ी भी हैं। क्रैमनिक ने इससे पहले अगस्त में फ्रांस में आठ खिलाड़ियों का शिविर आयोजित किया था। (प्रेट्र)

एबॉट की जगह शॉर्ट ऑस्ट्रेलियाई टीम में

मेलबर्न : ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को चोटिल तेज गेंदबाज सीन एबॉट की जगह शीर्ष क्रम के बल्लेबाज डि आर्ची शॉर्ट को भारत के आगामी दौरे के लिए आरोन फिंच की अगुआई वाली वनडे टीम में शामिल किया है। भारतीय दौरे की शुरुआत 14 जनवरी को मुंबई में होने वाले पहले वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच से होगी। दूसरा वनडे 17 जनवरी को राजकोट और तीसरा वनडे 19 जनवरी को बेंगलुरु में खेला जाएगा। एबॉट बिग बैश लीग में मांसपेशियों में खिंचाव के कारण चार सप्ताह के लिए बाहर हो गए, जिसके बाद शॉर्ट को 14 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया। तेज गेंदबाज पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिशेल स्टार्क और केन रिचर्डसन भारत दौरे पर आने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा हैं, इसलिए चयनकर्ताओं ने तेज गेंदबाज एबॉट की जगह शीर्ष क्रम के बल्लेबाज शॉर्ट को चुना, जो लेग स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं। शॉर्ट ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चार वनडे मैचों में 26.66 की औसत से 83 रन बनाए हैं। (प्रेट्र)

विराट कोहली ● फाइल फोटो, एपी

विजडन की टी-20 टीम में कोहली व बुमराह

दशक की टीम में पूर्व भारतीय कप्तान धौनी को नहीं मिली जगह ऑस्ट्रेलिया के फिंच को बनाया गया टीम का कप्तान

लंदन, प्रेट्र : भारतीय कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को विजडन ने दशक (2010-2019) की टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम में शामिल किया है, लेकिन महेंद्र सिंह धौनी इस टीम में जगह नहीं बना पाए। ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के कप्तान आरोन फिंच को टीम का कप्तान बनाया गया है, जिसमें दो अन्य ऑस्ट्रेलियाई शेन वॉटसन और ग्लेन मैक्सवेल शामिल हैं। टीम में इंग्लैंड के जोस बटलर और डेविड विली, अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मुहम्मद नबी और राशिद खान, न्यूजीलैंड के कोलिन मुनरो और श्रीलंका के लसित मलिंगा शामिल हैं।

विजडन ने कोहली के बारे में लिखा, 'कोहली का घरेलू टी-20 रिकॉर्ड उतार-चढ़ाव वाला रहा है, लेकिन टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। कोहली का औसत 53 रन का है, जो दशक में सर्वश्रेष्ठ है और जबकि उनकी निरंतरता उनके स्ट्राइक रेट से थोड़ा समझौता करती है, तब भी वह असाधारण नहीं, लेकिन अच्छी दर से स्कोर बनाने में सक्षम हैं। विजडन ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि तेज और स्पिन गेंदबाजी के सामने दमदार और विकेटों के बीच तेज दौड़ के कारण कोहली नंबर तीन के आदर्श खिलाड़ी हैं, जो शुरू में विकेट गिरने के बाद गेंदबाजी का डटकर सामना करके पारी संवारने में सक्षम हैं, लेकिन साथ ही अच्छी शुरुआत मिलने पर तेजी से रन बना सकते हैं। पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी होने पर कोहली इस एकादश के बल्लेबाजी क्रम में नीचे आएंगे।

बुमराह को भी मिली जगह : कोहली को विजडन ने दशक के पांच खिलाड़ियों में शामिल किया था। इनमें स्टीव स्मिथ, डेल स्टेन, एबी डिविलियर्स और एलिस पैरी भी शामिल थे। कोहली को जहां विजडन की दशक की टी-20 टीम में बल्लेबाजों में जगह मिली है तो वहीं गेंदबाजों में बुमराह अपने शानदार 'इकॉनोमी रेट' और डेथ ओवरों की बेहतरीन गेंदबाजी के कारण अंतिम एकादश में स्थान बनाने में सफल रहे। विजडन ने लिखा है कि बुमराह का ओवरऑल इकॉनोमी रेट 6.71 है, जो विश्व के तेज गेंदबाजों में डेल स्टेन के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ है। यह आंकड़ा तब और प्रभावशाली लगता है जब आप इस पर गौर करो कि उन्होंने अधिकतर गेंदबाजी डेथ ओवरों में की, जहां उनका 7.27 का इकॉनोमी रेट विश्व में सातवां सर्वश्रेष्ठ और तेज गेंदबाजों में सर्वश्रेष्ठ है। बुमराह अपनी टीम के लिए तीन ओवर डेथ ओवरों में करते रहे हैं। भारत की 2007 की टी-20 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान धौनी इस ऑलस्टार टीम में जगह नहीं बना पाने वाले प्रमुख खिलाड़ी हैं।

विजडन की दशक की टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम : आरोन फिंच (कप्तान), कोलिन मुनरो, विराट कोहली, शेन वॉटसन, ग्लेन मैक्सवेल, जोस बटलर, मुहम्मद नबी, डेविड विली, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, लसित मलिंगा।

एमएस धौनी ● फाइल फोटो, ट्विटर

पोंटिंग ने विराट को बनाया अपनी टीम का कप्तान

नई दिल्ली, एएफपी : इन दिनों सभी पूर्व क्रिकेटर साल 2019 के खत्म होने के साथ इस दशक (2010-2019) की अपनी-अपनी टेस्ट टीमें तैयार कर रहे हैं। इस मुहिम में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग भी शामिल हो गए हैं। पोंटिंग ने सोमवार को इस दशक (2010-2019) की अपनी टेस्ट एकादश की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की है।

इस पूर्व कंगारू कप्तान ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को अपनी इस खास टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी है। हालांकि पोंटिंग द्वारा चुनी गई टेस्ट एकादश में भारत से विराट ही एकमात्र खिलाड़ी हैं, जबकि पाकिस्तान से किसी भी खिलाड़ी को इसमें जगह नहीं मिली है। इस दशक की अपनी टेस्ट टीम की सूरत साफ करते हुए इस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने लिखा कि हर कोई इस दशक की टीम चुन रहा है तो मैंने सोचा मैं भी इस मस्ती में शामिल हो जाऊं। 2010 से यह होगी मेरी टेस्ट टीम। पोंटिंग की इस टीम में पांच खिलाड़ी ऐसे हैं, जो अपने-अपने देश की टेस्ट टीमों के कप्तान हैं या रहे हैं। अपनी टेस्ट एकादश में पोंटिंग ने इंग्लैंड से सर्वाधिक चार, ऑस्ट्रेलिया से तीन और भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका से एक- एक खिलाड़ी को जगह दी है। अपनी इस टेस्ट टीम में पंटर ने डेविड वार्नर और एलिस्टेयर कुक को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी है। नंबर तीन पर उन्होंने केन विलियमसन, चार पर स्टीव स्मिथ और कप्तान विराट कोहली को नंबर पांच पर बल्लेबाजी के लिए चुना है। पंटर की इस टीम में तीन तेज गेंदबाज, एक स्पिनर और बेन स्टोक्स के रूप में एकमात्र ऑलराउंडर खिलाड़ी है। विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी उन्होंने श्रीलंका के महान खिलाड़ी कुमार संगकारा को सौंपी है। दिलचस्प है कि पोंटिंग ने अपने दौर के किसी भी खिलाड़ी को जगह नहीं दी है, जबकि उनके दौर में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, मिस्बाह उल हक, माइकल क्लार्क, एबी डिविलियर्स, एमएस धौनी जैसे खिलाड़ी भी खेले हैं।

पोंटिंग की टेस्ट एकादश : डेविड वार्नर, एलिस्टेयर कुक, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली (कप्तान), कुमार संगकारा (विकेटकीपर), बेन स्टोक्स, डेल स्टेन, नाथन लियोन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन।

जसप्रीत बुमराह ● फाइल फोटो, एएफपी

अनाहत और अमीरा ने जीते पदक

नई दिल्ली, जेएनएन : भारतीय युवा स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत और अमीरा सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कॉटिश ओपन में अपने-अपने वर्ग में पदक जीते। अनाहत ने स्कॉटिश ओपन में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि अमीरा कांस्य पदक जीतने में सफल रहीं। यह टूर्नामेंट स्कॉटलैंड के एडिनबरा में 28 से 30 दिसंबर तक हुआ था। 2019 स्कॉटिश जूनियर ओपन के फाइनल मुकाबले में अनाहत ने मलेशिया की कीर्ति हरिधरन को आसानी से 11-1, 11-1, 11-1 से शिकस्त देकर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। मैच के बाद अनाहत ने कहा कि मैं अपने प्रदर्शन से खुश हूं। मैंने इस खिताब को जीतने के लिए कड़ी मेहनत की थी। मैं अपने शानदार प्रदर्शन के सिलसिले को अगले साल भी जारी रखने की कोशिश करूंगी। मुझे उम्मीद है कि नया साल मेरे करियर के लिए अच्छा रहेगा। वहीं, अमीरा ने अंडर-19 स्पर्धा में जापान की आयुमी वाटैनबी को 11-5, 11-2, 13-11 से मात देकर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया।

आइसीसी चार दिवसीय टेस्ट को अनिवार्य करने पर कर रही विचार

वजह
- व्यस्त कार्यक्रम में समय की बचत करने की है योजना
- विचार से सहमत नजर नहीं आए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पेन

मेलबर्न, प्रेट्र : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) 2023 से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल मुकाबलों को अनिवार्य रूप से चार दिवसीय करने पर विचार कर रही है, जिससे व्यस्त कार्यक्रम में समय की बचत की जा सके।

आइसीसी की क्रिकेट समिति 2023-2031 सत्र के लिए टेस्ट मैचों को औपचारिक रूप से पांच की जगह चार दिन के करने पर विचार करेगी। ईएसपीएनक्रिकइंफो के मुताबिक, इस विचार के पीछे कई वजह हैं, जिसमें आइसीसी और अधिक वैश्विक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहती है और बीसीसीआइ ने भी इस सत्र में अधिक द्विपक्षीय मुकाबलों की मांग की है। इसके अलावा दुनिया भर में टी-20 लीग का प्रसार हो रहा है और पांच दिवसीय मैच की मेजबानी में होने वाला खर्च भी शामिल है। अगर 2015-2023 सत्र में चार दिवसीय टेस्ट मैच खेले जाते तो खेल से 335 दिन बच जाते। चार दिवसीय टेस्ट कोई नई अवधारणा नहीं है। इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड और आयरलैंड ने चार दिवसीय टेस्ट खेला था। इससे पहले 2017 में दक्षिण अफ्रीका और जिंबाब्वे ने भी ऐसा ही मैच खेला था।

यह ऐसा मुद्दा है जिस पर खेल से जुड़े हितधारक अलग-अलग दृष्टिकोण रख सकते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) के प्रमुख केविन रॉबर्ट्स को लगता है कि चार दिवसीय टेस्ट पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। रॉबर्ट्स ने एसईएन रेडियो को बताया, 'यह ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें इस सप्ताह गंभीरता से विचार करना होगा। इस मामले पर भावनाओं से ऊपर उठना होगा, लेकिन इसे तथ्यों के हिसाब से देखा जाना चाहिए। हमें समय और ओवर के संदर्भ में यह देखने की जरूरत है कि पिछले 5-10 वर्षों में टेस्ट मैचों की औसत लंबाई क्या रही है।'

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन हालांकि इस विचार से बहुत उत्साहित नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'अगर ऐसा होता तो एशेज सीरीज में हमें जो नतीजे मिले वो नहीं मिलते। मुझे लगता है हर मैच पांचवें दिन तक चला था। टेस्ट क्रिकेट को यही अलग बनाता है, यह पांच दिनों का होता है और मानसिक एवं शारीरिक रूप से मुश्किल होता है। यह प्रथम श्रेणी में चार दिवसीय मैच के मुकाबले खिलाड़ियों की अधिक परीक्षा लेता है। मुझे लगता है शायद इसी सोच से इसे ऐसा रखा गया है, उम्मीद है कि यह बरकरार रहेगा।'

क्वालीफायर का ट्रायल फिक्स था : सरिता

नई दिल्ली, एएनआइ : मुक्केबाज सरिता देवी ने ओलंपिक क्वालीफायर ट्रायल मुकाबले में बाउट फिक्स किए जाने का आरोप लगाया है। फरवरी में होने वाले ओलंपिक क्वालीफायर के ट्रायल मुकाबले शनिवार को हुए। सरीता को यहां हार मिली, जिसके बाद उन्होंने मुकाबले को फिक्स किए जाने का आरोप लगाया है।

सरिता ने भारतीय बॉक्सिंग महासंघ (बीएफआइ) को पत्र लिखकर नाराजगी जताई। सरिता ने लिखा, 'मैं दोबारा कह रही हूं, यह बाउट फिक्स किया गया था। मैं साफ तौर से कहना चाहूंगी कि बीएफआइ के कार्यकारी निदेशक आरके सचेती, विदेशी कोच राफेल और छोटे लाल यादव वो लोग हैं, जो मेरे खिलाफ अक्सर ही साथ मिलकर काम करते हैं। यही वे लोग हैं जिन्होंने इस बाउट को फिक्स किया था। मैं ऐसी अन्यायपूर्ण चीजें को लंबे समय से सहन करती आ रही हूं, लेकिन अब समय आ गया है कि मेरे और बाकियों के साथ-साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊं।'

कोहली शीर्ष पर कायम

टेस्ट रैंकिंग

भारत के कुल पांच बल्लेबाज शीर्ष-20 में शामिल, गेंदबाजों की सूची में भी शीर्ष-20 में पांच भारतीय

दुबई, प्रेट्र : भारतीय कप्तान विराट कोहली वर्ष के आखिर में आइसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज रहेंगे, लेकिन लंबे प्रारूप के विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा एक पायदान नीचे पांचवें स्थान पर खिसक गए।

कोहली के 928 रेटिंग अंक हैं और वह दूसरे स्थान पर काबिज ऑस्ट्रेलियाई स्टार स्टीव स्मिथ (911) से काफी आगे हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन (822) तीसरे स्थान पर हैं। इस साल 11 टेस्ट मैचों में 1085 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई मार्नस लाबुशाने एक पायदान आगे चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। पुजारा 791 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर हैं, जबकि अंजिक्य रहाणे के 759 अंक हैं और वह सातवें स्थान पर हैं। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल पहले की तरह 12वें स्थान पर बने हुए हैं, लेकिन रोहित शर्मा एक पायदान ऊपर 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस तरह से भारत के कुल पांच बल्लेबाज शीर्ष-20 में शामिल हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 95 रन की पारी खेलकर अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले क्विंटन डिकॉक सोमवार को जारी नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष-10 में शामिल हो गए हैं।

गेंदबाजों में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 794 अंक लेकर छठे स्थान पर बने हुए हैं, जबकि स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (772 अंक) और तेज गेंदबाज मुहम्मद शमी (771 अंक) नौवें और 10वें स्थान पर बने हुए हैं। रवींद्र जडेजा (725 अंक) एक पायदान ऊपर 16वें, जबकि इशांत शर्मा (716 अंक) पहले की तरह 18वें स्थान पर बने हुए हैं। इस तरह से गेंदबाजी में भी भारत के पांच खिलाड़ी शीर्ष-20 में बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजी के अगुआ पैट कमिंस 902 अंक लेकर शीर्ष पर हैं।

कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की दावेदारी पेश करेगा आइओए

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) ने सोमवार को कहा कि वह 2026 या 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा। आइओए साथ ही निशानेबाजी को हटाए जाने को लेकर 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के बहिष्कार की मांग से भी पीछे हटने को सहमत हो गया।

आइओए अब कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की जरूरी स्वीकृति लेने के लिए सरकार से संपर्क करेगी। भारत ने 2010 में इन खेलों की मेजबानी की थी। यहां वार्षिक आम बैठक के दौरान यह फैसला किया गया। आइओए के महासचिव राजीव मेहता ने कहा, 'हमने 2026 या 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने का फैसला किया है और साथ ही हमने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी अपना दल भेजने का फैसला किया है।'

दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद चुना जाएगा डीडीसीए अध्यक्ष

तिहारा बोले, विपक्षी गुट ने किया डीडीसीए को बदनाम, गंभीर लोकसभा से इस्तीफा देकर ही आ सकते हैं राज्य संघ में

खेल संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने अपने अध्यक्ष पद का चुनाव कराने के लिए सोमवार को फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद का समय मांगा है। डीडीसीए ने साथ ही स्पष्ट कर दिया कि लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के पात्र नहीं हैं।

डीडीसीए सचिव विनोद तिहारा ने यहां कहा, 'लोकपाल दीपक वर्मा को अध्यक्ष पद का चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया जाएगा। चुनाव जनवरी के अंत में होने हैं, लेकिन आग्रह किया जाएगा कि यह फरवरी में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद हों।' रजत शर्मा के इस्तीफे के बाद खाली हुए अध्यक्ष पद के लिए गंभीर की उम्मीदवारी पर तिहारा ने कहा, 'दिल्ली क्रिकेट की सेवा के लिए उनका स्वागत है, लेकिन वह अध्यक्ष तभी बन सकते हैं जब सांसद के रूप में इस्तीफा दें।' रजत ने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था जिससे डीडीसीए में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चुनाव कराने की जरूरत पड़ी। तिहारा ने साथ ही रविवार को संपन्न विवादों से भरी वार्षिक आम सभा (एजीएम) के दौरान हाथापाई करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी वादा किया। एजीएम के दौरान हाथापाई भी हुई थी और इस दौरान न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा को डीडीसीए का नया लोकपाल नियुक्त किया गया। तिहारा ने विपक्षी गुट पर डीडीसीए को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एजीएम के दौरान अव्यवस्था में शामिल रहे राज्य संघ के अधिकारियों के खिलाफ एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई की जाएगी। एजीएम में संयुक्त सचिव राजन मनचंदा और अन्य सदस्यों के बीच मे धक्का-मुक्की हुई थी। तिहारा चाहते हैं कि लोकपाल दीपक वर्मा इस मामले को देखें और अपना फैसला दें। तिहारा ने कहा कि जिस तरह से प्रशासकों की छवि को खराब करने के लिए तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा गया है, वह दुखद है। वीडियो आप सभी के सामने है, आप उसे देख सकते हैं। अपने हिसाब से तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा गया है। हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते और चाहते हैं कि लोकपाल इस पर अंतिम फैसला लें। वह वीडियो को सबूत के तौर पर देख सकते हैं और मामले पर अपना फैसला सुना सकते हैं। हम हमेशा से मानते हैं कि क्रिकेट प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए है और इस तरह की चीजें सामने नहीं आनी चाहिए। यहां तक की जब बीसीसीआइ द्वारा जारी किए गए फंड हमारे पास आए तो हमने उन्हें क्रिकेट से संबंधित गतिविधियों, स्टाफ का वेतन देने, रोजमर्रा के खर्चे में ही इस्तेमाल किया।

भारतीय खेलों के लिए खुशनुमा रहा 2019

भारतीय खेलों के लिए साल 2019 बेहद खुशनुमा रहा। क्रिकेट के अलावा भारतीय खिलाड़ियों ने अन्य खेलों में भी उपलब्धियां हासिल कीं। अधिकतर हर खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर अपनी जगह मजबूत की। साल 2019 को भारतीय खेलों के बदलाव के तौर पर देखा जाएगा।

मैदान पर कोहली 'राजा' तो बाहर गांगुली 'महाराजा'

विराट कोहली और भारतीय क्रिकेट ने खत्म हो रहे साल में अच्छी प्रगति की, जबकि सौरव गांगुली ने बीसीसीआइ अध्यक्ष के रूप में नई पारी की शुरुआत की। भारत ने साथ ही 2019 में अंततः डे-नाइट टेस्ट खेला। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने में सफल रही, लेकिन विश्व कप सेमीफाइनल में कुछ मिनटों के खराब प्रदर्शन के कारण कोहली की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। मुश्किल के समय में भारतीय क्रिकेट की बागडोर संभालने के लिए पहचाने जाने वाले गांगुली सर्वसम्मति से बीसीसीआइ के 39वें अध्यक्ष बने। मैदान पर कोहली लगातार आगे बढ़ते रहे। वह तीनों प्रारूपों में 2455 रन बनाकर सबसे सफल बल्लेबाज रहे। उन्होंने अपने साथी रोहित शर्मा (2442) से 13 रन अधिक बनाए। रोहित ने टेस्ट क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज के रूप में नई पारी का आगाज किया और बेहद सफल रहे। भारतीय गेंदबाजों ने इस साल दबदबा बनाया, जो नई शुरुआत को दर्शाता है। इस साल भारत की ओर से चार गेंदबाजों ने अलग-अलग प्रारूपों में हैट्रिक लीं। वनडे क्रिकेट में भारत की ओर से दो हैट्रिक बनीं। पहले विश्व कप के दौरान मुहम्मद शमी ने अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली और फिर कुलदीप यादव ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। वहीं, जसप्रीत बुमराह वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में हैट्रिक लेने में सफल रहे, जबकि दीपक चाहर ने टी-20 क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली।

सिंधू बनीं विश्व चैंपियन, लक्ष्य बने स्टार

पीवी सिंधू ने विश्व चैंपियनशिप की पहली भारतीय विजेता होने का इतिहास रचा, लेकिन इसे छोड़कर उनके प्रदर्शन में पूरे साल गिरावट देखने को मिली, जबकि युवा खिलाड़ी लक्ष्य सेन भारतीय बैडमिंटन के नए स्टार बनकर उभरे, जिन्होंने इस वर्ष पांच खिताब अपने नाम किए। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी की जोड़ी ने साल 2019 में पुरुष डबल्स मुकाबलों में कुछ शानदार प्रदर्शन किया। सिंधू ने अगस्त में जापान की नोजोमी ओकुहारा को लगातार गेमों में पराजित कर विश्व चैंपियनशिप जीती थी। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं।

अन्य खेलों में भी हुआ नाम

भारत की कोनेरू हंपी ने रविवार को ही रूस के मास्को में हुई महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में चीन की लेई टिंगजी को टाईब्रेकर की सीरीज में हराकर खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा, एशियन गेम्स में भारतीय एथलीटों ने दमदार प्रदर्शन किया।

युवाओं ने बिखेरी निशानेबाजी में चमक

भारत के लिए यह साल निशानेबाजी में शानदार रहा। इलावेनिल वालारिवान ने आइएसएसएफ विश्व कप फाइनल्स में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीता। 17 साल की मनु भाकर ने एशियन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण जीता। सौरभ चौधरी ने इस साल गोल्डन टारगेट अवॉर्ड जीता। यह अवॉर्ड अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ द्वारा दिया जाता है। सौरभ पिस्टल में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी बने। 17 साल के दिव्यांश सिंह पंवार ने आइएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीता।

भारतीय हॉकी में जगी नई उम्मीद

भारतीय हॉकी के लिए 2018 मौके चूकने के कारण निराशा से जुड़ा रहा तो 2019 उम्मीद की नई किरण लेकर आया, जिसमें पुरुष और महिला दोनों टीमों ने अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालीफाई किया।

नागल ने रचा इतिहास

सुमित नागल ने दिग्गज रोजर फेडरर से एक सेट छीनकर भारतीय टेनिस को यादगार पल दिया। हालांकि, पूरे साल प्रशासन व खिलाड़ियों के मतभेदों के चलते कोर्ट के भीतर का प्रदर्शन हाशिये पर रहा। नागल ने दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में शुमार फेडरर को यूएस ओपन के पहले दौर में एक सेट में हराया। साल के अंत में भारतीय दिग्गज लिएंडर पेस का संन्यास की घोषणा करना भी चर्चा का विषय बन गया। वहीं, भारत ने डेविस कप में पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दी। इस दौरान पेस डेविस कप के सबसे सफल डबल्स खिलाड़ी बने। उन्होंने डेविस कप डबल्स में 44वीं जीत दर्ज की, जो कि एक नया रिकॉर्ड है।

कुश्ती में भारत को मिले ओलंपिक कोटे

यह साल कुश्ती में भारतीयों के लिए यादगार रहा। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत को चार ओलंपिक कोटे हासिल हुए। भारत के पदक के सबसे बड़े दावेदार बजरंग पूनिया, युवा पहलवान दीपक पूनिया, रवि व विनेश फोगाट ने देश को ओलंपिक का कोटा हासिल कराया। यह कोटे इन चारों पहलवानों ने कजाखिस्तान के नूर-सुल्तान में हुई विश्व चैंपियनशिप में हासिल हुए थे।

मुक्केबाजी में पंघाल ने दिलाई सफलताएं

भारतीय मुक्केबाजी के लिए रिंग में यह साल सफलताएं हासिल करने वाला रहा, जिसमें अमित पंघाल ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। वहीं ओलंपिक क्वॉलीफिकेशन के लिए टीम चयन भी विवादों में रहा। 23 साल के पंघाल पुरुष विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। ओलंपिक क्वॉलीफिकेशन के लिए चुनी गई टीम में मेरी कॉम विवादों में रहीं, जिनका निखत जरीन के साथ विवाद रहा, जबकि नीरज फोगाट (महिला) और सुमित सांगवान (पुरुष) के डोप टेस्ट में विफल होने से भारतीय मुक्केबाजी को झटका लगा।

न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट के लिए समरविले को टीम में लिया

वेलिंगटन, एएफपी : विल समरविले के सिडनी में खेलने के अनुभव को देखते हुए न्यूजीलैंड ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम में शामिल किया है। ऑफ स्पिनर समरविले ऑस्ट्रेलिया में पले बढ़े हैं और वह न्यू साउथ वेल्स की तरफ से शेफील्ड शील्ड में खेलते रहे हैं। उन्हें शुक्रवार से सिडनी में होने वाले टेस्ट मैच के लिए चोटिल ट्रेंट बोल्ट की जगह लिया गया है।

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर बहुत बधाई।
– विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान

फुटबॉल डायरी ▶ अग्यूरो और डि ब्रूने के गोल से 2–0 से जीता मौजूदा चैंपियन

शेफील्ड को हराकर जीत की राह पर लौटा सिटी

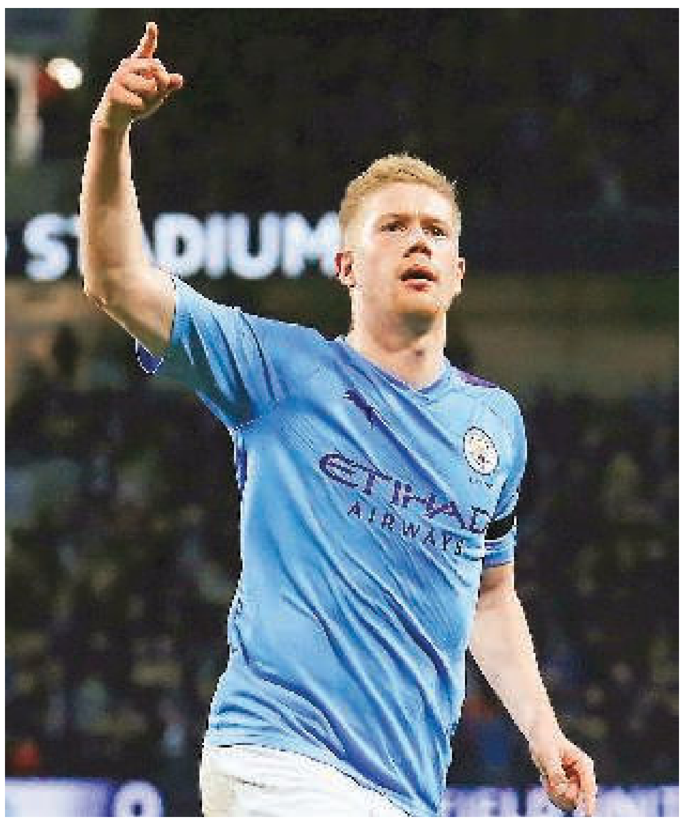

ईपीएल में शेफील्ड युनाइटेड के खिलाफ गोल करने के बाद जश्न मनाते मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर केविन डि ब्रूने। एएफपी

ईपीएल में सबसे तेज 100 मैच जीतने वाले मैनेजर बने गॉर्डियोला

लंदन, एएफपी : इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में रविवार को मौजूदा चैंपियन मैनचेस्टर सिटी ने शेफील्ड युनाइटेड को 2-0 से हरा दिया। सर्जियो अग्यूरो और केविन डि ब्रूने के गोल की मदद से सिटी ने जीत के साथ लीग में वापसी की, लेकिन तालिका में शीर्ष पर चल रहे लिवरपूल से वह अभी भी 14 अंक पीछे है। इस जीत की बदौलत उसने दूसरे स्थान पर काबिज लीसेस्टर सिटी से अपने अंकों का फासला कम कर दिया।

वीडियो असिस्टेंट रेफरी (वार) तकनीक ने एतिहाद में सिटी और शेफील्ड के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान अहम भूमिका निभाई। हाफ टाइम से पहले लेस मॉसेट ने गोल करके शेफील्ड को बढ़त दिलाई, लेकिन वार की मदद से उस गोल को रेफरी ने अयोग्य करार दिया। इसके बाद दूसरे हाफ में अग्यूरो ने डि ब्रूने के पास पर शानदार गोल के जरिये अपनी टीम को 52वें मिनट में बढ़त दिलाई। वहीं, डि ब्रूने ने निर्धारित समय से आठ मिनट पहले गोल करके सिटी को दोहरी बढ़त दिलाई, जो अंत तक कायम रही। इस जीत के साथ ही सिटी के मैनेजर पेप गॉर्डियोला ईपीएल में सबसे तेजी से 100 जीत दर्ज करने वाले मैनेजर बन गए। उन्होंने 100 जीत दर्ज करने के लिए 134 मैचों का सहारा लिया। गॉर्डियोला ने जोस मौरिन्हो के 142 मैचों में 100 जीत के रिकॉर्ड को तोड़ा। ईपीएल में दो दिन पहले ही सिटी को वोल्वरहैंप्टन के खिलाफ शिकस्त मिली थी, लेकिन इस जीत के साथ उसने 2019 का जीत के साथ समापन किया। तालिका में लिवरपूल 55 अंकों के साथ शीर्ष पर है, लीसेस्टर 42 अंकों के साथ दूसरे और सिटी 41 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।

भाग्यशाली रहा लिवरपूल : एनफील्ड में खेले गए मुकाबले में लिवरपूल ने वोल्वरहैंप्टन को 1-0 से शिकस्त दी। इस विवादस्पद मुकाबले में लिवरपूल भाग्यशाली रहा, जहां सादियो माने के इकलौते गोल की बदौलत उसने अपने घरेलू मैदान पर अजेय मुकाबलों के क्रम को 50 पहुंचा दिया। माने के गोल को पहले रेफरी ने हैंड बॉल की वजह से अयोग्य करार दे दिया, लेकिन वार ने उस गोल को सही ठहराया। इसके बाद वोल्वरहैंप्टन ने पेद्रो निटो के गोल के जरिये बराबरी हासिल की, लेकिन एक बार फिर वार उसके खिलाफ गया और गोल को ऑफ साइड की वजह से अयोग्य करार दिया गया।

वेस्टहम में मोएस की वापसी

लंदन, एएफपी : ईपीएल में संघर्ष कर रही वेस्टहम की टीम ने अनुभवी पूर्व खिलाड़ी डेविस मोएस को दोबारा अपना मैनेजर नियुक्त किया है। 2013–14 में मैनचेस्टर युनाइटेड के मैनेजर के कार्यकाल के बाद से मोएस का करियर कभी उबर नहीं पाया। 2017–18 में वह पहली बार वेस्टहम के मैनेजर बने थे और अब वह मैनुअल पेलेग्रिनी की जगह दोबारा क्लब के मैनेजर बनाए गए हैं। 56 वर्षीय मोएस 2018 में अपने छह महीने के कार्यकाल के बाद वेस्टहम को छोड़ने के बाद से किसी क्लब से नहीं जुड़ पाए थे।

मैच के दौरान फुटबॉलर की मौत

कोच्चि, आइएएनएस : भारतीय क्लब ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के पूर्व डिफेंडर आर धनराजन की रविवार रात को मलप्पुरम जिले के पेरिंथलम्ना में सेवेन्स फुटबॉल मैच खेलने के दौरान मौत हो गई। धनराजन 39 साल के थे। धनराजन खेलते समय अचानक मैदान पर गिर गए। उन्हें सांस लेने तकलीफ हो रही थी और सीने में दर्द भी हो रहा था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। धनराज ने संतोष ट्रॉफी में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था।

डुप्लेसिस ने 'बिग थ्री' मॉडल की आलोचना की

क्रिकेट डायरी

सेंचुरियन, एएफपी : दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डुप्लेसिस का मानना है कि क्रिकेट को कम नहीं, बल्कि अधिक संख्या में बड़े देशों की जरूरत है। रविवार को इंग्लैंड को पहले टेस्ट में 107 रन से हराने के बाद डुप्लेसिस से जब 'बिग थ्री' भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तथा एक अन्य देश की मौजूदगी वाली चार देशों की 'सुपर सीरीज' की योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप पिछले एक साल से देख सकते हैं कि बिग थ्री देशों के बीच क्या चल रहा है।

'सुपर सीरीज' में भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा एक और देश होगा, जिसे एक-एक कर के आमंत्रित किया जाएगा। डुप्लेसिस ने कहा कि शीर्ष तीन या तीन बड़े देशों के खिलाफ काफी मैच खेले जा रहे हैं। अगर आप इसमें अधिक टीमों को शामिल करेंगे तो यह और अच्छा हो सकता है। डुप्लेसिस ने बताया कि टेस्ट क्रिकेट में मैचों को लेकर काफी असमानता है, जहां आयरलैंड और अफगानिस्तान जैसे नए टेस्ट देशों को खुद के लिए मैच हासिल करने में संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई छोटे देश हैं जो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पा रहे।

इंग्लैंड के सिबले भी बीमार हुए

सेंचुरियन, एएफपी : सलामी बल्लेबाज डोमिनिक सिबले दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई इंग्लैंड टीम के बीमार हुए क्रिकेटरों की सूची में शामिल हो गए हैं। टीम के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि इस महीने दौरे के शुरू होने के बाद से 11 खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ के छह सदस्य किसी न किसी समय बीमार हुए। बीमारी के कारण पहले टेस्ट से बाहर रहे क्रिस वोक्स और जैक लीच की सेहत में सुधार है और लोग अब उनसे मिल सकते हैं। पूरी टीम मंगलवार को केपटाउन के लिए रवाना होगी। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच शुक्रवार से खेला जाएगा।

क्रिकेट के भद्र पुरुष विलियमसन ने दर्शकों के पास जाकर कहा धन्यवाद

मेलबर्न, एएफपी : न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन को क्रिकेट के भद्र पुरुषों में गिना जाता है। रविवार को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में मिली हार के बाद उन्होंने एक बार फिर अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत लिया।

चार दिन तक चले बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच को देखने कुल दो लाख दर्शक पहुंचे। इनमें से कई न्यूजीलैंड से भी मैच देखने पहुंचे थे। दोनों टीमें 32 साल बाद इस मैदान पर खेल रही थीं। न्यूजीलैंड की टीम का प्रदर्शन हालांकि बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन उनके प्रशंसकों के जोश में कोई कमी नहीं आई। वे लगातार अपनी टीम का समर्थन करते रहे।

मैच के बाद विलियमसन खुद उस स्टैंड में गए, जहां बड़ी संख्या में कीवी प्रशंसक बैठे थे। विलियमसन ने उन्हें टीम का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। विलियमसन का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग उनके इस व्यवहार की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं।

शेन वॉर्न, आपने कब स्टुअर्ट मैकगिल को मौका दिया : नाथन लियोन

सिडनी, एएफपी : ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन ने सिडनी टेस्ट से विश्राम लेने के शेन वॉर्न के सुझाव को दो टूक शब्दों में नकारते हुए सोमवार को कहा कि इस दिग्गज लेग स्पिनर ने क्या कभी अपने करियर में स्टुअर्ट मैकगिल को मौका देने की कोशिश की।

वॉर्न ने लियोन को न्यूजीलैंड के खिलाफ सिडनी टेस्ट से विश्राम देने और उनकी जगह लेग स्पिनर मिशेल स्वेपसन को अंतिम एकादश में रखने की वकालत की थी। वॉर्न ने कहा था कि अगर चयनकर्ता इस तीसरे और अंतिम टेस्ट के लिए एक स्पिनर का चयन करते हैं तो उन्हें लियोन को बाहर करके स्वेपसन को पदार्पण का मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि स्वेपसन को टेस्ट मैच का अनुभव दिलाने के लिए उन्हें मौका देना चाहिए। मेरा मानना है कि इसका भविष्य में फायदा मिलेगा, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में चार विकेट लेने वाले लियोन ने कहा कि उनके बाहर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वॉर्न जब खेला करते थे तो मैकगिल को बहुत कम मौके मिले और लियोन ने उसी का सहारा लिया।

एटीपी कप से हटे केई निशिकोरी

टेनिस

▶ कोहनी की चोट की वजह से हटे जापानी टेनिस स्टार

पर्थ, एएफपी : कोहनी की चोट से जूझ रहे जापान के टेनिस स्टार केई निशिकोरी ने सोमवार को अगले साल होने वाले पहले एटीपी कप से हटने का फैसला किया। चोट के कारण वह यूएस ओपन के बाद से टेनिस कोर्ट से बाहर चल रहे हैं। दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी रह चुके निशिकोरी फिलहाल 13वें स्थान पर हैं।

निशिकोरी ने निराशा जताई कि वह तीन जनवरी से शुरू होने वाली टीम स्पर्धा में अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, 'हमने अपनी टीम के साथ मिलकर यह फैसला किया कि मैं अब भी उच्च स्तर पर खेलने के लिए शत-प्रतिशत फिट नहीं हूं।' 30 वर्षीय निशिकोरी ने अक्टूबर में अपनी कोहनी की सर्जरी कराई थी और अभी यह साफ नहीं है कि वह 20 जनवरी से मेलबर्न पार्क में शुरू होने वाले साल के पहले पहले ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेल पाएंगे या नहीं। जापान एटीपी कप टीम में निशिकोरी की जगह योशीहितो निशिओका को शामिल किया गया है। निशिकोरी से पहले ब्रिटेन के दिग्गज एंडी मरे भी चोट के कारण इस प्रतियोगिता से हट गए थे जबकि रोजर फेडरर ने इसमें नहीं खेलने का फैसला किया था। यह टीम चैंपियनशिप तीन से 12 जनवरी के बीच ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगी, जिसमें 24 देशों को छह ग्रुप में रखा जाएगा जो राउंड रॉबिन आधार पर एक-दूसरे से खेलेंगे। इनमें शीर्ष पर रहने वाली आठ टीमें नॉकआउट में पहुंचेंगी।

कोर्ट ने ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर साधा निशाना

मेलबर्न, एएफपी : ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट ने एक बार फिर ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर निशाना साधा है और उन्हें शैतान करार दिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान मार्गरेट को सम्मानित किया जाना है। एक चर्च पादरी की भूमिका निभा रहीं 24 बार की ग्रैंडस्लैम चैंपियन मार्गरेट ने 2017 में भी ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि बच्चे सात और आठ साल की उम्र में अपना लिंग बदलने का निर्णय ले रहे हैं। यह बहुत गलत है।

बांग्लादेश में पहली बार हुई महिलाओं की बॉडीबिल्डिंग

ढाका, एएफपी : बांग्लादेश में महिलाओं के लिए पहली बार बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 19 साल की एक विद्यार्थी विजेता बनीं। दिलचस्प बात यह है कि बॉडीबिल्डिंग में महिला प्रतियोगिता बिकिनी या ऐसा कोई परिधान पहनती हैं, लेकिन इस प्रतियोगिता में महिलाओं ने पूरी तरह से ढके हुए वस्त्र पहने हुए थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कपड़ों को लेकर कोई विवाद खड़ा न हो जाए। मुस्लिम बहुल देशों में आम तौर पर इस तरह की प्रतियोगिताओं का चलन नहीं है। 29 प्रतियोगियों ने इसमें हिस्सा लिया और उनमें अवहोना रहमान को लोगों की भीड़ के सामने विजेता का ताज पहनाया गया।

विजेता रहमान समेत अन्य प्रतियोगियों ने स्टेज पर लैगिंग के साथ पूरी तरह से शरीर को ढकने वाली टी-शर्ट पहन रखी थी। रहमान ने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरी मेहनत रंग लाई और मैं विजेता बनीं। इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी।

रहमान ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर आलोचना के सवाल पर कहा कि मेरे दिमाग में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया। मुझे कभी नहीं लगा कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर मेरी आलोचना हो सकती है। मुझे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मेरे भाई ने काफी प्रेरित किया, वह अपना एक फिटनेस सेंटर चलाते हैं।

विविध

डॉ. ऊषा किरण खान को 'भारत–भारती' सम्मान

उप्र हिंदी संस्थान का 43वां स्थापना दिवस समारोह, योगी आदित्यनाथ ने साहित्यकारों को किया सम्मानित

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का 'भारत-भारती' सम्मान पटना की डॉ. ऊषा किरण खान को प्रदान किया गया। सोमवार को लखनऊ में संस्थान के 43वें स्थापना दिवस समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊषा किरण सहित कई साहित्यकारों को सम्मानित किया। बता दें पद्मश्री ऊषा किरण खान भामती उपन्यास (मैथिली साहित्य) के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं।

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साहित्य को अपना जीवन समर्पित करने वाले महान साहित्यकारों को सम्मानित करना मेरे लिए गौरवपूर्ण है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। इससे समाज की दिशा तय होती है। उन्होंने कहा कि हमारी लेखनी ऐसी होनी चाहिए जो मार्ग दर्शक के रूप में समाज को नई दिशा दे सके। समारोह में डॉ. मनमोहन सहगल को 'लोहिया साहित्य सम्मान' व डॉ. बदरी नाथ कपूर को 'हिंदी गौरव सम्मान' प्रदान किया। हालांकि डॉ. बदरी अस्वस्थ होने के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। योगी ने भगवान सिंह को 'महात्मा गांधी साहित्य सम्मान' व डॉ. ओम प्रकाश पांडेय को 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान' से नवाजा। डॉ. कमल कुमार को 'अवंतीबाई साहित्य सम्मान' व मणिपुर हिंदी परिषद इंफाल के महासचिव डॉ. अरिबम्ब ब्रज कुमार शर्मा को 'राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन सम्मान' दिया गया। डॉ. उदय नारायण गंगू को 'प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान' व डॉ. बंडार मेणिके विजेतुंग को 'हिंदी विदेश प्रसार सम्मान' से सम्मानित किया गया।

लखनऊ में सोमवार को आयोजित समारोह में डॉ. उषा किरण खान को भारत–भारती सम्मान से सम्मानित करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित (दाएं) और जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह (बाएं)। जागरण

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साहित्य समाज का मार्गदर्शक होता है। साहित्य का अर्थ है, जिसमें सबका हित हो। साहित्य के माध्यम से ही हम किसी समाज, राष्ट्र व संस्कृति को संबल प्रदान कर सकते हैं। साहित्यकार को समाज की ज्वलंत समस्याओं को रचनात्मक दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपनी लेखनी को खेमे, क्षेत्रीयता व जातीयता में बांटने का प्रयास करेंगे तो इससे साहित्यिक साधना भंग होगी। साथ ही समाज व देश का बड़ा नुकसान होगा।

रचनात्मक साहित्य को बढ़ावा दिया जाए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रचनात्मक साहित्य को बढ़ावा दिया जाए। रचनात्मक साहित्य के माध्यम से ही प्रगतिशील समाज की संकल्पना साकार हो सकती है। जो समाज अपनी विभूतियों को संरक्षित व संवर्धित करता है, वहीं समाज आगे बढ़ता है। हिंदी भारत को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा है।

पुस्तक का विमोचन किया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 'पं दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान' से सम्मानित डा. ओम प्रकाश पाण्डेय द्वारा रचित पुस्तक 'सांस्कृतिक विचार की अविराम भारतीय यात्रा' का विमोचन किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, जलशक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह, हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. सदानंद प्रसाद गुप्त तथा निदेशक श्रीकान्त मिश्र सहित बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी उपस्थित थे।

भोपाल के स्पा सेंटर पर छापा, सात युवतियां व पांच युवक गिरफ्तार

नईदुनिया, भोपाल: भोपाल के बागसेवनिया इलाके में क्राइम ब्रांच ने सोमवार को शाइन स्पा सेंटर पर छापा मारा। यहां देह व्यापार में लिप्त सात युवतियों और पांच ग्राहकों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें स्पा सेंटर की संचालिका भी शामिल है। यहां आने वाले ग्राहकों को कोड वर्ड 'हैप्पी एंडिंग' बताना पड़ता था। उसके बाद उसे कॉल गर्ल उपलब्ध कराई जाती थी। इस स्पा सेंटर के तार भोपाल के अलावा नागपुर, नासिक, मुंबई, जलगांव और इंदौर के कई स्पा सेंटरों से जुड़े हैं। वहां से कॉल गर्ल भोपाल के अलावा अन्य स्थानों पर भेजी जाती थीं। पुलिस अभी इस गिरोह से जुड़ी और भी अहम जानकारियां जुटा रही है।

भोपाल पुलिस के पास शहर के 30-40 स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियां चलने की सूचना मिली थी। इसी के तहत बागसेवनिया थाने के सामने शाइन स्पा सेंटर के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की। जिन 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें स्पा सेंटर की मालकिन रिया भी है। पकड़ी गई युवतियों में एक रायसेन की, जबकि बाकी सभी भोपाल की रहने वाली हैं। युवक भोपाल के आसपास के रहने वाले हैं। यह सेक्स रैकेट मुंबई, पूना, इंदौर समेत अन्य जगहों पर भी फैला हुआ है।

मोबाइल टावर से कमाई का झांसा देकर 11 लाख ठगे

जागरण संवाददाता, पानीपत

▶ जेई सुरजीत से आरोपित पांच साल से कर रहे थे ठगी

▶ 27 लाख रुपये का नकली ड्राफ्ट मिला तो ठगी का पता चला

▶ अंतरराज्यीय ठग गिरोह के बदमाशों को छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार

▶ कई राज्यों में लोगों से कर चुके हैं आठ करोड़ से अधिक की ठगी

पीडब्ल्यूडी के जेई (जूनियर इंजीनियर) को रिलायंस 4 जी मोबाइल टावर लगवाकर 45 लाख रुपये कमाने व 52 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन पाने का झांसा देकर अंतरराज्यीय ठग गिरोह ने पांच साल में 11 लाख रुपये की ठगी कर ली। गिरोह में शामिल महिला सहित नौ ठगों ने वारदात को अंजाम दिया। ठगों ने पीड़ित को 27 लाख रुपये का नकली बैंक ड्राफ्ट भेजा। तभी भड़ाफोड़ हुआ। ठगों को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पीडब्ल्यूडी कॉलोनी रहने वाले सुरजीत कुहाड़ ने पुलिस को शिकायत दी कि उनका जिला सोनीपत में बड़वासनी गांव है। उनके पास गांव में मोबाइल टावर लगवाने के लिए कॉल आया। उन्होंने 2 नवंबर 2015 को डॉक्यूमेंट कोरियर से हिसार भेज दिए। 16 दिसंबर को उन्हें बताया गया कि उनका रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस से बीमा हो गया है। नेहा शर्मा नाम की महिला ने फरवरी 2016 में बताया कि टावर लगवाने की एवज में 52 हजार रुपये प्रतिमाह, नौकर को वेतन और 45 लाख रुपये एडवांस मिलेंगे। उनसे नेहा शर्मा सहित नौ लोगों ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस और अन्य कई खातों में 11 लाख रुपये जमा करा लिए। उसके पास रशीद भी भेजी गई। 11 जून 2019 में उनके पास 27 लाख 78 हजार 690 रुपये का केनरा बैंक के नाम बेंगलुरु से ड्राफ्ट आया। उन्होंने बैंक मैनेजर से बातचीत की तो पता चला कि बैंक ड्राफ्ट फर्जी है। ठगों ने हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में मोबाइल टावर लगवाने का झांसा देकर लोगों से आठ करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी कर रखी है। छत्तीसगढ़ में भी महिला से 62 लाख रुपये ठग रखे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने गत दिनों नोएडा से ठगों को गिरफ्तार किया और उनसे 5000 मोबाइल फोन नंबर बरामद किए। पुलिस ने पीड़ित जेई सुरजीत कुहाड़ को भी अवगत करा दिया है कि उनसे ठगी के आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं।

पीड़ित जेई सुरजीत ने बताया कि ठग नेहा शर्मा ने कॉल कर बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। मोबाइल फोन भी टूट गया है। उसने कार्यालय में कॉल किया तो बाद में नेहा शर्मा वाट्सएप पर मैसेज करती रही कि पेमेंट के लिए बैंक से वेरीफिकेशन के लिए कॉल की जाएगी। ठग संजीव अग्रवाल भी उन्हें नकली बैंक ड्राफ्ट भेजकर बरगलता रहा।

नया साल मनाने गोवा पहुंचे आयरलैंड के प्रधानमंत्री

पणजी, प्रेट्र : आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर नया साल मनाने के लिए सोमवार को गोवा पहुंच गए। लियो वराडकर के पिता डॉ. अशोक वराडकर महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले के वराड गांव के रहने वाले थे और 1960 के आसपास ब्रिटेन चले गए थे।

लियो वराडकर भारत की निजी यात्रा पर हैं और उत्तरी गोवा जिले के प्लश रिजॉर्ट में ठहरे हैं। रिजॉर्ट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि निजी यात्रा होने की वजह से आयरलैंड के प्रधानमंत्री के लिए किसी सरकारी कार्यक्रम के आयोजन की योजना नहीं है। वह अपने परिवार के साथ एक जनवरी तक गोवा में रहेंगे। उसी दिन दोपहर में वह आयरलैंड लौट जाएंगे।

ब्रिटिश दुष्कर्म पीड़िता की मां ने वराडकर को किया ट्वीट : आयरलैंड में जन्मी ब्रिटिश नागरिक डेनियल मैक्लॉघलिन (28) की मां एंड्रिया ब्रेन्निगन ने लियो वराडकर को ट्वीट किया है। डेनियल की 2017 में गोवा में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एक स्थानीय युवक विकट भगत को गिरफ्तार किया गया था। एंड्रिया ने ट्वीट में लिखा, 'गोवा में नया साल मनाने के दौरान आयरलैंड के पीएम को आयरिश नागरिक डेनियल के दुष्कर्म और हत्या मामले पर भी बात करनी चाहिए। फास्ट ट्रैक होने के बावजूद आखिरकार मामले की सुनवाई इतनी धीमी क्यों चल रही है। अगर वह इस बारे में कुछ नहीं करते हैं तो यह बेहद शर्मनाक है।'

राजस्थान के तीन मंत्रियों ने की जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की वकालत

नरेन्द्र शर्मा, जयपुर

▶ कहा, अब देश में एक बच्चे को लेकर बने कानून

राजस्थान सरकार के तीन मंत्रियों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की पैरवी की है। तीनों मंत्रियों ने कहा कि अब हम दो और हमारे दो के स्थान पर हम दो एवं हमारे एक का नारा दिया जाना चाहिए। एक बच्चे को लेकर राजस्थान सहित देशभर में कानून बनना चाहिए।

राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने सोमवार शाम जयपुर के महिला अस्पताल में एक कार्यक्रम में कहा कि समय की मांग को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

गर्ग ने कहा कि अब दो नहीं एक बच्चे का कानून बने और जो बच्चों का पालन-पोषण नहीं कर सकते, उन्हें बच्चे पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। बच्चों को शिक्षा एव चिकित्सा की सुविधा वहन नहीं कर सकने वाले दंपतियों को बच्चे पैदा करने का अधिकार नही है।

डॉ.रघु शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार को इस कानून के बारे में विचार करना चाहिए। यदि केंद्र की तरफ से कोई पहल होगी तो राज्य सरकार इसमें सहमति देगी। उन्होंने कहा कि दो बच्चों का जमाना दो दशक पहले गया। अब तो एक बच्चे का युग आ गया है। खाचरियावास ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश और प्रदेश में बनना चाहिए। वह इस बात के पक्ष में हैं कि एक से अधिक बच्चे किसी भी दंपति के नहीं होने चाहिए। खाचरियावास ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की शुरुआत राजस्थान से हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की बढ़ती आबादी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम स्व. इंदिरा गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पहल की तो भाजपा के नेताओं ने ही विरोध किया था। लेकिन अब समय की मांग को देखते हुए उन्हें इस बारे में विचार करना चाहिए।

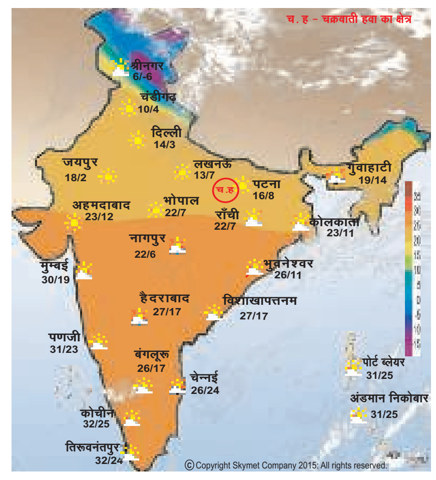

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में सुबह में शीतलहर रहेगी। कश्मीर के उत्तरी भागों में हल्की वर्षा व बर्फबारी होगी। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर घने कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा दिन का मौसम शुष्क व ठंडा बना रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	30/18/आंबा	अहमदाबाद	26/10/आंबा
कोलकाता	23/12/आंबा	बड़ौदा	27/13/सा
चेन्नई	31/23/आंबा	नागपुर	20/05/आंबा
हैदराबाद	27/16/आंबा	इन्दौर	24/12/आंबा
बंगलूरु	26/18/आंबा	राँची	21/14/व
त्रिवेन्द्रम	32/25/सा	पटना	22/15/आंबा
गुवाहाटी	18/13/व	जमशेदपुर	22/15/व
गंगटोक	02/-5/आंबा	पुणे	28/21/आंबा

भारतीय उपमहाद्वीप में कारोबार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी गठित

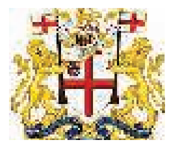

आज ही के दिन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सरकारी चार्टर द्वारा हुई थी। इस चार्टर पर इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने हस्ताक्षर किए थे। सर थॉमस स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। शुरुआत में इसका उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार करना था।

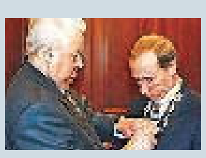

येल्तसिन का इस्तीफा, व्लादिमीर पुतिन बने रूस के राष्ट्रपति

आज ही के दिन 1999 में रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने इस्तीफा दे दिया था। येल्तसिन के बाद व्लादिमीर पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। इसके बाद 26 मार्च 2000 को पुतिन रूस के राष्ट्रपति चुने गए।

'गांधी' के लिए बेन किंग्सले को मिला था ऑस्कर

आज ही के दिन 1943 में कृष्ण पंडित भानजी यानी बेन किंग्सले का जन्म इंग्लैंड के यॉर्कशायर में हुआ था। उनके पिता एक भारतीय डॉक्टर और मां अभिनेत्री थीं। 1967 में थिएटर शुरू किया। 1972 में पहली फिल्म 'फीयर इज द की' रिलीज हुई। इस दौरान टीवी पर काफी काम किया। 1982 में आई फिल्म 'गांधी' में उन्होंने महात्मा गांधी की भूमिका निभाई। इसके लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर मिला। दो गोल्डन ग्लोब के साथ ग्रैमी, बाफ्टा और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं।

इधर-उधर की

होटल छोड़ 'कैप्सूल' में ठहर रहे लोग

पेरिस, एजेंसी : अपनी कल्पनाओं में हम अक्सर आलीशान घर की कल्पना करते हैं, लेकिन जापान के सस्ते 'कैप्सूल होटल' के बहुत छोटे कमरों का कॉन्सेप्ट दुनिया को पसंद आ रहा है। इटली के मिलान शहर में ऐसे कैप्सूल होटल पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए खूब लोकप्रिय हो रहे हैं। दरअसल इन होटलों के एक कमरे में सामान्य कमरे के स्थान में आठ कैप्सूल बनाए जा सकते हैं। डेढ़ से दो मीटर की माप के एक के ऊपर एक चार-चार कैप्सूल होते हैं। सुविधा के लिहाज से यह बड़े होटलों की बराबरी करते हैं। कैप्सूल के अंदर बेड, मोबाइल या लैपटॉप चार्जिंग प्लग, आलमारी, टेबल और टॉयलेट सुविधा होती है। कैप्सूल में ठहरने के लिए 15 सौ रुपये तक लगते हैं। हालांकि मिलान फैशन वीक के दौरान आपको 12 हजार रुपये तक देने पड़ सकते हैं। इस तरह के अनूठे होटल 1979 में जापान के ओसाका शहर में सामने आए। बाद में हवाई अड्डों पर इन्हें अपनाया गया।

बच्चों के बौद्धिक स्तर पता लगा सकता एमआरआइ

- रूस के स्कोलकोवो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने किया दावा
- अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डाटाबेस का किया किया प्रयोग

एमआरआइ से शरीर के आंतरिक अंगों की जांच होती है। प्रतीकात्मक

मॉस्को, प्रेट्र : हमारे सोचने और समझने की क्षमता ही हमें दूसरे जीवों से अलग करती है। किसी भी व्यक्ति की सोचने-समझने की यह क्षमता का अनुमान उसके बौद्धिक स्तर से लगाया जा सकता है। अब इस बौद्धिक स्तर का पता लगाने की दिशा में भी शोधकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। दरअसल, शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि इंसानों के आंतरिक अंगों और ऊतकों का पता लगाने में प्रयोग होने वाला मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआइ अब बच्चों के बौद्धिक स्तर का पता लगाने में भी मददगार साबित हो सकता है। हालिया अध्ययन में इसका दावा किया गया है।

इस तरह अध्ययन से लगाया पता : रूस के स्कोलकोवो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने गहरी समझ वाले थ्रीडी नेटवर्क आधारित सामूहिक पद्धतियों का प्रयोग करके यह विश्लेषण किया कि क्या एमआरआइ ब्रेन इमेज के जरिये बौद्धिक स्तर का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने यह पता लगाने के लिए अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआइएच) के डाटाबेस का प्रयोग किया। इस डाटाबेस में 9 से 10 साल के बच्चों के एमआरआइ इमेज थे।

अलग-अलग उम्र के लोगों के एमआरआइ का विश्लेषण : यह अध्ययन एडोलसेंट ब्रेन कॉगनिटिव डेवलपमेंट न्यूरोकॉगनिटिव प्रिडिक्शन जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसमें बौद्धिक स्तर या 'अस्थिर बौद्धिकता' का अनुमान लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अस्थिर बौद्धिकता में तार्किक रूप से सोचने और नई परिस्थितियों में समस्या का समाधान खोजने की क्षमता होती है। हालांकि, इसके लिए स्वतंत्र ज्ञान की हासिल करने की जरूरत होती है। शोधकर्ताओं ने स्वतंत्र और लक्षित बौद्धिक स्तर दोनों का अनुमान लगाया। इसमें अलग-अलग उम्र, लिंग, मस्तिष्क आकार या एमआरआइ स्कैनर का प्रयोग किया गया।

भावनात्मक विकास को समझने में भी मिलेगी मदद

शोध में शामिल पीएच.डी छात्र एकाटेरिना कोंद्रात्येवा ने बताया, 'हमने तंत्रिका जाल का अनुमान लगाने वाले थ्री डी के साथ विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया। इससे कोई भी उसके आयाम को कम किए बगैर इमेज को उसके मूल स्वरूप में वर्गीकृत कर सकता है। इस प्रक्रिया में किसी तरह की सूचना भी नष्ट नहीं होती है।' इस अध्ययन ने बच्चों की 'अस्थिर बौद्धिकता' और मस्तिष्क रचना में संबंध स्थापित करने में मदद की। शोधकर्ताओं ने बताया, हालांकि यह अनुमान पूरी तरह सही नहीं हो सकता है। फिर भी यह अध्ययन बच्चों की सोच-समझ, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास संबंधी विभिन्न पहलुओं को समझने में मददगार साबित हो सकता है।

बीजों से भोजन व ऊर्जा बनने की गुत्थी सुलझी

- जर्मनी की मुंस्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया अध्ययन
- कहा-विभिन्न हार्मोन्स के जरिये बीजों की शुरुआती वृद्धि को किया जाता है नियंत्रित

यह अध्ययन पीएनएएस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। फाइल

लंदन, प्रेट्र : किसी अनाज या पौधे का बीज विकसित होकर हमारे भोजन का हिस्सा बनता है और हमें ऊर्जा उपलब्ध कराता है। लेकिन, यह बीज कैसे भोजन और ऊर्जा में तब्दील होता है, यह अभी तक पता नहीं है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया है। अध्ययन के अनुसार, जब पौधे का बीज पानी के संपर्क में आता है, तो इसकी कुछ आंतरिक रासायनिक प्रक्रिया भोजन और ऊर्जा बनाती है। इस अध्ययन से खेती को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है। जर्मनी की मुंस्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया कि बीजों की शुरुआती वृद्धि पौधे के विभिन्न हार्मोन्स के जरिये नियंत्रित होता है। उन्होंने बताया कि इन पौधों के रसायनों पर गहराई से अध्ययन किया गया है, लेकिन बीज में ऊर्जा उपलब्ध कराने वाली प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। साथ ही, इस बारे में भी पता नहीं है कि कुशलता से खाद्य उत्पादन करने में कैसे मदद पहुंचाते हैं।

इस तरह किया गया अध्ययन : यह हालिया अध्ययन पीएनएएस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसमें एनर्जी मेटाबोलिज्म और रेडजोक्स केमिकल पाथवे दोनों का आकलन किया गया है, जो सल्फर पर निर्भर रहता है। अध्ययन में बीज के भीतर मौजूद अणुओं के बारे में बताया गया है, जो ऊर्जा उत्सर्जित करने के लिए सक्रिय किया जाता है। इस प्रक्रिया में सल्फर रेडोक्स प्रतिक्रियाओं में कुछ नियंत्रित अणुओं की मुख्य भूमिका होती है। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया में मॉलीक्यूलर एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट (एटीपी) और अन्य अणुओं को पाया। इन अन्य अणुओं में निकोटीनैमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट शामिल हैं।

स्पेक्ट्रम

उन्होंने सूखे बीजों और पानी 'युक्त' बीजों की तुलना की। यह पता लगाने के लिए कि क्या रेडोक्स पाथवे बीजों के विकास के लिए महत्वपूर्ण थे, शोधकर्ताओं की टीम ने आनुवंशिक तरीकों का उपयोग करके खास तरह प्रोटीन को निष्क्रिय कर दिया और उसके बाद संशोधित और गैर-संशोधित बीजों की प्रतिक्रिया की तुलना की। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में बीज को कृत्रिम रूप से बढ़ने दिया और पाया कि इन प्रोटीनों की कमी होने पर बीज बहुत कम सक्रिय रूप से अंकुरित होते हैं। उसके बाद उन्होंने रेडोक्स प्रोटीन की जांच की कि यह प्रक्रिया कहां हो रही है। उन्होंने प्रोटीन की जांच के लिए सक्रिय माइटोकॉन्ड्रिया को अलग किया और जल्दी से उन्हें ठंडा किया। शोधकर्ताओं ने जैव-रासायनिक तरीकों का प्रयोग करके एनर्जी मेटाबोलिज्म में कई छोटे-छोटे प्रोटीन की पहचान की।

खेती में हो सकता है उपयोगी : शोधकर्ताओं के अनुसार, इस अध्ययन के नतीजे खेती में उपयोगी साबित हो सकते हैं। अध्ययन में पाया गया कि जहां तक संभव हो बीजों की अंकुरण शक्ति बरकरार रखने की जरूरत होती है। यह भी ध्यान रखने की जरूरत होती है कि वे न्यूनतम नुकसान के साथ अंकुरित हों। मुंस्टर यूनिवर्सिटी और अध्ययन के सह-लेखक मार्कस श्वार्जलैंडर ने बताया, 'अंकुरण नियंत्रण की प्रारंभिक प्रक्रिया को देखते हुए हम बीज अंकुरण तंत्र की बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं। भविष्य में हम पता लगा सकते हैं कि फसल जैव-प्रौद्योगिकी में इस तरह के बदलाव का प्रयोग कैसे किया जा सकता है।'

घरों में भी तैयार हो सकेगी बिजली

तलाशी राह ▸ आइआइटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया नया मॉडल

'इलेक्ट्रोकेनेटिक स्ट्रीमिंग पोटेंशियल' में पानी प्रवाहित करने से पैदा होता है करंट

आइआइटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं के साथ इस अध्ययन के नेतृत्वकर्ता कल्याण रायडोंगिया (दाएं)।

गुवाहाटी, प्रेट्र : आपने कभी सोचा है कि यदि घरों में नल से बहने वाले पानी से बिजली तैयार हो सकती तो कैसा होता? वाकई यदि ऐसा हुआ तो इससे बिजली के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ सकती है। इसी सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी नई सामग्री विकसित की है, जिससे स्थिर और बहते पानी से बिजली पैदा की जा सकेगी।

जर्नल एसीएस अप्लाइड नैनोमैटेरियल्स में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि ऊर्जा स्रोतों के विकेंद्रीकरण का समर्थन करने के लिए छोटे पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन के इन नए तरीकों को घरेलू वातावरण में भी नियोजित किया जा सकता है यानी इन विधियों का घरों में भी इस्तेमाल कर बिजली तैयार की जा सकती है। स्थिर और बहते पानी से बिजली तैयार करने के लिए शोधकर्ताओं ने दो अलग-अलग तरीकों का उपयोग किया।

शोधकर्ताओं ने 'इलेक्ट्रोकेनेटिक स्ट्रीमिंग पोटेंशियल' नामक नैनोस्केल को छोटे पैमाने पर प्रवाहित होने वाले पानी से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तैयार किया है। इस नैनौस्केल की महत्ता का अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि घरों में अब नल से बहते पानी से भी बिजली तैयार की जा सकती है।

वहीं, दूसरी और कॉट्रेस्टिंग इंटरफेशियल एक्टिविटीज नामक एक अन्य प्रक्रिया की मदद से अलग-अलग तरीके के अर्धचालकों से स्थिर जल से भी बिजली उत्पन्न की जा सकती है।

बढ़ रहा है बिजली संकट : इस रिसर्च के नेतृत्वकर्ता और आइआइटी गुवाहाटी में रसायन विभाग के कल्याण रायडोंगिया ने कहा, 'जीवाश्म ईंधनों के घटते भंडार और पर्यावरण संबंधी समस्याओं की वजह से बिजली का संकट लगातर बढ़ता जा रहा है। इस संकट ने वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। उदाहरण के तौर पर सूर्य की रोशनी, हवा और समुद्री तरंगों आदि से ऊर्जा निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पानी से भी विभिन्न रूपों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे- नदी का प्रवाह, ज्वार यहां तक कि वर्षा की बूंदें जिन्हें ब्लू एनर्जी यानी 'नीली ऊर्जा' के रूप में जाना जाता है। हालांकि नदियों से पनबिजली प्राप्त करना 'ब्लू एनर्जी' का ही एक पारंपरिक रूप है। हाल के वर्षों में अन्य तरीकों से पानी की क्षमता के दोहन के प्रयास भी किए गए हैं।

ऐसे पैदा होती है बिजली : शोधकर्ताओं ने कहा कि इलेक्ट्रोकेनेटिक ऊर्जा भी ब्लू एनर्जी का ही एक रूप है। रायडोंगिया ने कहा,' जब तरल पदार्थ यानी पानी को छोटे चैनलों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है तो इससे यह चार्ज होने लगता है और विद्युत वोल्टेज उत्पन्न करने लगता है। इस ऊर्जा के जरिये एक मिनी-जेनरेट भी चलाया जा सकता है।

वहीं, स्थिर पानी में बिजली पैदा करने के लिए शोधकर्ताओं ने अर्धचालकों से बोरान और नाइट्रोजन के साथ ग्राफीन ऑक्साइड को अलग कर दिया, ग्राफीन के दो रूपों को दो फिल्टर पेपरों में लोड किया, जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करते थे। शोधकर्ताओं ने कहा कि पानी में दो फिल्टर पेपर डुबाने से 570 मिलीवोल्ट तक की क्षमता पैदा होती है, जो 80 घंटे तक स्थिर रहती है।

शोध अनुसंधान

मोटापे से कमजोर होती है बच्चों की याददाश्त

मोटापा पूरी दुनिया में महामारी की तरह सामने आ रहा है। हालिया शोध के मुताबिक, मोटापे से बच्चों की याददाश्त भी कमजोर होती है। साथ ही सोचने और योजना बनाने में भी उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वेरमॉन्ट और येल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस संबंध में अध्ययन किया है। अध्ययन के लिए 10,000 किशोरों के आंकड़े जुटाए गए। 10 साल चले अध्ययन के दौरान हर दो साल में उनकी जांच की गई और ब्लड सैंपल लिया गया। इस दौरान उनके दिमाग की स्कैनिंग भी की जाती रही। वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन बच्चों का ब्बीएमआइ ज्यादा होता है, उनका सेरेब्रल कॉर्टेक्स पतला हो जाता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक परत है जो दिमाग के बाहरी हिस्से को ढकती है। इसके पतले होने से दिमाग की सोचने, याद रखने जैसी क्षमताएं प्रभावित हो जाती हैं। - एएनआइ

मिल सकता है बढ़ती उम्र में नजर कमजोर होने का इलाज

बढ़ती उम्र के साथ नजर कमजोर होते जाने से जुड़ी बीमारी एज-रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन के इलाज की दिशा में उम्मीद की नई किरण दिखी है। वैज्ञानिकों ने बताया कि रेटिना में कुछ लाइट रिसेप्टर होते हैं जो प्रकाश को सोखते हैं। फिर उस सूचना पर काम करते हुए संदेश दिमाग तक पहुंचाया जाता है। रेटिना का केंद्रीय भाग मैक्यूला आंख से दिमाग तक पहुंचने वाली ज्यादातर सूचनाओं पर काम करता है। देखना, पढ़ना और चेहरे पहचानने जैसी विभिन्न गतिविधियां इसी से संभव हो पाती हैं। बढ़ती उम्र के साथ मैक्यूलर में खराबी से एएमडी की समस्या होती है। शोध में पाया गया है कि हमारा दिमाग सूचनाओं पर काम करते समय दृश्य के अंतर को आसानी से समझ लेता है। इससे कृत्रिम रेटिना की मदद से एएमडी के कारगर इलाज का रास्ता खुल सकता है। - एएनआइ

नए साल के स्वागत की तैयारी

दुनियाभर में नववर्ष के स्वागत में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रमुख बाजारों, ऐतिहासिक भवनों और प्रमुख स्थानों को रोशनी से जगमगाया जा रहा है। यह तस्वीर निकारागुआ की राजधानी मैनागुआ में क्रांति स्क्वायर की है, जहां भव्य तरीके से रोशनी की गई है। एएफपी

टीवी एंकर संग थिरके राष्ट्रपति अलेक्जेंडर

बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको (मध्य में हाथ उठाए) का राजधानी मिंस्क में टीवी एंकर पोलिना शुबा के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल, लुकाशेंको नववर्ष के एक समारोह में शरीक हुए थे। इसी दौरान टीवी एंकर ने उन्हें डांस का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। नए साल के जश्न में देश की राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य क्षेत्र की हस्तियां शामिल हुई थीं। एपी

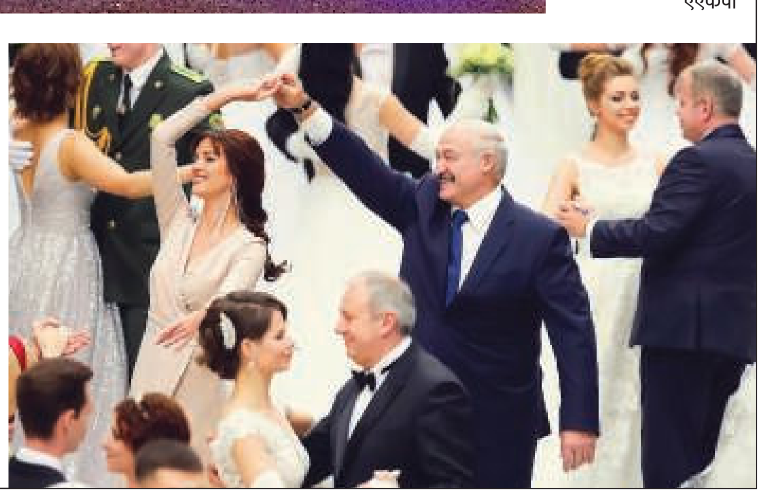

स्क्रीन शॉट

संसार में आने के बाद संतान से होता है पिता का लगाव : अक्षय कुमार

बीते शुक्रवार को रिलीज हुई अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म 'गुड न्यूज' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है। इस सप्ताहांत में फिल्म की कमाई करीब 64.9 करोड़ रुपये रही। 'गुड न्यूज' आईवीएफ प्रक्रिया से पहली बार संतान का सुख ले रहे दो कपल्स की कहानी है। फिल्म में आईवीएफ की प्रक्रिया के दौरान घालमेल होता है। उस वजह से अक्षय के किरदार की पत्नी के अंडाणु का निषेचन एक अन्य पुरुष के स्पर्म से हो जाता है। लिहाजा अपनी पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे से उसे लगाव नहीं होता है। असल जिंदगी में पहली बार पिता बनने के अपने अनुभव को साझा करते हुए अक्षय ने कहा, 'मां का अपनी संतान से लगाव गर्भावस्था के पहले दिन से ही रहता है, लेकिन पिता की भावनाएं संतान से इस दुनिया में आने के बाद ही जुड़ती हैं। मुझे याद है कि पहली बार पिता बनने के एहसास को समझने में मुझे दो महीने लग गए थे। जब संतान पिता की गोद में आकर उसे संबोधित करती है, तो एक झटके में ही पिता की सारी भावनाएं अपनी संतान के साथ जुड़ जाती हैं।' अक्षय बच्चों को सेक्स शिक्षा दिए जाने के हिमायती हैं और मानते हैं कि इसके बारे में बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। 'गुड न्यूज' में अक्षय के साथ करीना कपूर खान, कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिका में हैं। गुड न्यूज अक्षय की इस साल रिलीज होने वाली चौथी फिल्म है। उनकी पिछली तीन फिल्में 'केसरी', 'मिशन मंगल' और 'हाउसफुल 4' भी हिट रही थीं।

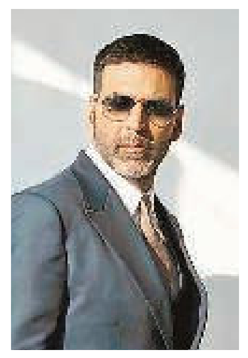

पहाड़ों के दोस्त...

साल 2019 का आज आखिरी दिन है। ज्यादातर फिल्मी हस्तियां छुट्टियां मना रही हैं। वरुण धवन अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ स्विट्जरलैंड में हैं। हाल में वहां से करीना कपूर खान और उनकी बहन करिश्मा कपूर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई थीं। अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ वरुण ने अपनी तस्वीर साझा की है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी स्विट्जरलैंड नए साल का जश्न मनाने पहुंचे हैं। दोनों जोड़ियां एक ही जगह पर एक-दूसरे से टकरा गईं। तस्वीर में वरुण की गर्लफ्रेंड नताशा भी नजर आ रही हैं। वरुण ने लिखा, 'पहाड़ों के दोस्त।' वरुण और अनुष्का 'सुई धागा : मेड इन इंडिया' कर चुके हैं।

पूरा परिवार एक फ्रेम में...

सलमान खान की भांजी और अर्पिता शर्मा-आयुष शर्मा की बेटी आयत की पहली तस्वीर सामने आई है। आयत का जन्म सलमान खान के जन्मदिन यानी 27 दिसंबर के दिन हुआ था। आयुष शर्मा ने अस्पताल से ही अपनी बेटी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं, जिसे उनके फैंस का बहुत प्यार मिल रहा है। एक तस्वीर में आयुष शर्मा, उनकी पत्नी अर्पिता, दोनों का तीन साल का बेटा आहिल और नन्ही परी आयत नजर आ रही हैं। आयुष ने लिखा, 'इस खूबसूरत दुनिया में तुम्हारा स्वागत है आयत। तुम हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आई हो। यही दुआ करता हूं कि तुम सबके जीवन में प्यार और खुशियों लेकर आओगी।'

'फाइटर' में नजर आएंगी राम्या कृष्णन

'बाहुबली' फेम राम्या कृष्णन अपनी वेब सीरीज 'क्वीन' को लेकर चर्चा में हैं। इसमें उनकी परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया जा रहा है। एक और खबर आई है कि फिल्ममेकर पुरी जगन्नाथ की अगली एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'फाइटर' में भी राम्या कृष्णन नजर आएंगी। इसमें वह दक्षिण के चर्चित अभिनेता विजय देवराकोंडा के साथ दिखेंगी। वह इसमें विजय की मां का किरदार निभाएंगी।

रिपोर्ट के अनुसार, 'फाइटर' के अधिकांश दृश्यों की शूटिंग मुंबई में की जाएगी और यह फिल्म आने वाले साल के जनवरी महीने में रिलीज की जाएगी। फिल्म को तेलुगु, हिंदी के अलावा कई अन्य भाषाओं में भी बनाया जाएगा। फिल्म में जाह्नवी कपूर भी लीड रोल में नजर आएंगी, ऐसी चर्चा बॉलीवुड में चल रही है।

नई तकनीक से कम होगी जेरेनियम खेती की लागत

मिलेगा लाभ

सीएसआइआर-केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित की पॉलीहाउस की सुरक्षात्मक शेड तकनीक

जेरेनियम की खेती की गुणवत्ता की जांच करते सीमैप के वैज्ञानिक। साभार : आइएसडब्ल्यू

नई दिल्ली। आइएसडब्ल्यू : सुगंधित पौधों की खेती किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी एक प्रमुख जरिया बन सकती है। जेरेनियम भी एक ऐसा ही सुगंधित पौधा है जिसका तेल बेहद कीमती होता है। लखनऊ स्थित सीएसआइआर-केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (सीमैप) के वैज्ञानिकों ने पॉलीहाउस की सुरक्षात्मक शेड तकनीक विकसित की है, जिससे जेरेनियम उगाने की लागत कम हो गई है।

आमतौर पर जेरेनियम के पौधे से पौध तैयार की जाती है। लेकिन, बारिश के दौरान पौध खराब हो जाती थी, जिसके कारण किसानों को पौध सामग्री काफी महंगी पड़ती थी। सीमैप के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित जेरेनियम की खेती की इस नई तकनीक से करीब 35 रुपये की लागत में तैयार होने वाला पौधा अब सिर्फ दो रुपये में तैयार किया जा सकेगा।

इस परियोजना नेतृत्व कर रहे सीमैप के वैज्ञानिक डॉ. सौदान सिंह ने बताया कि जेरेनियम की पौध को अब तक वातानुकूललित ग्लास हाउस में संरक्षित किया जाता था, लेकिन अब पॉलीहाउस की सुरक्षात्मक शेड तकनीक विकसित हो जाने से किसान के खेत पर ही काफी सस्ती लागत में इसे तैयार कर सकते हैं। एक एकड़ खेती के लिए करीब चार हजार पौधों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए 50-60 वर्ग मीटर का पॉलीहाउस बनाना होता है, जिसमें करीब 8-10 हजार रुपये का खर्च आता है। दोमट और बलुई दोमट मिट्टी में जेरेनियम की फसल बढ़िया होती है। इसकी खेती का सबसे उपयुक्त समय नवंबर महीने को माना जाता है। डॉ. सौदान सिंह ने बताया कि सीमैप ने सगंध फसल के अंतर्गत मेंथा के विकल्प के रूप में जेरेनियम को बढ़ावा देने के लिए अरोमा मिशन के अंतर्गत इसकी खेती शुरू की गई है। सीमैप अरोमा मिशन के तहत जेरेनियम की खेती को बढ़ावा देने के लिए मदर प्लांट भी उपलब्ध करा रहा है।

बढ़ाया जाएगा उत्पादन : सीमैप के कार्यकारी निदेशक डॉ. अब्दुल समद ने बताया कि सीमैप द्वारा अरोमा मिशन के तहत इस वर्ष जेरेनियम की पौध सामग्री से लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती हो सकेगी। उम्मीद की जा रही है कि इससे अगले वर्ष जून तक लगभग 750 किलो सुगंधित तेल प्राप्त किया जा सकेगा।

इन राज्यों में होती है खेती जेरेनियम मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका का पौधा है। इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में होती है। जेरेनियम के पौधे से प्राप्त तेल काफी कीमती होता है। भारत में इसकी औसत कीमत करीब 12 से 18 हजार रुपये प्रति लीटर है। मात्र चार माह की फसल में लगभग 80 हजार रुपये की लागत आती है और इससे करीब 1.50 लाख रुपये तक मुनाफा होता है।